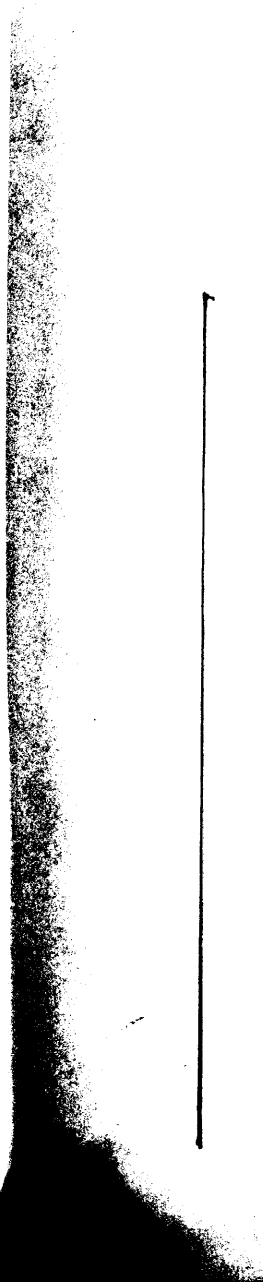


बैंकिंग परिचालन
और
विकास विभाग
के परिपत्र
1998

CIRCULARS OF THE
DEPARTMENT OF
BANKING OPERATIONS
AND DEVELOPMENT
1998





बैंकिंग परिचालन
और
विकास विभाग
के परिपत्र
1998

CIRCULARS OF THE
DEPARTMENT OF
BANKING OPERATIONS
AND DEVELOPMENT
1998



प्रकाशक :

ए. घोष

मुख्य महाप्रबंधक

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई 400 005

Published by :

A. Ghosh

Chief General Manager

Department of Banking Operations
and Development

Reserve Bank of India

Mumbai 400 005

मुद्रक :

मोना प्रिंटेर्स

इंडिया प्रिंटिंग हाऊस,

वडाला, मुंबई 400 031

Printed by :

Mona Printers

India Printing House

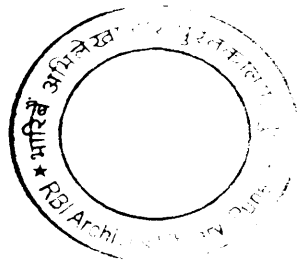
Wadala, Mumbai 400 031

भारत में मुद्रित

Printed In India

332.1130954
DBOD & RBI

7326 08



08 MAR 2011

सामान्य विषयवस्तु,
अनुभागवार अनुक्रमणिका
और कालानुक्रमणिका

**GENERAL CONTENTS,
SECTIONAL INDEX AND
CHRONOLOGICAL INDEX**

सामान्य विषयवस्तु

	पृष्ठ सं.
भाग II : जमाराशि	1
भाग III : ऋण नीति/बैंकों को पुनर्वित्त की समीक्षा	11
भाग IV : निवेश	15
भाग V : अग्रिम	67
भाग VI : ऋण नियंत्रण - सामान्य	105
भाग VII : ऋण सूचना	151
भाग VIII : नियुक्तियाँ/पारिश्रमिक	157
भाग IX : विवरणी	159
भाग X : विविध	185
क) शाखा विस्तार	185
ख) बैंकों द्वारा शुरू किये गये गैर-पारंपारिक कार्य - व्यापारी बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड प्रणाली, किराया खरीद व्यवसाय, आदि	188
ग) बैंकों में ग्राहक सेवा	192
घ) बैंकों में धोखाधड़ी, आदि	196
ड) अन्य200	
भाग XI : बैंकों में हिन्दी का प्रयोग	419

GENERAL CONTENTS

	Page No.
Section II : Deposits	1
Section III : Review of Credit Policy/Refinance to banks	11
Section IV : Investments	15
Section V : Advances	67
Section VI : Credit Control - General	105
Section VII : Credit Information	151
Section VIII : Appointments/Remuneration	157
Section IX : Returns	159
Section X : Miscellaneous :	185
a) Branch expansion	185
b) Non-traditional type of work taken up by banks-Merchant banking, credit card system, hire-purchase business etc.	188
c) Customer Service in banks	192
d) Frauds, etc. in banks	196
e) Others	200
Section XI : Use of Hindi in banks	419

अनुभागवार अनुक्रमणिका

परिपत्र संख्या और दिनांक	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.

भाग II जमाराशि

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 7/13.01.09/98 दिनांक 20.1.1998	वापस आ रहे भारतीयों के विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) खातों का आरएफसी खातों/निवासी रुपया खातों में परिवर्तन-ब्याज की अदायगी	1
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 11/13.01.08/98 दिनांक 10.2.1998	स्वसहायता (सेल्फ हेल्प) समूहों के नाम से बचत बैंक खाते खोलना	2
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 25/13.01.08/98 दिनांक 2.4.1998	फार्मर्स क्लब-विकास वालंटियर वाहिनी के नाम में बचत बैंक खाते खोलना	4
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 28/13.01.09/98 दिनांक 4.4.1998	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) जमाराशि का अवधिपूर्व आहरण-स्वैप लागत की वसूली	5
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 69/13.01.10/98 दिनांक 3.7.1998	दान	6
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 93/21.02.045/98 दिनांक 8.9.1998	ब्याज दर के विभिन्न दायरों के अनुसार जमाराशियों और अग्रिमों के ब्यौरे	8

भाग III ऋण नीति/बैंकों को पुनर्वित्त की समीक्षा

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 14/24.91.001/98 दिनांक 16.2.1998	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने के लिए अनुमति-निजी क्षेत्र म्युच्युअल फंड	11
बैंपविवि. सं. बीसी. 58/24.91.001/98 दिनांक 12.6.1998	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति-निजी क्षेत्र के म्युच्युअल फंड	12
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 107/13.07.05/98-99 दिनांक 11.11.1998	बैंकों द्वारा बिलों का पुनर्भाजन	13

परिपत्र संख्या और दिनांक	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
		भाग IV निवेश
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 2/24.76.002/97-98 दिनांक 5.1.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	15
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 1/24.76.002/97-98 दिनांक 5.1.1998	हाज़िर-वायदा लेनदेन (निदेश)	16
बैंपविवि. सं. बीसी. 8/12.02.001/97-98 दिनांक 22.1.1998	भारत सरकार द्वारा जारी 6 प्रतिशत कैपिटल इंडेक्स बांड, 2002 का मूल्यन	17
बैंपविवि. सं. बीसी. 31/24.76.002/97-98 दिनांक 29.4.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	21
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 30/24.76.002/97-98 दिनांक 29.4.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	22
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 39/24.76.002/98 दिनांक 6.5.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन	23
बैंपविवि. सं. एफएससी बीसी. 41/24.76.002/97-98 दिनांक 18.5.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	29
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 40/24.76.002/98 दिनांक 18.5.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	30
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 46/24.76.002/97-98 दिनांक 25.5.1998	हाज़िर-वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	31
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 45/24.76.002/98 दिनांक 25.5.1998	हाज़िर-वायदा लेनदेन (निदेश)	32

परिपत्र संख्या और दिनांक	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 57/24.76.002/97-98 दिनांक 12.6.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	33
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 56/24.76.002/98 दिनांक 12.6.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	34
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 65/24.76.002/87-98 दिनांक 29.6.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	35
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 64/24.76.002/98 दिनांक 29.6.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	36
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 68/24.76.002/97-98 दिनांक 3.7.1998	प्रतिवर्ती हाज़िर-वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	37
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 67/24.76.002/98 दिनांक 3.7.1998	प्रतिवर्ती हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	38
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 71/24.76.002/97-98 दिनांक 8.7.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	43
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 70/24.76.002/98 दिनांक 8.7.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	44
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 75/21.04.048/98 दिनांक 4.8.1998	सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का अर्जन-खंडित अवधि के लिए ब्याज - लेखांकन की प्रक्रिया	46
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 78/13.07.05/98-99 दिनांक 8.8.1998	कंपनी निकायों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश और हामीदारी	47
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 80/24.76.002/98 दिनांक 10.8.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	48

परिपत्र संख्या और दिनांक	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 79/24.76.002/98 दिनांक 10.8.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	49
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 82/24.76.002/98 दिनांक 13.8.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	51
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 81/24.76.002/98 दिनांक 13.8.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	52
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 88/24.76.002/98 दिनांक 24.8.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	53
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 87/24.76.002/98 दिनांक 24.8.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	54
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 92/24.76.002/98 दिनांक 7.9.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	55
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 91/24.76.002/98 दिनांक 7.9.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	56
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 96/24.76.002/98 दिनांक 21.9.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	57
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 95/24.76.002/98 दिनांक 21.9.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	58
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 98/24.76.002/98 दिनांक 7.10.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	59
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 97/24.76.002/98 दिनांक 7.10.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	60

परिपत्र संख्या और दिनांक	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 102/24.76.002/98-99 दिनांक 30.10.1998	सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा लेनदेन	61
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 113/24.76.002/98 दिनांक 4.12.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	63
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 112/24.76.002/98 दिनांक 4.12.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	64
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 117/24.76.002/98 दिनांक 15.12.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	65
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 116/24.76.002/98 दिनांक 15.12.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	66
		भाग V
		अग्रिम
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 47/13.01.09/98 दिनांक 28.5.1998	एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ऋण तथा एफसीएनआर (बी)/एनआरएनआर पूल से ऋण	67
आईसीडी. सं. 47/3840/04.02.01/97-98 दिनांक 11.6.1998	निर्यात ऋण	69
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 55/13.03.00/98 दिनांक 11.6.1998	अग्रिमों पर ब्याज दरें	72
आईसीडी. सं. 5/04.02.01/98-99 दिनांक 6.8.1998	निर्यात ऋण - ब्याज दरें	73
बैंपविवि. सं. बीसी. 77/13.07.01/98 दिनांक 6.8.1998	अग्रिमों पर ब्याज दरें	74

परिपत्र संख्या और दिनांक	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 83/21.04.012/98 दिनांक 18.8.1998	जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट	78
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 90/13.07.05/98-99 दिनांक 28.8.98	शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर बैंक वित्त-मास्टर परिपत्र	79
बैंपविवि. सं. आईबीएस. बीसी. 104/23.37.001/98-99 दिनांक 12.11.1998	भारत स्थित बैंकों द्वारा विदेश स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं को ऋण/ऋण से इतर सुविधाएं तथा विदेश स्थित पार्टियों को क्रेता का ऋण और स्वीकृति वित्त की सुविधाएं प्रदान करना	98
बैंपविवि. सं. डीआइआर बीसी. 115/13.07.05/98-99 दिनांक 9.12.1998	संपार्श्विक जमानत के रूप में धारित प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण	101

भाग VI
ऋण नियंत्रण (सामान्य)

बैंपविवि. सं. बीसी. 5/12.01.001/97-98 दिनांक 16.1.1998	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि (प्रावरण पत्र)	105
बैंपविवि. सं. बीसी. 4/12.01.001/97-98 दिनांक 16.1.1998	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि (अधिसूचना)	106
बैंपविवि. सं. बीसी. 6/12.02.001/97-98 दिनांक 16.1.1998	नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात (सीआरआर/एसएलआर) बनाये रखने में कमियां होने पर दंड ब्याज दर	107
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 13/21.01.023/98 दिनांक 12.2.1998	चल आस्तियां रखने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तिय कंपनियों की प्रतिभूतियों की नामित बैंकों के पास अभिरक्षा	109
बैंपविवि. सं. बीसी. 20/12.02.001/97-98 दिनांक 18.3.1998	नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात (सीआरआर/एसएलआर) बनाये रखने में कमी होने पर दंड स्वरूप ब्याज दर	110

परिपत्र संख्या और दिनांक	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. बीसी. 22/12.01.001/97-98 दिनांक 23.3.1998	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती - (प्रावरण पत्र)	111
बैंपविवि. सं. बीसी. 21/12.01.001/97-98 दिनांक 23.3.1998	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती - (अधिसूचना)	113
बैंपविवि. सं. बीसी. 26/12.02.001/97-98 दिनांक 2.4.1998	नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात (सीआरआर/एसएलआर) बनाये रखने में कमी होने पर दंड स्वरूप ब्याज दर	114
बैंपविवि. सं. डीआइआर बीसी. 36/13.03.00/98 दिनांक 29.4.1998	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय (प्रावरण पत्र)	115
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 33/13.03.00/98 दिनांक 29.4.1998	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	124
बैंपविवि. सं. डीआइआर बीसी. 34/13.03.00/98 दिनांक 29.4.1998	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	132
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 35/13.03.00/98 दिनांक 29.4.1998	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	137
बैंपविवि. सं. बीसी. 44/12.01.001/97-98 दिनांक 20.5.1998	10प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अंतर्गत 3 मई 1991 तथा 17 अप्रैल 1992 के बीच जब्त शेष राशियों का निर्मोचन (प्रावरण पत्र)	140
बैंपविवि. सं. बीसी. 43/12.01.001/97-98 दिनांक 20.5.1998	10प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अंतर्गत 3 मई 1991 तथा 17 अप्रैल 1992 के बीच जब्त शेष राशियों का निर्मोचन (अधिसूचना)	141
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 60/13.03.00/98 दिनांक 15.6.1998	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय	144

परिपत्र संख्या और दिनांक	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. बीसी. 86/12.01.001/98-99 दिनांक 20.8.1998	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि (प्रावरण पत्र)	148
बैंपविवि. सं. बीसी. 85/12.01.001/98-99 दिनांक 20.8.1998	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि (अधिसूचना)	150

भाग VII
ऋण सूचना

बैंपविवि. सं. डीएल. बीसी. 23/20.16.002/98 दिनांक 24.3.1998	सूचना का प्रकटीकरण - मुकदमा दायर खातों की सूची प्रस्तुत करना	151
बैंपविवि. सं. डीएल. बीसी. 106/20.16.003/98-99 दिनांक 11.11.1998	फ्लॉपी डिस्क्रेट पर चूककर्ताओं की सूची और मुकदमा दायर खातों का विवरण प्रस्तुत करना	152
बैंपविवि. सं. डीएल. बीसी. 109/20.16.002/98-99 दिनांक 18.11.1998	चूककर्ता उधारकर्ताओं संबंधी सूचना का प्रकटीकरण - 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के मुकदमा दायर खातों की सूची का प्रकाशन	154

भाग VIII
नियुक्तियाँ/पारिश्रमिक

बैंपविवि. सं. बीसी. 54/08.95.004/98 दिनांक 10.6.1998	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी - निदेशकों को देय बैठक शुल्क/अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/प्रबंध निदेशकों/निदेशकों को देय यात्रा और विराम भत्ता	157

परिपत्र संख्या और दिनांक	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
		भाग IX विवरणी
बैंपविवि. सं. बीसी. 3/12.03.001/97-98 दिनांक 10.1.1998	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 फार्म IX में विवरण प्रस्तुत करना - दावा न की गयी जमाराशियां	159
बैंपविवि. सं. बीसी. 15/12.05.005/97-98 दिनांक 24.2.1998	मुख्य वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्रों से संबंधित विवरणियों की समीक्षा, युक्तिकरण और पुनर्चना	160
बैंपविवि. सं. बीसी. 89/12.01.001/98-99 दिनांक 24.8.1998	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) - फार्म ए में विवरणी	164
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 118/24.76.002/98 दिनांक 26.12.1998	संविभाग प्रबंधन सेवाओं के लिए सूचना प्रणाली	183
		भाग X विविध
	क) शाखा विस्तार	
	ख) बैंकों द्वारा शुरू किये गये गैर-पारंपारिककार्य - व्यापारी बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड प्रणाली, किराया खरीद व्यवसाय, आदि	
	ग) बैंकों में ग्राहक सेवा	
	घ) बैंकों में धोखाधड़ी, आदि	
	ङ) अन्य	
	क) शाखा विस्तार	
बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 74/22.01.001/98 दिनांक 29.7.1998	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23-प्रखण्ड/सेवा क्षेत्र के बाहर ग्रामीण शाखाओं का स्थानांतरण तथा ग्रामीण शाखाएं बंद करना	185

परिपत्र संख्या और दिनांक	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
	ख) बैंकों द्वारा शुरू किये गये गैर-पारंपारिककार्य - व्यापारी बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड प्रणाली, किराया खरीद व्यवसाय, आदि	
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 49/24.01.001/98 दिनांक 2.6.1998	बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत रिपोर्टें/ समीक्षा	188
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 50/24.01.011/98 दिनांक 2.6.1998	देशी क्रेडिट कार्ड कारोबार में बैंकों का प्रवेश	189
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 61/24.47.001/98 दिनांक 23.6.1998	स्टॉकइनवेस्ट योजना	191
	ग) बैंकों में ग्राहक सेवा	
बैंपविवि. सं. बीसी. 100/09.07.007/98-99 दिनांक 12.10.1998	बूढ़े/बीमार/अक्षम ग्राहकों द्वारा बैंक खातों का परिचालन	192
	घ) बैंकों में धोखाधड़ी, आदि	
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 24/21.01.023/98 दिनांक 30.3.1998	बैंकों में धोखाधड़ी/लाभांश/ब्याज वारंटों तथा धन-वापसी आदेशों के लिए सममूल्य सुविधा की स्वीकृति	196
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 59/21.01.023/98 दिनांक 15.6.1998	सेवानिवृत्ति से पूर्व बैंक अधिकारियों की मंजूरी संबंधी शक्तियां	198
	ड) अन्य	
बैंपविवि. सं. आइबीएस. 1410/23.67.001/97-98 दिनांक 1.1.1998	स्वर्ण/चांदी का आयात	200

परिपत्र संख्या और दिनांक	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. बीसी. 9/21.04.018/98 दिनांक 27.1.1998	बैंकों का तुलनपत्र-प्रकटीकरण	201
बैंपविवि. सं. बीसी. 10/09.08.001/97-98 दिनांक 3.2.1998	कार्य स्थलों में यौन उत्पीड़न - ऐसे उत्पीड़न को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शी सिद्धांत-उनका कार्यान्वयन	203
बैंपविवि. सं. आइबीएस. 1816/23.67.001/97-98 दिनांक 4.2.1998	सोना/चांदी/प्लेटिनम की बिक्री - नकद रूप में अदायगी	212
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 12/21.01.023/98 दिनांक 11.2.1998	आंकड़े प्रस्तुत करना - गोपनीयता संबंधी दायित्वों का उल्लंघन	214
बैंपविवि. सं. बीसी. 16/09.07.007/97-98 दिनांक 27.2.1998	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन)	216
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 17/21.04.048/98 दिनांक 4.3.1998	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - कृषि अग्रिम	217
बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 18/23.67.001/97-98 दिनांक 4.3.1998	सोना/चांदी का आयात	219
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 19/21.01.023/97-98 दिनांक 10.3.1998	भारत में विभिन्न संघों/संगठनों द्वारा विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विदेशी अभिदान	220
बैंपविवि. सं. आइबीएस. 1929/23.67.001/97-98 दिनांक 14.3.1998	भारत सरकार द्वारा जारी 6 प्रतिशत कैपिटल स्वर्ण का आयात	223
बैंपविवि. सं. बीसी. 27/12.06.114/97-98 दिनांक 3.4.1998	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन- 'दि टोरोन्टो-डोमिनियन बैंक'	224

परिपत्र संख्या और दिनांक	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 29/21.04.048/98 दिनांक 11.4.1998	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण प्रावधान तथा अन्य संबंधित मामले-निवेशों का मूल्यन	225
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 32/21.04.018/98 दिनांक 29.4.1998	पूंजी पर्याप्तता, तुलनपत्रों में प्रकटीकरण	236
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 42/21.04.018/98 दिनांक 19.5.1998	लेखा मानदंड 11 (संशोधित)	238
बैंपविवि. सं. बीसी. 48/08.95.004/98 दिनांक 30.5.1998	अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा विदेश में अधिकारिक दौरे	239
बैंपविवि. सं. पीएसबीएस. बीसी. 72/16.13.100/98-99 दिनांक 10.7.1998	निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयर जारी करना	241
बैंपविवि. सं. एमसी. 2/19.06.02/97-98 दिनांक 20.7.1998	अप्रैल 1998-मार्च 2000 की अवधि के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों हेतु कार्य-योजना	242
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 73/21.04.018/98 दिनांक 27.7.1998	अंतर शाखा खाते - पुरानी बकाया जमा प्रविष्टियां	244
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 94/21.04.098/98 दिनांक 10.9.1998	आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली	246
बैंपविवि. सं. 174/09.06.001/98-99 दिनांक 24.9.1998	ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए कार्यदल - सिफारिशें	347
बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 99/23.09.001/98-99 दिनांक 9.10.1998	भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा लाभ का प्रेषण	349

परिपत्र संख्या और दिनांक	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. बीसी. 101/12.04.002/98-99 दिनांक 15.10.1998	तार अंतरण भुनाई सुविधा-नवीकरण	353
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 103/21.01.002/98 दिनांक 31.10.1998	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय	354
बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 105/22.01.03/98 दिनांक 11.11.1998	वाणिज्य बैंकों द्वारा अपने उपयोग (अर्थात् कार्यालय और स्टाफ के निवास) के लिए पट्टा/किराया के आधार पर आवास का अर्जन	370
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 108/21.01.023/98 दिनांक 17.11.1998	विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विदेशी अंशदानों की स्वीकृति	390
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 110/21.02.051/98 दिनांक 18.11.1998	ऐसे लेनदेन जिनके बारे में सभी प्रलेखों में स्थायी खाता सं. (पीएन) या सामान्य सूचकांक रजिस्टर (जीआइआर) संख्या दी जानी है - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3 में जारी 9 अक्टूबर 1998 की अधिसूचना	407
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 119/21.01.002/98 दिनांक 28.12.1998	मौद्रिक और ऋण नीति उपाय - पूंजी पर्याप्तता अनुपात - वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी बांडों/प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों पर जोखिम भार	412
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 120/21.04.048/98 दिनांक 29.12.1998	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड-प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित कृषि ऋण	413
बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 1519/23.67.001/97-98 दिनांक 31.12.1998	स्वर्ण ऋण	415

परिपत्र संख्या और दिनांक	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.

भाग XI
बैंकों में हिन्दी का प्रयोग

बैंपविवि. सं. बीसी. 51/06.02.01/98 दिनांक 2.6.1998	हिन्दी संवर्ग का निर्माण और हिन्दी पदों को भरना	419
बैंपविवि. सं. बीसी. 62/06.02.01/98 दिनांक 26.6.1998	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 75वीं बैठक - अनुवर्ती कार्रवाई	421

SECTIONAL INDEX

Circular No & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.

SECTION II DEPOSITS

DBOD No. Dir. BC 7/13.01.09/98 dated 20.1.1998	Conversion of FCNR(B) Accounts of the Returning Indians into RFC Accounts/ Resident Rupee Account - Payment of interest	1
DBOD No. Dir. BC 11/13.01.08/98 dated 10.2.1998	Opening of savings bank accounts in the name of Self-Help Groups (SHGs)	2
DBOD No. Dir. BC 25/13.01.08/98 dated 2.4.1998	Opening of savings bank accounts in the name of Farmers' Clubs-Vikas Volunteer Vahini (VVV)	4
DBOD No. Dir. BC 28/13.01.09/98 dated 4.4.1998	Premature withdrawals of FCNR(B) deposit - Recovery of swap cost	5
DBOD No. Dir. BC 69/13.01.10/98 dated 3.7.1998	Donations	6
DBOD No. BP. BC 93/21.02.045/98 dated 8.9.1998	Break-down of Deposits and Advances according to different interest rate ranges	8

SECTION III REVIEW OF CREDIT POLICY/REFINANANCE TO BANKS

DBOD No. FSC. BC 14/24.91.001/98 dated 16.2.1998	Permission to participate in Call/Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	11
DBOD No. BC 58/24.91.001/98 dated 12.6.1998	Permission to participate in Call/Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	12
DBOD No. Dir. BC 107/13.07.05/98-99 dated 11.11.1998	Rediscounting of Bills by banks	13

Circular No & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.

SECTION IV INVESTMENTS

DBOD No. FSC.BC. 2/24.76.002/97-98 dated 5.1.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	15
DBOD No. FSC. BC. 1/24.76.002/97-98 dated 5.1.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	16
DBOD No. BC. 8/12.02.001/97-98 dated 22.1.1998	Valuation of 6 per cent Capital Indexed Bonds, 2002 issued by Government of India	17
DBOD No. BC 31/24.76.002/97-98 dated 29.4.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	21
DBOD No. FSC. BC 30/24.76.002/97-98 dated 29.4.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	22
DBOD No. FSC.BC 39/24.76.002/98 dated 6.5.1998	Ready Forward Transactions	23
DBOD No. FSC.BC 41/24.76.002/97-98 dated 18.5.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	29
DBOD No. FSC.BC 40/24.76.002/98 dated 18.5.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	30
DBOD No. FSC.BC 46/24.76.002/97-98 dated 25.5.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	31
DBOD No. FSC. BC 45/24.76.002/98 dated 25.5.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	32

Circular No & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD No. FSC.BC 57/24.76.002/97-98 dated 12.6.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	33
DBOD No.FSC. BC 56/24.76.002/98 dated 12.6.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	34
DBOD No. FSC.BC 65/24.76.002/98 dated 29.6.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	35
DBOD No. FSC.BC 64/24.76.002/98 dated 29.6.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	36
DBOD No. FSC.BC 68/24.76.002/97-98 dated 3.7.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	37
DBOD No. FSC.BC 67/24.76.002/98 dated 3.7.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	38
DBOD No. FSC.BC 71/24.76.002/97-98 dated 8.7.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	43
DBOD No. FSC.BC 70/24.76.002/98 dated 8.7.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	44
DBOD No. BP.BC 75/21.04.048/98 dated 4.8.1998	Acquisition of Government and other approved securities - Broken period interest - Accounting procedure	46
DBOD No. Dir. BC 78/13.07.05/98-99 dated 8.8.1998	Investment in and underwriting of shares and debentures of corporate bodies	47
DBOD No. FSC.BC 80/24.76.002/98 dated 10.8.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	48

Circular No & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD No. FSC.BC 79/24.76.002/98 dated 10.8.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	49
DBOD No. FSC.BC 82/24.76.002/98 dated 13.8.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	51
DBOD No. FSC.BC 81/24.76.002/98 dated 13.8.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	52
DBOD No. FSC.BC 88/24.76.002/98 dated 24.8.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	53
DBOD No. FSC.BC 87/24.76.002/98 dated 24.8.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	54
DBOD No. FSC.BC 92/24.76.002/98 dated 7.9.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	55
DBOD No. FSC.BC 91/24.76.002/98 dated 7.9.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	56
DBOD No. FSC.BC 96/24.76.002/98 dated 21.9.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	57
DBOD No. FSC.BC 95/24.76.002/98 dated 21.9.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	58
DBOD No. FSC.BC 98/24.76.002/98 dated 7.10.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	59
DBOD No. FSC.BC 97/24.76.002/98 dated 7.10.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	60

Circular No & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD No.FSC.BC 102/24.76.002/98-99 dated 30.10.1998	Ready Forward Transactions (Repos) Government and other Approved Securities	61
DBOD No. FSC.BC 113/24.76.002/98 dated 4.12.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	63
DBOD No. FSC.BC 112/24.76.002/98 dated 4.12.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	64
DBOD No. FSC.BC 117/24.76.002/98 dated 15.12.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	65
DBOD No. FSC.BC 116/24.76.002/98 dated 15.12.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	66
SECTION V ADVANCES		
DBOD No. Dir. BC 47/13.01.09/98 dated 28.5.1998	Loans against FCNR(B) deposits and loans out of FCNR(B)/NRNR pools.	67
IECD No. 47/ 3840/04.02.01/97-98 dated 11.6.1998	Export Credit	69
DBOD No. Dir. BC 55/13.03.00/98 dated 11.6.98	Interest rates on advances (Directive)	72
IECD No. 5/04.02.01/98-99 dated 6.8.1998	Export Credit - Interest rates	73
DBOD No. BC 77/13.07.01/98 dated 6.8.1998	Interest rates on advances (Directive)	74

Circular No & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD No. BP.BC 83/21.04.012/98 dated 18.8.1998	Relaxations to trade and industry in the State of Jammu & Kashmir	78
DBOD No. Dir. BC 90/13.07.05/98-99 dated 28.8.1998	Bank Finance against shares and debentures - Master Circular	79
DBOD No. IBS.BC 104/23.37.001/98-99 dated 12.11.1998	Extension of credit/non-credit facilities to Indian Joint Ventures/ Wholly Owned Subsidiaries abroad and extension of buyer's credit and acceptance finance to overseas parties by banks in India	98
DBOD No. Dir. BC 115/13.07.05/98-99 dated 9.12.1998	Dematerialisation of Securities held as collaterals	101

SECTION VI CREDIT CONTROL (GENERAL)

DBOD No. BC 5/12.01.001/97-98 dated 16.1.1998	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Increase in Cash Reserve Ratio (CRR) (Covering letter)	105
DBOD No. BC 4/12.01.001/97-98 dated 16.1.1998	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Increase in Cash Reserve Ratio (CRR) (Notification)	106
DBOD No. BC 6/12.02.001/97-98 dated 16.1.1998	Penal rate of interest on the shortfall in the maintenance of CRR/SLR	107
DBOD No. BP.BC 13/21.01.023/98 dated 12.2.1998	Custody of securities of NBFCs with designated banks towards maintenance of liquid assets.	109
DBOD No. BC 20/12.02.001/97-98 dated 18.3.1998	Penal rate of interest on the shortfall in the maintenance of CRR/SLR	110

Circular No & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD No. BC 22/12.01.001/97-98 dated 23.3..1998	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio(CRR) (Covering letter)	111
DBOD No.BC 21/12.01.001/97-98 dated 23.3.1998	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio(CRR) - (Notification)	113
DBOD No. BC 26/12.02.001/97-98 dated 2.4.1998	Penal rate of interest on the shortfall in the maintenance of CRR/SLR	114
DBOD No. Dir. BC 36/13.03.00/98 dated 29.4.1998	Monetary and Credit Policy Measures (Covering letter)	115
DBOD No. Dir. BC 33/13.03.00/98 dated 29.4.1998	Interest rates on advances (Directive)	124
DBOD No. Dir. BC 33/13.03.00/98 dated 29.4.1998	Interest rates on deposits (Directive)	132
DBOD No. Dir. BC. 34/13.03.00/98 dated 29.4.1998	Interest rates on deposits held under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) Scheme (Directive)	137
DBOD No. BC 44/12.01.001/97-98 dated 20.5.1998	Release of balance impounded between 3 rd May 1991 and 17 th April 1992 under 10 per cent incremental CRR (Covering letter)	140
DBOD No. BC 43/12.01.001/97-98 dated 20.5.1998	Release of balance impounded between 3 rd May 1991 and 17 th April 1992 under 10 per cent incremental CRR (Notification)	141
DBOD No. Dir. BC 60/13.03.00/98 dated 15.6.1998	Monetary and Credit Policy Measures	144

Circular No & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD No. BC 86/12.01.001/98-99 dated 20.8.1998	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Increase in Cash Reserve Ratio (CRR) (Covering letter)	148
DBOD No. BC 85/12.01.001/98-99 dated 20.8.1998	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Increase in Cash Reserve Ratio (CRR) (Notification)	150

SECTION VII CREDIT INFORMATION

DBOD No. DL. BC 23/20.16.002/98 dated 24.3.1998	Disclosure of information - Submission of list of suit - filed accounts	151
DBOD No. DL. BC 106/20.16.003/98-99 dated 11.11.1998	Submission of list of defaulters on floppy diskettes and submission of statement of suit-filed accounts	152
DBOD No. DL. BC 109/20.16.002/98-99 dated 18.11.1998	Disclosure of Information regarding defaulting borrowers - Publication of list of suit-filed accounts of Rs. 1 crore and above.	154

SECTION VIII APPOINTMENTS / REMUNERATION

DBOD No. BC 54/08.95.004/98 dated 10.6.1998	Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949 - Sitting fees payable to the Directors/ Travelling and Halting Allowance payable to the Chairmen and Chief Executive Officers/ Managing Directors/Directors	157

Circular No & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.

SECTION IX RETURNS

DBOD No. BC 3/12.03.001/97-98 dated 10.1.1998	Section 26 of Banking Regulation Act, 1949 - Submission of Return in Form IX - Unclaimed deposits	159
DBOD No. BC 15/12.05.005/97-98 dated 24.2.1998	Review, Rationalisation and Redesigning of Returns relating to Core Commercial Banking Areas	160
DBOD No. BC 89/12.01.001/98-99 dated 24.8.1998	Section 42(2) of Reserve Bank of India Act, 1934 - Return in Form A	164
DBOD No. FSC.BC 118/24.76.002/98 dated 26.12.1998	Information System for Portfolio Management Services (PMS)	183

SECTION X MISCELLANEOUS

(a) **BRANCH EXPANSION**
(b) **NON-TRADITIONAL TYPE OF WORK TAKEN UP BY
BANKS-MERCHANT BANKING, CREDIT CARD
SYSTEM, HIRE-PURCHASE BUSINESS ETC.**
(c) **CUSTOMER SERVICE IN BANKS**
(d) **FRAUDS ETC. IN BANKS**
(e) **OTHERS**

DBOD No. BL.BC 74/22.01.001/98 dated 29.7.1998	Section 23 of the Banking Regulation Act 1949 - Shifting of rural branches outside the Block/Service Area and closure of rural branches	185

(b) **NON-TRADITIONAL TYPE OF WORK TAKEN UP BY
BANKS-MERCHANT BANKING, CREDIT CARD
SYSTEM, HIRE-PURCHASE BUSINESS ETC.**

DBOD No. FSC.BC 49/24.01.001/98 dated 2.6.1998	Reports/Reviews submitted by banks to RBI	188

Circular No & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD No. FSC.BC 50/24.01.011/98 dated 2.6.1998	Entry of banks into domestic Credit Card business	189
DBOD No. FSC.BC 61/24.47.001/98 dated 23.6.1998	Stockinvest Scheme	191
(c) CUSTOMER SERVICE IN BANKS		
DBOD No. BC 100/09.07.007/98-99 dated 12.10.1998	Operation of bank accounts by old/ sick/incapacitated customers	192
(d) FRAUDS ETC. IN BANKS		
DBOD No. BP.BC 24/21.01.023/98 dated 30.3.1998	Frauds in banks/grant 'at par' facility for dividend/interest warrants and refund orders	196
DBOD No. BP.BC 59/21.01.023/98 dated 15.6.1998	Sanctioning power of bank officials prior to retirement	198
(e) OTHERS		
DBOD No. IBS. 1410/23.67.001/97-98 dated 1.1.1998	Import of Gold/Silver	200
DBOD No. BC 9/21.04.018/98 dated 27.1.1998	Balance Sheet of banks - Disclosures	201
DBOD No. BC 10/09.08.001/97-98 dated 3.2.1998	Sexual harassment in work places - Guidelines by Supreme Court to prevent such harassment - Implementation thereof	203
DBOD No. IBS 1816/23.67.001/97-98 dated 4.2.98	Sale of Gold/Silver/Platinum - Payment in cash	212

Circular No & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD No. BP.BC 12/21.01.023/98 dated 11.2.1998	Furnishing of data - violation of secrecy obligations	214
DBOD No. BC 16/09.07.007/97-98 dated 27.2.1998	Electronic Clearing Service (Credit Clearing)	216
DBOD No. BP.BC 17/21.04.048/98 dated 4.3.1998	Prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning - Agricultural Advances	217
DBOD No. IBS.BC 18/23.67.001/97-98 dated 4.3.1998	Import of Gold/Silver	219
DBOD No. BP.BC 19/21.01.023/97-98 dated 10.3.1998	Receipt of foreign contribution by various Associations/ Organisations in India under Foreign Contribution (Regulation) Act,1976	220
DBOD No.IBS 1929/23.67.001/97-98 dated 14.3.1998	Import of Gold	223
DBOD No. BC 27/12.06.114/97-98 dated 3.4.1998	Inclusion in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934 - "The Toronto -Dominion Bank"	224
DBOD No. BP. BC 29/21.04.048/98 dated 11.4.1998	Income recognition, asset classification, provisioning and other related matters - Valuation of investments	225
DBOD No. BP.BC 32/21.04.018/98 dated 29.4.1998	Capital Adequacy - Disclosures in Balance Sheets	236
DBOD No. BP.BC 42/21.04.018/98 dated 19.5.1998	Accounting Standard 11 (Revised)	238
DBOD No. BC 48/08.95.004/98 dated 30.5.1998	Official visits abroad by Chairman and Chief Executive Officer	239

Circular No & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD No. PSBS.BC 72/16.13.100/98-99 dated 10.7.1998	Issue of shares by private sector banks	241
DBOD No. MC 2/19.06.02/97-98 dated 20.7.1998	Action Plan for Private Sector Banks for the period April 1998 - March 2000	242
DBOD No. BP.BC 73/21.04.018/98 dated 27.7.1998	Inter-branch accounts - Old outstanding credit entries	244
DBOD No. BP.BC 94/21.04.098/98 dated 10.9.1998	Asset - Liability Management (ALM) System	246
DBOD No. 174/09.06.001/98-99 dated 24.9.1998	Working Group to review the functioning of Debt Recovery Tribunals (DRTs) - Recommendations	347
DBOD No. IBS.BC 99/23.09.001/98-99 dated 9.10.1998	Remittance of profits by Foreign Banks operating in India	349
DBOD No. BC 101/12.04.002/98-99 dated 15.10.1998	TT Discounting facility - Renewal	353
DBOD No. BP.BC 103/21.01.002/98 dated 31.10.1998	Monetary and Credit Policy Measures	354
DBOD No. BL.BC 105/22.01.03/98 dated 11.11.1998	Acquisition of accommodation on lease/ rental basis by commercial banks for their use(i.e. for office and residence of staff)	370
DBOD No. BP.BC 108/21.01.023/98 dated 17.11.1998	Acceptance of foreign contributions under Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976	390

Circular No & date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD No. BP.BC 110/21.02.051/98 dated 18.11.1998	Transactions in relation to which Permanent Account Number(PAN) or General Index Register (GIR) Number to be quoted in all documents - Notification dated 9 th October 1998 issued in the Gazette of India, extraordinary part II, Section 3 by Central Board of Direct Taxes.	407
DBOD No. BP.BC 119/21.01.002/98 dated 28.12.1998	Monetary & Credit Policy Measures -Capital Adequacy Ratio - Risk weight on bank's investments in bonds/ securities issued by Financial Institutions	412
DBOD No. BP.BC 120/21.04.048/98 dated 29.12.1998	Prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning - Agricultural loans affected by natural calamities	413
DBOD No. IBS. 1519/23.67.001/97-98 dated 31.12.1998	Gold loan	415

SECTION XI USE OF HINDI IN BANKS

DBOD No. BC 51/06.02.01/98 dated 2.6.1998	Formation of Hindi cadre and filling up of Hindi posts	419
DBOD No. BC 62/06.02.01/98 dated 26.6.1998	75 th Meeting of Official Language Implementation Committee of public sector banks - Follow-up action	421

कालक्रमानुसार विषय-सूची

परिपत्र संख्या और दिनांक	विषय	खण्ड
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. आइबीएस. 1410/23.67.001/97-98 दिनांक 1.1.1998	स्वर्ण/चांदी का आयात	X (ङ)
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 1/24.76.002/97-98 दिनांक 5.1.1998	हाज़िर-वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 2/24.76.002/97-98 दिनांक 5.1.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. बीसी. 3/12.03.001/97-98 दिनांक 10.1.1998	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 फार्म IX में विवरण प्रस्तुत करना - दावा न की गयी जमाराशियां	IX
बैंपविवि. सं. बीसी. 4/12.01.001/97-98 दिनांक 16.1.1998	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 5/12.01.001/97-98 दिनांक 16.1.1998	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 6/12.02.001/97-98 दिनांक 16.1.1998	नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात (सीआरआर/एसएलआर) बनाये रखने में कमियां होने पर दंड ब्याज दर	VI
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 7/13.01.09/98 दिनांक 20.1.1998	वापस आ रहे भारतीयों के विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) खातों का आरएफसी खातों/निवासी रुपया खातों में परिवर्तन-ब्याज की अदायगी	II
बैंपविवि. सं. बीसी. 8/12.02.001/97-98 दिनांक 22.1.1998	भारत सरकार द्वारा जारी 6 प्रतिशत कैपिटल इंडेक्स्ड बांड, 2002 का मूल्यन	IV
बैंपविवि. सं. बीसी. 9/21.04.018/98 दिनांक 27.1.1998	बैंकों का तुलनपत्र-प्रकटीकरण	X (ङ)
बैंपविवि. सं. बीसी. 10/09.08.001/97-98 दिनांक 3.2.1998	कार्य स्थलों में यौन उत्पीड़न - ऐसे उत्पीड़न को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शी सिद्धांत-उनका कार्यान्वयन	X (ङ)

परिपत्र और संख्या दिनांक	विषय	खण्ड
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. आइबीएस. 1816/23.67.001/97-98 दिनांक 4.2.1998	सोना/चांदी/प्लेटिनम की बिक्री - नकद रूप में अदायगी	X (ड)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 11/13.01.08/98 दिनांक 10.2.1998	स्वसहायता (सेल्फ हेल्प) समूहों के नाम से बचत बैंक खाते खोलना	II
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 12/21.01.023/98 दिनांक 11.2.1998	आंकड़े प्रस्तुत करना - गोपनीयता संबंधी दायित्वों का उल्लंघन	X (ड)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 13/21.01.023/98 दिनांक 12.2.1998	चल आस्तियां रखने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तिय कंपनियों की प्रतिभूतियों की नामित बैंकों के पास अभिरक्षा	VI
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 14/24.91.001/98 दिनांक 16.2.1998	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने के लिए अनुमति-निजी क्षेत्र म्युच्युअल फंड	III
बैंपविवि. सं. बीसी. 15/12.05.005/97-98 दिनांक 24.2.1998	मुख्य वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्रों से संबंधित विवरणियों की समीक्षा, युक्तिकरण और पुनर्रचना	IX
बैंपविवि. सं. बीसी. 16/09.07.007/97-98 दिनांक 27.2.1998	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन)	X (ड)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 17/21.04.048/98 दिनांक 4.3.1998	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - कृषि अग्रिम	X (ड)
बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 18/23.67.001/97-98 दिनांक 4.3.1998	सोना/चांदी का आयात	X (ड)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 19/21.01.023/97-98 दिनांक 10.3.1998	भारत में विभिन्न संघों/संगठनों द्वारा विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विदेशी अभिदान	X (ड)
बैंपविवि. सं. आइबीएस. 1929/23.67.001/97-98 दिनांक 14.3.1998	भारत सरकार द्वारा जारी 6 प्रतिशत कैपिटल स्वर्ण का आयात	X (ड)

परिपत्र और संख्या दिनांक	विषय	खण्ड
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. बीसी. 20/12.02.001/97-98 दिनांक 18.3.1998	नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात (सीआरआर/एसएलआर) बनाये रखने में कमी होने पर दंड स्वरूप ब्याज दर	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 21/12.01.001/97-98 दिनांक 23.3.1998	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती - (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 22/12.01.001/97-98 दिनांक 23.3.1998	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती - (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि. सं. डीएल. बीसी. 23/20.16.002/98 दिनांक 24.3.1998	सूचना का प्रकटीकरण - मुकदमा दायर खातों की सूची प्रस्तुत करना	VII
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 24/21.01.023/98 दिनांक 30.3.1998	बैंकों में धोखाधड़ी/लाभांश/ब्याज वारंटों तथा धन-वापसी आदेशों के लिए सममूल्य सुविधा की स्वीकृति	X (घ)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 25/13.01.08/98 दिनांक 2.4.1998	फार्मर्स क्लब-विकास वालंटियर वाहिनी के नाम में बचत बैंक खाते खोलना	II
बैंपविवि. सं. बीसी. 26/12.02.001/97-98 दिनांक 2.4.1998	नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात (सीआरआर/एसएलआर) बनाये रखने में कमी होने पर दंड स्वरूप ब्याज दर	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 27/12.06.114/97-98 दिनांक 3.4.1998	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन- 'दि टोरोन्टो-डोमिनियन बैंक'	X (ङ)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 28/13.01.09/98 दिनांक 4.4.1998	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) जमाराशि का अवधिपूर्व आहरण-स्वैप लागत की वसूली	II
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 29/21.04.048/98 दिनांक 11.4.1998	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान तथा अन्य संबंधित मामले - निवेशों का मूल्यन	X (ड़)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 30/24.76.002/97-98 दिनांक 29.4.1998	हाजिर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV

परिपत्र और संख्या दिनांक	विषय	खण्ड
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. बीसी. 31/24.76.002/97-98 दिनांक 29.4.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 32/21.04.018/98 दिनांक 29.4.1998	पूंजी पर्याप्तता, तुलनपत्रों में प्रकटीकरण	X (इ)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 33/13.03.00/98 दिनांक 29.4.1998	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	VI
बैंपविवि. सं. डीआइआर बीसी. 34/13.03.00/98 दिनांक 29.4.1998	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	VI
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 35/13.03.00/98 दिनांक 29.4.1998	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	VI
बैंपविवि. सं. डीआइआर बीसी. 36/13.03.00/98 दिनांक 29.4.1998	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 39/24.76.002/98 दिनांक 6.5.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 40/24.76.002/98 दिनांक 18.5.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी बीसी. 41/24.76.002/97-98 दिनांक 18.5.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 42/21.04.018/98 दिनांक 19.5.1998	लेखा मानदंड 11 (संशोधित)	X (इ)
बैंपविवि. सं. बीसी. 43/12.01.001/97-98 दिनांक 20.5.1998	10प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अंतर्गत 3 मई 1991 तथा 17 अप्रैल 1992 के बीच जन्त शेष राशियों का निर्मोचन (अधिसूचना)	VI

परिपत्र और संख्या दिनांक	विषय	खण्ड
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. बीसी. 44/12.01.001/97-98 दिनांक 20.5.1998	10प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अंतर्गत 3 मई 1991 तथा 17 अप्रैल 1992 के बीच जब्त शेष राशियों का निर्मोचन (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 45/24.76.002/98 दिनांक 25.5.1998	हाज़िर-वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 46/24.76.002/97-98 दिनांक 25.5.1998	हाज़िर-वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 47/13.01.09/98 दिनांक 28.5.1998	एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ऋण तथा एफसीएनआर (बी)/एनआरएनआर पूल से ऋण	V
बैंपविवि. सं. बीसी. 48/08.95.004/98 दिनांक 30.5.1998	अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा विदेश में अधिकारिक दौरे	X (इ)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 49/24.01.001/98 दिनांक 2.6.1998	बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत रिपोर्टें/समीक्षा	X (ख)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 50/24.01.011/98 दिनांक 2.6.1998	देशी क्रेडिट कार्ड कारोबार में बैंकों का प्रवेश	X (ख)
बैंपविवि. सं. बीसी. 51/06.02.01/98 दिनांक 2.6.1998	हिन्दी संवर्ग का निर्माण और हिन्दी पदों को भरना	XI
बैंपविवि. सं. बीसी. 54/08.95.004/98 दिनांक 10.6.1998	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी - निदेशकों को देय बैठक शुल्क/अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/प्रबंध निदेशकों/निदेशकों को देय यात्रा और विराम भत्ता	VIII
आइईसीडी. सं. 47/3840/04.02.01/97-98 दिनांक 11.6.1998	निर्यात ऋण	V

परिपत्र और संख्या दिनांक	विषय	खण्ड
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 55/13.03.00/98 दिनांक 11.6.1998	अग्रिमों पर ब्याज दें	V
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 56/24.76.002/98 दिनांक 12.6.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 57/24.76.002/97-98 दिनांक 12.6.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. बीसी. 58/24.91.001/98 दिनांक 12.6.1998	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति-निजी क्षेत्र के म्युच्युअल फंड	III
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 59/21.01.023/98 दिनांक 15.6.1998	सेवानिवृत्ति से पूर्व बैंक अधिकारियों की मंजूरी संबंधी शक्तियां	X (घ)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 60/13.03.00/98 दिनांक 15.6.1998	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय	VI
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 61/24.47.001/98 दिनांक 23.6.1998	स्टॉकइनवेस्ट योजना	X (ख)
बैंपविवि. सं. बीसी. 62/06.02.01/98 दिनांक 26.6.1998	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 75वीं बैठक - अनुवर्ती कार्रवाई	XI
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 64/24.76.002/98 दिनांक 29.6.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 65/24.76.002/87-98 दिनांक 29.6.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 67/24.76.002/98 दिनांक 3.7.1998	प्रतिवर्ती हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV

परिपत्र और संख्या दिनांक	विषय	खण्ड
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 68/24.76.002/97-98 दिनांक 3.7.1998	प्रतिवर्ती हाज़िर-वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 69/13.01.10/98 दिनांक 3.7.1998	दान	II
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 70/24.76.002/98 दिनांक 8.7.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 71/24.76.002/97-98 दिनांक 8.7.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. पीएसबीएस. बीसी. 72/16.13.100/98-99 दिनांक 10.7.1998	निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयर जारी करना	X (ड)
बैंपविवि. सं. एमसी. 2/19.06.02/97-98 दिनांक 20.7.1998	अप्रैल 1998-मार्च 2000 की अवधि के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों हेतु कार्य-योजना	X (ड)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 73/21.04.018/98 दिनांक 27.7.1998	अंतर शाखा खाते - पुरानी बकाया जमा प्रविष्टियां	X (ड)
बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 74/22.01.001/98 दिनांक 29.7.1998	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23-प्रखण्ड/सेवा क्षेत्र के बाहर ग्रामीण शाखाओं का स्थानांतरण तथा ग्रामीण शाखाएं बंद करना	X (क)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 75/21.04.048/98 दिनांक 4.8.1998	सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का अर्जन-खंडित अवधि के लिए ब्याज - लेखांकन की प्रक्रिया	IV
आईसीडी. सं. 5/04.02.01/98-99 दिनांक 6.8.1998	निर्यात ऋण - ब्याज दरें	V
बैंपविवि. सं. बीसी. 77/13.07.01/98 दिनांक 6.8.1998	अग्रिमों पर ब्याज दरें	V

परिपत्र और संख्या दिनांक	विषय	खण्ड
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 78/13.07.05/98-99 दिनांक 8.8.1998	कंपनी निकायों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश और हामीदारी	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 79/24.76.002/98 दिनांक 10.8.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 80/24.76.002/98 दिनांक 10.8.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 81/24.76.002/98 दिनांक 13.8.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 82/24.76.002/98 दिनांक 13.8.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 83/21.04.012/98 दिनांक 18.8.1998	जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट	V
बैंपविवि. सं. बीसी. 85/12.01.001/98-99 दिनांक 20.8.1998	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 86/12.01.001/98-99 दिनांक 20.8.1998	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 87/24.76.002/98 दिनांक 24.8.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 88/24.76.002/98 दिनांक 24.8.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. बीसी. 89/12.01.001/98-99 दिनांक 24.8.1998	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) - फार्म ए में विवरणी	IX

परिपत्र और संख्या दिनांक	विषय	खण्ड
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 90/13.07.05/98-99 दिनांक 28.8.98	शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर बैंक वित्त-मास्टर परिपत्र	V
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 91/24.76.002/98 दिनांक 7.9.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 92/24.76.002/98 दिनांक 7.9.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 93/21.02.045/98 दिनांक 8.9.1998	ब्याज दर के विभिन्न दायरों के अनुसार जमाराशियों और अग्रिमों के ब्यौरे	II
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 94/21.04.098/98 दिनांक 10.9.1998	आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली	X (ड)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 95/24.76.002/98 दिनांक 21.9.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 96/24.76.002/98 दिनांक 21.9.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. 174/09.06.001/98-99 दिनांक 24.9.1998	ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए कार्यदल - सिफारिशें	X
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 97/24.76.002/98 दिनांक 7.10.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 98/24.76.002/98 दिनांक 7.10.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV (ड)
बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 99/23.09.001/98-99 दिनांक 9.10.1998	भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा लाभ का प्रेषण	X (ड)

परिपत्र और संख्या दिनांक	विषय	खण्ड
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. बीसी. 100/09.07.007/98-99 दिनांक 12.10.1998	बूढ़े/बीमार/अक्षम ग्राहकों द्वारा बैंक खातों का परिचालन	X (ग)
बैंपविवि. सं. बीसी. 101/12.04.002/98-99 दिनांक 15.10.1998	तार अंतरण भुनाई सुविधा-नवीकरण	X (ङ)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 102/24.76.002/98-99 दिनांक 30.10.1998	सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा लेनदेन	IV
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 103/21.01.002/98 दिनांक 31.10.1998	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय	X (ङ)
बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 105/22.01.03/98 दिनांक 11.11.1998	वाणिज्य बैंकों द्वारा अपने उपयोग (अर्थात् कार्यालय और स्टाफ के निवास) के लिए पट्टा/किराया के आधार पर आवास का अर्जन	X (ङ)
बैंपविवि. सं. डीएल. बीसी. 106/20.16.003/98-99 दिनांक 11.11.1998	फ्लॉपी डिस्कट पर चूककर्ताओं की सूची और मुकदमा दायर खातों का विवरण प्रस्तुत करना	VII
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 107/13.07.05/98-99 दिनांक 11.11.1998	बैंकों द्वारा बिलों का पुनर्भाजन	III
बैंपविवि. सं. आईबीएस. बीसी. 104/23.37.001/98-99 दिनांक 12.11.1998	भारत स्थित बैंकों द्वारा विदेश स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं को ऋण/ऋण से इतर सुविधाएं तथा विदेश स्थित पार्टियों को क्रेता का ऋण और स्वीकृति वित्त की सुविधाएं प्रदान करना	V
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 108/21.01.023/98 दिनांक 17.11.1998	विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विदेशी अंशदानों की स्वीकृति	X (ङ)
बैंपविवि. सं. डीएल. बीसी. 109/20.16.002/98-99 दिनांक 18.11.1998	चूककर्ता उधारकर्ताओं संबंधी सूचना का प्रकटीकरण - 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के मुकदमा दायर खातों की सूची का प्रकाशन	VII

परिपत्र और दिनांक	विषय	खण्ड
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 110/21.02.051/98 दिनांक 18.11.1998	ऐसे लेनदेन जिनके बारे में सभी प्रलेखों में स्थायी खाता सं. (पीएएन) या सामान्य सूचकांक रजिस्टर (जीआइआर) संख्या दी जानी है - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3 में जारी 9 अक्टूबर 1998 की अधिसूचना	X (ड)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 112/24.76.002/98 दिनांक 4.12.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 113/24.76.002/98 दिनांक 4.12.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. डीआइआर बीसी. 115/13.07.05/98-99 दिनांक 9.12.1998	संपार्श्विक जमानत के रूप में धारित प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण	V
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 116/24.76.002/98 दिनांक 15.12.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 117/24.76.002/98 दिनांक 15.12.1998	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 118/24.76.002/98 दिनांक 26.12.1998	संविभाग प्रबंधन सेवाओं के लिए सूचना प्रणाली	IX
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 119/21.01.002/98 दिनांक 28.12.1998	मौद्रिक और ऋण नीति उपाय - पूंजी पर्याप्तता अनुपात - वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी बांडों/ प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों पर जोखिम भार	X (ड)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 120/21.04.048/98 दिनांक 29.12.1998	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड- प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित कृषि ऋण	X (ड)
बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 1519/23.67.001/97-98 दिनांक 31.12.1998	स्वर्ण ऋण	X (ड)

CHRONOLOGICAL INDEX

Circular No & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD No. IBS. 1410/23.67.001/97-98 dated 1.1.1998	Import of Gold/Silver	X (e)
DBOD No. FSC. BC. 1/24.76.002/97-98 dated 5.1.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC. 2/24.76.002/97-98 dated 5.1.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. BC 3/12.03.001/97-98 dated 10.1.1998	Section 26 of Banking Regulation Act, 1949 - Submission of Return in Form IX - Unclaimed deposits	IX
DBOD No. BC 4/12.01.001/97-98 dated 16.1.1998	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Increase in Cash Reserve Ratio (CRR) (Notification)	VI
DBOD No. BC 5/12.01.001/97-98 dated 16.1.1998	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Increase in Cash Reserve Ratio (CRR) (Covering letter)	VI
DBOD No. BC 6/12.02.001/97-98 dated 16.1.1998	Penal rate of interest on the shortfall in the maintenance of CRR/SLR	VI
DBOD No. Dir. BC 7/13.01.09/98 dated 20.1.1998	Conversion of FCNR(B) Accounts of the Returning Indians into RFC Accounts/ Resident Rupee Account - Payment of interest	II
DBOD No. BC. 8/12.02.001/97-98 dated 22.1.1998	Valuation of 6 per cent Capital Indexed Bonds, 2002 issued by Government of India	IV
DBOD No. BC 9/21.04.018/98 dated 27.1.1998	Balance Sheet of banks - Disclosures	X(e)
DBOD No. BC 10/09.08.001/97-98 dated 3.2.1998	Sexual harassment in work places - Guidelines by Supreme Court to prevent such harassment - Implementation thereof	X(e)

Circular No & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD No. IBS 1816/23.67.001/97-98 dated 4.2.1998	Sale of Gold/Silver/Platinum - Payment in cash	X(e)
DBOD No. Dir. BC 11/13.01.08/98 dated 10.2.1998	Opening of savings bank accounts in the name of Self-Help Groups (SHGs)	II
DBOD No. BP.BC 12/21.01.023/98 dated 11.2.1998	Furnishing of data - violation of secrecy obligations	X(e)
DBOD No. BP.BC 13/21.01.023/98 dated 12.2.1998	Custody of securities of NBFCs with designated banks towards maintenance of liquid assets.	VI
DBOD No.FSC.BC 14/24.91.001/98 dated 16.2.1998	Permission to participate in Call/Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	III
DBOD No.BC 15/12.05.005/97-98 dated 24.2.1998	Review, Rationalisation and Redesigning of Returns relating to Core Commercial Banking Areas	IX
DBOD No. BC 16/09.07.007/97-98 dated 27.2.1998	Electronic Clearing Service (Credit Clearing)	X(e)
DBOD No. BP.BC 17/21.04.048/98 dated 4.3.1998	Prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning - Agricultural Advances	X(e)
DBOD No. IBS.BC 18/23.67.001/97-98 dated 4.3.1998	Import of Gold/Silver	X(e)
DBOD No. BP.BC 19/21.01.023/97-98 dated 10.3.1998	Receipt of foreign contribution by various Associations/ Organisations in India under Foreign Contribution (Regulation) Act,1976	X(e)
DBOD No.IBS 1929/23.67.001/97-98 dated 14.3.1998	Import of Gold	X(e)

Circular No & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD No.BC 20/12.02.001/97-98 dated 18.3.1998	Penal rate of interest on the shortfall in the maintenance of CRR/SLR	VI
DBOD No.BC 21/12.01.001/97-98 dated 23.3.1998	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio(CRR) - (Notification)	VI
DBOD No. BC 22/12.01.001/97-98 dated 23.3..1998	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio(CRR) - (Covering letter)	VI
DBOD No. DL. BC 23/20.16.002/98 dated 24.3.1998	Disclosure of information - Submission of list of suit - filed accounts	VII
DBOD No. BP.BC 24/21.01.023/98 dated 30.3.1998	Frauds in banks/grant 'at par' facility for dividend/interest warrants and refund orders	X (d)
DBOD No. Dir. BC 25/13.01.08/98 dated 2.4.1998	Opening of savings bank accounts in the name of Farmer's Clubs - Vikas Volunteer Vahini (VVV)	II
DBOD No. BC 26/12.02.001/97-98 dated 2.4.1998	Penal rate of interest on the shortfall in the maintenance of CRR/SLR	VI
DBOD No. BC 27/12.06.114/97-98 dated 3.4.1998	Inclusion in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934 - "The Toronto -Dominion Bank"	X (e)
DBOD No. Dir. BC 28/13.01.09/98 dated 4.4.1998	Premature withdrawals of FCNR(B) deposit - Recovery of swap cost	II
DBOD No. BP. BC 29/21.04.048/98 dated 11.4.1998	Income recognition, asset classification, provisioning and other related matters - Valuation of investments	X(e)
DBOD No. FSC. BC 30/24.76.002/97-98 dated 29.4.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	IV

Circular No & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD No. BC 31/24.76.002/97-98 dated 29.4.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. BP.BC 32/21.04.018/98 dated 29.4.1998	Capital Adequacy - Disclosures in Balance Sheets	X (e)
DBOD No. Dir. BC 33/13.03.00/98 dated 29.4.1998	Interest rates on advances (Directive)	VI
DBOD No. Dir. BC 34/13.03.00/98 dated 29.4.1998	Interest rates on deposits (Directive)	VI
DBOD No. Dir. BC. 35/13.03.00/98 dated 29.4.1998	Interest rates on deposits held under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) Scheme (Directive)	VI
DBOD No. Dir. BC 36/13.03.00/98 dated 29.4.1998	Monetary and Credit Policy Measures (Covering letter)	VI
DBOD No. FSC.BC 39/24.76.002/98 dated 6.5.1998	Ready Forward Transactions	IV
DBOD No. FSC.BC 40/24.76.002/98 dated 18.5.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC 41/24.76.002/97-98 dated 18.5.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. BP.BC 42/21.04.018/98 dated 19.5.1998	Accounting Standard 11 (Revised)	X (e)
DBOD No. BC 43/12.01.001/97-98 dated 20.5.1998	Release of balance impounded between 3 rd May 1991 and 17 th April 1992 under 10 per cent incremental CRR (Notification)	VI

Circular No & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD No. BC 44/12.01.001/97-98 dated 20.5.1998	Release of balance impounded between 3 rd May 1991 and 17 th April 1992 under 10 per cent incremental CRR (Covering letter)	VI
DBOD No. FSC. BC 45/24.76.002/98 dated 25.5.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC. BC 46/24.76.002/97-98 dated 25.5.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. Dir. BC 47/13.01.09/98 dated 28.5.1998	Loans against FCNR(B) deposits and loans out of FCNR(B)/NRNR pools.	V
DBOD No. BC 48/08.95.004/98 dated 30.5.1998	Official visits abroad by Chairman and Chief Executive Officer	X(e)
DBOD No. FSC. BC 49/24.01.001/98 dated 2.6.1998	Reports/Reviews submitted by banks to RBI	X(b)
DBOD No. FSC. BC 50/24.01.011/98 dated 2.6.1998	Entry of banks into domestic Credit Card business	X(b)
DBOD No. BC 51/06.02.01/98 dated 2.6.1998	Formation of Hindi cadre and filling up of Hindi posts	XI
DBOD No. BC 54/08.95.004/98 dated 10.6.1998	Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949 - Sitting fees payable to the Directors/ Travelling and Halting Allowance payable to the Chairmen and Chief Executive Officers/ Managing Directors/Directors	VIII
IECD No. 47/ 3840/04.02.01/97-98 dated 11.6.1998	Export Credit	V

Circular No & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD No. Dir. BC 55/13.03.00/98 dated 11.6.1998	Interest rates on advances (Directive)	V
DBOD No.FSC. BC 56/24.76.002/98 dated 12.6.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC 57/24.76.002/97-98 dated 12.6.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. BC 58/24.91.001/98 dated 12.6.1998	Permission to participate in Call/Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	III
DBOD No. BP.BC 59/21.01.023/98 dated 15.6.1998	Sanctioning power of bank officials prior to retirement	X(d)
DBOD No. Dir. BC 60/13.03.00/98 dated 15.6.1998	Monetary and Credit Policy Measures	VI
DBOD No. FSC.BC 61/24.47.001/98 dated 23.6.1998	Stockinvest Scheme	X(b)
DBOD No. BC 62/06.02.01/98 dated 26.6.1998	75 th Meeting of Official Language Implementation Committee of public sector banks - Follow-up action	XI
DBOD No. FSC.BC 64/24.76.002/98 dated 29.6.1998	Ready Forward Transctions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC 65/24.76.002/98 dated 29.6.1998	Ready Forward Transctions (Covering letter)	IV
DBOD No. FSC.BC 67/24.76.002/98 dated 3.7.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	IV

Circular No & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD No. FSC.BC 68/24.76.002/97-98 dated 3.7.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. Dir. BC 69/13.01.10/98 dated 3.7.1998	Donations	II
DBOD No. FSC.BC 70/24.76.002/98 dated 8.7.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC 71/24.76.002/97-98 dated 8.7.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. PSBS.BC 72/16.13.100/98-99 dated 10.7.1998	Issue of shares by private sector banks	X(e)
DBOD No. MC 2/19.06.02/97-98 dated 20.7.1998	Action Plan for Private Sector Banks for the period April 1998 - March 2000	X(e)
DBOD No. BP.BC 73/21.04.018/98 dated 27.7.1998	Inter-branch accounts - Old outstanding credit entries	X(e)
DBOD No. BL.BC 74/22.01.001/98 dated 29.7.1998	Section 23 of the Banking Regulation Act 1949 - Shifting of rural branches outside the Block/Service Area and closure of rural branches	X(a)
DBOD No. BP.BC 75/21.04.048/98 dated 4.8.1998	Acquisition of Government and other approved securities - Broken period interest - Accounting procedure	IV
IECD No. 5/04.02.01/98-99 dated 6.8.1998	Export Credit - Interest rates	V
DBOD No. BC 77/13.07.01/98 dated 6.8.1998	Interest rates on advances (Directive)	V

Circular No & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD No. Dir. BC 78/13.07.05/98-99 dated 8.8.1998	Investment in and underwriting of shares and debentures of corporate bodies	IV
DBOD No. FSC.BC 79/24.76.002/98 dated 10.8.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC 80/24.76.002/98 dated 10.8.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. FSC.BC 81/24.76.002/98 dated 13.8.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC 82/24.76.002/98 dated 13.8.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. BP.BC 83/21.04.012/98 dated 18.8.1998	Relaxations to trade and industry in the State of Jammu & Kashmir	V
DBOD No. BC 85/12.01.001/98-99 dated 20.8.1998	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Increase in Cash Reserve Ratio (CRR) (Notification)	VI
DBOD No. BC 86/12.01.001/98-99 dated 20.8.1998	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Increase in Cash Reserve Ratio (CRR) (Covering letter)	VI
DBOD No. FSC.BC 87/24.76.002/98 dated 24.8.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC 88/24.76.002/98 dated 24.8.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. BC 89/12.01.001/98-99 dated 24.8.1998	Section 42(2) of Reserve Bank of India Act, 1934 - Return in Form A	IX

Circular No & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD No. Dir. BC 90/13.07.05/98-99 dated 28.8.1998	Bank Finance against shares and debentures - Master Circular	V
DBOD No. FSC.BC 91/24.76.002/98 dated 7.9.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC 92/24.76.002/98 dated 7.9.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. BP.BC 93/21.02.045/98 dated 8.9.1998	Break-down of Deposits and Advances according to different interest rate ranges	II
DBOD No. BP.BC 94/21.04.098/98 dated 10.9.1998	Asset - Liability Management (ALM) System	X(e)
DBOD No. FSC.BC 95/24.76.002/98 dated 21.9.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC 96/24.76.002/98 dated 21.9.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. 174/09.06.001/98-99 dated 24.9.1998	Working Group to review the functioning of Debt Recovery Tribunals (DRTs) - Recommendations	X(e)
DBOD No. FSC.BC 97/24.76.002/98 dated 7.10.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC 98/24.76.002/98 dated 7.10.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. IBS.BC 99/23.09.001/98-99 dated 9.10.1998	Remittance of profits by Foreign Banks operating in India	X(e)

Circular No & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD No. BC 100/09.07.007/98-99 dated 12.10.1998	Operation of bank accounts by old/ sick/incapacitated customers	X(c)
DBOD No. BC 101/12.04.002/98-99 dated 15.10.1998	TT Discounting facility - Renewal	X(e)
DBOD No.FSC.BC 102/24.76.002/98-99 dated 30.10.1998	Ready Forward Transactions (Repos) Government and other Approved Securities	IV
DBOD No. BP.BC 103/21.01.002/98 dated 31.10.1998	Monetary and Credit Policy Measures	X(e)
DBOD No.BL.BC 105/22.01.03/98 dated 11.11.1998	Acquisition of accommodation on lease/ rental basis by commercial banks for their use(i.e. for office and residence of staff)	X(e)
DBOD No. DL.BC 106/20.16.003/98-99 dated 11.11.1998	Submission of list of defaulters on floppy diskettes and submission of statement of suit-filed accounts	VII
DBOD No. Dir. BC 107/13.07.05/98-99 dated 11.11.1998	Rediscounting of Bills by banks	III
DBOD No. IBS.BC 104/23.37.001/98-99 dated 12.11.1998	Extension of credit/non-credit facilities to Indian Joint Ventures/ Wholly Owned Subsidiaries abroad and extension of buyer's credit and acceptance finance to overseas parties by banks in India	V
DBOD No. BP.BC 108/21.01.023/98 dated 17.11.1998	Acceptance of foreign contributions under Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976	X(e)
DBOD No. DL.BC 109/20.16.002/98-99 dated 18.11.1998	Disclosure of Information regarding defaulting borrowers - Publication of list of suit-filed accounts of Rs. 1 crore and above.	VII

Circular No & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD No. BP.BC 110/21.02.051/98 dated 18.11.1998	Transactions in relation to which Permanent Account Number(PAN) or General Index Register (GIR) Number to be quoted in all documents - Notification dated 9 th October 1998 issued in the Gazette of India, extraordinary part II, Section 3 by Central Board of Direct Taxes.	X(e)
DBOD No. FSC.BC 112/24.76.002/98 dated 4.12.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC 113/24.76.002/98 dated 4.12.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. Dir. BC 115/13.07.05/98-99 dated 9.12.1998	Dematerialisation of Securities held as collaterals	V
DBOD No. FSC.BC 116/24.76.002/98 dated 15.12.1998	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC 117/24.76.002/98 dated 15.12.1998	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. FSC.BC 118/24.76.002/98 dated 26.12.1998	Information System for Portfolio Management Services (PMS)	IX
DBOD No. BP.BC 119/21.01.002/98 dated 28.12.1998	Monetary & Credit Policy Measures - Capital Adequacy Ratio - Risk weight on bank's investments in bonds/ securities issued by Financial Institutions	X(e)

Circular No & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD No. BP.BC 120/21.04.048/98 dated 29.12.98	Prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning - Agricultural loans affected by natural calamities	X(e)
DBOD No. IBS. 1519/23.67.001/97-98 dated 31.12.1998	Gold loan	X(e)

भाग II
जमाराशि

SECTION II
DEPOSITS

बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.7/13.01.09/98

DBOD.No. Dir.BC.7/13.01.09/98

20 जनवरी 1998
30 पौष 1919 (शक)

January 20, 1998
Pausa 30, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

वापस आ रहे भारतीयों के विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) खातों का आरएफसी खातों/निवासी रुपया खातों में परिवर्तन-ब्याज की अदायगी

CONVERSION OF FCNR(B) ACCOUNTS OF THE RETURNING INDIANS INTO RFC ACCOUNTS/ RESIDENT RUPEE ACCOUNTS - PAYMENT OF INTEREST

कृपया 20 जनवरी 1993 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं. बीसी. 68/13.01.09/93 देखें, जिसमें निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खातों में परिवर्तन के प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर)/अनिवासी बाह्य (एनआरई) जमाराशियों के परिपक्वतापूर्व आहरण के लिए दंड से छूट प्रदान की गयी है तथा साथ ही दिनांक 24 दिसंबर 1996 का परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 162/13.01.09/96 देखें, जिसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति दी गयी है कि वे आरएफसी खाते में परिवर्तन के लिए न्यूनतम निर्धारित अवधि पूरी करने के पहले परिपक्वतापूर्व आहरित विदेशी मुद्रा अनिवासी (ए) जमाराशियों पर ब्याज अदा कर सकते हैं।

Please refer to our Circular DBOD.No.BC.68/13.01.09/93 dated 20 January 1993 advising exemption from levy of Penalty for premature withdrawal of FCNR/NRE Deposits for the purpose of conversion to Resident Foreign Currency Accounts (RFC) and Circular DBOD.No.Dir.BC. 162/13.01.09/96 dated 24 December 1996 permitting banks to pay interest on prematurely withdrawn FCNR (A) Deposits before completion of minimum stipulated period for conversion into RFC Account.

2. 6 माह की न्यूनतम निर्धारित अवधि पूरी करने के पहले एफसीएनआर (बी) जमाराशि को आरएफसी/निवासी रुपया खाते में परिवर्तित करने के मामले में ब्याज अदा करने की अनुमति के लिए कई बैंकों ने हाल में हमसे संपर्क किया है। अब बैंकों को इस बात की अनुमति देने का निर्णय लिया

2. A number of banks have recently approached us to permit them to pay interest in case of conversion of FCNR (B) Deposit into RFC/Resident Rupee Account before completion of minimum stipulated period of 6 months. It has since been decided to

गया है कि वे अपने विवेक के अनुसार एफसीएनआर खाते के आरएफसी/निवासी रुपया खाते में परिवर्तन के समय ब्याज अदा कर सकते हैं, भले ही छह महीने की न्यूनतम परिपक्वता अवधि पूरी न की गयी हो, बशर्ते ब्याज की दर आरएफसी खाता योजना के तहत धारित बचत बैंक जमाराशियों पर देय ब्याज दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. उक्त अनुदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35ए के तहत जारी किये गये हैं।

भवदीय

(एम.पी.कोठारी)
महा प्रबंधक

बैंपविवि सं.निदेश. बीसी.11/13.01.08/98

10 फरवरी 1998
21 माघ 1919 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

स्वसहायता (सेल्फ हेल्प) समूहों के नाम से बचत बैंक खाते खोलना

कृपया दिनांक 4 जनवरी 1993 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 63/13.01.08/92-93 देखें, जिसमें यह सूचित किया गया था कि राष्ट्रीय कृषि

allow banks to pay interest at their discretion at the time of conversion of FCNR Account into RFC/Resident Rupee Account even if the same has not run for a minimum maturity of 6 months, subject to the condition that the rate of interest should not exceed the rate payable on savings bank deposits held under RFC Account Scheme.

3. The above instructions are issued under Sections 21 and 35A of the Banking Regulations Act, 1949.

Yours faithfully

(M.P. Kothari)
General Manager

DBOD. No. DIR.BC.11/13.01.08/98

February 10, 1998
Magha 21, 1919(Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sirs,

**OPENING OF SAVINGS BANK
ACCOUNTS IN THE NAME OF SELF-
HELP GROUPS (SHGs)**

Please refer to our circular DBOD No. BC.63/13.01.08/92-93 dated January 4, 1993 advising that Self-Help Groups,

और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रारंभ की गई प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा वित्त-पोषित पंजीकृत अथवा अपंजीकृत स्वसहायता समूहों को बैंकों में बचत बैंक खाता खोलने की अनुमति दी जा सकती है ।

2. अब यह सूचित किया जाता है कि पंजीकृत अथवा अपंजीकृत स्वसहायता समूह जो कि अपने सदस्यों के बीच बचत की आदतों को बढ़ावा देने के कार्य में संलग्न हैं [देखें हमारे ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को संबोधित परिपत्र आरपीसीडी.सं. पीएल. बीसी. 120/04.09.22/95-96 का पैराग्राफ 7 तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रायोजक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संबोधित दिनांक 1 अक्टूबर 1996 का परिपत्र सं. एनबी/डीपीडी. एनएफएस/1238/ सीडीआईडी/ 92-ए/96-97 का पैराग्राफ 8] बचत बैंक खाते खोलने के लिए पात्र होंगे । यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि बचत बैंक खाता खोलने से पहले स्वसहायता समूहों द्वारा बैंकों से पहले ऋण सुविधाएं प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है ।

भवदीय

(एस. पी. पाडगांवकर)

उप महा प्रबंधक

registered or unregistered, financed by banks under a pilot project launched by National Bank for Agriculture and Rural Development may be allowed to open savings bank accounts with banks.

2. It is now advised that Self-Help Groups (SHGs), registered or unregistered, which are engaged in promoting the savings habits among their members [c.f. paragraph 7 of Circular RPCD No. PL.BC. 120/04.09.22/95-96 dated April 2, 1996 addressed to Scheduled Commercial Banks (excluding RRBs) by our Rural Planning and Credit Department and paragraph 8 of Circular No. NB/DPD. NFS/1238/CDID/92.A/96-97 dated October 1, 1996 addressed to the Sponsor Banks and Regional Rural Banks by National Bank for Agriculture and Rural Development] will be eligible to open savings bank accounts. It is further clarified that SHGs need not necessarily have already availed of credit facilities from the banks before opening of savings bank accounts.

Yours faithfully

(S.P. Padgaonkar)

Deputy General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी.25/13.01.08/98

DBOD. No.Dir.BC. 25/13.01.08/98

2 अप्रैल 1998
12 चैत्र 1920 (शक)

April 2, 1998
Chaitra 12, 1920 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

फार्मर्स क्लब - विकास वालंटियर
वाहिनी के नाम में बचत बैंक खाते
खोलना

OPENING OF SAVINGS BANK
ACCOUNTS IN THE NAME OF
FARMERS' CLUBS-VIKAS
VOLUNTEER VAHINI (VVV)

कृपया समय समय पर यथासंशोधित 27 दिसम्बर 1985 के हमारे निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 के पैराग्राफ 3(i) का अवलोकन करें, जिसके अनुसार बैंकों को कुछ निकायों/संगठनों के नाम में बचत बैंक खाते खोलने से मना किया गया है। अपने सदस्यों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने वाले स्वयं सहायता दलों को 10 फरवरी 1998 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 11/13.01.08/98 द्वारा बचत बैंक खाते खोलने की अनुमति दी गयी थी। फार्मर्स क्लब - विकास वालंटियर वाहिनी नामक ग्रामीण किसानों/उद्यमियों के अनौपचारिक दलों के नाम में बचत बैंक खाते खोलने से संबंधित मामले की जांच की गयी है और अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे फार्मर्स क्लबों को नामित बैंकों में बचत बैंक खाते खोलने की अनुमति दी जाये।

Please refer to paragraph 3(i) of our directive DBOD. No. Dir.BC. 151/C347-85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, in terms of which banks have been prohibited from opening savings bank accounts in the name of certain bodies/ organisations. Self Help Groups engaged in promoting the savings habit among their members were allowed to open savings bank accounts vide our circular DBOD No. DIR. BC.11/13.01.08/98 dated February 10, 1998. The issue relating to opening of savings bank accounts in the name of Farmers' Clubs - Vikas Volunteer Vahini (VVV) informal groups of rural farmers/ entrepreneurs, has been examined and it has now been decided that such Farmers' Clubs may be allowed to open savings bank accounts with the designated banks.

भवदीय

Yours faithfully

(एस.पी. पाडगांवकर)
उप महा प्रबंधक

(S.P. Padgaonkar)
Deputy General Manager

4 अप्रैल 1998
14 चैत्र 1920 (शक)

April 4, 1998
Chaitra 14, 1920 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

**विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक)
जमाराशि का अवधिपूर्व आहरण - स्वैप
लागत की वसूली**

**PREMATURE WITHDRAWAL OF
FCNR (B) DEPOSIT - RECOVERY OF
SWAP COST**

कृपया आप 29 अप्रैल 1993 का हमारा निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 115/13.01.09/93 देखें। उसके पैराग्राफ V के अनुसार विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) [विमुअ (बैं)] योजना के अंतर्गत जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण के मामले में दंड लगाने का बैंकों को विवेकाधिकार दिया गया है।

Please refer to our Directive DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated 29 April 1993. In terms of paragraph V thereof, banks have been given discretionary powers to levy Penalty in case of premature withdrawal of a deposit under FCNR (Banks) Scheme.

2. कुछ बैंकों ने यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या वे विमुअ (बैंक) योजना के अंतर्गत अवधिपूर्व आहरण के मामले में स्वैप लागत की वसूली कर सकते हैं। हमने इस मामले की जांच की है और यह सूचित करते हैं कि चूंकि योजना के अंतर्गत विनिमय जोखिम बैंकों को वहन करना है और उन्हें दंड लगाने का भी विवेकाधिकार है, अतः बैंक विमुअ (बैंक) जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण के मामले में स्वैप लागत की वसूली के लिए अपने विवेकाधिकार से दंड लगा सकते हैं। जिन मामलों में विमुअ (बैंक) जमाराशियों का अवधिपूर्व आहरण निर्धारित न्यूनतम छः महीने पूर्ण होने से पहले किया जाता है, ऐसी स्थिति में कोई ब्याज देय नहीं होता, उन मामलों में भी बैंक स्वैप लागत

2. A few banks have sought clarification whether they could recover swap cost in case of premature withdrawal of FCNR (B) deposits. The matter has been examined by us and it is advised that since exchange risk under the Scheme is to be borne by the banks and they also have the discretion to levy Penalty, the banks may levy penalty to recover the swap cost at their discretion in instances of premature withdrawal of FCNR(B) deposits. Where premature withdrawal of FCNR(B) deposits takes place before completion of the minimum stipulated period of six months in which

की वसूली के लिए अपने विवेकाधिकार से दंड लगा सकते हैं। परंतु, दंड लगाने की बात जमाराशियां स्वीकार करते समय जमाकर्ताओं को स्पष्ट बतायी जानी चाहिए।

3. यदि जमाराशियां स्वीकार करते समय जमाकर्ताओं को दंड के प्रावधान की जानकारी नहीं दी जाती, तो अवधिपूर्व आहरण के कारण होनेवाली जोखिम हानि बैंकों को उठानी पड़ेगी।

भवदीय

(एम. पी. कोठारी)
महा प्रबंधक

बैंपविवि सं. डीआइआर बीसी. 69/13.01.10/98

03 जुलाई 1998
12 आषाढ़ 1920 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

दान

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बैंकों को पिछले साल के प्रकाशित लाभ के एक प्रतिशत तक 'सामान्य' दान देने की अनुमति है। इसके अलावा बैंकों को पिछले साल के प्रकाशित लाभ के दो प्रतिशत की समग्र वार्षिक अधिकतम सीमा के भीतर राष्ट्रीय

event no interest is payable, banks may at their discretion levy Penalty to cover the swap cost. However, the components of Penalty should be clearly brought to the notice of the depositors at the time of acceptance of the deposits.

3. If the depositors are not informed of the Penalty provisions at the time of the acceptance of the deposit, the exchange loss arising on account of premature withdrawal will have to be borne by the banks.

Yours faithfully

(M.P. Kothari)
General Manager

DBOD. No. Dir.BC. 69/13.01.10/98

July 3, 1998
Aashadha 12, 1920 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks,

Dear Sir,

DONATIONS

As per the existing instructions, banks are permitted to make "Normal" donations up to one percent of the published profit to the previous year. Besides, banks are also allowed to make donations to National

निधियों तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त/प्रायोजित अन्य निधियों में दान करने की भी अनुमति है। कुछ दान/अंशदान छूटप्राप्त हैं, जैसा कि 2 दिसंबर 1989 के हमारे परिपत्र बैंपवि. सं. डीआइआर. बीसी. 52/सी.347 (जे)-89 के पैरा 3 (vii) (क) से (घ) में तथा 18 जून 1990 के परिपत्र बैंपवि. सं. डीआइआर. बीसी. 121/सी.347 (जे)-90 में दर्शाया गया है। हानि उठानेवाले अलग-अलग बैंकों के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन करने पर एक वर्ष में तीन लाख रुपये तक इस तरह के दान की अनुमति दी जाती है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि, जहां तक हो सके, परिसर के निर्माण/दानप्राप्त करनेवालों के अन्य पूंजीगत व्यय के लिए दानराशियां न दी जायें।

2. समीक्षा करके तथा दान के संबंध में पिछले सभी अनुदेशों का अतिक्रमण करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि लाभ कमाने वाले बैंक एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के बैंक के प्रकाशित लाभ के एक प्रतिशत तक कुल दान कर सकते हैं, जिसमें पहले छूटप्राप्त श्रेणी के अंतर्गत किये गये दान तथा राष्ट्रीय निधियों और अन्य निधियों में किये गये दान शामिल होंगे। बैंकों को पिछले साल के प्रकाशित लाभ के एक प्रतिशत की निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक दान करने से मना किया गया है। तथापि, हानि उठानेवाले बैंक एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ पांच लाख रुपये का कुल दान कर सकते हैं। एक वर्ष में अनुमत सीमा में से उपयोग न की गयी राशि को दान देने के प्रयोजन के लिए अगले साल आगे नहीं ले जाना चाहिए।

Funds and other Funds recognised/ sponsored by the Central or State Government within the overall annual ceiling of two percent of the published profit of the previous year. Certain donations/ contributions are exempted as indicated in para 3(vii)(a) to (d) of our circular DBOD. No. Dir. BC. 52/C.347(J)-89 dated December 2, 1989 and DBOD. No. Dir. BC.121/c. 347(j)-90 dated June 18, 1990. In individual cases of loss making banks, on an application being made to Reserve Bank of India, permission is given to make such donations upto Rs. 3 lakhs in a year. Banks have also been advised to ensure that as far as possible donations are not made for construction of premises/other capital expenditure of the donees.

2. On a review and in supersession of all previous instructions in regard to donations it has now been decided that profit making banks may make donations during a financial year, aggregating up to one percent of the published profit of the bank for the previous year inclusive of donations earlier under exempted category and donations to National Funds and other Funds. Banks are prohibited from making donations in excess of the prescribed ceiling of one percent of the published profit of the previous year. However, loss making banks can make donations totalling Rs. 5 lakhs only in a financial year. Un-utilised amount of the permissible limit in a year should not be carried forward to the next year for the purpose of making donations.

3. दान के प्रयोजन के संबंध में बैंक स्वयं निर्णय ले सकते हैं। बैंकों के निदेशक बोर्ड इनके संबंध में स्पष्ट नीति निर्धारित कर सकते हैं (i) दान के प्रयोजन सहित दान देने के संबंध में, (ii) इस संबंध में कि दान को जमा संग्रहण से सम्बद्ध नहीं किया जाना चाहिए तथा (iii) दान कुछ दान प्राप्त करने वालों तक संकेंद्रित न होकर सुवितरित होना चाहिए आदि।

4. बैंक अब तक की तरह अपने निदेशक बोर्डों को दान की वार्षिक समीक्षा प्रस्तुत करना जारी रखें।

भवदीय

(एम.पी. कोठारी)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 93/21.02.045/98

8 सितंबर 1998
17 भाद्र 1920 (शक)

अध्यक्ष, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

ब्याज दर के विभिन्न दायरों के अनुसार
जमाराशियों और अग्रिमों के ब्यौरे

कृपया 5 अगस्त 1986 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.
सं. बीपी.बीसी. 82/सी.469(59)-86 देखें, जिसमें

3. Banks may take their own decision in regard to the purpose of the donations. The Boards of Directors of banks may clearly lay down a policy (i) of making donations including the purpose for which donations may be given (ii) that it should not be linked to deposit mobilisation and (iii) the donations should be fairly well distributed rather than being concentrated on a few donees etc.

4. The banks may continue to submit annual review of donations to their Boards of Directors as hitherto.

Yours faithfully

(M.P. Kothari)
General Manager

DBOD. No. BP.BC. 93/21.02.045/98

September 8, 1998
Bhadra 17, 1920(Saka)

Chairmen of all Scheduled Commercial
Banks (excluding Regional Rural Banks)

Dear Sirs,

**BREAK-DOWN OF DEPOSITS AND
ADVANCES ACCORDING TO
DIFFERENT INTEREST RATE
RANGES**

Please refer to our circular DBOD No.
BP.BC.82/C.469(59)-86 dated 5th August

बैंकों को सूचित किया गया था कि वे हमारे पास एक विवरण भेजें जिसमें ब्याज दरों के विभिन्न दायरों के अनुसार हर छमाही के अंत में बकाया कुल जमाशायियों और अग्रिमों (भारत में) के ब्यौरे दिये गये हों। स्थिति की समीक्षा करने पर उक्त सूचना एकत्र नहीं करने का निर्णय लिया गया है। अतः आप जून 1998 को समाप्त छमाही से हमारे पास उक्त विवरण प्रस्तुत करना बंद कर दें।

भवदीय

(जे. बी. म्हात्रे)
उप महा प्रबंधक

1986 advising Banks to submit to us a statement showing break-down of aggregate deposits and advances (in India), outstanding as at the end of every half year according to different interest rate ranges. On a review of the position, it has been decided to dispense with the collection of the above information. You may, therefore, discontinue furnishing the statements to us commencing from the half year ended June 1998.

Yours faithfully

(J.B. Mhatre)
Deputy General Manager

भाग III
ऋण नीति/ बैंकों को पुनर्वित्त
की समीक्षा

SECTION III
REVIEW OF CREDIT POLICY/
REFINANCE TO BANKS

16 फरवरी 1998
27 माघ 1919 (शक)

February 16, 1998
Magha 27, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक और अन्य संस्थाएं
जिन्हें मांग/सूचना मुद्रा बाजार और बिल
पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने के लिए अनुमति
दी गयी हो

All Commercial Banks and other
institutions permitted to participate in
Call/Notice Money Market and Bills
Rediscounting Scheme

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

मांग/सूचना मुद्रा बाजार और बिल
पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने के लिए
अनुमति - निजी क्षेत्र म्युच्युअल फंड

PERMISSION TO PARTICIPATE IN
CALL/NOTICE MONEY MARKET
AND BILLS REDISCOUNTING
SCHEME - PRIVATE SECTOR
MUTUAL FUNDS

कृपया दिनांक 27 जून 1995 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.
सं. एफएससी. बीसी. 68/24.91.001/95 के अनुबंध
I के भाग बी की क्रम सं. 30 देखें, जिसके अंतर्गत
सीआरबी म्युच्युअल फंड को केवल उधारदाता के रूप
में मांग/सूचना मुद्रा बाजार (रात भर की मांग मुद्रा और
14 दिन तक की अवधि वाली अल्प सूचना मुद्रा) तथा
बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति दी गयी
थी। मांग/सूचना मुद्रा और बिल पुनर्भुनाई बाजारों में
भाग लेने के लिए सीआरबी म्युच्युअल फंड को दी
गयी अनुमति, आगामी सूचना जारी होने तक, वापस
लेने का निर्णय लिया गया है।

Please refer to Serial No. 30. Part B of
Annexure I to our circular No. DBOD FSC.
BC.68/24.91.001-95 dated June 27. 1995 in
terms of which CRB Mutual Fund was
permitted to participate only as lender in
Call/Notice Money Market (overnight call
money and short notice money for period
upto and including 14 days) and Bills
Rediscounting Scheme. It has been decided
to withdraw the permission granted to CRB
Mutual Fund to operate in Call/Notice
money and Bills Rediscounting markets till
further notice.

भवदीया

Yours faithfully

(देवकी मुत्तुकृष्णन)
महा प्रबंधक

(Devaki Muthukrishnan)
General Manager

बैंपविवि.सं. बीसी. 58/24.91.001/98

DBOD.No. BC.58/24.91.001/98

12 जून 1998
22 ज्येष्ठ 1920 (शक)

June 12, 1998
Jyestha 22, 1920 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल
पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति
- निजी क्षेत्र के म्युच्युअल फंड

**PERMISSION TO PARTICIPATE IN
CALL/NOTICE MONEY MARKET
AND BILLS REDISCOUNTING
SCHEME - PRIVATE SECTOR
MUTUAL FUNDS**

कृपया 27 जून 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 68/24.91.001/95 देखें, जिसके अनुसार आइसीआइसीआइ म्युच्युअल फंड को मांग/सूचना मुद्रा/बिल पुनर्भुनाई बाज़ार में ऋणदाता के रूप में प्रवेश की अनुमति दी गयी थी। आइसीआइसीआइ म्युच्युअल फंड का नाम बदलकर प्रूडेंशियल आइसीआइसीआइ म्युच्युअल फंड किये जाने से, यह सूचित किया जाता है कि प्रूडेंशियल आइसीआइसीआइ म्युच्युअल फंड को ऋणदाता के रूप में, मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार (रातभर के लिए मांग मुद्रा और 14 दिन तक की अवधि के लिए अल्पसूचना मुद्रा) और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति दी गयी है।

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC. 68/24.91.001-95 dated 27th June 1995 in terms of which ICICI Mutual Fund, was permitted access in the call/notice money/bills rediscounting market as lender. With the change in name of ICICI Mutual Fund to Prudential ICICI Mutual Fund, it is advised that Prudential ICICI Mutual Fund is permitted to participate, only as a lender, in the Call/Notice Money Market (overnight call money and short notice money for period upto and including 14 days) and Bills Rediscounting Scheme.

भवदीया

Yours faithfully

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

11 नवंबर 1998
20 कार्तिक 1920 (शक)

November 11, 1998
Kartika 20, 1920 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

All Scheduled Commercial banks

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

बैंकों द्वारा बिलों का पुनर्भाजन

REDISCOUNTING OF BILLS BY BANKS

कृपया 27 जुलाई 1992 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 8/16.13.100/92-93 का पैराग्राफ 3(vii) देखें, जिसके अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भुनाये गये बिलों को पुनः भुनाने की अनुमति बैंकों को नहीं है ।

Please refer to paragraph 3(vii) of our circular DBOD No. BC. 8/16.13.100/92-93 dated July 27, 1992 in terms of which banks are not allowed to rediscount bills discounted by non-bank financial companies.

2. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां परिवहन क्षेत्र, विशेषतः ट्रक, कार, तिपहिया और अन्य हलके वाणिज्यिक वाहनों सहित वाणिज्यिक वाहनों के क्षेत्र, की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं । तथापि, बैंकों से पुनर्भाजन की सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण इन अपेक्षाओं को पूरा करने में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की क्षमता पर प्रतिबंध लग जाता है । हम समझते हैं कि इस प्रकार के वित्तपोषण से संबंधित बिल वाणिज्यिक वाहनों की वास्तविक बिक्री से संबंधित होते हैं, जिसका सत्यापन किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक वाहन का अलग इंजिन नंबर और चैसिस नंबर होता है, जो बिल के साथ प्रस्तुत बीजक में दर्ज रहता है ।

2. The non-bank finance companies are playing an important role in meeting the financing needs of the transport sector particularly the commercial vehicles segment including trucks, cars, three wheelers and other light commercial vehicles. However, the ability of the NBFCs to meet these requirements is constrained because of non-availability of rediscounting facilities from banks. We understand that the bills arising from such financing represent genuine sale of commercial vehicles which can be verified as each vehicle has a distinct engine number and chasis number recorded on the invoice accompanying the bills.

3. उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि उधार देने संबंधी सामान्य सुरक्षा उपायों

3. In view of the above, it has been decided that banks may rediscount bills

की शर्त पर हल्के वाणिज्यिक वाहनों सहित वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री के संबंध में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भुनाये गये बिल बैंकों द्वारा पुनः भुनाये जा सकते हैं ।

भवदीय

(राधेश्याम)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

discounted by NBFCs arising from sale of commercial vehicles including light commercial vehicles subject to normal lending safeguards.

Yours faithfully

(Radhe Shyam)

Additional Chief General Manager

भाग IV
निवेश

SECTION IV
INVESTMENTS

बैंपविवि.सं.बीसी. 2/24.76.002/97-98

5 जनवरी 1998
15 पौष 1919 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर - वायदा लेनदेन

कृपया अप उपर्युक्त विषय से संबंधित 20 अक्टूबर 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 114/24.76.002/97 देखें ।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब भारत सरकार के 6 प्रतिशत कैपिटल इंडेक्स्ड बांड 2002 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें ।

3. इस संबंध में जारी किया गया 5 जनवरी 1998 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 1/24.76.002/97 संलग्न है ।

भवदीय

(ए. घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No. FSC.BC. 2/24.76.002/97-98

January 5, 1998
Pausha 15, 1919 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
all Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD. No. FSC. BC. 114/24.76.002/97 dated October 20, 1997 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 6 per cent Government of India Capital Indexed Bonds 2002 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

2. A directive DBOD. No. FSC.BC.1/ 24.76.002/97-98 dated January 5, 1998 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

5 जनवरी 1998
15 पौष 1919 (शक)

January 5, 1998
Pausha 15, 1919 (Saka)

हाज़िर - वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 2561 के अनुसरण में भारत सरकार के 6 प्रतिशत कैपिटल इंडेक्स्ड बांड 2002 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत सरकार के 6 प्रतिशत कैपिटल इंडेक्स्ड बांड 2002 के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक भारत सरकार के 6 प्रतिशत कैपिटल इंडेक्स्ड बांड 2002 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे ।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India. (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S.O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S.O. 425 (E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved 6 per cent Government of India Capital Indexed Bonds 2002 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 6 per cent Government of India Capital Indexed Bonds 2002 subject to the condition that :

1. the banks would undertake all transactions of ready forward in 6 per cent Government of India Capital Indexed Bonds 2002 only at Mumbai.
2. such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

22 जनवरी 1998
2 माघ 1919 (शक)

January 22, 1998
Magha 2, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष/
मुख्य कार्यपालक

The Chairmen/Chief Executives of
all Scheduled Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

भारत सरकार द्वारा जारी 6 प्रतिशत
कैपिटल इंडेक्स्ड बांड, 2002 का मूल्यन

**VALUATION OF 6 PERCENT CAPITAL
INDEXED BONDS, 2002 ISSUED BY
GOVERNMENT OF INDIA**

कृपया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अंतर्गत चल आस्तियों के रखरखाव से संबंधित दिनांक 23 मार्च 1985 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 34/सी. 233 ए-85 के अनुबंध II के पैराग्राफ 24 का तथा दिनांक 20 जून 1992 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 143 ए/24.48.001/91-92 के अनुबंध का अवलोकन करें, जिसमें निवेश संबंधी लेनदेनों के लिए लेखांकन मानक निर्धारित किये गये हैं।

Please refer to paragraph 24 of Annexure II to our Circular DBOD. No. Leg. BC. 34/C.233A-85 dated 23 March 1985 relating to maintenance of liquid assets under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 and the Annexure to our Circular DBOD. No. FSC. BC. 143A/24.48.001/91-92 dated June 20, 1992, wherein the accounting standards for investment transactions have been prescribed.

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा उनकी 19 दिसम्बर 1997 की अधिसूचना सं. 4(13)-डब्ल्यू एंड एम/96 द्वारा जारी कैपिटल इंडेक्स्ड बांडों के संबंध में तीन महीने की पश्चता के साथ थोक मूल्य सूचकांक को हिसाब में लेते हुए गणना किये गये सूचकांक अनुपात का प्रयोग करके 'लागत' निकाली जाये। उदाहरणार्थ, मार्च 1998 महीने के सूचकांक अनुपात की गणना करने के लिए नवंबर 1997 महीने के थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाये। एक

2. It is clarified that in respect of the Capital Indexed Bonds issued by Government of India vide its Notification No. 4(13)/W&M/96 dated December 19, 1997, the 'cost' may be reckoned by using the index ratio calculated by taking the WPI with a three months' lag. For example, the WPI for the month of November 1997 may be used to calculate the index ratio for the

निदर्शनात्मक उदाहरण अनुबंध में दिया गया है ।
'लागत' के इस समायोजन के साथ बैंक मानक मूल्यन
प्रक्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं ।

भवदीय

(ए.एल. नरसिंहन)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

month of March 1998. An illustrative
example is given in the Annexure. With this
adjustment of the 'cost', the banks can then
use the standard valuation procedures.

Yours faithfully

(A. L. Narasimhan)
Additional Chief General Manager

उदाहरण

31 मार्च 1998 को 5 वर्षीय कैपिटल
इंडेक्स्ड बांड, 2002 की 'लागत' की गणना

बांड सममूल्य पर दिसंबर 1997 में जारी किये गये थे । अगस्त 1997 के थोक मूल्य सूचकांक को आधार थोक मूल्य सूचकांक के रूप में लिया गया था । इसी तरह दिसंबर 2002 में मोचन मूल्य की अदायगी के लिए संदर्भ थोक मूल्य सूचकांक के रूप में अगस्त 2002 के थोक मूल्य सूचकांक को लिया गया है । इस प्रकार, पूंजी के सूचकांकन के लिए तीन महीनों की स्पष्ट पश्चता का अनुसरण किया गया है । कैपिटल इंडेक्स्ड बांडों के मूल्यन के प्रयोजन के लिए 'लागत' ज्ञात करने के लिए यही सिद्धांत लागू किया जा सकता है । यदि बांड का मूल्यन मार्च 1998 में किया जाना हो तो नवंबर 1997 के थोक मूल्य सूचकांक को संदर्भ थोक मूल्य सूचकांक के रूप में लेते हुए सूचकांक अनुपात की गणना की जा सकती है । इस प्रकार जहां किसी वर्ष में मार्च को समाप्त प्रत्येक तिमाही के लिए अंश के रूप में पिछले साल के नवंबर के थोक मूल्य सूचकांक को लिया जायेगा, वहीं हर साल जून, सितंबर तथा दिसंबर महीनों में समाप्त अन्य तिमाहियों के लिए सूचकांक अनुपात अंश के रूप में संबंधित वर्षों के फरवरी, मई तथा अगस्त के थोक मूल्य सूचकांक को लेगा ।

मान लें कि नवंबर 1997 के लिए थोक मूल्यों का मासिक औसत सूचकांक (1981-82 = 100) 329.90 है । संदर्भ थोक मूल्य सूचकांक 329.90 है । आधार थोक मूल्य सूचकांक अर्थात् अगस्त 1997 का थोक मूल्य सूचकांक 326.00 है । कैपिटल इंडेक्स्ड बांडों की

ILLUSTRATION

Calculation of 'cost' of the 5 year Capital Indexed Bonds, 2002 as on March 31, 1998

The bonds were issued in December 1997 at par. The Wholesale Price Index (WPI) for August 1997 was taken as the Base WPI. Similarly the Reference WPI for payment of the redemption value in December 2002 is taken as the WPI for August 2002. Thus, a clear 3 months' lag is followed for indexation of capital. The same principle can be applied for arriving at 'Cost' for the purpose of valuation of Capital Indexed Bonds. If the valuation of the bond is to be done in March 1998, the index ratio can be calculated by taking the WPI for November 1997 as the Reference WPI. While thus for every quarter ending March of a year, the numerator will take WPI of November of the previous year, for other quarters ending in months viz. June, September and December, every year, the index ratio will take in the numerator WPI for February, May and August of the respective years.

Assuming that the Monthly Average Index of Wholesale Prices (1981-82 = 100) for November 1997 is 329.90. The Reference WPI is 329.90. The base WPI, i.e. the WPI for August 1997 is 326.00. The calculation

‘लागत’ की गणना निम्नानुसार की जायेगी :

$$\begin{aligned} \text{मार्च 1998 के लिए सूचकांक अनुपात} &= \frac{\text{नवंबर 1997 के लिए थोक मूल्य सूचकांक}}{\text{आधार थोक मूल्य सूचकांक}} \\ &= \frac{329.90}{326} \\ &= 1.01196 \text{ अथवा } 1.01 \\ &\quad \text{(दशमलव के दो अंकों तक पूर्णांकित)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{31.3.1998 को मूल्यन के लिए बांडों की लागत} \\ = \text{रु. } 100 \times 1.01 = \text{रु. } 101.00 \end{aligned}$$

of 'Cost' of Capital Indexed Bonds is illustrated below :

$$\begin{aligned} \text{Index Ratio for March 1998} &= \frac{\text{WPI for November 1997}}{\text{Base WPI}} \\ &= \frac{329.90}{326} \\ &= 1.01196 \text{ or } 1.01 \\ &\quad \text{(rounded to two decimal places)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cost of the bonds for valuation as on} \\ \text{31.3.1998} &= \text{Rs. } 100 \times 1.01 = \text{Rs. } 101.00 \end{aligned}$$

29 अप्रैल 1998
9 वैशाख 1920 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 5 जनवरी 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 2/24.76.002/97-98 देखें ।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब निम्नलिखित चार दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें ।

11.57 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2004
12.15 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2008
11.10 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2003
11.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2006

3. इस संबंध में जारी किया गया 29 अप्रैल 1998 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 30/24.76.002/97-98 संलग्न है ।

भवदीय

(ए. घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

April 29, 1998
Vaishakha 9, 1919 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD. No.FSC. BC. 2/24.76.002/97-98 dated January 5, 1998 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the following four Government dated securities for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

11.57 per cent Government Stock 2004
12.15 per cent Government Stock 2008
11.10 per cent Government Stock 2003
11.75 per cent Government Stock 2006

3. A directive DBOD. No. FSC.BC. 30/24.76.002/97-98 dated April 29, 1998 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

29 अप्रैल 1998
9 वैशाख 1920 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2561 के अनुसरण में निम्नलिखित चार सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त सरकारी प्रतिभूतियों के हाज़िर वायदा लेनेदेन कर सकते हैं :

1. बैंक उक्त चार सरकारी प्रतिभूतियों के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

11.57 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2004
12.15 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2008
11.10 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2003
11.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2006

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

April 29, 1998
Vaishakha 9, 1920 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification NO. S.O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S.O.425 (E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the following four Government dated securities for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in the said Government securities subject to the condition that :

- 1) the banks would undertake all transactions of ready forward in the said four Government securities only at Mumbai.
- 2) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

11.57 per cent Government Stock 2004
12.15 per cent Government Stock 2008
11.10 per cent Government Stock 2003
11.75 per cent Government Stock 2006

(S. Gurumurthy)
Executive Director

6 मई 1998
16 वैशाख 1920 (शक)

May 6, 1998
Vaishakha 16, 1920 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

हाज़िर वायदा लेनदेन

READY FORWARD TRANSACTIONS

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर हमारा 22 जून 1996 का परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 80/24.76.002/96 देखें ।

Please refer to our circular DBOD. No. FSC. BC. 80/24.76.002/96 dated June 22, 1996 on the above subject.

2. भारत सरकार ने अपनी 18 मार्च 1998 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 225 (ई) (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा पहले बतायी गयी संस्थाओं के अलावा निम्नलिखित संस्थाओं को ऐसी पात्र संस्थाओं के रूप में अधिसूचित किया है, जो खजाना बिलों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार के परामर्श से यथा-अनुमोदित भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकेंगी ।

2. The Government of India, vide their notification No.S.O. 225(E) dated March 18, 1998 (copy enclosed) have notified the following institutions as eligible institutions in addition to the institutions indicated earlier to undertake ready forward transactions in Treasury Bills and in such dated securities of the Government of India as are approved by the RBI in consultation with the Government.

- (i) डी.एस.पी. मेरिल लिंच लि.
- (ii) सीएट फाइनेंसियल सर्विसेज लि.
- (iii) कोटक महिन्द्रा कैपिटल कंपनी (अनलिमिटेड)
- (iv) बिरला ग्लोबल फाइनेंस कंपनी लि.
- (v) होआरे गोवेट (इंडिया) सिक्योरिटीज लि.
- (vi) दिल विकास फाइनेंस लि.
- (vii) एसआरआईआई इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लि.
- (viii) टावर कैपिटल एण्ड सिक्योरिटीज प्रा.लि.

- (i) DSP Merrill Lynch Ltd.
- (ii) Ceat Financial Services Ltd.
- (iii) Kotak Mahindra Capital Company (unlimited)
- (iv) Birla Global Finance Company Ltd.
- (v) Hoare Govett (India) Securities Ltd.
- (vi) Dil Vikas Finance Ltd.
- (vii) SREI International Securities Ltd.
- (viii) Tower Capital and Securities Pvt. Ltd.

(ix) टाटा फाइनेंस सिक्योरिटीज लि.

अतः बैंक उक्त संस्थाओं के साथ विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में हाजिर वायदा लेनदेन कर सकते हैं ।

भवदीया

(चित्रा चंद्रमौलिश्वरन)
महा प्रबंधक

(ix) Tata Finance Securities Ltd.

It would, therefore, be in order for banks to enter into ready forward transactions in the specified securities with the above institutions.

Yours faithfully

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

भारत का राजपत्र
भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(सी.एम.एवं ई.सी.बी. प्रभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 मार्च, 1998

का.आ. 225 (अ) - प्रतिभूति संविदा (विनियमन)
अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 16 की
उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य
विभाग) में दिनांक 27 जून, 1969 की भारत सरकार
की अधिसूचना संख्या आ. 2561 में और संशोधन
करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में :-

(क) दूसरे परन्तुक में, क्रम संख्या (viii) के बाद
निम्नलिखित क्रम संख्याएं जोड़ दी जाएं,
अर्थात् :-

- “(ix) डी.एस.पी. मेरिल लिंच लि.;
(x) सीएट फाइनेंशियल सर्विसेज लि.;
(xi) कोटक महिन्द्रा कैपिटल कंपनी
(अनलिमिटेड);
(xii) बिरला ग्लोबल फाइनेंस कंपनी लि.;
(xiii) होआरे गोवेट (इंडिया) सिक्योरिटीज
लि.,;
(xiv) दिल विकास फाइनेंस लि.;
(xv) एस.आर.ई. आई. इंटरनेशनल
सिक्योरिटीज लि.;
(xvi) टावर कैपिटल एण्ड सिक्योरिटीज
प्रा. लि.;
(xvii) टाटा फाइनेंस सिक्योरिटीज लि.।”

THE GAZETTE OF INDIA
PART II - Section 3 - Sub-section (ii)
Published by Authority

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(CM & ECB Division)

NOTIFICATION
New Delhi, the 18th March, 1998

S.O. 225 (E). – In exercise of the powers
conferred by sub-section (1) of section 16
of the Securities Contracts (Regulation) Act,
1956 (42 of 1956), the Central Government
hereby further amends the notification of the
Government of India in the Ministry of
Finance (Department of Economic Affairs)
number S.O. 2561, dated the 27th June,
1969, namely : –

In the said notification :—

(a) in the second proviso, after serial
number (viii), the following serial
numbers shall be inserted, namely : –

- “(ix) DSP Merrill Lynch Ltd.;
(x) Ceat Financial Services Ltd.;
(xi) Kotak Mahindra Capital
Company (unlimited),
(xii) Birla Global Finance
Company Ltd.;
(xiii) Hoare Govett (India)
Securities Ltd.;
(xiv) Dil Vikas Finance Ltd.;
(xv) SREI International Securities
Ltd.;
(xvi) Tower Capital and Securities
Pvt. Ltd.;
(xvii) Tata Finance Securities Ltd.”

(ख) क्रम संख्या (xxvii) के बाद चौथे परन्तुक के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में निम्नलिखित क्रम संख्याएं जोड़ दी जाएं, अर्थात् :-

“(xxvii क) डी.एस.पी. मेरिल लिंच लि. का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत निगमित कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय तुलसियानी चैम्बर्स, पश्चिमी स्कंध, 11वां तल, 212, बैकबे रिक्लेमेशन, मुंबई - 400021 में है;

(xxvii ख) सीएट फाइनेंशियल सर्विसेज लि. का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत निगमित कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय 31, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता - 700001 में है;

(xxvii ग) कोटक महिन्द्रा कैपिटल कंपनी (अनलिमिटेड) का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत निगमित कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय बख्तावर, दूसरा तल, 229, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400021 में है;

(xxvii घ) बिरला ग्लोबल फाइनेंस

(b) in the Explanation occurring below fourth proviso after serial number (xxvii), the following serial numbers shall be inserted, namely :-

"(xxvii a) DSP Merrill Lynch Ltd., means a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at Tulsiani Chambers, West Wing, 11th Floor, 212, Backbay Reclamation, Mumbai - 400021;

(xxvii b) Ceat Financial Services Ltd., means a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at 31, Netaji Subhas Road, Calcutta - 700001;

(xxvii c) Kotak Mahindra Capital Company (unlimited) means a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at Bakhtawar, 2nd Floor, 229, Nariman Point, Mumbai - 400021;

(xxvii d) Birla Global Finance

	कंपनी लि. का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत निगमित कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय ए-54, एम. आई. डी. सी. इंडस्ट्रियल एरिया मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400093 में है;		Company Ltd. means a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at A-54, M.I.D.C., Marol Industrial Area, Andheri (East), Mumbai - 400093;
(xxvii ड)	होआरे गोवेट (इंडिया) सिक्योरिटीज़ लि. का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत निगमित कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय चौथा तल, महिन्द्रा टावर्स, डा. जी. एम. भोंसले मार्ग, वरली, मुंबई - 400018 में है;	(xxvii e)	Hoare Govett (India) Securities Ltd., means a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at Fourth Floor, Mahindra Towers, Dr. G.M. Bhosale Marg, Worli, Mumbai - 400018;
(xxvii च)	दिल विकास फाइनेंस लि. का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत निगमित कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय 317, मेकर चैम्बर्स V, 221, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400021 में है;	(xxvii f)	Dil Vikas Finance Ltd., means a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at 317, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai - 400021;
(xxvii छ)	एस. आर. ई. आई. इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ लि. का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत निगमित कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय श्री गणेश सेंटर, 216, ए.जे.सी. बोस रोड,	(xxvii g)	SREI International Securities Ltd., means a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at Sree Ganesh Centre, 216, A.J.C. Bose

- (xxvii ज) कलकत्ता - 700017 में है;
टावर कैपिटल एण्ड
सिक्वोरिटीज प्रा.लि. का
अर्थ है कंपनी अधिनियम,
1956 (1956 का 1) के
तहत निगमित कंपनी और
इसका पंजीकृत कार्यालय
ए.बी.ए.एन. हाउस, 25/
31, रोपवॉक लेन, ऑफ
रैम्पार्ट रो, फोर्ट, मुंबई -
400001 में है;
- (xxvii झ) टाटा फाइनेंस सिक्वोरिटीज
लि. का अर्थ है कंपनी
अधिनियम, 1956 (1956
का 1) के तहत निगमित
कंपनी और इसका पंजीकृत
कार्यालय जिजि हाउस,
दामोदरदास सुखड़ावाला
मार्ग, मुंबई - 400001 में
है।”

(एफ.सं. 1/32/एस.ई./97)

डॉ. यु. शरत चन्द्रन, संयुक्त सचिव,

टिप्पणी : प्रमुख अधिसूचना दिनांक 27-6-1969 के
भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3 में पृष्ठ 839 पर
प्रकाशित दिनांक 27-6-1969 के का.आ. सं. 2561
के अन्तर्गत जारी की गई थी और उत्तरवर्ती अधिसूचनाएं
का.आ. 425 (अ.), का. आ. सं. 750 (अ.),
का.आ. 434 (अ.) और का.आ. 764 (अ.) क्रमशः
1-6-1994, 18-10-1994, 13-6-1996 और 6-11-
1997 को भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप-
खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थीं।

- (xxvii h) Tower Capital and
Securities Pvt. Ltd.,
means a company
incorporated under the
Companies Act, 1956 (1
of 1956) and having its
registered office at ABAN
house, 25/31, Ropewalk
Lane, Off Rampart Row,
Fort, Mumabi - 400001;
- (xxvii i) Tata Finance Securities
Ltd., means a company
incorporated under the
Comapnies Act, 1956 (1
of 1956) and having its
registered office at Jiji
House, Damodardas
Sukhadwala Marg,
Mumbai - 400001."

[F. No. 1/32/SE/97]

DR. U.SARAT CHANDRAN, Jt. Secy.

Note : The Principal notification was issued
under S.O. No. 2561 dated 27-6-1969
published in the Gazette of India Part II,
Section 3, page 839 dated 27-6-1969 and
subsequent notifications S.O. 425 (E), S.O.
No. 750(E), S.O. 434 (E) and S.O. 764 (E)
were published in the Gazette of India Part
II, Section 3, Sub-section (ii) on 1-6-1994,
18-10-1994, 13-6-1996 and 6-11-1997
respectively.

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 41/24.76.002/97-98

18 मई 1998
28 वैशाख 1920 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक, सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 29 अप्रैल 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी.बी.सी. 31/24.76.002/97-98 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 12.00 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2008 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 18 मई 1998 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी.बी.सी. 40/24.76.002/97-98 संलग्न है।

भवदीया

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No. FSC. BC. 41/24.76.002/97-98

May 18, 1998
Vaishakha 28, 1920 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of all Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD. No. FSC. BC. 31/24.76.002/97-98 dated April 29, 1998 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 12 per cent Government Stock 2008 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD. No. FSC. BC. 40/24.76.002/97-98 dated May 18, 1998 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

18 मई 1998
28 वैशाख 1920 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 425(ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में 12.00 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2008 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 12.00 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2008 में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं:

1. बैंक 12.00 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2008 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे:
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

Sec. IV

May 18, 1998
Vaishakha 28, 1920 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S.O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S.O. 425 (E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the 12.00 per cent Government Stock 2008 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 12.00 per cent Government Stock 2008 subject to the condition that

- i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 12.00 per cent Government Stock 2008 only at Mumbai.
- ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 46/24.76.002/97-98

25 मई 1998
4 ज्येष्ठ 1920 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक, सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 18 मई 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी.बी.सी. 41/24.76.002/97-98 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 11.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2004 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 25 मई 1998 का एक निदेश बैंपविवि. सं.एफएससी.बीसी. 45/24.76.002/97-98 संलग्न है।

भवदीया

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No. FSC. BC. 46/24.76.002/97-98

May 25, 1998
Jayestha 4, 1920 (Saka)

**The Chairmen/Chief Executives of all
Commercial Banks**

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD. No. FSC. BC. 41/24.76.002/97-98 dated May 18, 1998 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 11.50 per cent Government Stock 2004 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD. NO. FSC. BC. 45/24.76.002/97-98 dated May 25, 1998 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

25 मई 1998
4 ज्येष्ठ 1920 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 425(ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में 11.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2004 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 11.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2004 में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं:

1. बैंक 11.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2004 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

Sec. IV

May 25, 1998
Jyestha 28, 1920 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S.O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S.O. 425 (E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the 11.50 per cent Government Stock 2004 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 11.50 per cent Government Stock 2004 subject to the condition that :

- i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 11.50 per cent Government Stock 2004 only at Mumbai.
- ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General ledger (SGL) Accounts.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 57/24.76.002/97-98

12 जून 1998
22 ज्येष्ठ 1920 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक, सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 25 मई 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 46/24.76.002/97-98 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 11.90 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2007 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 12 जून 1998 का एक निदेश बैंपविवि. सं.एफएससी.बीसी. 56/24.76.002/97-98 संलग्न है।

भवदीया

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महाप्रबंधक

DBOD.No. FSC. BC. 57/24.76.002/97-98

June 12, 1998
Jyestha 22, 1920 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of all Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD. No. FSC. BC. 46/24.76.002/97-98 dated May 25, 1998 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 11.90 per cent Government Stock 2007 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD. No. FSC.BC.56/24.76.002/97-98 dated June 12, 1998 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

12 जून 1998
22 ज्येष्ठ 1920 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूँकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425(ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस. ओ. 2561 के अनुसरण में 11.90 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2007 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 11.90 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2007 में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं:

1. बैंक 11.90 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2007 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

Sec. IV

June 12, 1998
Jyestha 4, 1920 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No.S.O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S.O. 425 (E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the 11.90 per cent Government Stock 2007 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 11.90 per cent Government Stock 2007 subject to the condition that :

- i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 11.90 per cent Government Stock 2007 only at Mumbai.
- ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 65/24.76.002/97-98

29 जून 1998
8 आषाढ़ 1920 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक, सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 12 जून 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 57/24.76.002/97-98 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब निम्नलिखित दो सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें।

11.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2004
12.10 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2008

3. इस संबंध में जारी किया गया 29 जून 1998 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 64/24.76.002/97-98 संलग्न है।

भवदीया

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महाप्रबंधक

DBOD.No. FSC. BC. 65/24.76.002/97-98

June 29, 1998
Aashadha 8, 1920 (Saka)

**The Chairmen/Chief Executives of all
Commercial Banks**

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD. No. FSC. BC. 57/24.76.002/97-98 dated June 12, 1998 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the following two Government dated securities for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

11.75 per cent Government Stock, 2004
12.10 per cent Government Stock, 2008

3. A directive DBOD.No.FSC. BC. 64/24.76.002/97-98 dated June 29, 1998 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

29 जून 1998
8 आषाढ़ 1920 (शक)

June 29, 1998
Aashadha 8, 1920 (Saka)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूँकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425(ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में निम्नलिखित दो सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त सरकारी प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं:

1. बैंक उक्त दो सरकारी प्रतिभूतियों के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

11.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2004
12.10 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2008

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No.S.O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S.O. 425 (E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the following two Government dated securities for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in the said Government securities subject to the condition that :

- i) the banks would undertake all transactions of ready forward in the said two Government securities only at Mumbai.
- ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

11.75 per cent Government Stock, 2004
12.10 per cent Government Stock, 2008

(S. Gurumurthy)
Executive Director

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 68/24.76.002/97-98

3 जुलाई 1998
12 आषाढ़ 1920 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक, सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

प्रतिवर्ती हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 9 दिसंबर 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 151/24.76.002/97-98 देखें।

2. भारत सरकार ने अब पहले सूचित की गयी संस्थाओं के अलावा 5 बैंकेतर संस्थाओं को सभी परिपक्वताओं के खजाना बिलों में और भारत सरकार की ऐसी दिनांकित प्रतिभूतियों में, जो कि केन्द्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं, प्रतिवर्ती हाज़िर-वायदा संविदाएं करने के लिए अधिसूचित किया है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी 24 अप्रैल 1998 की अधिसूचना सं. 345(ई) की एक प्रति संलग्न है।

3. तदनुसार, उसमें उल्लिखित बैंकेतर संस्थाएं जब बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के साथ प्रतिवर्ती हाज़िर वायदा संविदाएं करें तो शर्त यह है कि बैंकेतर संस्थाएं लेनदेन के प्रथम चरण में प्रतिभूतियां खरीदेंगी और दूसरे चरण में प्रतिभूतियां वापस बेचेंगी।

DBOD.No. FSC. BC. 68/24.76.002/97-98

July 3, 1998
Aashada 12, 1920 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of all Commercial Banks

Dear Sir,

REVERSE READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our Circular DBOD. No.FSC.BC. 151/24.76.002/97-98 dated 9th December 1997 on the above subject.

2. The Government of India has since notified 5 non-bank entities in addition to the institutions indicated earlier to undertake **Reverse Ready Forward contracts** in Treasury Bills of all maturities and in such dated securities of Government of India as are approved by the Reserve Bank of India in consultation with Central Government. A copy of the Notification No. 345(E) dated April 24, 1998 issued by government of India in this regard is enclosed.

3. Accordingly, when the non-bank entities mentioned therein enter into Reverse Ready Forward contracts with banks and primary dealers, it is stipulated that the non-bank entities will be purchasing securities in the first leg and will be selling back securities in the second leg of the transaction.

4. इस संबंध में जारी किया गया 3 जुलाई 1998 का एक निदेश बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 67/24.76.002/97-98 संलग्न है।

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 67/24.76.002/97-98

3 जुलाई 1998
12 आषाढ़ 1920 (शक)

प्रतिवर्ती हाज़िर वायदा लेनदेन

भारत सरकार ने प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561, दिनांक 6 नवंबर 1997 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 764(ई) द्वारा यथासंशोधित, (जिसे इसमें इसके बाद “अधिसूचना” कहा गया है) के अनुसार 5 बैंकेतर संस्थाओं को (जिन्हें दिनांक 24 अप्रैल 1998 की भारत सरकार की संलग्न अधिसूचना सं.एस.ओ. 345(ई) में सूचीबद्ध किया गया है) यह अनुमति प्रदान की है कि वे भारत सरकार द्वारा जारी सभी परिपक्वताओं वाले खजाना बिलों में तथा भारत सरकार की उन दिनांकित प्रतिभूतियों में, जिन्हें केन्द्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया हो, प्रतिवर्ती हाज़िर वायदा संविदाएं कर सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा

4. A directive DBOD No. FSC.BC 67/24.76.002/97-98 dated 3 July 1998 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

DBOD.No. FSC. BC. 67/24.76.002/97-98

July 3, 1998
Aashadha 12, 1920 (Saka)

**REVERSE READY FORWARD
TRANSACTIONS**

The Government of India, in terms of Notification No. S.O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S.O. 764(E) dated November 6, 1997 (hereinafter referred to as "the Notification") and issued in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act 1956 has permitted 5 non-bank entities (listed in the Government of India Notification S.O. 345(E) dated April 24, 1998 annexed) to enter into reverse ready forward contracts in Treasury Bills of all maturities issued by Government of India and in such dated securities of Government of India as are approved by the Reserve Bank of India, in

35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा बैंकों को इसकी अनुमति प्रदान करता है कि वे उक्त संस्थाओं से प्रतिवर्ती हाज़िर वायदा सौदे इस शर्त पर स्वीकार कर सकते हैं कि -

- i. भारत सरकार द्वारा जारी सभी परिपक्वताओं के खजाना बिलों में तथा केन्द्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में प्रतिवर्ती हाज़िर वायदा सौदे मुंबई में ही किये जायें।
- ii. ऐसे लेनदेन भारतीय रिज़र्व बैंक में सहायक सामान्य लेजर खातों के माध्यम से किये जाएंगे।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

consultation with the Central Government. The Reserve Bank of India in exercise of the powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to accept reverse ready forward deals by the aforesaid entities subject to the condition that

- i) reverse ready forward deals in Treasury Bills of all maturities issued by Government of India and in such dated securities of Government of India as are approved by Reserve Bank of India in consultation with the Central Government are undertaken only at Mumbai.
- ii) such transactions shall be put through Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts with Reserve Bank of India.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

भारत का राजपत्र
भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(सी.एम.एवं ई.सी.बी. प्रभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1998

का.आ. 345 (अ) - प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) में दिनांक 27 जून, 1969 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 2561 में और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में :-

(क) तीसरे परन्तुक में, क्रम संख्या (न) के बाद निम्नलिखित क्रम संख्याएं जोड़ दी जाएं, अर्थात् :-

“(प) एल.आई.सी. म्यूचुअल फण्ड;
(फ) जे.एम. म्यूचुअल फण्ड;
(ब) बिड़ला म्यूचुअल फण्ड;
(भ) कोठारी पायनियर म्यूचुअल फण्ड;
(म) जार्डिन फ्लेमिंग म्यूचुअल फंड;”

(ख) क्रम संख्या (xxvii झ) के बाद चौथे परन्तुक के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में निम्नलिखित क्रम संख्याएं जोड़ दी जाएं, अर्थात् :-

THE GAZETTE OF INDIA
PART II - Section 3 - Sub-section (ii)
Published by Authority

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(CM & ECB Division)

NOTIFICATION
New Delhi, the 24th April, 1998

S.O. 345 (E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) number S.O. 2561, dated the 27th June, 1969, namely : –

In the said notification :—

(a) in the third proviso, after serial number(s), the following serial numbers shall be inserted, namely :—

“(t) LIC Mutual Fund;
(u) J.M. Mutual Fund;
(v) Birla Mutual Fund;
(w) Kothari Pioneer Mutual Fund;
(x) Jardine Fleming Mutual Fund;”

(b) in the Explanation occurring below fourth proviso after serial number (xxvii-i), the following serial numbers shall be inserted, namely :—

“(xxvii ज) “एल.आई.सी. म्यूचुअल फण्ड” का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 की संख्या 1) के तहत निगमित कंपनी जीवन बीमा सहयोग एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे निगम भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रायोजित न्यास और इसका पंजीकृत कार्यालय इंडस्ट्रियल एश्योरेस बिल्डिंग, चौथा तल, मुंबई - 400020 में स्थित है;

(xxvii ट) “जे.एम. म्यूचुअल फण्ड” का अर्थ है जे.एम. फाइनेशियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कन्सलटेंट्स सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रायोजित न्यास और इसकी प्रबंध-व्यवस्था कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 की सं. 1) के तहत पंजीकृत जे.एम. कैपिटल मैनेजमेंट लि. द्वारा की जा रही है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय 141, मेकर चैम्बर्स III, नारीमन प्वाइंट, मुंबई- 400025 में स्थित है;

(xxvii ठ) “बिड़ला म्यूचुअल फण्ड” का अर्थ है बिड़ला ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा प्रायोजित न्यास और इसकी प्रबंध-व्यवस्था कंपनी

“(xxvii j) “LIC Mutual Fund” means a trust sponsored by Life Insurance Corporation of India, a corporation managed by Jeevan Bima Sahayog Asset Management Company Limited, a company incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) and having its registered office at Industrial Assurance Building, 4th Floor, Mumbai - 400020;

(xxvii k) “J.M. Mutual Fund” means a trust sponsored by J.M. Financial and Investment Consultancy Services Limited and managed by J.M. Capital Management Ltd., registered under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956), and having its registered office at 141, Maker Chambers III, Nariman Point, Mumbai - 400025;

(xxvii l) “Birla Mutual Fund” means a trust sponsored by Birla Global Finance Limited, and managed by Birla Capital International

अधिनियम, 1956 (1956 की संख्या 1) के तहत पंजीकृत कंपनी बिड़ला कैपिटल इंटरनेशनल ए एम सी लिमिटेड द्वारा की जा रही है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय वोल्टास इंटरनेशनल हाउस, तीसरा तल, 28, एन.जी.एन. वैद्य मार्ग, (बैंक स्ट्रीट), फोर्ट, मुंबई, में स्थित हैं;

AMC Limited, a company registered under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956), and having its registered office at Voltas International House, 3rd floor, 28, NGN Vaidya Marg (Bank Street), Fort, Mumbai;

(xxvii ड) “कोठारी पायनियर म्यूचुअल फण्ड” का अर्थ है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रायोजित न्यास और इसकी प्रबन्ध-व्यवस्था कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 की संख्या 1) के तहत पंजीकृत कंपनी कोठारी पायनियर ए एम सी लिमिटेड द्वारा की जा रही है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय एल डोरेडो बेसमेंट, नंगंबक्कम हाइरोड, चेन्नई - 600034 में स्थित हैं;

(xxvii m) "Kothari Pioneer Mutual Fund" means a trust sponsored by Investment Trust of India Limited, and managed by Kothari Pioneer AMC Limited, a company registered under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956), and having its registered office at Eldorado Basement, Nungambakkam High Road, Chennai - 600034

(xxvii ढ) “जार्डिन फ्लेमिंग म्यूचुअल फण्ड” का अर्थ है जार्डिन फ्लेमिंग इंडिया सिक्योरिटीज़ लिमिटेड द्वारा प्रायोजित न्यास और इसकी प्रबन्ध-व्यवस्था जार्डिन फ्लेमिंग इंडिया ए.एम. लिमिटेड द्वारा की जा रही है

(xxvii n) "Jardine Fleming Mutual Fund" means a trust sponsored by Jardine Fleming India Securities Limited, and managed by Jardine Fleming India AM Limited, and having its registered office at

तथा इसका पंजीकृत
कार्यालय आमेचंद मैन्शन,
16 मैडम कामा रोड, मुम्बई
- 400001 में स्थित है ।

Amerchand Mansion, 16,
Madame Cama Road,
Mumbai - 400001."

(एफ.सं. 1/32/एस.ई./97)

[F. No. 1/32/SE/97]

डा. यु. शरत चन्द्रन, संयुक्त सचिव,

DR. U. SARAT CHANDRAN, Jt. Secy.

टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 27-6-1969 के भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3 में पृष्ठ 839 पर प्रकाशित दिनांक 27-6-1969 के का.आ. सं. 2561 के अन्तर्गत जारी की गई थी और उत्तरवर्ती अधिसूचनाएं का.आ. 425 (अ.), का. आ. सं. 750 (अ.), का.आ. 434 (अ.) और का.आ. 764 (अ.) और का.आ. 225 (अ) क्रमशः दिनांक 1-6-1994, 18-10-1994, 13-6-1996, 6-11-1997 और 18-3-1998 को भारत के राजपत्र भाग II, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थीं ।

Note : The principal notification was published under S.O. No. 2561 dated 27-6-1969 published in the Gazette of India Part II, Section 3, page 839 dated 27-6-1969 and subsequent notification S.O. 425(E), S.O. No. 750(E), S.O. 434 (E), S.O. 754(E) and S.O. 225(E) were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) on 1-6-94, 18-10-1994, 13-6-1996, 6-11-1997 and 18-3-1998 respectively.

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 71/24.76.002/97-98

DBOD.No. FSC. BC. 71/24.76.002/97-98

8 जुलाई 1998
17 आषाढ़ 1920 (शक)

July 8, 1998
Aashadha 4, 1920 (Saka)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

The Chairmen/Chief Executives of all
Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

हाज़िर वायदा लेनदेन

READY FORWARD TRANSACTIONS

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 29 जून 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 65/24.76.002/97-98 देखें ।

Please refer to our circular DBOD. No. FSC. BC. 65/24.76.002/97-98 dated June 29, 1998 on the above subject.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब निम्नलिखित तीन सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें ।

11.55 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001

11.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2003

12.25 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2010

3. इस संबंध में जारी किया गया 8 जुलाई 1998 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी 70/24.76.002/97-98 संलग्न है ।

भवदीय

(श्यामला गोपीनाथ)

अपर मुख्य महाप्रबंधक

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 70/24.76.002/98

8 जुलाई 1998

17 आषाढ़ 1920 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the following three Government dated securities for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

11.55 per cent Government Stock, 2001

11.75 per cent Government Stock, 2003

12.25 per cent Government Stock, 2010

3. A directive DBOD. No. FSC.BC. 70/24.76.002/97-98 dated July 8, 1998 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully

(Shyamala Gopinath)

Additional Chief General Manager

DBOD.No. FSC. BC. 70/24.76.002/98

July 8, 1998

Aashadha 17, 1920 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S.O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S.O.

की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2561 के अनुसरण में निम्नलिखित तीन सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त सरकारी प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक उक्त तीन सरकारी प्रतिभूतियों के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे ।

11.55 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001
 11.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2003
 12.25 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2010

(एस. गुरुमूर्ति)
 कार्यपालक निदेशक

425 (E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the following three Government dated securities for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in the said Government securities subject to the condition that :

- i) the banks would undertake all transactions of ready forward in the said three Government securities only at Mumbai.
- ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

11.55 per cent Government Stock, 2001
 11.75 per cent Government Stock, 2003
 12.25 per cent Government Stock, 2010

(S. Gurumurthy)
 Executive Director

4 अगस्त 1998
13 श्रावण 1920 (शक)

August 4, 1998
Shravana 13, 1920 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों
का अर्जन - खंडित अवधि के लिए
ब्याज - लेखांकन की प्रक्रिया

ACQUISITION OF GOVERNMENT
AND OTHER APPROVED
SECURITIES - BROKEN PERIOD
INTEREST - ACCOUNTING
PROCEDURE

यह पाया गया है कि कुछ बैंक लागत मूल्य में शामिल
खंडित अवधि के ब्याज (अर्जन के समय तक खरीदी
गयी प्रतिभूतियों पर प्रोद्भूत ब्याज) को इस आधार पर
पूंजीकृत करते हैं कि खरीद के समय विक्रेता को अदा
किये गये ऐसे प्रोद्भूत ब्याज को कर प्रयोजनों के लिए
राजस्व व्यय नहीं माना जाता ।

It is observed that some banks capitalise the
Broken Period Interest (interest accrued on
the securities purchased upto the time of
acquisition) included in the cost price, on
the ground that such accrued interest paid
to the seller at the time of purchase is not
recognised as a Revenue Expenditure for tax
purposes.

इस मामले की जांच की गयी है और अर्जन के समय
सरकारी प्रतिभूतियों पर अदा किये गये खंडित अवधि
के ब्याज के लेखांकन में एकरूपता लाने के लिए तथा
इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा
निर्धारित लेखांकन मानदंडों का अनुपालन करने के लिए
यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को लागत के हिस्से
के रूप में विक्रेता को अदा किये गये खंडित अवधि के
ब्याज को पूंजीकृत नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें
इसे लेखांकन मानदंड 13 के अनुसार लाभ और हानि
खाते के अंतर्गत व्यय की एक मद के रूप में लेना
चाहिए ।

The matter has been examined and with a
view to bringing about uniformity in the
accounting treatment of Broken Period
Interest on Government Securities paid at
the time of acquisition and also complying
with the Accounting Standards prescribed
by the Institute of Chartered Accountants of
India, it has been decided that banks should
not capitalise the Broken Period Interest paid
to seller as part of cost, but treat it as an
item of expenditure under Profit and Loss
Account as per AS 13.

कृपया यह नोट करें कि उक्त लेखांकन पद्धति में कराधान संबंधी निहितार्थों को हिसाब में नहीं लिया गया है, अतः बैंकों को आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित तरीके से आयकर संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 78/13.07.05/98-99

8 अगस्त 1998
17 श्रावण 1920 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

कंपनी निकायों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश और हामीदारी

कृपया आप 28 मई 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 60/13.07.05/97 देखें, जिसके अनुसार बैंकों को सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों सहित इक्विटी शेयरों, कंपनियों के परिवर्तनीय डिबेंचरों और उन पारस्परिक निधि योजनाओं के यूनिटों में निवेश की अनुमति दी गयी है, जिनकी राशि एकमात्र रूप से कंपनी ऋण के लिखतों में ही निवेश नहीं की जानी है ।

It may please be noted that the accounting treatment explained above does not take into account taxation implications and hence banks will have to comply with the requirements of Income Tax Authorities in the manner prescribed by them.

Yours faithfully

(C.R. Muralidharan)
General Manager

DBOD.No. Dir. BC. 78/13.07.05/98-99

August 8, 1998
Shravana 17, 1920 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

**INVESTMENTS IN AND
UNDERWRITING OF SHARES AND
DEBENTURES OF CORPORATE
BODIES**

Please refer to our circular DBOD. Dir. BC.60/13.07.05/97 dated May 28, 1997, in terms of which banks are allowed to invest in equity shares including PSU shares, convertible debentures of corporates and in units of Mutual Fund Schemes, the corpus of which is not exclusively invested in

बैंकों को यह अनुमति पिछले वर्ष की वृद्धिशील जमा राशियों के 5 प्रतिशत की सीमा के भीतर है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित उद्यम पूंजी निधियों की इक्विटी में निवेश भी इक्विटी लिखतों में निवेश के लिए निर्धारित पांच प्रतिशत की सीमा के भीतर रखने के पात्र होंगे।

भवदीय

(राधे श्याम)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 80/24.76.002/98

10 अगस्त 1998

19 श्रावण, 1920 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 8 जुलाई 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 71/24.76.002/97-98 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा

corporate debt instruments within the limit of 5% of incremental deposits of the previous year. It is clarified that investments in equity in dedicated venture capital funds meant for Information Technology is also eligible for inclusion within the five per cent limit prescribed for investments in equity instruments.

Yours faithfully

(Radhe Shyam)

Additional Chief General Manager

DBOD.No. FSC. BC. 80/24.76.002/98

August 10, 1998

Shravana 19, 1920 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of all
Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD. No. FSC. BC. 71/24.76.002/97-98 dated July 8, 1998 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now

अब निम्नलिखित दो सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें ।

11.95 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2004
12.22 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2008

3. इस संबंध में जारी किया गया 10 अगस्त 1998 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 79/24.76.002/97-98 संलग्न है ।

भवदीय

(राधेश्याम)

अपर मुख्य महाप्रबंधक

approved the following two Government dated securities for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

11.95 per cent Government Stock, 2004
12.22 per cent Government Stock, 2008

3. A directive DBOD. No. FSC. BC.79/24.76.002/97-98 dated August 10, 1998 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully

(Radhe Shyam)

Additional Chief General Manager

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 79/24.76.002/98

10 अगस्त 1998
19 श्रावण, 1920 (शक)

DBOD.No. FSC. BC. 79/24.76.002/98

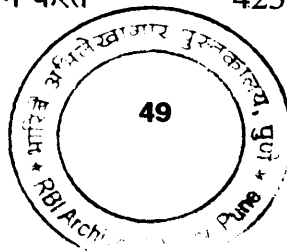
August 10, 1998
Sharavana 19, 1920 (Saka)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S.O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S.O. 425 (E) dated June 1, 1994 and issued by



Sec. IV

हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2561 के अनुसरण में निम्नलिखित दो सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त सरकारी प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक उक्त दो सरकारी प्रतिभूतियों के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे :
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे ।

11.95 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2004
12.22 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2008

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the following two Government dated securities for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in the said Government securities subject to the condition that :

- i) the banks would undertake all transactions of ready forward in the said two Government securities only at Mumbai.
- ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

11.95 per cent Government Stock, 2004
12.22 per cent Government Stock, 2008

(S. Gurumurthy)
Executive Director

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 82/24.76.002/98

13 अगस्त 1998
22 श्रावण 1920 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 10 अगस्त 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 80/24.76.002/98 देखें ।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 11.68 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2002 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें ।

3. इस संबंध में जारी किया गया 13 अगस्त 1998 का एक निदेश बैंपविवि.सं. एफएससी. बीसी. 81/24.76.002/98 संलग्न है ।

भवदीय

(राधे श्याम)
अपर मुख्य महाप्रबंधक

DBOD.No. FSC. BC. 82/24.76.002/98

August 13, 1998
Sharavana 22, 1920 (Saka)

**The Chairmen/Chief Executives of all
Commercial Banks**

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD. No. FSC.BC. 80/24.76.002/98 dated August 10, 1998 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 11.68 per cent Government Stock, 2002 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD. No. FSC. BC. 81/24.76.002/98 dated August 13, 1998 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully

(Radhe Shyam)
Additional Chief General Manager

13 अगस्त 1998
22 श्रावण, 1920 (शक)

August 13, 1998
Sharavana 22, 1920 (Saka)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2561 के अनुसरण में 11.68 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2002 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 11.68 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2002 में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक 11.68 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2002 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेज़र (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे ।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

Sec. IV

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S.O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S.O. 425(E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the 11.68 per cent Government Stock, 2002 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 11.68 per cent Government Stock, 2002 subject to the condition that :

- i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 11.68 per cent Government Stock, 2002 only at Mumbai.
- ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 88/24.76.002/98

24 अगस्त 1998
2 भाद्र 1920 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 13 अगस्त 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 82/24.76.002/98 देखें ।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 11.78 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2003 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें ।

3. इस संबंध में जारी किया गया 24 अगस्त 1998 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 87/24.76.002/98 संलग्न है ।

भवदीय

(राधे श्याम)

अपर मुख्य महाप्रबंधक

DBOD.No. FSC. BC. 88/24.76.002/98

August 24, 1998
Bhadra 2, 1920 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of all
Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD. No. FSC. BC. 82/24.76.002/98 dated August 13, 1998 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 11.78 per cent Government Stock, 2003 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD. No. FSC.BC. 87/24.76.002/98 dated August 24, 1998 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully

(Radhe Shyam)

Additional Chief General Manager

24 अगस्त 1998
2 भाद्र 1920 (शक)

August 24, 1998
Bhadra 2, 1920 (Saka)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2561 के अनुसरण में 11.78 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2003 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 11.78 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2003 में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक 11.78 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2003 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेज़र (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे ।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S.O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S.O. 425(E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the 11.78 per cent Government Stock, 2003 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 11.78 per cent Government Stock, 2003 subject to the condition that :

- i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 11.78 per cent Government Stock, 2003 only at Mumbai.
- ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 92/24.76.002/98

7 सितंबर 1998
16 भाद्र 1920 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 24 अगस्त 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 88/24.76.002/98 देखें ।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 12.40 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2013 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें ।

3. इस संबंध में जारी किया गया 7 सितंबर 1998 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 91/24.76.002/98 संलग्न है ।

भवदीय

(राधे श्याम)
अपर मुख्य महाप्रबंधक

DBOD.No. FSC. BC. 92/24.76.002/98

September 7, 1998
Bhadra 16, 1920 (Saka)

**The Chairmen/Chief Executives of all
Commercial Banks**

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD. No. FSC.BC. 88/24.76.002/98 dated August 24, 1998 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 12.40 per cent Government Stock, 2013 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD. No. FSC. BC. 91/24.76.002/98 dated September 7, 1998 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully

(Radhe Shyam)
Additional Chief General Manager

7 सितंबर 1998
16 भाद्र 1920 (शक)

September 7, 1998
Bhadra 16, 1920 (Saka)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2561 के अनुसरण में 12.40 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2013 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 12.40 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2013 में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक 12.40 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2013 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे :
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेज़र (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे ।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No.S.O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S.O. 425(E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the 12.40 per cent Government Stock, 2013 for the purpose of ready forward contracts, the bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 12.40 per cent Government Stock, 2013 subject to the condition that :

- i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 12.40 per cent Government Stock, 2013 only at Mumbai.
- ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

21 सितंबर 1998
30 भाद्र 1920 (शक)

September 21, 1998
Bhadra 30, 1920 (Saka)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

The Chairmen/Chief Executives of all
Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

हाज़िर वायदा लेनदेन

READY FORWARD TRANSACTIONS

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 7 सितंबर 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 92/24.76.002/98 देखें ।

Please refer to our circular DBOD. No. FSC. BC. 92/24.76.002/98 dated September 7, 1998 on the above subject.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब निम्नलिखित दो सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें :

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the following two Government dated securities for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

11.98 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2004
12.25 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2008

11.98 per cent Government Stock, 2004
12.25 per cent Government Stock, 2008

3. इस संबंध में जारी किया गया 21 सितंबर 1998 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 95/24.76.002/98 संलग्न है ।

3. A directive DBOD. No. FSC.BC. 95/24.76.002/98 dated September 21, 1998 issued in this regard is enclosed.

भवदीय

Yours faithfully

(राधे श्याम)
अपर मुख्य महाप्रबंधक

(Radhe Shyam)
Additional Chief General Manager

21 सितंबर 1998
30 भाद्र 1920 (शक)

September 21, 1998
Bhadra 30, 1920 (Saka)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2561 के अनुसरण में निम्नलिखित दो सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त सरकारी प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक उक्त दो सरकारी प्रतिभूतियों के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे ।

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No.S.O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S.O. 425(E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the following two Government dated securities for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in the said Government securities subject to the condition that :

- i) the banks would undertake all transactions of ready forward in the said two Government securities only at Mumbai.
- ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

11.98 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2004
12.25 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2008

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 98/24.76.002/98

7 अक्टूबर 1998
15 आश्विन 1920 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 21 सितंबर 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 96/24.76.002/98 देखें ।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 11.40 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2000 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेज़र (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें ।

11.98 per cent Government Stock, 2004
12.25 per cent Government Stock, 2008

(S. Gurumurthy)
Executive Director

DBOD.No. FSC. BC. 98/24.76.002/98

October 7, 1998
Ashwina 15, 1920 (Saka)

**The Chairmen/Chief Executives of all
Commercial Banks**

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD. No. FSC. BC. 96/24.76.002/98 dated September 21, 1998 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 11.40 per cent Government Stock, 2000 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. इस संबंध में जारी किया गया 7 अक्टूबर 1998 का एक निदेश बैंपवि. सं. एफएससी. बीसी. 97/24.76.002/98 संलग्न है ।

भवदीय

(राधे श्याम)

अपर मुख्य महाप्रबंधक

3. A directive DBOD. No. FSC. BC. 97/24.76.002/98 dated October 7, 1998 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully

(Radhe Shyam)

Additional Chief General Manager

बैंपवि. सं. एफएससी. बीसी. 97/24.76.002/98

7 अक्टूबर 1998

15 आश्विन 1920 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2561 के अनुसरण में 11.40 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2000 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि

DBOD.No. FSC. BC. 97/24.76.002/98

October 7, 1998

Ashwina 15, 1920 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S.O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S.O. 425(E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the 11.40 per cent Government Stock, 2000 for the purpose of ready forward contracts, the bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act,

वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 11.40 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2000 में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक 11.40 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2000 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे ।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 102/24.76.002.98-99

30 अक्टूबर 1998
8 कार्तिक 1920 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया 30 अक्टूबर 1998 के गवर्नर के परिपत्र एम्पीडी. बीसी. 181/07.01.279/98-99 के मद 38 का अवलोकन करें । अंतर बैंक देयताओं को प्रारक्षित

1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 11.40 per cent Government Stock, 2000 subject to the condition that :

- i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 11.40 per cent Government Stock, 2000 only at Mumbai.
- ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

DBOD.No. FSC. BC. 102/24.76.002.98-99

October 30, 1998
Kartika 8, 1920 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

**READY FORWARD TRANSACTIONS
(REPOs) IN GOVERNMENT AND
OTHER APPROVED SECURITIES**

Please refer to item 38 of our Governor's circular MPD.BC.181/07.01.279/98-99 dated 30th October 1998. In the backdrop

नकदी निधि अनुपात के रखरखाव की अपेक्षा से मुक्त किये जाने (3 प्रतिशत की न्यूनतम सांविधिक अपेक्षा को छोड़कर) की पृष्ठभूमि में तथा पुनः खरीद (रिपो) बाज़ार में बैंकों तथा अन्य प्रतिभागियों को अधिक लचीले तौर पर उनकी चलनिधि समायोजित करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि 31 अक्टूबर 1998 से सभी परिपक्वताओं के खजाना बिलों और भारत सरकार की अधिसूचित दिनांकित प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा लेनदेनों की न्यूनतम अवधि संबंधी प्रतिबंध हटा लिया जाये ।

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त अनुदेश जारी किये हैं ।

भवदीय

(राधे श्याम)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

of the inter-bank liabilities having been exempted from the requirements of maintenance of CRR (except for the statutory minimum requirement of 3 per cent) and with a view to enabling banks and other participants in the repo market to adjust their liquidity in a more flexible manner, it has been decided to withdraw the restriction of the minimum period for ready-forward (repo) transactions in Treasury Bills of all maturities and notified Government of India dated securities effective from October 31, 1998.

2. The above instructions are issued by the Reserve Bank of India in exercise of powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949.

Yours faithfully

(Radhe Shyam)

Additional Chief General Manager

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 113/24.76.002/98

4 दिसंबर 1998

13 अग्रहायण 1920 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 7 अक्टूबर 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 98/24.76.002/98 देखें ।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 12.60 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2018 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेज़र (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें ।

3. इस संबंध में जारी किया गया 4 दिसंबर 1998 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 112/24.76.002/98 संलग्न है ।

भवदीय

(राधे श्याम)

अपर मुख्य महाप्रबंधक

DBOD.No. FSC. BC. 113/24.76.002/98

December 4, 1998

Agrahayana 13, 1920 (Saka)

**The Chairmen/Chief Executives of all
Commercial Banks**

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD. No. FSC.BC. 98/24.76.002/98 dated October 7, 1998 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 12.60 per cent Government Stock, 2018 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD. No. FSC. BC. 112/24.76.002/98 dated December 4, 1998 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully

(Radhe Shyam)

Additional Chief General Manager

4 दिसंबर 1998

13 अग्रहायण 1920 (शक)

December 4, 1998

Agrahayana 13, 1920 (Saka)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2561 के अनुसरण में 12.60 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2018 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 12.60 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2018 में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक 12.60 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2018 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे ।

(एस.पी. तलवार)
उप गवर्नर

Sec. IV

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S.O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S.O. 425(E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the 12.60 per cent Government Stock, 2018 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 12.60 per cent Government Stock, 2018 subject to the condition that :

- i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 12.60 per cent Government Stock, 2018 only at Mumbai.
- ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(S.P. Talwar)
Deputy Governor

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 117/24.76.002/98

DBOD.No. FSC. BC. 117/24.76.002/98

15 दिसंबर 1998
24 अग्रहायण 1920 (शक)

December 15, 1998
Agrahayana 24, 1920 (Saka)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

The Chairmen/Chief Executives of all
Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

हाज़िर वायदा लेनदेन

READY FORWARD TRANSACTIONS

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 4 दिसम्बर 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 113/24.76.002/98 देखें ।

Please refer to our circular DBOD. No. FSC. BC. 113/24.76.002/98 dated December 4, 1998 on the above subject.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 11.47 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें ।

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 11.47 per cent Government Stock, 2001 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. इस संबंध में जारी किया गया 15 दिसंबर 1998 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 116/24.76.002/98 संलग्न है ।

3. A directive DBOD. No. FSC. BC. 116/24.76.002/98 dated December 15, 1998 issued in this regard is enclosed.

भवदीय

Yours faithfully,

(राधे श्याम)
अपर मुख्य महाप्रबंधक

(Radhe Shyam)
Additional Chief General Manager

15 दिसंबर 1998
24 अग्रहायण 1920 (शक)

December 15, 1998
Agrahayana 24, 1920 (Saka)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2561 के अनुसरण में 11.47 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 11.47 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001 में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक 11.47 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे ।

(खिज़र अहमद)
कार्यपालक निदेशक

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S.O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S.O. 425(E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the 11.47 per cent Government Stock, 2001 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 11.47 per cent Government Stock, 2001 subject to the condition that :

- i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 11.47 per cent Government Stock, 2001 only at Mumbai.
- ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(Khizer Ahmed)
Executive Director

ભાગ V
અગ્રિમ

SECTION V
ADVANCES

28 मई 1998
7 ज्येष्ठ 1919 (शक)

May 28, 1998
Jyestha 7, 1920 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ऋण तथा एफसीएनआर (बी)/एनआरएनआर पूल से ऋण

LOANS AGAINST FCNR (B) DEPOSITS AND LOANS OUT OF FCNR(B)/NRNR POOLS

कृपया उपर्युक्त विषय पर 21 अक्टूबर 1997 के गवर्नर के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 165/07.01.279/97-98 का पैरा 17 (छ) (iii) देखें। इस संबंध में इसी तारीख के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. डीआइआर. बीसी. 133/13.01.09/97 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) (एफसीएनआर (बी)) जमाराशि की जमानत पर दिये जाने वाले ऋणों और अग्रिमों तथा इस योजना के अधीन जुटाये जानेवाले संसाधनों से ऋण देने के संबंध में बहुविध निर्धारण समाप्त कर दिये जायें। तदनुसार, यह भी निश्चय किया गया था कि इस प्रकार के ऋणों और अग्रिमों को अग्रिमों पर ब्याज दर निदेश के उपबंधों के अधीन लाया जाये (देखें 21 अक्टूबर 1997 का निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 123/13.07.01/97-98)। कुछ बैंकों ने हमें अभिवेदन किया है कि अक्टूबर 1997 में ऋण नीति में परिवर्तन घोषित किये जाने के पहले उन्होंने रुपयों में ऋणों की संविदा मूल ऋण दर (पीएलआर) से कम नियत दर पर कर ली थी तथा यदि 22 अक्टूबर 1997 से ब्याज दर परिवर्तन लागू किये गये तो उन्हें ऋणकर्ताओं के साथ ऐसे ऋणों के संबंध में शर्तों पर पुनः बातचीत करनी होगी। हम स्पष्ट करना

Please refer to paragraph 17 (g) (iii) of Governor's Circular No. CPC.BC. 165/07.01.279/97-98 dated October 21, 1997 on the above mentioned subject. In this connection, a reference is also invited to our Circular DBOD. No. Dir. BC. 133/13.01.09/97 of even date in terms of which it was decided to dispense with multiple prescriptions on loans and advances against FCNR(B) Deposits and lending out of resources mobilised under the Scheme. Accordingly, it was further decided to bring such loans and advances under the provisions of Interest Rate Directive on advances (c.f. DBOD. No. Dir. BC.123/13.07.01/97-98 dated October 21, 1997). Some of the banks have represented to us that they had contracted fixed rate loans in rupees below PLR before the announcement of change in the credit policy in October 1997 and they will have to re-negotiate the terms on such loans with the borrowers if the interest rate changes are effected from October 22, 1997. We wish to clarify that

चाहते हैं कि हमारा ऊपर उल्लिखित निदेश भावी स्वरूप का होने के कारण सभी बैंकों को ऊपर उल्लिखित 21 अक्टूबर 1997 के हमारे निदेश में निर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों के अधीन 22 अक्टूबर 1997 को या उसके बाद दिये गये या नवीकृत किये गये सभी ऋणों के संदर्भ में हमारे निदेश में निर्दिष्ट ब्याज दरों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2. एनआरएनआर योजना के अंतर्गत जुटाये गये संसाधनों में से ऋण देने के संबंध में, कतिपय बैंकों ने ऐसे ऋण प्रदान करने के संबंध में लागू ब्याज दरों के बारे में हमसे पूछा है। हम विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग द्वारा जारी 4 जून 1992 के एडी (एमए सीरीज) परिपत्र सं. 35 के पैरा 6 तथा 11 जून 1992 के हमारे निदेश बैंपवि. सं. डीआइआर. बीसी. 139/13.01.09/92 के पैरा X में निहित उपबंधों की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनमें निर्दिष्ट किया गया है कि बैंक ऐसी जमाराशियों की जमानत पर जमा धारकों को दिये गये रुपया ऋणों/ओवरड्राफ्टों पर मार्जिन तथा ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह अनुदेश अब भी लागू है। एनआरएनआर योजना के अधीन जुटाये गये संसाधनों में से दिये गये अन्य सभी अग्रिमों के संबंध में समय-समय पर अग्रिमों से संबंधित हमारे ब्याज दर निदेश के उपबंध लागू होंगे।

यह परिपत्र बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क के अधीन जारी किया गया है।

भवदीय

(एम.पी. कोठारी)
महा प्रबंधक

Sec. V

our aforesaid Directive being prospective in nature, all banks should ensure to adhere to the rates of interest as stipulated in our Directive in respect of all loans granted or renewed on or after October 22, 1997 under the various categories mentioned in our Directive dated October 21, 1997, referred to above.

2. As regards lending out of resources mobilised under NRNR Scheme, we have received certain enquiries from the banks regarding rates of interest applicable on grant of such loans. We invite attention to the provisions contained in paragraph 6 of AD (MA Series) Circular No. 35 dated June 4, 1992 issued by the Exchange Control Department as also paragraph X of our Directive DBOD. No. Dir. BC. 139/13.01.09/92 dated June 11, 1992 stipulating that banks are free to determine the margin and the rates of interest on rupee loans/over-drafts granted to deposit holders against the security of such deposits. This instruction continues to be in force. All other advances made out of resources mobilised under NRNR scheme will attract the provisions of our interest rates Directive on advances as issued from time to time.

This circular is issued under Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949.

Yours faithfully

(M.P. Kothari)
General Manager

11 जून 1998

June 11, 1998

वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्ष/
मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

निर्यात ऋण

यह निर्णय लिया गया है कि निर्यात की वृद्धि दर को और बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सहयोगी उपाय के रूप में एक विशेष सुविधा के अन्तर्गत निर्यातकों को ऋण प्रदान किया जाए। यह सुविधा अस्थायी है तथा 31 दिसंबर 1999 तक उपलब्ध होगी। उक्त अवधि के बाद यह सुविधा नवीकृत नहीं की जाएगी। इस सुविधा के अंतर्गत निर्यातकों को, अप्रैल 1997 से मार्च 1998 के वित्त वर्ष की अवधि में किए गए निर्यात से अधिक निर्यात के लिए, बैंकों द्वारा 12 जून 1998 से 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर रुपया ऋण प्रदान किया जाएगा। 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पोतलदान-पूर्व रुपया ऋण के लिए 180 दिनों तक तथा पोतलदानोत्तर रुपया ऋण के लिए 90 दिनों के लिए लागू होगी। इस संबंध में 11 जून 1998 के पत्र डीबीओडी.सं.डीआईआर.बीसी. 55/13.03.00/98 द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की एक प्रति संलग्न है। अन्य निर्यात ऋणों के संबंध में दिनांक 29 अप्रैल 1998 के हमारे परिपत्र आईईसीडी.सं. 41/04.02.01/97-98 में दिए गए विवरण के अनुसार ही ब्याज की दरें लागू होंगी।

The Chairmen/Chief Executives of
commercial banks

Dear Sir,

EXPORT CREDIT

As an additional measure of support to step up the rate of growth of exports, it has been decided to extend to exporters credit under a special facility. This facility is temporary and would be available upto December 31, 1999. It would not be renewed beyond this period. Under the facility, banks should provide exporters rupee credit at 6.5 per cent per annum effective June 12, 1998 for their exports over and above the level achieved during the financial year April 1997-March 1998. The interest rate at 6.5 per cent per annum would be available for pre-shipment rupee credit upto a period of 180 days and post-shipment rupee credit upto a period of 90 days. A copy of the Directive DBOD No. Dir. BC. 55/13.03.00/98 dated June 11, 1998 issued in this regard is enclosed. The interest rates applicable in respect of other export credit would continue to be as indicated in our Circular IECD. No. 41/04.02.01/97-98 dated April 29, 1998.

2. वित्तीय सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्यातकों द्वारा अप्रैल

2. Financing banks are advised to obtain satisfactory documentary evidence, and keep

1997 से मार्च 1998 की अवधि में किए गए निर्यात के स्तर के संबंध में सन्तोषजनक दस्तोवेजी साक्ष्य प्राप्त कर लें तथा उसे रिकार्ड में रखें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि विशेष सुविधा के अंतर्गत केवल बढ़े हुए निर्यात के लिए ही वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाए।

3. इस विशेष सुविधा के अंतर्गत प्रदान किए गए रुपया निर्यात ऋण के शत-प्रतिशत भाग के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक से 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर पुनर्वित्त की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। निर्यात हेतु पुनर्वित्त सुविधा के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलग से विस्तृत अनुदेश जारी किए जा रहे हैं।

4. दिनांक 6 अक्टूबर 1993 के परिपत्र सं. आईईसीडी.ईएफडी.14/04.02.11/93-94, दिनांक 8 नवंबर 1993 के परिपत्र सं. ईएफडी.21/04.02.15/93-94 और 3 सितंबर 1994 के परिपत्र सं. 10/04.02.15/94-95 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार बैंकों को इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया है कि वे लंदन-अंतर-बैंक प्रस्तुत दर से संबंधित दरों पर विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण प्रदान करें। बैंक विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण प्रदान करने से संबंधित अपनी आवश्यकताएं मुख्यतः विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) इत्यादि निधियों से पूरी करते हैं। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तथा निर्यातकों को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण और अधिक प्रभावी ढंग से सुलभ कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि बैंक जिस लंदन-अंतर-बैंक प्रस्तुत दर पर धन प्राप्त करते हैं (विद्‌होल्टिंग टैक्स को छोड़कर), उससे 1.5 प्रतिशत से अधिक का लाभ न लें (जबकि उन्हें इस समय लंदन-अंतर-बैंक प्रस्तुत दर से 2/2.5 प्रतिशत अधिक लाभ लेने की अनुमति प्रदान की गई है)।

it on their records, regarding the level of exports achieved by the exporter during the period April 1997-March 1998 and to ensure that only the 'incremental' export is financed under the special facility.

3. Rupee export credit provided under the special facility will be eligible for refinance by RBI at interest rate of 4 per cent per annum to the extent of 100 per cent of such credit. The detailed instructions regarding Export Refinance are being issued by RBI separately.

4. Banks have been authorised to grant export credit in foreign currency, at rates linked to LIBOR, vide instructions contained in circulars IECD. No. EFD.14/04.02.11/93-94 dated 6th October 1993, EFD. 21/04.02.15/93-94 dated 8th November 1993 and 10/04.02.15/94-95 dated 3rd September 1994. Banks meet the requirements of export credit in foreign currency mainly from their FCNR(B) etc. funds. In the light of this position and with a view to enabling exporters to access export credit in foreign currency more effectively at internationally competitive rates, it has been decided that banks should charge a spread of not more than 1.5 per cent over LIBOR (excluding withholding tax) as against 2/2.5 per cent over LIBOR presently permitted to be charged.

5. निर्यातक और इनकी प्रतिनिधि संस्थाएँ रिज़र्व बैंक को बार-बार बताती रही हैं कि निर्यातकों को ऋण/अतिरिक्त ऋण समय पर मंजूर नहीं किया जाता। उन्होंने रिज़र्व बैंक को यह भी बताया है कि बैंक निर्यातकों की ऋण-सीमा में वृद्धि से संबंधित अनुरोध पर विचार करने से पूर्व समर्थक प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए जोर देते हैं। रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात ऋण को प्रमुखता और महत्त्व प्रदान करने वाले इसके सभी उपायों को, बैंकों के स्तर पर अधिकारों का पर्याप्त प्रत्यायोजन और आवश्यकताओं पर आधारित तथा समय से ऋण की मंजूरी सुनिश्चित करते हुए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करके, पूरा समर्थन प्राप्त हो। निर्यातक अपनी इच्छानुसार रुपया अथवा विदेशी मुद्रा के रूप में निर्यात-ऋण ले सकते हैं। अतः यह संभव होना चाहिए कि निर्यातक जब भी चाहें, बिना किसी कठिनाई के या बैंकों की शाखाओं में बिना किसी विलम्ब के, विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण प्राप्त कर सकें। अतः बैंकों की शाखाओं में बिना किसी विलम्ब के, विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण प्राप्त कर सकें। अतः बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आन्तरिक दिशानिर्देशों/अपनी क्रियाविधियों से संबद्ध सभी पहलुओं की तत्काल समीक्षा करें ताकि उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

भवदीय

(ए. चन्द्रमौलीश्वरन)

मुख्य महाप्रबंधक

5. Exporters and their representative bodies have been frequently representing to the Reserve Bank that exporters do not get credit limits/enhancement in credit limits sanctioned in time. They have also been representing to the Reserve Bank that collateral security is being insisted upon by banks before considering request for enhancements in credit limits. Reserve Bank is keen to ensure that all its measures according primacy and importance to export credit with a view to achieving export growth are fully supported at the level of banks through suitable guidelines ensuring adequate delegation of powers and sanction of need-based and timely credit. Exporters have the option to avail themselves of export credit either in rupee or foreign currency. It should, therefore, be possible for exporters to avail of export credit in foreign currency when they choose to do so without experiencing any difficulty or delay at the branches of banks. Banks are, therefore, advised to review all aspects of their internal guidelines/procedures immediately to achieve the above objective.

Yours faithfully

(A. Chandramouliswaran)

Chief General Manager

11 जून 1998

June 11, 1998

अग्रिमों पर ब्याज की दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 तथा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और उचित है, यह निर्देश देता है कि इस दिशानिर्देश के संलग्नक में यथानिर्दिष्ट मद 4(4) दिनांक 29 अप्रैल 1998 के इसके दिशानिर्देश सं.बीसी. 33/13.03.00/98 के संलग्नक में दिनांक 12 जून 1998 से जोड़ दी जाए और उसकी मद 4(5) के रूप में पुनर्संख्यांकित कर दिया जाए।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 11 जून 1998 के निदेश सं. डीआईआर. बीसी. 55/13.03.00/98 का अनुलग्नक

4. निर्यात ऋण

- (4) अप्रैल 1997 से मार्च 1998 के दौरान किए गए निर्यात से अधिक निर्यात की मात्रा के लिए निर्यात ऋण पर लागू दर

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that, with effect from June 12, 1998, item 4(4) as indicated in the enclosure to this Directive be added to the Annexure to its Directive No. BC.33/13.03.00/98 dated April 29, 1998 and item 4(4) therein be renumbered as item 4(5).

(S. Gurumurthy)
Executive Director

Enclosure to Directive No. Dir. BC. 55/13.03.00/98 dated June 11, 1998

4. Export Credit

- (4) The rate applicable to Export Credit for exports over and above the level achieved during the period April 1997-March 1998

(अ) 180 दिन तक पोतलदानपूर्व ऋण 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष

(ब) पोतलदानोत्तर ऋण

(i) पारवहन अवधि के लिए मांग बिल 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(फेडाई द्वारा यथानिर्दिष्ट) 6.5 प्रतिशत

(ii) मियादी बिल 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(निर्यात बिलों की मुद्दत, फेडाई द्वारा निर्दिष्ट पारवहन अवधि और छूट की अवधि सहित, जो भी लागू हो, कुल अवधि के लिए) 90 दिन तक

(a) Pre-shipment credit upto a period of 180 days 6.5 per cent per annum

(b) Post-shipment credit

(i) Demand bills for transit period (as specified by FEDAI) 6.5 per cent per annum

(ii) Usance Bills 6.5 per cent per annum
(For total period comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI and grace period whichever applicable) Upto 90 days

औनिऋवि.सं. 5/04.02.01/98-99

IECD.No.5/04.02.01/98-99

6 अगस्त 1998

August 6, 1998

सभी वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,

The Chairmen/Chief Executives of all Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

निर्यात ऋण - ब्याजदर

EXPORT CREDIT - INTEREST RATES

कृपया दिनांक 29 अप्रैल 1998 का हमारा परिपत्र सं. औनिऋवि. 41/04.02.01/97-98 देखें।

Please refer to circular IECD No. 41/04.02.01/97-98 dated April 29, 1998.

2. यह निर्णय लिया गया है कि 6 अगस्त 1998 से पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर घटा दी जाय। संशोधित ब्याज दरें संलग्नक में दी गई हैं। ब्याज दरों में की गई कमी 31 मार्च 1999 तक लागू रहेगी। 1 अप्रैल 1999 से इस परिपत्र के जारी किए जाने से पहले की ब्याजदरें स्वतः लागू हो जाएँगी, बशर्ते इसमें कोई अन्य परिवर्तन की सूचना न दी जाए।

2. It has been decided that effective August 6, 1998, interest rates on pre-shipment and post-shipment rupee export credit should be reduced. The revised rates are given in the Annexure. The reduction in the interest rates would be up to 31st March 1999. As from 1st April 1999, the interest rates applicable prior to the issue of this circular will come into force automatically unless notified otherwise.

3. ब्याजदरों में की गई इस कमी का लाभ 6 अगस्त 1998 से, केवल नये ऋणों पर ही नहीं, बल्कि वर्तमान ऋणों पर भी ऋण की शेष अवधि के लिए दिया जाएगा।

4. निर्यात ऋण पर ब्याजदर में किए गए उपर्युक्त परिवर्तन बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांक 6 अगस्त 1998 के दिशा निर्देश बैंपविवि सं.बीसी 77/13.07.01/98 में समाहित हैं।

भवदीय,

(ए. चन्द्रमौलीश्वरन)
मुख्य महाप्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीसी. 77/13.07.01/98

6 अगस्त 1998

ऋणों पर ब्याजदरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35ए के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि जनहित में ऐसा करना उपयुक्त और आवश्यक है, एतद्वारा निदेश देता है कि दिनांक 29 अप्रैल 1998 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआईआर.बीसी 33/13.07.01/97-98 के संलग्नक में निर्दिष्ट निर्यात ऋण पर ब्याज दरें, इस निदेश की तारीख से 31 मार्च 1999 तक, इस निदेश के संलग्नक के स्तंभ 3 में बताए गए अनुसार बदल दी जायें। यदि अन्यथा सूचित न किया जाये

3. The benefit of the reduction in the interest rates as above, with effect from August 6, 1998 will be applicable not only to fresh advances but also to existing advances for the remaining period of credit.

4. The changes made in the interest rates on export credit as above have been incorporated in the Directive DBOD No. BC.77/13.07.01/98 dated August 6, 1998.

Yours faithfully

(A. Chandramouliswaran)
Chief General Manager

DBOD.No. BC. 77/13.07.01/98

August 6, 1998

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that the interest rate on export credit, indicated in Annexure to its Directive DBOD. No. Dir. BC. 33/13.07.01/97-98 dated April 29, 1998, be changed as given in column 3 of the Annexure enclosed to this Directive, from the date of this Directive and

तो 1 अप्रैल 1999 से संलग्नक के स्तंभ 2 में दी
गए ब्याज दरें लागू हो जाएंगी।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

upto March 31, 1999. As from April 1, 1999,
the interest rates as given in column 2 of the
Annexure will be applicable unless notified
otherwise.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

संलग्नक
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निर्यात ऋणों पर ब्याजदरें

	परिपत्र जारी किये जाने से पहले अर्थात् 5 अगस्त 1998 तक लागू ब्याज दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष)	6 अगस्त 1998 से 3 मार्च 1999 तक ले ब्याज दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष)	
1.	2.	3.	
4. निर्यात ऋण			
(1) पोतलदानपूर्व ऋण			
(i) (क) 80 दिन तक	11.00	9.00	
(ख) 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक	14.00	12.00	
(ii) सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों पर, निर्यात ऋण और प्रत्यय गारंटी निगम की गारंटी के अंतर्गत (90 दिन तक)	11.00	9.00	
(2) पोतलदानोत्तर ऋण			
(i) पारवहन अवधि के लिए माँग बिल (फेडाई द्वारा यथानिर्दिष्ट)	11.00 से अधिक नहीं	9.00	
(ii) मीयादी बिल (निर्यात बिलों की मुददत, फेडाई द्वारा निर्दिष्ट पारवहन अवधि और जिन मामलों में लागू हो उनमें छूट की अवधि सहित कुल अवधि के लिए)	11.00 से अधिक नहीं	9.00	
(क) 90 दिन तक			
(ख) 90 दिन से अधिक और पोतलदान की तारीख से 6 माह तक	13.00	11.00	
(iii) सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों पर निर्यात ऋण गारंटी निगम की गारंटी के अंतर्गत (90 दिन तक)	11.00 से अधिक नहीं	9.00	
(iv) अनाहरित शेष पर 90 दिन तक	11.00 से अधिक नहीं	9.00	

ANNEXURE
Interest rates on Export Credit of scheduled commercial banks

	Rate of interest (per cent per annum) as applicable prior to the issue of the circular, i.e. upto August 5, 1998	Rate of interest (per cent per annum) effective August 6, 1998 and upto March 31, 1999	
1.	2.	3.	
4. Export Credit			
(1) Pre-shipment Credit			
(i) (a) Upto 180 days	11.00	9.00	
(b) Beyond 180 days and upto 270 days	14.00	12.00	
(ii) Against incentives receivable from Government covered by ECGC guarantee (upto 90 days)	11.00	9.00	
(2) Post-shipment Credit			
(i) Demand bills for transit period (as specified by FEDAI)	Not exceeding 11.00	9.00	
(ii) Usance Bills (For total period comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI, and grace period wherever applicable)	Not exceeding 11.00	9.00	
(a) Upto 90 days			
(b) Beyond 90 days and upto six months from the date of shipment	13.00	11.00	
(iii) Against incentives receivable from Government covered by ECGC guarantee (upto 90 days)	Not exceeding 11.00	9.00	
(iv) Against undrawn balances (upto 90 days)	Not exceeding 11.00	9.00	

(v) पोतलदान की तारीख से 11.00 से 9.00
एक वर्ष के अन्दर देय अधिक नहीं
प्रतिधारण धन पर (केवल
आपूर्ति भाग के लिए)
(90 दिन तक)

(3) आस्थगित ऋण

(i) 180 दिन से अधिक स्वेच्छा से * स्वेच्छा से *
के लिए आस्थगित ऋण

**(4) निर्यात ऋण जिसका
अन्यथा उल्लेख नहीं
किया गया है**

(क) पोतलदानपूर्व ऋण स्वेच्छा से * स्वेच्छा से *
(ख) पोतलदानोत्तर ऋण 20.00 20.00
(न्यूनतम) (न्यूनतम)

* स्वेच्छा से : बैंक अपनी मर्जी से ब्याज दर निश्चित कर सकते हैं।

(v) Against retention Not 9.00
money (for supplies exceeding
portion only) payable 11.00
within one year from
the date of shipment
(upto 90 days)

(3) Deferred Credit

(i) Deferred credit for the Free* Free*
period beyond 180 days

**(4) Export Credit not
otherwise specified**

(a) Pre-shipment credit Free* Free*
(b) Post-shipment credit 20.00 20.00
(minimum) (minimum)

*Free = the bank is free to decide the rate of
interest to be charged.

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 83/21.04.012/98-99

DBOD.No. Dir.BC.83/21.04.012/98-99

18 अगस्त 1998
27 श्रावण 1920 (शक)

August 18, 1998
Shravana 27, 1920 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

जम्मू और कश्मीर राज्य में
व्यापार और उद्योग को छूट

RELAXATIONS TO TRADE AND
INDUSTRY IN THE STATE OF
JAMMU & KASHMIR

कृपया आप हमारा 14 मार्च 1997 का परिपत्र बैंपविवि. सं.बी.पी.बी.सी. 20/21.04.012/97 देखें. जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य में ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को छूट/ऋण में ढील की अवधि 31 मार्च 1998 तक बढ़ाने की सूचना दी गयी है। यह निर्णय लिया गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को मौजूदा छूट/ऋण में ढील की अवधि आगे और एक वर्ष अर्थात् मार्च 1999 तक बढ़ा दी जाये।

Please refer to our circular letter DBOD. No. BP. BC. 20/21.04.012/97 dated March 14, 1997 extending the period of concessions/ credit relaxations to the borrowers/ customers in the State of Jammu & Kashmir upto 31 March 1998. It has been decided that the existing concessions/credit relaxations to borrowers/customers in the State of Jammu and Kashmir will continue to be operative for a further period of one year i.e. upto 31 March 1999.

2. इस संबंध में कृपया अपने नियंत्रक/शाखा कार्यालयों को उपयुक्त अनुदेश जारी करें।

2. Suitable instructions may please be issued to your controlling/branch offices in this regard.

भवदीय

Yours faithfully

(श्री. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

(C.R. Muralidharan)
General Manager

बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.90/13.07.05/98-99

DBOD.No. Dir.BC.90/13.07.05/98-99

28 अगस्त 1998
6 भाद्र 1920 (शक)

August 28, 1998
Bhadra 6, 1920 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

शेयरों और डिबेंचरों पर बैंक वित्त-
मास्टर परिपत्र

**BANK FINANCE AGAINST SHARES
AND DEBENTURES - MASTER
CIRCULAR**

आपको विदित ही है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने शेयरों की जमानत पर अग्रिम देने के संबंध में बैंकों को समय-समय पर दिशा-निर्देश/अनुदेश/निदेश जारी किये हैं। बैंकों को प्रचलित अनुदेश एक ही स्थान पर मिल सकें, इस दृष्टि से इस विषय पर सभी वर्तमान दिशा-निर्देशों को शामिल करते हुए एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है, जो संलग्न है। हम यह सूचित करते हैं कि इस मास्टर परिपत्र से रिज़र्व बैंक द्वारा इस विषय में अब तक जारी किये गये परिपत्रों में दिये गये सभी पिछले अनुदेश निरस्त हो जाते हैं।

As you are aware the Reserve Bank of India has, from time to time, issued a number of guidelines/instructions/directives to banks in regard to advances against shares. To enable banks to have the current instructions at one place, a Master Circular containing all existing guidelines on the subject has been prepared and is enclosed. We advise that this Master Circular supersedes all the previous instructions contained in the Circulars issued by the RBI so far.

भवदीय

Yours faithfully

(राधे श्याम)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

(Radhe Shyam)
Additional Chief General Manager

शेयरों, यूनितों, डिबेंचरों और सरकारी क्षेत्र के बांडों की जमानत पर अग्रिम

1. सामान्य दिशा-निर्देश:

शेयरों और डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर अग्रिम देने के सभी मामलों में बैंकों द्वारा जाने वाले सामान्य दिशा-निर्देश अनुबंध में दिये गये हैं।

2. शेयरों/डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर अग्रिम व्यक्तियों, शेयर और स्टॉक दलालों तथा बाजार-निर्माताओं (मार्केट मेकर्स) को नीचे पैरा 3 से 6 तक में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार दिये जायें। अन्य ऋणकर्ताओं को ऋण देने के संबंध में बैंक नीचे पैराग्राफ 7 और 8 देखें। पैराग्राफ 9 में पारस्परिक निधियों की यूनितों की जमानत पर अग्रिमों के संबंध में उल्लेख है।

3. व्यक्तियों को अग्रिम

बैंक शेयरों, डिबेंचरों अथवा बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम निम्नलिखित शर्तों पर दे सकते हैं:

(i) **ऋण का प्रयोजन:** शेयरों, डिबेंचरों और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के बांडों की जमानत पर ऋण व्यक्तियों को उनकी आकस्मिक और व्यक्तिगत स्वरूप की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिये जा सकते हैं अथवा ये शेयरों/डिबेंचरों/बांडों के अधिकार निर्गम या नये निर्गम में अभिदान करने के लिए अथवा द्वितीयक बाज़ार में

ADVANCES AGAINST SHARES, UNITS, DEBENTURES AND PUBLIC SECTOR UNDERTAKING (PSU) BONDS

1. General Guidelines:

The Annexure lays down the general guidelines to be followed by banks in all cases of grant of advances against shares and debentures/bonds.

2. Advances against security of shares/debentures/bonds may be given to individuals, share and stock brokers and market makers, as per guidelines detailed in paragraphs 3 to 6 below. In regard to loans to other borrowers, banks may please refer to paragraphs 7 and 8 below. Paragraph 9 relates to advances against units of mutual funds.

3. Advances to individuals

Banks may grant advances against the security of shares, debentures or bonds to individuals subject to the following conditions :

(i) **Purpose of the Loan :** Loan against shares, debentures and bonds of public sector undertakings (PSUs) may be granted to individuals to meet contingencies and personal needs or for subscribing to rights or new issues of shares/debentures/bonds or for purchase in the secondary market,

खरीद के लिए दिये जा सकते हैं। ये ऋण व्यक्ति द्वारा धारित शेयरों/डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर दिये जा सकते हैं।

(ii) **अग्रिम की राशि:** यदि शेयर, डिबेंचर और सरकारी क्षेत्र के बांड भौतिक रूप में धारित हों तो उनकी जमानत पर ऋण प्रति ऋणकर्ता 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि उक्त प्रतिभूतियां भौतिक रूप में धारित न हो तो 10 लाख रुपये की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जा सकती है।

(iii) **मार्जिन:** बैंक भौतिक रूप में धारित इक्विटी शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के बाज़ार मूल्य के न्यूनतम 50 प्रतिशत का मार्जिन रखें। अभौतिक रूप में धारित शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के मामले में न्यूनतम मार्जिन 25 प्रतिशत रखा जाना चाहिए। यह केवल न्यूनतम मार्जिन है और बैंक शेयरों के लिए उच्चतर मार्जिन निर्धारित कर सकते हैं, चाहे शेयर भौतिक रूप में हों या अभौतिक रूप में। अधिमान शेयरों/अपरिवर्तनीय डिबेंचरों और बांडों की जमानत पर अग्रिमों के लिए मार्जिन की अपेक्षाएँ बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित की जायें।

(iv) **ऋण देने संबंधी नीति:** प्रत्येक बैंक शेयरों/डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को ऋण देने के लिए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक ऋण

against the security of shares/debentures/bonds held by the individual.

(ii) **Amount of advance :** Loans against the security of shares, debentures and PSU bonds if held in physical form should not exceed the limit of Rs. 10 lakhs per borrower. The limit of Rs. 10 lakhs has been enhanced to Rs. 20 lakhs if the securities are held in dematerialised form.

(iii) **Margin :** Banks should maintain a minimum margin of 50 percent of the market value of equity shares/convertible debentures held in physical form. In the case of shares/convertible debentures held in dematerialised form, a minimum margin of 25 percent should be maintained. These are minimum margin stipulations and banks may stipulate higher margins for shares whether held in physical form or dematerialised form. The margin requirements for advances against preference shares/non-convertible debentures and bonds may be determined by the banks themselves.

(iv) **Lending policy :** Each bank should formulate with the approval of the Board a Lending Policy for grant of advances to individuals against

संबंधी नीति बनायें। इसके लिए इस प्रकार के अग्रिमों पर लागू होने वाले दिशा-निर्देशों का, जो अनुबंध में दिये गये हैं, ध्यान रखा जाये। बैंकों को ऋण मूल्यांकन के लिए ऋणकर्ता से एक घोषणापत्र प्राप्त करना चाहिए, जिसमें उसके द्वारा अन्य बैंकों से लिये गये ऋण बताये जायें। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा कि किसी कंपनी या कंपनियों के समूह के शेयरों पर इस प्रकार की सहायता भिन्न-भिन्न बैंकों से न ली जाये। एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में प्रत्येक बैंक इस प्रकार के अग्रिमों की कुल सीमा निर्धारित करने पर भी विचार कर सकता है।

4. शेयरों और स्टॉक दलालों को अग्रिम

(i) बैंक और उनकी सहायक (अनुषंगी) कंपनियां बदला लेनदेनों को वित्त प्रदान करने का कार्य न करें।

(ii) शेयरों और स्टॉक दलालों को उनके द्वारा व्यापार में लगे स्टॉक के रूप में धारित शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर उनकी आवश्यकता के आधार पर ओवरड्राफ्ट सुविधायें/ऋण सुविधा प्रदान की जाये। इस प्रकार के वित्त के लिए आवश्यकता पर आधारित अपेक्षाओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिसके लिए ऋण लेने वाले की वित्तीय स्थिति, उसके अपने खाते में परिचालनों और ग्राहकों की ओर से परिचालनों, अर्जित आय, स्टॉक और शेयरों के पण्यावर्त की अवधि तथा इस बात को ध्यान में रखा जाये कि दलाल को

shares/debentures/bonds keeping in view the general guidelines given in the Annexure as applicable to such advances. Banks should obtain a declaration from the borrower indicating the extent of loans availed of by him from other banks as input for credit evaluation. It would also be necessary to ensure that such accommodation from different banks is not obtained against shares of a single company or a group of companies. As a prudential measure, each bank may also consider laying down an aggregate limit of such advances.

4. Advances to share and stock brokers

(i) Banks and their subsidiaries should not undertake financing of 'Badla' transactions.

(ii) Share and stock brokers may be provided need based overdraft facilities/line of credit against shares and debentures held by them as stock-in-trade. A careful assessment of need based requirements for such finance should be made taking into account the financial position of the borrower, operations on his own account and on behalf of clients, income earned, the average turnover period of stocks and shares and the extent to which the broker's funds are required to be

अपने कारोबारी परिचालनों में उसकी कितनी निधियां रखनी हैं। स्टॉक और शेयर दलालों द्वारा शेयरों और डिबेंचरों में अपनी ओर से बड़े पैमाने पर बैंक वित्त से निवेश को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। प्रतिभूति के रूप में रखी गयी प्रतिभूतियां ऐसी होनी चाहिए कि उनकी राशि आसानी से प्राप्त हो सके।

(iii) शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिमों के लिए 10 लाख/20 लाख रुपये की उच्चतम सीमा शेयर और स्टॉक दलालों के मामले में लागू नहीं होगी और उनके लिए अग्रिम आवश्यकता के आधार पर होने चाहिए।

(iv) बैंक सुपुर्दगी और भुगतान के बीच अंतर को पूरा करने के लिए नकदी हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत उन स्टॉक दलालों को कार्यशील पूंजी सुविधायें दे सकते हैं जिन्होंने सेबी/शेयर बाजारों द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का अनुपालन किया है। यह सुविधा संस्थागत ग्राहकों अर्थात् वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों, पारस्परिक निधियों और बैंकों की ओर से डीवीपी लेनदेनों के संबंध में दी जाये। इस प्रकार की सुविधा की अवधि कम होगी और वह ऋण प्रवाह के अंतर को ध्यान में रखते हुए वित्त संबंधी आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर और लेनदेन में विनियोजन के लिए स्टॉक दलाल की निधियों तथा दलाल की समग्र वित्तीय स्थिति पर आधारित होगी। अलग-अलग लेनदेनों के आधार पर उपयोग पर निगरानी रखी जायेगी। मार्जिन स्वयं बैंकों द्वारा निर्धारित किया जाये और बैंक सुरक्षा संबंधी पर्याप्त उपाय करें तथा निगरानी तंत्र बनायें।

involved in his business operations. Large scale investment in shares and debentures on own account by stock and share brokers with bank finance, should not be encouraged. The securities lodged as collateral should be easily marketable.

(iii) The ceiling of Rs. 10 lakhs/Rs. 20 lakhs for advances against shares/debentures to individuals will not be applicable in the case of share and stock brokers and the advances would be need based.

(iv) Banks may grant working capital facilities to stock brokers registered with SEBI and who have complied with capital adequacy norms prescribed by SEBI/Stock exchanges to meet the cash flow gap between delivery and payment for DVP transactions undertaken on behalf of institutional clients viz. FIs, FIIIs, mutual funds and banks. The duration of such a facility will be short and would be based on an assessment of the financing requirements keeping in view the cash flow gaps, the broker's funds required to be deployed for the transaction and the overall financial position of the broker. The utilisation will be monitored on the basis of individual transactions. Margins may be determined by the banks themselves and banks may institute

adequate safeguards and monitoring mechanisms.

(v) बैंक शेयर और स्टॉक दलालों की ओर से जमानत की राशि के बदले में शेयर बाज़ार को गारंटी जारी कर सकते हैं। यह गारंटी शेयर बाज़ारों द्वारा यथानिर्धारित बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार्य सीमा तक ही होगी। बैंक शेयर बाज़ार विनियमों के अनुसार मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं के लिए भी गारंटी जारी कर सकते हैं। बैंक प्रत्येक आवेदनकर्ता दलाल की आवश्यकता का अनुमान लगाये और जोखिम की उच्चतम सीमा सहित सामान्य तथा आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करें।

(v) Banks may issue guarantees on behalf of share and stock brokers in favour of stock exchanges in lieu of security deposit to the extent it is acceptable in the form of bank guarantee as laid down by stock exchanges. Banks may also issue guarantees in lieu of margin requirements as per stock exchange regulations. The bank should assess the requirement of each applicant borrower, observe usual and necessary safeguards including the exposure ceilings.

(vi) अनुबंध के पैराग्राफ (vii) में उल्लिखित भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में बैंक के नाम शेयरों के अंतरण से संबंधित अपेक्षा शेयर और स्टॉक दलालों को दिये गये अग्रिमों के संबंध में लागू नहीं होगी, बशर्ते इस प्रकार के शेयर अधिक से अधिक नौ महीने की अवधि के लिए जमानत के रूप में रखे गये हों। अभौतिक रूप में रखे गये शेयरों के मामले में निक्षेप (डिपोजिटरी) प्रणाली में गिरवी (प्लेज) रखने की सुविधा है और बैंक इस प्रकार की सुविधा का लाभ उठाये तथा इस प्रकार के मामलों में शेयरों को बैंक के नाम अंतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी, धारण करने की अवधि कुछ भी हो। शेयर और स्टॉक दलालों को आवश्यकतानुसार गिरवी रखे गये शेयरों को बदलने (प्रतिस्थापित करने) की स्वतंत्रता होगी। खाते में चूक होने की स्थिति में बैंक

vi) The requirement relating to transfer of shares in bank's name in respect of shares held in physical form mentioned in paragraph (vii) in the Annexure shall not apply in respect of advances granted to share and stock brokers provided such shares are held as security for a period not exceeding nine months. In the case of dematerialised shares, the depository system provides a facility for pledging and banks may avail themselves of this facility and in such cases there will not be need to transfer the shares in the name of the bank irrespective of the period of holding. The share and stock brokers are free to substitute the shares pledged by them as and when

को अपने नाम शेयर अंतरित करने के विकल्प का प्रयोग करना चाहिए।

(vii) बैंक सेबी के पास पंजीकृत शेयर और स्टॉक दलालों को ही अग्रिम देंगे, जो सेबी/ शेयर बाजारों द्वारा निर्धारित उन पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का अनुपालन करते हों।

5. **बाजार-निर्याताओं को बैंक वित्त**
अनुमोदित बाजार-निर्माताओं की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक आवश्यकता के आधार पर वित्त प्रदान कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए वे ऋण जोखिम की सीमाओं, मूल्यन की पद्धति आदि के सहित वित्त प्रदान करने के लिए उचित मानदंड अपनायें। वे नीचे दिये गये दिशा-निर्देशों का भी पालन करें:

(क) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अग्रिम देने के लिए शेयर बाजार द्वारा अनुमोदित बाजार-निर्माता पात्र होंगे।

(ख) बाजार-निर्माण (मार्केट मेकिंग) केवल इक्विटी के लिए ही नहीं होना चाहिए बल्कि ऋण प्रतिभूतियों के लिए भी होना चाहिए जिनमें राज्य और केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां भी शामिल हैं।

(ग) बाजार-निर्माताओं की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं पर आधारित राशि का निर्धारण करने में बैंकों को बाजार निर्माण

necessary. In case of a default in the account, the bank should exercise the option to get the shares transferred in its name.

(vii) Banks shall grant advances only to share and stock brokers registered with SEBI and who comply with capital adequacy norms prescribed by SEBI/Stock Exchanges.

5. **Bank Finance for Market Makers**
Banks may provide need based finance to meet the genuine credit requirements of approved Market Makers. For this purpose, they should lay down appropriate norms for financing them including exposure limits, method of valuation, etc. They should also follow the guidelines given below :

(a) Market Makers approved by stock exchange would be eligible for grant of advances by scheduled commercial banks.

(b) Market Making may not only be for equity but also for debt securities including State and Central Government securities.

(c) Banks should exercise their commercial judgement in determining the need based working capital

संबंधी परिचालनों को ध्यान में रखते हुए अपने वाणिज्यिक विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

(घ) बाज़ार-निर्माताओं को अग्रिम देते समय बैंक अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर सामान्य विवेकपूर्ण मार्जिन निर्धारित कर सकते हैं।

(ङ) बाज़ार-निर्माताओं के लिए अग्रिमों के संबंध में बैंक उन स्क्रिप्स के अतिरिक्त अन्य स्क्रिप भी संपार्श्विक जमानत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं जिन स्क्रिप्स के लिए बाज़ार निर्माण संबंधी परिचालन किये जा रहे हैं।

(च) संपार्श्विक जमानत के रूप में प्रस्तुत की गयी प्रतिभूतियों में शेयर/डिबेंचर/बांड/भारतीय यूनिट ट्रस्ट सहित पारस्परिक निधियों की यूनिटें और साथ ही केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं।

(छ) बैंक यह सुनिश्चित करें कि बाज़ार-निर्माण के लिए दिये गये अग्रिमों का उपयोग बाज़ार-निर्माण-प्रयोजन के लिए निर्धारित स्क्रिप से भिन्न शेयरों में निवेश के लिए न किया जाये। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी-तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

(ज) शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम के संबंध में व्यक्तियों के लिए निर्धारित 10 लाख/20 लाख रुपये की उच्चतम सीमा बाज़ार-निर्माताओं के मामले में लागू नहीं होगी।

requirements of Market Makers by taking into account the Market Making operations.

(d) Banks may prescribe normal prudential margin based on their commercial judgement while extending advances to Market Makers.

(e) Banks may accept, as collateral for the advances to the Market Makers, scrips other than the scrips in which the market making operations are undertaken.

(f) Securities offered as collateral may include shares/debentures/bonds/units of mutual funds including UTI as well as securities of Central and State Governments.

(g) Banks should ensure that advances provided for Market Making are not diverted for investment in shares other than the scrip earmarked for Market Making purpose. For this purpose, a suitable follow-up and monitoring mechanism must be evolved.

(h) The ceiling of Rs. 10 lakhs/Rs. 20 lakhs for advances against shares/debentures to individuals will not be applicable in the case of Market Makers.

6. प्रत्येक बैंक स्टॉक दलालों तथा बाज़ार निर्माताओं को अग्रिम देने के लिए एक विस्तृत ऋण नीति निर्धारित करे और दलालों की ओर से गारंटियां देने के लिए भी नीति बनाये। इसमें अनुबंध में दिये गये सामान्य दिशा-निर्देशों के साथ ही निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाये:

- इस प्रकार के अग्रिमों/गारंटियों का प्रयोजन और उपयोग
- इस प्रकार के अग्रिमों का मूल्यन
- नियंत्रण संबंधी बातें, जिनमें विशेष रूप से इस प्रकार के वित्तपोषण की अनोखी विशेषताओं और जोखिमों को पहचाना जाये
- रखा जाने वाला मार्जिन
- संपार्श्विक जमानत की पद्धति
- संपार्श्विक जमानत पर लिये गये शेयरों तथा अन्य प्रतिभूतियों के मूल्यन की आवृत्ति
- मूल्यन की आवृत्ति तिमाही में कम से कम एक बार होनी चाहिए
- बैंक के नाम शेयर अंतरण करने के लिए दिशा-निर्देश
- वैयक्तिक ऋणों के लिए अधिकतम राशि (रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण एकल ऋणकर्ता के लिए सीमा के अंतर्गत हो)। निदेशक मंडल इस क्षेत्र के संबंध में बैंक की कुल राशि के बारे में सीमा तय करने पर भी विचार कर सकता है।

6. Each bank should lay down a detailed loan policy for granting advances to Stock Brokers and Market Makers and also a policy for grant of guarantees on behalf of brokers which should keep in view the general guidelines given in the Annexure and include inter alia, the following :

- purpose and use of such advances/ guarantees
- pricing of such advances
- control features that specifically recognise the unique characteristics and risks of such financing
- margins to be maintained
- method of valuation of collateral
- frequency of valuation of shares and other securities taken as collateral.
- frequency of valuation of shares may at least be once in a quarter.
- guidelines for transfer of shares in bank's name
- maximum exposure for individual credits (within the RBI prescribed prudential Single Borrower Limit). The Board may also consider laying down a limit on the aggregate exposure of the bank to this sector.

- संविभाग की कुल राशि, इसकी गुणवत्ता और निष्पादन की समीक्षा की जानी चाहिए और निदेशक मंडल को कम से कम छमाही आधार पर प्रस्तुत की जानी चाहिए

7. शेयरों/डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर अन्य ऋणकर्ताओं को अग्रिम

औद्योगिक, कंपनी तथा अन्य ऋणकर्ताओं के लिए शेयरों और डिबेंचरों की प्राथमिक जमानत पर अग्रिम देने का प्रश्न सामान्यतः नहीं उठना चाहिए। परंतु कार्यशील पूंजी अथवा अन्य उत्पादक प्रयोजनों के लिए दिये गये जमानती ऋणों के लिए संपार्श्विक जमानत के रूप में इस तरह की प्रतिभूतियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से इतर ऋणकर्ताओं से स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार के मामलों में बैंक अधिक से अधिक अभौतिक रूप में शेयर स्वीकार करें। बैंक प्रवर्तकों के शेयरों को, जहां अभौतिकीकृत करने की सुविधा उपलब्ध हो, अभौतिक रूप में ही शेयरों को स्वीकार करें।

नयी परियोजना स्थापित करने अथवा मौजूदा कारोबार के विस्तार करने अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छोड़कर अन्य यूनिटों द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त कार्यशील पूंजी जुटाने के प्रयोजन में ऐसी स्थिति हो सकती है जहां इस प्रकार के ऋणकर्ता दीर्घावधि संसाधन जुटाने तक के लिए मार्जिन के लिए अपेक्षित निधियां जुटाने में समर्थ न हों। इस प्रकार के मामलों में मार्जिन के द्वारा शेयरों और डिबेंचरों की संपार्श्विक जमानत प्राप्त करने में बैंकों को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्था अस्थायी स्वरूप की

- the aggregate portfolio, its quality and performance should be reviewed and put up at least on a half-yearly basis to the Board.

7. Advances to other borrowers against shares/debentures/bonds

The question of granting advances against primary security of shares and debentures including promoters shares to industrial, corporate or other borrowers should not normally arise. However, such securities can be accepted as collateral for secured loans granted as working capital or for other productive purposes from borrowers other than NBFCs. In such cases banks may increasingly accept shares in dematerialised form. Banks may accept shares of promoters only in dematerialised form wherever demat facility is available.

In the course of setting up of new projects or expansion of existing business or for the purpose of raising additional working capital required by units other than NBFCs, there may be situations where such borrowers are not able to find the required funds towards margin, pending mobilisation of long term resources. In such cases, there would be no objection to the banks obtaining collateral security of shares and debentures by way of

होगी और एक वर्ष से अधिक समय के लिए जारी नहीं रहेगी। अपेक्षित निधियां जुटाने में और निर्धारित अवधि में अग्रिम की चुकौती करने के संबंध में ऋणकर्ता की क्षमता के संबंध में बैंक संतुष्ट हो लें।

8. प्रवर्तकों के अंशदान की वित्त-व्यवस्था के लिए बैंक ऋण

किसी कंपनी की इक्विटी पूंजी में प्रवर्तकों का अंशदान उनके अपने संसाधनों से आना चाहिए और बैंक सामान्यतः अन्य कंपनियों के शेयर लेने के लिए अग्रिम न दें। परन्तु शेयरों की जमानत पर कंपनियों को ऋण देने के संबंध में बैंकों को अनुमति यथासंभव भौतिक रूप में उनके द्वारा धारित शेयरों की जमानत पर देने की है, जिससे कि नयी कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों का अंशदान पूरा हो सके। यह संसाधन जुटाने के पूर्वानुमान के अधीन होगा तथा अनुबंध में दिये गये सामान्य दिशा-निर्देशों के अलावा निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर होगा:

(i) ऋणों के मार्जिन और चुकौती की अवधि बैंकों द्वारा निर्धारित की जाये।

(ii) प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए कंपनियों को मंजूर किये गये ऋण बैंकों के शेयरों में निवेश माने जाने चाहिए और इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, कंपनियों के

margin. Such arrangements would be of a temporary nature and may not be continued beyond a period of one year. Banks have to satisfy themselves regarding the capacity of the borrower to raise the required funds and to repay the advance within the stipulated period.

8. Bank Loans for Financing Promoters contribution

The promoters' contribution towards the equity capital of a company should come from their own resources and the bank should not normally grant advances to take up shares of other companies. However, banks are permitted to extend loans to corporates against the security of shares (as far as possible in dematerialised form) held by them to meet the promoters' contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources subject to the following terms and conditions, in addition to the general guidelines given in the Annexure :

(i) The margin and period of repayment of the loans may be determined by the banks.

(ii) Loans sanctioned to corporates for meeting promoters' contribution should be treated as banks' investments in shares and would thus

शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा सूचना प्रौद्योगिकी के लिए समन्वित उद्यम पूंजी निधियों की इक्विटी में निवेशों के लिए निर्धारित पिछले वर्ष की वृद्धिशील जमाराशि के 5 प्रतिशत की उच्चतर सीमा के अधीन होगी।

(iii) बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त सुरक्षात्मक उपायों के साथ आंतरिक दिशा-निर्देश बनाये।

(iv) भारतीय निर्यात-आयात बैंक की पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत बैंक विदेशी संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में इक्विटी प्राप्त करने के लिए पात्र भारतीय प्रवर्तकों को गुणदोष के आधार पर आवधिक ऋण मंजूर करें, बशर्ते आवधिक ऋण भारतीय निर्यात आयात बैंक द्वारा पुनर्वित्त के लिए अनुमोदित हों।

9. पारस्परिक निधियों की यूनिटों की जमानत पर अग्रिम

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिट 64 योजना के यूनिटों सहित पारस्परिक निधियों के यूनिटों की जमानत पर अग्रिम देते समय बैंक निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करें:

(i) वे यूनिट शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हों अथवा पारस्परिक निधि के यूनिटों के लिए पुनर्खरीद की सुविधा ऋण देने के समय

come under the ceiling of 5 per cent of the incremental deposits of the previous year prescribed for investments in shares/convertible debentures of PSUs, corporate bodies, units of mutual fund schemes and in equity of dedicated venture capital funds meant for information technology.

(iii) With the approval of the Boards of Directors, the banks should formulate internal guidelines with appropriate safeguards for this purpose.

(iv) Under the refinance scheme of Export-Import Bank of India, the banks may sanction term loans on merits to eligible Indian promoters for acquisition of equity in overseas joint ventures/wholly owned subsidiaries, provided the term loans have been approved by the EXIM Bank for refinance.

9. Advances against Units of mutual funds

While granting advances against Units of mutual funds including Units of UNIT 64 Scheme of UTI, the banks should follow the guidelines given below.

(i) The Units should be listed in the Stock Exchanges or repurchase facility for the Units of mutual fund

उपलब्ध हो।

(ii) यूनितों ने प्रासंगिक योजना में निर्धारित न्यूनतम रुद्धता अवधि (लॉक-इन-पीरियड) पूरी कर ली हो।

(iii) अग्रिमों की राशि शुद्ध आस्ति मूल्य/पुनर्खरीद मूल्य अथवा बाज़ार मूल्य (जो भी कम हो) से सम्बद्ध होनी चाहिए न कि अंकित मूल्य से।

(iv) जहां कहीं निर्धारित हो शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम के लिए यथा लागू मात्रा और मार्जिन की अपेक्षार्ये अग्रिम पर लागू होगी। मार्जिन की गणना शुद्ध आस्ति मूल्य/पुनर्खरीद मूल्य अथवा बाज़ार मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर की जायेगी।

(v) अग्रिम प्रयोजन अभिमुख होने चाहिए, जिनके संबंध में निदेशक की ऋण आवश्यकता का ध्यान रखा जाये। पारस्परिक निधियों की अन्य योजना में अभिदान करने अथवा बिक्री बढ़ाने के लिए अथवा शेयरों/डिबेंचरों/बांडों की खरीद के लिए अग्रिम नहीं दिये जाने चाहिए।

10. शेयरों/डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर अग्रिमों की रिपोर्ट देना

बैंक शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर दिये गये अग्रिमों के ब्यौरे प्रत्येक तिमाही अर्थात् मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर के अंत की स्थिति बताते हुए संलग्न फार्मेट में प्रस्तुत करें। ये विवरणियां भारतीय रिज़र्व बैंक

should be available at the time of lending.

(ii) The Units should have completed the minimum lock-in-period stipulated in the relevant scheme.

(iii) The amount of advances should be linked to the Net Asset Value (NAV)/repurchase price or the market value, whichever is less and not to the face value.

(iv) The advance would attract the quantum and margin requirements as applicable to advance against shares and debentures wherever stipulated. The margin should be calculated on the NAV/repurchase price or market value, whichever is less.

(v) The advances should be purpose-oriented, taking into account the credit requirement of the investor. Advances should not be granted for subscribing to or boosting up the sales of another scheme of the mutual funds or for the purchase of shares/debentures/bonds.

10. **Reporting of advances against shares/debentures/bonds**

Banks should submit in the enclosed Format details of advances granted by them against shares and debentures as on the last Reporting Friday of each Quarter viz. March, June, September and December. The Returns should

(बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय) के पास संबंधित तिमाही के अगले महीने की 15 तारीख तक अवश्य पहुंच जायें।

अनुबंध

शेयरों/डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर अग्रिमों पर लागू सामान्य दिशा-निर्देश

- (i) शेयरों की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) और (3) और 20(1)(क) में दिये गये सामान्य उपबंधों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उपर्युक्त धारा 19(2) और 19(3) के अंतर्गत सीमायें निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु अभौतिकीकृत रूप में धारित शेयरों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- (ii) किस चीज़ की जमानत पर अग्रिम दिये जा रहे हैं, इसकी अपेक्षा बैंकों को इस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए कि अग्रिम किस प्रयोजन के लिए हैं। शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम देने पर विचार करते समय बैंकों को स्वीकृति, मूल्यांकन और मंजूरी के बाद की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सामान्य क्रियाविधि का पालन आवश्यक करना चाहिए।
- (iii) शेयरों/डिबेंचरों/बांडों की प्राथमिक जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिमों को अलग और भिन्न रूप में रखा जाना चाहिए तथा उन्हें अन्य अग्रिम के साथ नहीं जोड़ना चाहिए।

reach the Reserve Bank of India (DBOD, Central Office) not later than the 15th of the succeeding month of the Quarter to which it relates.

Annexure

General guidelines applicable to advances against shares/debentures/bonds

- (i) Statutory provisions regarding the grant of advances against shares contained in Sections 19(2) and (3) and 20(1) (a) of the Banking Regulation Act 1949 should be strictly observed. Shares held in dematerialised form should also be included for the purpose of determining the limits under Section 19(2) and 19(3) *ibid*.
- (ii) Banks should be concerned with what the advances are for, rather than what the advances are against. While considering grant of advances against shares/debentures banks must follow the normal procedures for the sanction, appraisal and post sanction follow-up.
- (iii) Advances against the primary security of shares/debentures/bonds should be kept distinct and separate and not combined with any other advance.

- (iv) जिस कंपनी के शेयरों/डिबेंचरो/बांडों को जमानत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है उसके शेयरों और डिबेंचरों की विवरण संबंधी क्षमता और उस कंपनी की शुद्ध मूल्यवत्ता और कार्य के बारे में बैंक स्वयं संतुष्ट हो लें।
- (v) अग्रिम की जमानत के रूप में जब शेयर/डिबेंचर/बांड रखे जायें तो उनका मूल्यन प्रचलित बाज़ार मूल्य पर किया जाना चाहिए।
- (vi) जब किसी ऋणकर्ता अथवा ऋणकर्ताओं के समूह द्वारा शेयरों के बड़े ब्लॉक की जमानत पर अग्रिम मांगे जायें तो बैंकों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शेयरों की जमानत पर दिये गये अग्रिमों का उपयोग किसी कंपनी/कंपनियों में नियंत्रणकारी हित प्राप्त करने अथवा उसे बनाये रखने के लिए अथवा अंतर कंपनी निवेशों को सुविधाजनक बनाने या बनाये रखने के लिए न किया जाये।
- (vii) अंशतः प्रदत्त शेयरों की जमानत पर अग्रिम नहीं दिये जाने चाहिए। जब किसी ऋणकर्ता को दिये गये अग्रिमों की सीमा/सीमायें 10 लाख रुपये से अधिक हो जायें तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उक्त शेयर/डिबेंचर/बांड बैंक के नाम में अंतरित कर दिये जायें और यह कि बैंक को इस प्रकार के शेयरों के संबंध में एकमात्र और बिनाशर्त मतदान का अधिकार है। इस प्रयोजन के लिए शेयरों/डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर बैंक के सभी कार्यालयों द्वारा किसी एकल ऋणकर्ता को दी गयी कुल सीमायें हिसाब में ली जानी चाहिए। जब
- (iv) Banks should satisfy themselves about the marketability of the shares/debentures and the networth and working of the company whose shares/debentures/bonds are offered as security.
- (v) Shares/debentures/bonds should be valued at prevailing market prices when they are lodged as security for advances.
- (vi) Banks should exercise particular care when advances are sought against large blocks of shares by a borrower or a group of borrowers. It should be ensured that advances against shares are not used to enable the borrower to acquire or retain a controlling interest in the company/companies or to facilitate or retain inter-corporate investments.
- (vii) No advance against partly paid shares shall be granted. Whenever the limit/limits of advances granted to a borrower exceeds Rs. 10 lakhs, it should be ensured that the said shares/debentures/bonds are transferred in the bank's name and that the bank has exclusive and unconditional voting rights in respect of such shares. For this purpose the aggregate of limits against shares/debentures/bonds granted by a bank at all its offices to a single borrower should be taken into

प्रतिभूतियां अभौतिक रूप में रखी जायें तो यह अपेक्षित है कि बैंक के नाम में शेयर अंतरित करने की अपेक्षा लागू नहीं होगी और बैंक इस संबंध में अपना स्वयं का निर्णय ले सकते हैं। परन्तु बैंक अभौतिक रूप में रखी गयी धारित प्रतिभूतियों को रिगवी रखने के लिए डिपोजिटरी प्रणाली में दी गयी सुविधा का लाभ उठायें, जिसके अंतर्गत ऋणकर्ता द्वारा गिरवी रखी गयी प्रतिभूतियां ऋण देनेवाले बैंक के पक्ष में ब्लॉक हो जाती हैं। ऋणकर्ता द्वारा चूक करने के मामले में और बैंक द्वारा गिरवी लागू करने के विकल्प का प्रयोग करने के मामले में शेयर और डिबेंचर बैंक के नाम तुरंत अंतरित हो जाने चाहिए।

account. Where securities are held in dematerialised form, the requirement relating to transfer of shares in bank's name will not apply and banks may take their own decision in this regard. Banks should however avail of the facility provided in the depository system for pledging securities held in dematerialised form under which the securities pledged by the borrower get blocked in favour of the lending bank. In case of default by the borrower and on the bank exercising the option of invocation of pledge, the shares and debentures get transferred in the bank's name immediately.

(viii) मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के संबंध में बैंक अपना निर्णय ले सकते हैं और इस प्रयोजन के लिए क्रियाविधि निर्धारित कर सकते हैं।

(viii) Banks may take their own decision in regard to exercise of voting rights and may prescribe procedures for this purpose.

(ix) बैंक इस बात से सुनिश्चित हो लें कि गिरवी रखी गयी स्क्रिप, चुराये हुए/डुप्लीकेट/जाली/बेनामी नहीं हैं। यदि उन्हें किसी अनियमितता की जानकारी मिले तो वे उसकी सूचना रिज़र्व बैंक को तत्काल दें।

(ix) Banks should ensure that the scrips lodged with them as security are not stolen/duplicate/fake/benami. Any irregularities coming to their notice should be immediately reported to RBI.

(x) निदेशक मंडल शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम मंजूर करने के लिए प्राधिकारी के उचित स्तर का निर्णय करें। वे इस प्रकार के अग्रिम देने के लिए आंतरिक दिशा-निर्देश और सुरक्षा संबंधी उपाय भी तय करें।

(x) The Boards of Directors may decide the appropriate level of authority for sanction of advances against shares/debentures. They may also frame internal guidelines and safeguards for grant of such advances.

- (xi) भारत में कार्यरत बैंकों को इस प्रकार के लेनदेन का पक्ष नहीं बनना चाहिए, जैसे कि अन्य बैंकों के पक्ष में समर्थन गारंटी जारी करना अथवा अग्रिम देना, जो भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के ग्राहकों को ऋण देने के लिए किसी अन्य विदेशी शाखा द्वारा दिये जा रहे हैं, जिससे कि ऋणकर्ता भारतीय कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों/बांडों में निवेश कर सकें।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

- (i) “शेयरों” का अभिप्राय शेयर से है और इसमें हर तरह के शेयर और स्टॉक शामिल हैं।
- (ii) “डिबेंचर” का अभिप्राय वही है जो कंपनी अधिनियम, 1956 में परिभाषित है।
- (iii) “शेयर दलाल” से अभिप्राय ऐसे शेयर दलाल से है जो सेबी में पंजीकृत है और मान्यप्राप्त शेयर बाज़ार का सदस्य है।
- (iv) “अग्रिमों” में हर तरह के नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट, ऋण और अग्रिम शामिल हैं।
- (v) “शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिमों” में शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर सभी प्रकार के अग्रिम शामिल हैं, चाहे वे मूल जमानत द्वारा हों अथवा संपार्श्विक जमानत द्वारा।

- (xi) Banks operating in India should not be a party to transactions such as making advances or issuing back-up guarantees favouring other banks for extending credit to clients of Indian nationality/origin by some of their overseas branches, to enable the borrowers to make investments in shares and debentures/bonds of Indian companies.

Explanatory notes

- (i) "Shares" mean and include shares and stocks of every description.
- (ii) "Debenture" means the same as defined in the Companies Act, 1956.
- (iii) "Share broker" means a share broker who is registered with SEBI and is a member of a recognised stock exchange.
- (iv) "Advances" include cash credit, overdraft, loans and advances of every description.
- (v) "Advances against security of shares/debentures", include all types of advances against shares/debentures whether by way of principal security or collateral security.

फार्मेट (संदर्भ: पैरा 10)

शेयरों, डिबेचरों और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के बांडों की जमानत/संपार्श्विक जमानत पर 1 लाख रुपये और उससे अधिक की कुल ऋण सीमाओं और उनमें बकाया का विवरण-
मार्च/जून/सितंबर/दिसंबर-- के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति

बैंक का नाम:

(राशि लाख रुपये)

क	ख	ग	घ	ड
ऋणकर्ता की श्रेणी	मंजूर की गयी कुल सीमाएं	कुल बकाया	'ग' में से वे अग्रिम जो शेयरों, डिबेचरों और सरकारी क्षेत्र के बांडों में आगे निवेश करने के लिए दिये गये	अन्य प्रयोजन
	पार्टियों की सं.	राशि	पार्टियों की सं.	राशि
	पार्टियों की सं.	राशि	पार्टियों की सं.	राशि

- क) व्यक्ति
ख) निवेश फार्म/कंपनी
ग) शेयर और स्टॉक
दलाल
घ) न्यास और इंडॉमेंट
ड) औद्योगिक और
व्यापारिक प्रतिष्ठान
च) अन्य
जोड़

- टिप्पणी : 1. केवल 1 लाख रुपये और उससे अधिक की सीमाओं के संबंध में बकाया राशि की ही जानकारी दी जाये।
2. ये सीमाएं ऋण, ओवरड्राफ्ट नकदी ऋण आदि के रूप में हो सकती हैं।
3. आंकड़े महने के अंतिम शुक्रवार से संबंधित होने चाहिए।
4. स्तंभ (घ) और (ड) का जोड़ (ग) के बराबर होना चाहिए।
5. 'व्यक्ति' में एक से अधिक व्यक्तियों को उनके नाम से दिये गये अग्रिम शामिल होंगे।
6. 'औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों' में वे स्वामित्व/भागीदारी फर्म और निजी/सार्वजनिक सीमित कंपनियां शामिल होंगी, जो व्यापार अथवा उद्योग चलाती हैं।

Format (vide Para 10)

Statement of Aggregate Credit Limits of Rs. 1 lakh and above against the security/collateral of shares, debentures and public sector bonds and outstandings thereagainst as on the last Reporting Friday of March/June/September/December

Name of the Bank :

(Amount in lakhs of rupees)

A Category of borrowers	B Aggregate limits sanctioned		C Total outstanding		D Of 'C' Advances extended for further investments in shares, debentures and public sector bonds		E Other purposes	
	No. of parties	Amount	No. of parties	Amount	No. of parties	Amount	No. of parties	Amount

- a) Individuals
- b) Investment firms/
companies
- c) Share and stock
brokers
- d) Trusts and
endowments
- e) Industrial and
trading concerns
- f) Others
- Total :

- Note:
1. Only outstandings in respect of limits of Rs. 1 lakh and above need be furnished.
 2. The limits may be by way of loan, overdraft, cash credit etc.
 3. Figures should relate to the last Friday of the month.
 4. Total of columns (D) and (E) should tally with (C).
 5. 'Individual' will include advances to more than one person in their own names.
 6. 'Industrial and Trading concerns' will include proprietorship/partnership firms and private/public limited companies engaged in trade or industry.

12 नवंबर 1998
21 कार्तिक 1920 (शक)

November 12, 1998
Kartika 21, 1920 (Saka)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक, सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

Chairmen/Chief Executives of all
Commercial Banks (excluding Regional
Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

भारत स्थित बैंकों द्वारा विदेश स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं को ऋण/ऋण से इतर सुविधाएं तथा विदेश स्थित पार्टियों को क्रेता का ऋण और स्वीकृति वित्त की सुविधाएं प्रदान करना

EXTENSION OF CREDIT/NON-CREDIT FACILITIES TO INDIAN JOINT VENTURES/WHOLLY OWNED SUBSIDIARIES ABROAD AND EXTENSION OF BUYER'S CREDIT AND ACCEPTANCE FINANCE TO OVERSEAS PARTIES BY BANKS IN INDIA

बैंकों को विदेश स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं को ऋण/ऋण से इतर सुविधाएं (अर्थात् साखपात्र और गारंटी) प्रदान करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। बैंकों को अपने विवेक पर, भारत से माल और सेवाओं के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेश स्थित पार्टियों को क्रेता का ऋण/स्वीकृति वित्त प्रदान करने की भी अनुमति दी गयी है। तथापि उक्त ऋण सुविधाएं अहासित स्तर-I पूंजी के 5% की सीमा के अधीन होंगी। उच्चतर सीमाओं के संबंध में रिज़र्व बैंक गुणवत्ता के आधार पर विचार कर सकता है। ऐसी सुविधाएं प्रदान करते समय बैंकों को निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करना चाहिए:

It has been decided to allow banks to extend credit/non-credit facilities (viz. letters of credit and guarantees) to Indian Joint Ventures/Wholly Owned Subsidiaries abroad. Banks are also permitted to provide at their discretion, buyer's credit/acceptance finance to overseas parties for facilitating export of goods and services from India. The above exposures will, however be subject to a limit of 5% of the unimpaired Tier-1 capital. Higher limits could be considered by Reserve Bank on merits. While extending such facilities banks should comply with the following conditions :

(i) ऋण सिर्फ उन संयुक्त उद्यमों को स्वीकृत

(i) Loans will be granted to only those

किये जायेंगे जिनमें भारतीय कंपनी की हिस्सेदारी 51% से अधिक है।

joint ventures where the holding by the Indian company is more than 51%.

(ii) ऐसे अंतरदेशीय उधार से उत्पन्न ऋण और ब्याज दर जोखिमों के प्रबंधन के लिए उचित प्रणाली लागू हो।

(ii) Proper systems for management of credit and interest rate risks arising out of such cross border lending are in place.

(iii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 25 का अनुपालन किया गया हो।

(iii) Section 25 of the B.R. Act, 1949 is complied with.

(iv) विदेशी मुद्रा खातों यथा एफसीएनआर (बी), ईईएफसी, आरएफसी आदि में रखी निधियों का, जिनके संबंध में बैंकों को विनियम जोखिम का प्रबंधन करना पड़ता है, उपयोग इस तरह की उधार राशियों के लिए संसाधन आधार के रूप में किया जाना चाहिए।

(iv) The resource base for such lendings should be funds held in foreign currency accounts such as, FCNR(B), EEFC, RFC etc. in respect of which banks have to manage the exchange risk.

(v) इस तरह के लेनदेनों से उत्पन्न अवधिपूर्णता संबंधी बेमेल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित समग्र अंतराल सीमाओं के भीतर हों तथा

(v) Maturity mismatches arising out of such transactions are within the overall gap limits approved by RBI and

(vi) देशी ऋण/ऋण से इतर सुविधाओं पर लागू पूंजी पर्याप्तता, ऋण सुविधा संबंधी मानदंड आदि के संबंध में सभी मौजूदा सुरक्षा उपायों/विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया हो।

(vi) All existing safeguards/prudential guidelines relating to capital adequacy, exposure norms etc. applicable to domestic credit/non-credit exposures are adhered to.

2. निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए ऐसी ऋण/ऋण से इतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक उचित ऋण नीति तैयार करनी चाहिए:

2. The banks should, with the approval of the Board, frame a proper loan policy for extending such credit/non-credit facilities, keeping in view, inter alia, the following :

(क) ऐसे ऋणों की स्वीकृति परियोजनाओं के

(a) Grant of such loans are based on

उचित मूल्यांकन और उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर आधारित हो, न कि परियोजनाओं को समर्थन देनेवाले प्रवर्तकों की प्रतिष्ठा मात्र पर। गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्रदान करने के लिए निधि आधारित सीमाओं जैसी ही सख्त जांच की जानी चाहिए।

(ख) जिन देशों में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाएं स्थित हों, वहां विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त करने अथवा पुनः प्रत्यावर्तन आदि के संबंध में इन कंपनियों पर कोई प्रतिबंध लागू न हों तथा अनिवासी बैंकों को विदेश में प्रतिभूतियों/आस्तियों पर विधिक प्रभार प्राप्त करने की अनुमति तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका निपटान करने का अधिकार होना चाहिए।

3. इस परिपत्र के अनुसार प्रदान की गयी ऋण/ऋण से इतर सुविधाओं के संबंध में 31 मार्च और 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार छमाही समीक्षा रिपोर्ट निदेशक मंडलों के समक्ष प्रस्तुत की जाये। रिपोर्ट की एक प्रति सूचना के लिए हमें प्रेषित की जाये।

भवदीया

(देवकी मुत्तुकृष्णन)
महा प्रबंधक

proper appraisal and commercial viability of the projects and not merely on the reputation of the promoters backing the projects. Extension of non-fund based facilities should be subjected to the same rigorous scrutiny as fund based limits.

(b) The countries where the joint ventures/wholly owned subsidiaries are located should have no restrictions applicable to these companies in regard to obtaining foreign currency loans or for repatriation etc. and should permit non-resident banks to have legal charge on securities/assets abroad and the right of disposal in case of need.

3. A half-yearly Review Report as at 31st March and 30th September of credit/non-credit facilities extended as per this circular may be put up to the Board of Directors. A copy of the Report may be forwarded to us for our information.

Yours faithfully

(Devaki Muthukrishnan)
General Manager

9 दिसम्बर 1998
18 अग्रहाण्य 1920 (शक)

December 9, 1998
Agrahayana 18, 1920 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

संपार्श्विक जमानत के रूप में धारित
प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण

DEMATERIALISATION OF
SECURITIES HELD AS
COLLATERALS

कृपया आप 9 दिसम्बर 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 153/13.07.05/97 देखें, जिसमें सूचित किया गया था कि बैंक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अधिसूचित 8 प्रतिभूतियों के लेनदेनों का निपटान केवल डिपोजिटरी के माध्यम से करें। सेबी ने अब घोषणा की है कि संलग्न सूची (अनुबंध I) के अनुसार 12 प्रतिभूतियों का व्यापार 4 जनवरी 1999 से सभी प्रमुख शेयर बाजारों में केवल अभौतिक रूप में करना अधिदेशात्मक है। इसके अतिरिक्त 15 फरवरी 1999 से और 19 प्रतिभूतियां भी अनिवार्य अभौतिकीकृत सूची में शामिल की जायेंगी (अनुबंध II)। अभौतिकीकृत रूप में अधिदेशात्मक व्यापार प्रारंभ होने के बाद बैंकों के पास यदि अनुबंध I और II में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर भौतिक रूप में होंगे तो वे उन्हें बेच नहीं सकेंगे।

Please refer to our circular DBOD. Dir. BC.153/13.07.05/97 dated December 9, 1997 wherein it was advised that banks may settle transactions in the eight securities as notified by Securities Exchange Board of India (SEBI) only through depository. SEBI has now announced, commencing from January 4, 1999 mandatory trading by all of 12 securities in only demat form on major stock exchanges as per list enclosed (Annexure I). Further, commencing from February 15, 1999, another 19 securities will be included in the compulsory demat list (Annexure II). After the commencement of mandatory trading in demat form, the banks will not be able to sell the shares of the companies listed in Annexure I and II if held in physical form.

हो सकता है कि कुछ बैंकों ने उक्त अनुबंधों में सूचीबद्ध कंपनियों के भौतिक शेयरों की जमानत पर अपने ग्राहकों को अग्रिम दिये हों। इस प्रकार के

It is possible that some banks would have given advances to their clients against physical shares of companies listed in the

कर्जदार यदि चुकौती करने में चूक करें तो बैंक उन शेयरों को बेच नहीं सकेंगे और संपार्श्विक जमानत का मूल्य शून्य हो जायेगा। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अभौतिकीकृत रूप में अनिवार्य व्यापार के संबंध में सेबी द्वारा घोषित तारीखों से काफी पहले ऐसे शेयरों को अभौतिकीकृत करवाने के लिए तत्काल कदम उठायें।

2. बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे अन्य स्क्रिप्स में अभौतिकीकृत रूप में अधिदेशात्मक व्यापार की सेबी की घोषणाओं पर भी ध्यान दें, ताकि जमानत की सुरक्षा के लिए पहले से आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

भवदीय

(राधे श्याम)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

Annexures. In the event of such borrowers defaulting on the repayment, the banks will not be able to sell them and the collaterals may turn to be of nil value. Banks are therefore, advised to take immediate steps to get them dematerialised well before the dates announced by SEBI regarding compulsory trading in demat form.

2. Banks are also advised to watch for any SEBI announcements mandating trade in demat form in other scrips also, so that necessary actions are taken for safeguarding the security well in advance.

Yours faithfully

(Radhe Shyam)

Additional Chief General Manager

अनुबंध I

Annexure I

4 जनवरी 1999 से सभी के द्वारा अनिवार्यतः
अभौतिक रूप में व्यापार करने के लिए सेबी की
अधिदेशात्मक सूची

SEBI mandated list of securities for
compulsory trading by all from
January 4, 1999

1. बैंक ऑफ इंडिया (बीओआइ)	1. Bank of India (BOI)
2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल)	2. Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL)
3. बीएसइएस लि.	3. BSES Ltd.
4. हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (एचडीएफसी)	4. Housing Development Finance Corporation Ltd. (HDFC)
5. आइसीआइसीआइ लि.	5. ICICI Ltd.
6. इंडसइंड बैंक लि.	6. IndusInd Bank Ltd.
7. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आइडीबीआई)	7. Industrial Development Bank of India (IDBI)
8. इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लि.	8. Infosys Technologies Ltd.
9. लार्सन एंड टूब्रो (एल एंड टी)	9. Larsen and Toubro (L&T)
10. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)	10. State Bank of India (SBI)
11. विदेश संचार निगम लि. (वीएसएनएल)	11. Videsh Sanchar Nigam Ltd. (VSNL)
12. विप्रो लि.	12. Wipro Ltd.

अनुसंघ II

**15 फरवरी 1999 से सभी के द्वारा अनिवार्यतः
अभौतिक रूप में व्यापार करने के लिए सेबी की
अधिदेशात्मक सूची**

1. एसिया ब्राउन बोवेरी लि. (एबीबी)
2. एसियन पेंट्स लि.
3. एसेसिएटेड सीमेंट कंपनी लि. (एसीसी)
4. बजाज ऑटो लि.
5. बिड़ला ग्लोबल फाइनेंस लि. (बीजीएफएल)
6. कैस्ट्रोल इंडिया लि.
7. कोचिन रिफाइनरीज लि.
8. डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज लि.
9. गैस अथोरिटी ऑफ इंडिया लि.
(जीएआइएल)
10. गुजरात अंबुजा सीमेंट लि.
11. हीरो होंडा मोटर्स लि.
12. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
(एचपीसीएल)
13. मद्रास रिफाइनरीज लि. (एमआरएल)
14. महिंद्रा एंड महिंद्रा लि. (एम एंड एम)
15. एनआइआईटी लि.
16. रानबेक्सी लेबोरेटरीज लि.
17. टाटा टी लि.
18. थर्मैक्स लि.
19. टीवीएस सुजुकी लि.

Annexure II

**SEBI mandated list of securities for
compulsory trading by all from
February 15, 1999**

1. Asea Brown Boveri Ltd. (ABB)
2. Asian Paints Ltd.
3. Associated Cement Company Ltd.
(ACC)
4. Bajaj Auto Ltd.
5. Birla Global Finance Ltd. (BGFL)
6. Castrol India Ltd.
7. Cochin Refineries Ltd.
8. Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
9. Gas Authority of India Ltd.
(GAIL)
10. Gujarat Ambuja Cements Ltd.
11. Hero Honda Motors Ltd.
12. Hindustan Petroleum Corporation
Ltd. (HPCL)
13. Madras Refineries Ltd. (MRL)
14. Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M)
15. NIIT Ltd.
16. Ranbaxy Laboratories Ltd.
17. Tata Tea Ltd.
18. Thermax Ltd.
19. TVS Suzuki Ltd.

भाग VI
ऋण नियंत्रण (सामान्य)

SECTION VI
CREDIT CONTROL (GENERAL)

16 जनवरी 1998
26 पौष 1919 (शक)

January 16, 1998
Pausha 26, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी
निधि अनुपात (सी आर आर) में वृद्धि

SECTION 42(1) OF THE RESERVE
BANK OF INDIA ACT, 1934 -
INCREASE IN CASH RESERVE
RATIO (CRR)

कृपया आप उप गवर्नर महोदय का 16 जनवरी 1998 का परिपत्र सं. एमपीडी. बीसी. 171/07.01.279/97-98 देखें। वर्तमान मौद्रिक और विदेशी मुद्रा स्थिति और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहले ही किये गये उपायों तथा हाल की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों की समीक्षा करने पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) रखने से संबंधित निर्धारणों में निम्नलिखित परिवर्तन किये जा रहे हैं:

Please refer to Deputy Governor's Circular No. MPD/BC/171/07.01.279/97-98 dated January 16, 1998. On a review of the current monetary and foreign exchange situation, the measures already taken by the Reserve Bank of India in this regard and the recent international developments, following change is effected in the prescription relating to maintenance of CRR :

2. प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि : यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रखे जाने वाले 10.00 प्रतिशत के प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को आधा प्रतिशत बढ़ाकर 17 जनवरी 1998 से प्रारंभ पखवाड़े से 10.50 प्रतिशत कर दिया जाये।

2. Increase in Cash Reserve Ratio (CRR) :

It has been decided to increase the Cash Reserve Ratio (CRR) to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) by one half of one percentage point from 10.00 per cent to 10.50 per cent with effect from the fortnight beginning January 17, 1998.

3. यह उल्लेख किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए)

3. It may be mentioned that all other prescriptions regarding maintenance of

के अंतर्गत रखे जाने वाले प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात से संबंधित अन्य सभी निर्धारण जारी रहेंगे।

4. 16 जनवरी 1998 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं.4/12.01.001/97-98 की प्रति संलग्न है।

5. हम इस बात का पुनः उल्लेख करना चाहते हैं कि कुछ देयताओं पर शून्य प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के निर्धारण सहित, जैसा कि विधि के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, विभिन्न श्रेणी की देयताओं पर विविध निर्धारणों को देखते हुए कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखा जाने वाला प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 03 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

भवदीय

(डी.वी. झवेरी)
महा प्रबंधक

बैंपविवि सं.बी.सी. 4/12.01.001/97-98

16 जनवरी 1998
26 पौष 1919 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 02

incremental Cash Reserve Ratio under Section 42(1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934 would continue.

4. A copy of the relative notification DBOD. No. BC. 4/12.01.001/97-98 dated January 16, 1998 is enclosed.

5. We may reiterate that in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities, including zero prescription of CRR on certain liabilities, as stipulated under the law, effective CRR maintained by Scheduled Commercial Banks on total Net Demand and Time Liabilities should not be less than 3 per cent.

Yours faithfully

(D.V. Jhaveri)
General Manager

DBOD.No.BC. 4/12.01.001/97-98

January 16, 1998
Pausha 26, 1919 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Proviso to Sub-section (1) of Section 42 of the RBI Act, 1934 (2 of 1934) and in

दिसम्बर 1997 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 147/12.01.001/97-98 का प्रतिस्थापन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) रखा जाने वाला औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 17 जनवरी 1998 से आरंभ पखवाड़े से 10.5 प्रतिशत होगा।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. बीसी. 6/12.02.001/97-98

16 जनवरी 1998
26 पौष 1919 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात (सीआरआर/एसएलआर) बनाये रखने में कमियां होने पर दंड ब्याज दर

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 21 अक्टूबर 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 136/12.02.001/97-98 देखें।

2. इस संबंध में, हम आपका ध्यान अपने उप गवर्नर के 16 जनवरी 1998 के परिपत्र सं.

supersession of its Notification No. DBOD. BC. 147/12.01.001/97-98 dated December 02, 1997 the Reserve Bank of India hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) shall be 10.50 per cent with effect from the fortnight beginning January 17, 1998

(S. Gurumurthy)
Executive Director

DBOD.No.BC. 6/12.02.001/97-98

January 16, 1998
Pausha 26, 1919 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

**PENAL RATE OF INTEREST ON THE
SHORTFALL IN THE MAINTENANCE
OF CRR/SLR**

Please refer to our circular DBOD. No. BC. 136/12.02.001/97-98 dated 21st October 1997 on the captioned subject.

2. In this connection, we invite your attention to paragraph 1(a) of our Deputy

एमपीडी. बीसी. 171/07.01.279/97-98 के पैराग्राफ 1(क) की ओर आकर्षित करते हैं जिसके अनुसार आज (16 जनवरी 1998) कारोबार समाप्ति पर बैंक दर दो प्रतिशत अंक बढ़ा कर 9 प्रतिशत वार्षिक से 11 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी है। इसके फलस्वरूप, नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाये रखने में कम रहने वाली राशि पर वसूल की जाने वाली दंड ब्याज दर जो बैंक दर से संबद्ध है 16 जनवरी 1998 को कारोबार समाप्ति पर संशोधित हो गयी है।

भवदीय

(डी.वी. झवेरी)

महा प्रबंधक

Governor's Circular No. MPD. BC. 171/07.01.279/97-98 dated January 16, 1998 in terms of which the Bank Rate has been increased by two percentage points, i.e., from the present level of '9.00 per cent per annum' to '11.00 per cent per annum' with effect from the close of business to-day (January 16, 1998). Consequently, the penal rate of interest charged on the amount of shortfalls in the maintenance of Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR) which is linked to Bank Rate stands revised from the close of business on January 16, 1998.

Yours faithfully,

(D.V. Jhaveri)

General Manager

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.13/21.01.023/98

DBOD.No.BP.BC. 13/21.01.023/98

12 फरवरी 1998
23 माघ 1919 (शक)

February 12, 1998
Magha 23, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

चल आस्तियां रखने के लिए गैर-बैंकिंग
वित्तीय कंपनियों की प्रतिभूतियों की
नामित बैंकों के पास अभिरक्षा

**CUSTODY OF SECURITIES OF
NBFCs WITH DESIGNATED BANKS
TOWARDS MAINTENANCE OF
LIQUID ASSETS**

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 9 सितम्बर 1997 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 103/21.01.023/97 का पैरा 2 देखें। यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 451 बी के अधीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक की शाखा की अभिरक्षा में रखी जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों/गारंटी बांडों का मूल्यन ऐसी प्रतिभूतियों के चालू बाजार मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। किन्तु यदि ऐसी प्रतिभूतियों के बाजार भाव (कोटेशन) उपलब्ध न हों (अर्थात् प्रतिभूतियां कोट न की गई हों) तो इनका मूल्यन कारोबारी (कैरिंग) लागत पर किया जाना चाहिए।

Please refer to para 2 of our circular DBOD. No. BP.BC. 103/21.01.023/97 dated September 9, 1997 on the above subject. It is clarified that the Government securities/ guaranteed bonds required to be held by NBFCs under Section 45IB of the Reserve Bank of India Act, 1934 in the custody of a branch of a scheduled commercial bank should be valued at a price not exceeding the current market price of such securities. If, however, market quotations for such securities are not available (i.e. securities are not quoted), these securities should be valued at their carrying cost.

भवदीया

Yours faithfully

(श्रीमती चित्रा चन्द्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी.20/12.02.001/97-98

18 मार्च 1998
27 फाल्गुन 1919 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात (सीआरआर/एसएलआर) बनाये रखने में कमी होने पर दंड स्वरूप ब्याज दर

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 16 जनवरी 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 6/12.02.001/97-98 देखें।

2. इस संबंध में, हम आपका ध्यान अपने उप गवर्नर के 18 मार्च 1998 के परिपत्र सं. एम्पीडी. बीसी. 172/07.01.279/97-98 की ओर आकर्षित करते हैं जिसके अनुसार आज (18 मार्च 1998) कारोबार समाप्ति पर बैंक दर आधा प्रतिशत अंक कम कर 11 प्रतिशत वार्षिक से 10.5 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी है। इसके फलस्वरूप, नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाये रखने में कम रहने वाली राशि पर वसूल की जाने वाली दंड स्वरूप ब्याज दर, जो बैंक दर से संबद्ध है, 18 मार्च 1998 को कारोबार समाप्ति पर संशोधित हो गयी है।

भवदीय

(डी.वी. झवेरी)
महा प्रबंधक

DBOD.No. Dir.BC.20/12.02.001/97-98

March 18, 1998
Phalgun 27, 1919 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

**PENAL RATE OF INTEREST ON THE
SHORTFALL IN THE MAINTENANCE
OF CRR/SLR**

Please refer to our circular DBOD No. BC. 6/12.02.001/97-98 dated 16th January 1998 on the captioned subject.

2. In this connection, we invite your attention to Deputy Governor's circular No. MPD. BC. 172/07.01.279/97-98 dated 18th March 1998 in terms of which the Bank Rate has been reduced by one half of one percentage point i.e. from "11.00 percent per annum" to "10.5 percent per annum" with effect from the close of business today (18th March 1998). Consequently, the penal rate of interest charged on the amount of shortfalls in the maintenance of Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR) which is linked to Bank Rate stands revised from the close of business on 18th March 1998.

Yours faithfully

(D.V. Jhaveri)
General Manager

23 मार्च 1998

2 चैत्र 1920 (शक)

March 23, 1998

Chaitra 2, 1920 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि
अनुपात में कटौती

SECTION 42(1) OF THE RESERVE
BANK OF INDIA ACT, 1934 -
REDUCTION IN CASH RESERVE
RATIO (CRR)

कृपया उक्त विषय पर 23 मार्च 1998 का गवर्नर का परिपत्र सं. एमपीडी/बीसी/173/07.01.279/97-98 देखें। वर्तमान में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से अपेक्षित है कि वे अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं (शून्य सीआरआर संबंधी निर्धारणों के अधीन आने वाली देयताओं को छोड़कर) का 10.50 प्रतिशत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखें। अब यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रखे जाने वाले सीआरआर में निम्नानुसार 0.25 प्रतिशत अंक के दो चरणों में आधा प्रतिशत अंक

Please refer to Governor's Circular No. MPD/BC/173/07.01.279/97-98 dated March 23, 1998 on the above subject. At present, under Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 all the Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) are required to maintain with Reserve Bank of India a Cash Reserve Ratio (CRR) of 10.50 per cent of their net demand and time liabilities (excluding liabilities subject to zero CRR prescriptions). It has now been decided to reduce the CRR to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) by

की कमी करके उसे 10.5 प्रतिशत से 10.00 प्रतिशत कर दिया जाए :

प्रभावी तारीख (अर्थात् निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ पखवाड़ा)	शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत)
28 मार्च 1998	10.25
11 अप्रैल 1998	10.00

2. यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के रख रखाव संबंधी अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् बनी रहेंगी।

3. दिनांक 23 मार्च 1998 की संबंधित अधिसूचना बैंपवि. सं. बीसी. 21/12.01.001/97-98 की एक प्रति संलग्न है।

4. यह बात दुहरायी जाती है कि विधि के अंतर्गत किये गये प्रावधानों के अनुसार कुछ देयताओं पर शून्य सीआरआर के निर्धारण सहित विभिन्न श्रेणी की देयताओं पर किये गये अलग-अलग निर्धारणों को ध्यान में रखते हुए कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखा गया प्रभावी सीआरआर 3 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

भवदीय

(डी.वी. झवेरी)
महा प्रबंधक

one half of one percentage point from 10.50 percent to 10.00 per cent in two phases of 0.25 percentage point each as set out below :

Effective Date (i.e. fortnight beginning from)	CRR on net demand and time liabilities (per cent)
March 28, 1998	10.25
April 11, 1998	10.00

2. It may be mentioned that all other prescriptions regarding maintenance of incremental Cash Reserve Ratio under Section 42 (1A) of Reserve Bank of India Act, 1934, would continue.

3. A copy of the relative notification DBOD. No. BC. 21/12.01.001/97-98 dated March 23, 1998 is enclosed.

4. It may be reiterated that in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities including a prescription of a zero CRR on some liabilities, as stipulated under the law, effective CRR maintained by Scheduled Commercial Banks on total net demand and time liabilities should not be less than 3 per cent.

Yours faithfully

(D.V. Jhaveri)
General Manager

23 मार्च 1998
2 चैत्र 1920 (शक)

March 23, 1998
Chaitra 2, 1920 (Saka)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 16 जनवरी 1998 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 4/12.01.001/97-98 का प्रतिस्थापन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) रखा जाने वाला औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात नीचे लिखी गयी तारीखों से उनके सामने बताया प्रतिशत अंक होगा।

प्रभावी तारीख (अर्थात् निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ पखवाड़ा)	शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत)
28 मार्च 1998	10.25
11 अप्रैल 1998	10.00

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Proviso to Sub-section (1) of Section 42 of the RBI Act, 1934 (2 of 1934) and in supersession of its Notification No. DBOD.BC. 4/12.01.001/97-98 dated January 16, 1998, the Reserve Bank of India hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) shall, from effective dates mentioned below, be at the percentage points as indicated thereagainst.

Effective Date (i.e. fortnight beginning from)	Cash Reserve Ratio on net demand and time liabilities (per cent)
March 28, 1998	10.25
April 11, 1998	10.00

(S. Gurumurthy)
Executive Director

2 अप्रैल 1998
12 चैत्र 1920 (शक)

April 2, 1998
Chaitra 12, 1920 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

All Scheduled Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात (सीआरआर/एसएलआर) बनाये रखने में कमी होने पर दंड स्वरूप ब्याज दर

PENAL RATE OF INTEREST ON THE SHORTFALL IN THE MAINTENANCE OF CRR/SLR

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 18 मार्च 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 20/12.02.001/97-98 देखें।

Please refer to our circular DBOD. No. BC. 20/12.02.001/97-98 dated 18th March 1998 on the captioned subject.

2. इस संबंध में, हम आपका ध्यान अपने उप गवर्नर के 2 अप्रैल 1998 के परिपत्र सं. एमपीडी. बीसी. 174/07.01.279/97-98 की ओर आकर्षित करते हैं जिसके अनुसार आज (2 अप्रैल 1998) कारोबार समाप्ति पर बैंक दर आधा प्रतिशत अंक कम कर 10.50 प्रतिशत वार्षिक से 10.00 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी है। इसके फलस्वरूप, नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाये रखने में कम रहने वाली राशि पर वसूल की जाने वाली दंड स्वरूप ब्याज दर, जो बैंक दर से संबद्ध है, 2 अप्रैल 1998 को कारोबार समाप्ति पर संशोधित हो गयी है।

2. In this connection, we invite your attention to Deputy Governor's circular No. MPD. BC. 174/07.01.279/97-98 dated 2nd April 1998 in terms of which the Bank Rate has been reduced by one half of one percentage point i.e. from "10.50 percent per annum to 10.00 percent per annum" with effect from the close of business today (2nd April 1998). Consequently, the penal rate of interest charged on the amount of shortfalls in the maintenance of Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR) which is linked to Bank Rate stands revised from the close of business on 2nd April 1998.

भवदीय

Yours faithfully

(डी.वी. झवेरी)
महा प्रबंधक

(D.V. Jhaveri)
General Manager

29 अप्रैल 1998
9 वैशाख 1920 (शक)

April 29, 1998
Vaisakha 9, 1920 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

The Chairmen of all Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय

MONETARY AND CREDIT POLICY MEASURES

कृपया आप गवर्नर महोदय का 29 अप्रैल 1998 का पत्र सं. एमपीडी. बीसी. 175/07.01.279/97-98 देखें, जिसके साथ “1998-99 की पहली छमाही के लिए मौद्रिक और ऋण नीति” पर विवरण संलग्न किया गया है। नीतिगत उपायों में परिणामी परिवर्तन नीचे दिये गये हैं:

Please refer to Governor's letter No. MPD. BC.175/07.01.279/97-98 dated April 29, 1998 enclosing the statement on "Monetary and Credit Policy for the First Half of 1998-99". The consequent changes in policy measures are detailed below:

1. जमा दरें

1. Deposit Rates

(क) देशी मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम अवधिपूर्णता

(a) Minimum period of maturity of domestic term deposits

पहली जुलाई 1996 के परिपत्र बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.90/13.01.01/96 के अनुसार देशी मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम अवधि 46 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गयी थी। अब इन देशी मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम अवधि को घटाकर 30 दिन से 15 दिन करने का निर्णय लिया गया है।

In terms of Circular DBOD. No. Dir. BC. 90/13.01.01/96 dated July 1, 1996 the minimum period of domestic term deposits was reduced from 46 days to 30 days. It has now been decided to further reduce the minimum period of maturity of domestic term deposits from 30 days to 15 days.

(ख) देशी मीयादी जमाराशियों/ एनआरई जमाराशियों का अवधिपूर्व आहरण

15 मार्च 1997 के परिपत्र बैंपवि. सं. डीआइआर. बीसी.22/13.01.05/97 के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे मीयादी जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण की अनुमति दें और जमाराशियां जितनी अवधि तक बैंक के पास रहें उतनी अवधि के लिए लागू दर अथवा संविदा की दर, जो भी कम हो, में से अवधिपूर्व आहरण के लिए एक प्रतिशत का दंड घटाकर ब्याज अदा करें। अब यह निर्णय किया गया है कि देशी मीयादी जमाराशियों और एनआरई मीयादी जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण के लिए अपनी दंडात्मक ब्याज दर तय करने की बैंकों को अनुमति दी जाये। यह छूट नयी जमाराशियों और मौजूदा जमाराशियों के नवीकरण के लिए लागू होगी। परंतु बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जमाकर्ताओं को जमा दर के साथ-साथ लागू दंडात्मक दर की भी जानकारी दी जाये।

(ग) देशी मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें

यह निर्णय किया गया है कि समान अवधिपूर्णता वाली देशी मीयादी जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दरें अपने विवेकानुसार देने की बैंकों को अनुमति दी जाये, जो निम्नलिखित

(b) Premature withdrawal of domestic term deposits/NRE deposits

As per our Circular DBOD. No. Dir. BC. 22/13.01.05/97 dated March 15, 1997, banks are required to allow premature withdrawal of term deposits and pay interest at the rate applicable to the period for which the deposit had remained with the bank or at a contracted rate, whichever is lower, less one per cent penalty for the premature withdrawal. It has now been decided to permit banks to determine their own penal interest rates for premature withdrawal of domestic term deposits and NRE term deposits. This relaxation will apply to fresh deposits and renewal of existing deposits. Banks shall however, ensure that the depositors are made aware of the applicable penal rate along with the deposit rate.

(c) Interest rates on domestic term deposits

It has been decided to permit banks at their discretion to offer differential rates of interest on domestic term deposits of the same maturity, subject to the

शर्तों पर होगी:

(i) समान अवधिपूर्णता वाली जमाराशियों के लिए ब्याज की भिन्न-भिन्न दरें देने की अनुमति 15 लाख रुपये और उससे अधिक की देशी मीयादी जमाराशियों के लिए होगी। इसलिए बैंक एक ही अवधिपूर्णता वाली 15 लाख रुपये और उससे अधिक की जमाराशियों के लिए चाहें तो समान दर दे सकते हैं अथवा भिन्न-भिन्न ब्याज दरें दे सकते हैं। परंतु 15 लाख रुपये से कम की समान अवधिपूर्णता वाली जमाराशियों के लिए समान दर लागू होगी।

(ii) बैंकों को चाहिए कि जिन जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दरें अदा की जानी हो, उनके सहित जमाराशियों पर देय ब्याज दरों की अनुसूची वे पहले ही बता दें। बैंक द्वारा अदा की जाने वाली ब्याज दरें अनुसूची के अनुसार होनी चाहिए तथा वे जमाकर्ता और बैंक के बीच बातचीत के अधीन नहीं होनी चाहिए।

(iii) बैंकों के बोर्डों को इस संबंध में नीति निर्धारित करनी चाहिए।

बैंकों को नीति में परिवर्तन की प्रभावी तारीख यथाशीघ्र घोषित करनी चाहिए।

(घ) विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना [(एफसी-एनआर(बी))]

रिज़र्व बैंक के 21 अक्टूबर 1997 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 140/13.01.09/97 के

following conditions :

(i) The permission to offer varying rates of interest for deposits of the same maturity will apply to domestic term deposits of Rs. 15 lakhs and above. Banks may therefore offer same rate of interest or differential rates of interest for deposits of Rs. 15 lakhs and above of the same maturity. For deposits below Rs. 15 lakhs the same rate will apply for deposits of the same maturity.

(ii) Banks should disclose in advance the schedule of interest rates payable on deposits including deposits on which differential interest will be paid. Interest rates paid by the bank should be as per the schedule and not be subject to negotiation between the depositor and the bank.

(iii) The Boards of banks should lay down a policy in this regard.

Banks should announce the effective date of change in the policy at the earliest.

(d) Foreign Currency Non Resident Accounts (Banks) Scheme [(FCNR(B))]

In terms of RBI Circular DBOD. No. Dir. BC. 140/13.01.09/97 dated October 21,

अनुसार एक वर्ष और उससे अधिक की जमाराशियों के संबंध में ब्याज संबंधित मुद्रा/समाप्ति अवधि के लिए विनिमय दरों की उच्चतम सीमा के भीतर अदा किया जायेगा। छः महीने और उससे अधिक, परन्तु एक वर्ष से कम की जमाराशियों पर तथा अस्थिर दर वाली जमाराशियों पर ब्याज संबंधित मुद्रा/समाप्ति अवधि के लिए लंदन अंतर-बैंक प्रस्तुत दर (लिबोर) की उच्चतम सीमा के भीतर अदा किया जायेगा। दीर्घावधि जमाराशियां जुटाने को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, यह निर्णय किया गया है कि एक वर्ष और उससे अधिक की एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा को 50 आधार अंक बढ़ा दिया जाये। छः महीने और उससे अधिक परन्तु एक वर्ष से कम की जमाराशियों पर तथा अस्थिर दर वाली जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा 25 आधार अंक कम कर दी जायेगी।

(ड) अतिदेय एफसीएनआर (बी) और एनआरई जमाराशियों का नवीकरण

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार ऐसी अतिदेय एफसीएनआर/एनआरई जमाराशियों के मामले में, जहां अतिदेय अवधि 14 दिन से अधिक हो, बैंकों के लिए अपेक्षित था कि वे 29 जुलाई 1988 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 9 और 11.सी347(1)-88 में निर्दिष्ट

1997 interest shall be paid in respect of deposits of one year and above, within the ceiling of Swap rates for the respective currency/maturity. On deposits of six months and above but less than one year and floating rate deposits, interest shall be paid within the ceiling of LIBOR for the respective currency/maturity. In order to encourage mobilisation of long term deposits, it has been decided that the interest rate ceiling on FCNR(B) deposits of one year and above be increased by 50 basis points. On deposits of six months and above but less than one year and floating rate deposits, the interest rate ceiling will be reduced by 25 basis points.

(e) Renewal of overdue FCNR(B) and NRE deposits

As per existing instructions in case of overdue FCNR/NRE deposits where the overdue period exceeds 14 days, the banks are required to pay simple interest as specified in the directive DBOD. NO. DIR. BC. 9 and 11/C.347(I)-88 dated July

साधारण ब्याज अदा करें। अब यह निश्चय किया गया है कि बैंकों को अतिदेय एफसीएनआर (बी) तथा एनआरई जमाराशियों पर, इन जमाराशियों को नवीकृत किये जाने की शर्त पर, अपनी स्वयं की ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति दी जाये।

देशी मीयादी जमाराशियों एफसीएनआर (बी) तथा एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरों में परिवर्तनों की प्रभावी तारीखें बैंकों द्वारा यथाशीघ्र घोषित की जायेंगी।

2. उधार दरें

- (i) **2.00 लाख रुपये तक की ऋण सीमाओं पर ब्याज दर**
हमारे 21 अक्टूबर 1997 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 124/13.07.01/97-98 में निहित अनुदेशों के अनुसार 25,000 रुपये तक की ऋण सीमाओं पर ब्याज दर 12 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी। 25,000 रुपये से अधिक और 2 लाख रुपये तक की ऋण सीमाओं के लिए दर 13.5 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं होनी थी। 2 लाख रुपये और उससे कम के छोटे ऋणकर्ताओं हेतु ऋण के प्रवाह के लिए प्रोत्साहनहीनता समाप्त करने के लिए अब यह निश्चय किया गया है कि 2 लाख रुपये और उससे कम की ऋण सीमाओं पर ब्याज मूल उधार दर (पीएलआर) से अधिक नहीं होनी

29, 1988. It has now been decided to permit the banks to fix their own interest rates on overdue FCNR(B) and NRE deposits subject to these deposits being renewed.

The effective dates of changes in interest rates on domestic term deposits, FCNR(B) and NRE deposits shall be announced by banks as early as possible.

2. Lending Rates

- (i) **Interest rate on credit limits upto Rs. 2.00 lakh**
In terms of instructions contained in our Circular DBOD. No. Dir. BC. 124/13.07.01/97-98 dated October 21, 1997, interest rate on credit limits upto Rs. 25,000/- was prescribed at 12 per cent. For credit limits of over Rs. 25,000/- and upto Rs. 2 lakh the rate was not to exceed 13.5 percent per annum. In order to remove the disincentive to the flow of credit towards small borrowers of Rs. 2 lakh, and below, it has now been decided that interest on credit limits of Rs. 2 lakh and below shall not

चाहिए जो संबंधित बैंक के सबसे अच्छे ऋणकर्ताओं को उपलब्ध है।

(ii) देशी/एनआरई मीयादी जमाराशियों पर अग्रिम

4 जुलाई 1996 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 98/13.01.04/96 के साथ पढ़े जाने वाले रिज़र्व बैंक के 29 सितंबर 1995 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 109/13.01.09/95 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार, देशी/एनआरई मीयादी जमाराशियों की जमानत पर दिये गये 2 लाख रुपये तक के ऋणों और अग्रिमों पर वसूल की जाने वाली ब्याज दर जमा दरों से दो प्रतिशत अंक अधिक है तथा 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों लिए वसूल की जाने वाली दर बैंक की अपनी मूल उधार दर से कम नहीं है। अब यह निश्चय किया गया है कि जमाकर्ता को देशी/एनआरई जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम के लिए पीएलआर के बराबर या उससे कम की ब्याज दर होनी चाहिए।

ऊपर उल्लिखित परिवर्तनों की प्रभावी तारीख बैंकों द्वारा यथाशीघ्र घोषित की जायेगी।

उपर्युक्त परिवर्तनों को निर्देशित करने वाले 29 अप्रैल 1998 के

exceed the Prime Lending Rate which is available to the best borrowers of the concerned bank.

(ii) Advances against domestic/NRE term deposits

As per instructions in RBI Circular DBOD. No. Dir. BC. 109/13.01.09/95 dated September 29, 1995 read with Circular DBOD. No. Dir. BC. 98/13.01.04/96 dated July 4, 1996, interest rate chargeable on loans and advances granted against domestic/NRE term deposits upto Rs. 2 lakh is two percentage points above deposit rates and for advances over Rs. 2 lakh the interest rate chargeable is not less than bank's own PLR. It has now been decided that advances against domestic/NRE deposits to the depositor, should be at an interest rate equal to PLR or less.

The effective date of changes mentioned above shall be announced by banks as early as possible.

Amending Directives DBOD. Nos. Dir. BC. 33, 34 & 35/

संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं.
डीआईआर. बीसी. 33, 34 और
35/13.03.00/98 संलग्न हैं।

13.03.00/98 dated April 29,
1998 enumerating the above
changes are enclosed.

3. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर ऋण और अग्रिम

6 सितंबर 1996 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 116/13.07.05/96 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार बैंकों को अलग-अलग ऋणकर्ताओं को शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर प्रति ऋणकर्ता 10 लाख रुपये की उच्चतम सीमा तक ऋण और अग्रिम प्रदान करने की अनुमति दी गयी थी और उन्हें शेयरों की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए 50 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन भी बनाये रखना था। अब यह निश्चय किया गया है कि यदि अग्रिम ऐसे शेयरों और डिबेंचरों द्वारा जमानत प्राप्त हैं जो भौतिक रूप में नहीं हैं तो उक्त उच्चतम सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर अलग-अलग प्रति ऋणकर्ता 20 लाख रुपये कर दिया जाये। भौतिक रूप में न रहने वाले शेयरों की जमानत पर न्यूनतम मार्जिन निर्धारण को भी घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

4. मुद्रा बाज़ार

(i) जमा प्रमाणपत्र

हमारे 8 अगस्त 1996 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 109/21.03.063/96 के अनुसार जमा प्रमाणपत्र की न्यूनतम निश्चित अवरुद्धता अवधि (लॉक-इन-पीरियड) को 46 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया था। अब यह निश्चय किया गया है कि जमा

3. **Loans and advances against shares and debentures**

In terms of instructions contained in circular DBOD. No. Dir. BC. 116/13.07.05/96 dated September 6, 1996, banks were permitted to grant loans and advances to individuals against shares/debentures upto a ceiling of Rs. 10 lakh per borrower and were also required to maintain a minimum margin of 50 per cent for advances against shares. It has now been decided to increase the ceiling of Rs. 10 lakh to Rs. 20 lakh per individual borrower, if the advances are secured by shares and debentures held in dematerialised form. The minimum margin prescription against dematerialised shares also stands reduced to 25 per cent.

4. **Money Market**

(i) **Certificates of Deposits (CDs)**

As per our Circular DBOD. No. BP. BC. 109/21.03.063/96 dated August 8, 1996 the minimum lock-in-period for CDs was reduced from 46 days to 30 days. It has now been decided that the minimum lock-in-period for CDs be reduced from

प्रमाणपत्र की न्यूनतम निश्चित
अवरुद्धता अवधि को 30 दिन से
घटाकर 15 दिन कर दिया जाये।

30 days to 15 days.

**(ii) मुद्रा बाज़ार म्यूचुअल फंड
(एमएमएमएफ)**

3 जुलाई 1996 के परिपत्र बैपविवि. सं. एफसीएस. बीसी. 95/24.01.013/96 के अनुसार मुद्रा बाज़ार म्यूचुअल फंड की इकाइयों के लिए न्यूनतम निश्चित अवरुद्धता अवधि को 46 दिन से घटाकर 30 कर दिया गया था। अब यह निश्चय किया गया है कि न्यूनतम निश्चित अवरुद्धता अवधि को 30 दिन से और घटाकर 15 दिन कर दिया जाये। योजना के अन्य सभी परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश अपरिवर्तित हैं।

(ii) Money Market Mutual Funds (MMMFs)

In terms of Circular DBOD. No. FSC. BC. 95/24.01.013/96 dated July 3, 1996, the minimum lock-in-period for units of MMMFs was reduced to 30 days from 46 days. It has now been decided to further reduce the minimum lock-in-period from 30 days to 15 days. All other operative guidelines relating to the Scheme remain unchanged.

5. अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश का मूल्यन

10 अप्रैल 1997 के परिपत्र बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 31/21.04.048/97 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार 1997-98 के दौरान अनुमोदित प्रतिभूतियों में 'चालू' और 'स्थायी' निवेशों का अनुपात 60 : 40 निर्धारित था। विवेकपूर्ण लेखांकन मानक अपनाने तथा निवेश संविभाग के "बाज़ार के अनुसार" मूल्यन की दिशा में बढ़ना जारी रखने के उपायों के अनुरूप, यह निश्चय किया गया है कि बैंक अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश के कम से कम 70 प्रतिशत को 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 'चालू' के रूप में वर्गीकृत करें। उद्देश्य यह है कि अनुमोदित प्रतिभूतियों में चालू

5. Valuation of banks' investments in approved securities

In terms of instructions contained in Circular DBOD. No. BP. BC. 31/21.04.048/97 dated April 10, 1997, the ratio of 'Current' and 'Permanent' investments in approved securities during 1997-98 was prescribed at 60:40. Consistent with the measures to adopt prudent accounting standards and to continue to move towards "Mark to Market" valuation of investment portfolio, it has been decided that banks shall classify a minimum of 70 percent of the investments in approved securities as

निवेशों के अनुपात को, अंतरराष्ट्रीय सर्वोकृष्ट प्रथा की तरह, अगले तीन वर्षों में 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाये।

6. सीआरआर/एसएलआर बनाये रखने में कमी पर दंडात्मक ब्याज दर

बैंक दर को आज (29 अप्रैल 1998) कारोबार समाप्त होने के समय से एक प्रतिशत अंक घटाये जाने अर्थात् वार्षिक 10 प्रतिशत से घटाकर वार्षिक 9.00 प्रतिशत किये जाने से, प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाये रखने में कमी की राशि पर वसूल की जाने वाली दंडात्मक ब्याज दर आज (29 अप्रैल 1998) कारोबार समाप्त होने के समय से संशोधित हो जायेगी।

भवदीय

(अमलेन्दु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

'current' for the year ending March 31, 1999. It is intended to increase the ratio of current investments in approved securities progressively in line with international best practice, to 100 per cent in next three years.

6. **Penal Rate of Interest on the shortfall in the maintenance of CRR/SLR**

With the reduction brought about in the Bank Rate by one percentage point i.e. from "10 percent per annum to 9.00 percent per annum" with effect from the close of business today (29th April 1998), the Penal Rate of Interest charged on the amount of shortfalls in the maintenance of Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio will stand revised with effect from the close of business today (29th April 1998).

Yours faithfully

(A. Ghosh)
Chief General Manager

29 अप्रैल 1998
9 वैशाख 1920 (शक)

April 29, 1998
Vaisakha 9, 1920 (Saka)

अग्रिमों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि समय-समय पर संशोधित 21 सितंबर 1990 के उसके निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 18/सी. 96/90 का अनुबंध, संबंधित बैंकों द्वारा घोषित तारीखों से, इस निदेश से संलग्न संशोधित अनुबंध द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2. समय-समय पर यथासंशोधित 21 सितंबर 1990 के उपर्युक्त निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that, with effect from such dates as may be announced by respective banks, the Annexure to its Directive DBOD. No. Dir. BC. 18/C.96/90 dated September 21, 1990, as amended from time to time, shall be substituted by the revised Annexure enclosed to this Directive.

2. All other terms and conditions contained in the said Directive dated September 21, 1990 *ibid*, as amended from time to time, shall remain unchanged.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

अनुबंध
वाणिज्य बैंकों के रुपया अग्रिमों के लिए ब्याज दरों का विन्यास
(ब्याज कर छोड़ कर)

		ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)	
सीमा की मात्रा	वर्तमान मीयादी ऋण सहित सभी अग्रिम	<u>संशोधित</u>	
1. (क) रु. 25,000 तक	12.0	] न्यूनतम उधार दर से अधिक नहीं	
(ख) रु. 25,000/- से अधिक और 2 लाख रुपये तक	13.5 से अधिक नहीं		
(ग) 2 लाख रुपये से अधिक	मुक्त	मुक्त	
2. (i) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण	मुक्त	मुक्त	
(ii) शेयरों और डिबेंचरों/बांडों पर व्यक्तियों को ऋण	मुक्त	मुक्त	
(iii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में न आने वाले अन्य निजी ऋण	मुक्त	मुक्त	
3. चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले पण्यों के लिए उधार दर	चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले पण्यों पर दिये जाने वाले ऋण/अग्रिम/नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट	मुक्त	मुक्त
4. निर्यात-ऋण			
(1) पोतलदान पूर्व ऋण			
(i) (क) 180 दिन तक	12.0	11.0	
(ख) 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक	14.0	14.0	
(ii) भा.नि.ऋ.गा. निगम की गारंटी में शामिल सरकार से प्राप्य नकदी प्रोत्साहनों पर (90 दिन तक)	12.0	11.0	
(2) पोतलदान के बाद का ऋण			
(i) मांग बिल-मार्गस्थ अवधि के लिए (जैसा कि भा.वि.मु.व्या. संघ द्वारा विनिर्दिष्ट है)	11.0 से अधिक नहीं	11.0 से अधिक नहीं	

सीमा की मात्रा	वर्तमान मीयादी ऋण सहित सभी अग्रिम	संशोधित
(ii) मीयादी बिल (निर्यात बिल की मीयादी अवधि, मार्गस्थ अवधि, जैसा कि भा. वि.मु. व्या. संघ द्वारा विनिर्दिष्ट है, और जहां लागू हो, वहां छूट अवधि को मिलाकर कुल अवधि)		
(क) 90 दिन तक	11.0 से अधिक नहीं	11.0 से अधिक नहीं
(ख) 90 दिन से अधिक और पोतलदान की तारीख से छः महीने तक	13.0 (केवल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए)	13.0
(iii) भा.नि.ऋ.गा. निगम की गारंटी द्वारा रक्षित सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों पर (90 दिन तक)	11.0 से अधिक नहीं	11.0 से अधिक नहीं
(iv) अनाहरित शेष राशि पर (90 दिन तक)	11.0 से अधिक नहीं	11.0 से अधिक नहीं
(v) पोतलदान की तारीख से एक वर्ष के भीतर देय प्रतिधारण धन पर (केवल आपूरित भाग के लिए) (90 दिन तक)	11.0 से अधिक नहीं	11.0 से अधिक नहीं
(3) आस्थगित ऋण 180 दिन से अधिक अवधि के लिए आस्थगित ऋण		
	मुक्त	मुक्त
(4) अन्यथा अविनिर्दिष्ट निर्यात ऋण		
(क) पोतलदान पूर्व ऋण	20.0 (न्यूनतम) —	नहीं
(ख) पोतलदान के बाद का ऋण	—	20.0 (न्यूनतम)
5. विभेदक ब्याज दर अग्रिम	4.0	4.0
6. (क) अंतिम हिताधिकारियों और निविष्टि सहायता देने वाली एजेंसियों को आगे ऋण देने के लिए	6 (क) अंतिम हिताधिकारियों तथा निविष्टि सहायता देने वाली एजेंसियों को आगे ऋण देने के	अपरिवर्तित

सीमा की मात्रा	वर्तमान मीयादी ऋण सहित सभी अग्रिम	संशोधित
मध्यवर्ती एजेंसियों (आवास को छोड़कर) को प्रदत्त वित्त	लिए मध्यवर्ती एजेंसियों (आवास को छोड़कर) को प्रदत्त वित्त के लिए 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों की श्रेणी की ऋण सीमाओं के लिए प्रत्येक बैंक की मूल उधार दर से 1.5 प्रतिशत अंक कम की दर होगी।	
6 (ख) अंतिम हिताधिकारियों को आगे ऋण देने के लिए आवास वित्त मध्यवर्ती एजेंसियों को प्रदत्त वित्त	6 (ख) आवास वित्त मध्यवर्ती एजेंसियों को प्रदत्त वित्त के लिए विभिन्न दरों पर ब्याज, बशर्ते वे लागू मूल उधार दर से कम हों।	अपरिवर्तित

टिप्पणी:

जहां ऋण प्रा.कृ.ऋ.स./बड़े आकार की बहु उ.स./कृ.से.स. के माध्यम से दिये जाने हैं वहां बैंकों द्वारा प्रा. कृ.ऋ.स./बड़े आकार की बहु उ.स./कृ.से.स. से लिये जाने वाले ब्याज की दर ऊपर मद 1 (क) और 1 (ख) में बतायी गयी अंतिम ऋणकर्ता के लिए लागू दरों से 1.5 प्रतिशत अंक कम होगी। मद 1(ग) के संदर्भ में दर प्रत्येक बैंक की उपयुक्त मूल उधार दर से 1.5 प्रतिशत अंक कम होगी।

ANNEXURE
Interest Rate structure excluding Interest Tax
for rupee advances of commercial banks

		Rate of interest (Per cent per annum)	
Size of limit		<u>Existing</u> All advances inclu- ding Term loans	<u>Revised</u>
1.	(a) Upto and inclusive of Rs. 25,000	12.0	Not exceeding Prime Lending Rate (PLR)
	(b) Over Rs. 25,000 and upto Rs. 2 lakhs	Not exceeding 13.5	
	(c) Over Rs. 2 lakhs	Free	Free
2.	(i) Loans for purchase of consumer durables	Free	Free
	(ii) Loans to individuals against shares and debentures/bonds	Free	Free
	(iii) Other non-priority sector personal loans	Free	Free

**Lending rate for commodities
coming within the purview of
Selective Credit Control (SCC)**

Loans/Advances/Cash Credit/Overdrafts against commodities subject to SCC	Free	Free

Size of limit	<u>Existing</u> All advances including Term loans	<u>Revised</u>
4. Export Credit		
(1) Pre-shipment Credit		
(i) (a) Upto 180 days	12.0	11.0
(b) Beyond 180 days and upto 270 days	14.0	14.0
(ii) Against incentives receivable from Government covered by ECGC Guarantee (upto 90 days)	12.0	11.0
(2) Post-shipment Credit		
(i) Demand bills for transit period (as specified by FEDAI)	Not exceeding 11.0	Not exceeding 11.0
(ii) Usance Bills (For total period comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI and grace period wherever applicable)		
(a) Upto 90 days	Not exceeding 11.0	Not exceeding 11.0
(b) Beyond 90 days and upto 6 months from date of shipment	13.0 (for the period beyond 90 days)	13.0
(iii) Against incentives receivable from Government covered by ECGC Guarantee (upto 90 days)	Not exceeding 11.0	Not exceeding 11.0

Size of limit	<u>Existing</u> All advances inclu- ding Term loans	<u>Revised</u>
(iv) Against undrawn balances (upto 90 days)	Not exceeding 11.0	Not exceeding 11.0
(v) Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (upto 90 days)	Not exceeding 11.0	Not exceeding 11.0
3. Deferred Credit		
Deferred credit for the period beyond 180 days	free	free
4. Export Credit not otherwise specified	20.0 (minimum)	—
(a) Pre-shipment credit	—	free
(b) Post-shipment credit	—	20.0 (minimum)
5. DRI advances	4.0	4.0
6(a) Finance granted to intermediary agencies (excluding those for housing) for onlending to ultimate beneficiaries and agencies providing input support.	6(a) For finance granted to intermediary agencies (excluding those for housing) for on- lending to ultimate bene- ficiaries and agencies providing input support, the rate will be 1.5 per centage points below each bank's Prime Lending Rate for credit limits in the category of advances over Rs. 2 lakhs.	No change

Size of limit	<u>Existing</u>	<u>Revised</u>
	All advances including Term loans	
6(b) Finance granted to housing finance intermediary agencies for onlending to ultimate beneficiaries	6(b) For finance granted to housing finance intermediary agencies interest at different rates provided they are below the applicable Prime Lending Rate.	No change

Note :

Where loans are routed through PACS/LAMPS/FSS, the rate of interest to be charged by banks to the PACS/LAMPS/FSS shall be 1.5 percentage points lower than the rates to the ultimate borrowers indicated in item 1(a) and 1(b) above. In respect of item 1(c), the rate will be 1.5 percentage points below the appropriate Prime Lending Rate of each bank.

29 अप्रैल 1998
9 वैशाख 1920 (शक)

April 29, 1998
Vaishakha 9, 1920 (Saka)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसम्बर 1985 के अपने निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्वारा यह निदेश देता है कि

- i) उपर्युक्त निदेश के अनुबंध I को संशोधित अनुबंध द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- ii) उपर्युक्त निदेश के पैरा 8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:

"8. मीयादी जमाराशियों का समय से पूर्व आहरण

- (i) जमाकर्ता के अनुरोध पर बैंक जमाराशि की अवधि पूरी होने से पूर्व, जिस पर राशि जमा करते समय सहमति व्यक्त की गयी थी, किसी मीयादी जमा की अवधि-समाप्ति से पूर्व आहरण की अनुमति देगा। मीयादी जमाराशियों के समय से पूर्व आहरण के लिए अपनी स्वयं की दंडस्वरूप ब्याज दरें निश्चित करने की स्वतंत्रता होगी। यह नयी जमाराशियों और जमाराशियों के नवीकरण पर लागू होगा। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in modification of its Directive DBOD. No. Dir. BC. 151/C.347-85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that

- (i) Annexure 1 to the aforesaid Directive shall be substituted by the revised Annexure.
- (ii) paragraph 8 of the aforesaid Directive shall be substituted by the following :

"8. Premature withdrawal of term deposit

- (i) The bank on request from the depositor, shall allow withdrawal of a term deposit before completion of the period of the deposit agreed upon at the time of making the deposit. The bank shall have the freedom to determine their own penal interest rates for premature withdrawal of term deposits. This will apply to fresh deposits and renewal of deposits. The

जमाकर्ताओं को जमाराशि की दर के साथ-साथ लागू दंड स्वरूप दर से भी अवगत कराया जायेगा।

(ii) ऐसे परिवर्तनों की प्रभावी तारीख बैंकों द्वारा यथाशीघ्र घोषित की जायेगी”

(iii) उपर्युक्त निदेश के पैरा 17 के खंड (ग) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“(ग) एक ही तारीख को और समान अवधि पूर्णता के लिए स्वीकृत जमाराशियों पर, चाहे ऐसी जमाराशियां बैंक के एक ही कार्यालय में या अलग-अलग कार्यालयों में स्वीकार की गयी हों, एक जमाराशि और दूसरी जमाराशि के बीच, जमाराशि पर अदा की जाने वाली ब्याज दर के मामले में विभेद कर सकते हैं, किंतु जमाराशियों की मात्रा के आधार पर 15 लाख रुपये और उससे अधिक की देशी मीयादी जमाराशियों के संदर्भ में। भिन्न-भिन्न ब्याज दरें देने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर होगी :

(क) समान अवधिपूर्णता वाली जमाराशियों के लिए ब्याज की भिन्न-भिन्न दरें देने की अनुमति 15 लाख रुपये और उससे अधिक की देशी मीयादी जमाराशियों के लिए होगी। इसलिए बैंक एक ही अवधिपूर्णता वाली 15 लाख रुपये और उससे अधिक की जमाराशियों के लिए चाहें तो समान दर दे सकते हैं अथवा भिन्न-भिन्न ब्याज दरें दे सकते हैं। परंतु 15 लाख रुपये से कम की समान अवधिपूर्णता वाली जमाराशियों के लिए समान दर लागू होगी।

bank shall ensure that the depositors are made aware of the applicable penal rate along with the deposit rate.

(ii) The effective date of such changes shall be announced by banks as early as possible”

(iii) the clause (c) of paragraph 17 of the aforesaid Directive shall be substituted by the following :

“(c) discriminate in the matter of rate of interest paid on deposits, between one deposit and another, accepted on the same date and for the same maturity whether such deposits are accepted at the same office or at different offices of the bank, except in respect of domestic term deposits of Rs. 15 lakh and above on the basis of size of deposits. The permission to offer varying rates of interest will be subject to the following conditions :

(a) The permission to offer varying rates of interest for deposits of the same maturity shall apply to domestic term deposits of Rs. 15 lakh and above. Banks may therefore offer same rate of interest or differential rates of interest for domestic deposits of Rs. 15 lakh and above. For domestic deposits below Rs. 15 lakh of the same maturity the same rate will apply.

(ख) बैंकों को चाहिए कि जिन जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दरें अदा की जानी हो, उनके सहित जमाराशियों पर देय ब्याज दरों की अनुसूची वे पहले ही बता दें। बैंक द्वारा अदा की जाने वाली ब्याज दरें अनुसूची के अनुसार होनी चाहिए तथा वे जमाकर्ता और बैंक के बीच बातचीत के अधीन नहीं होनी चाहिए।

बैंकों को नीति में परिवर्तन की प्रभावी तारीख यथाशीघ्र घोषित करनी चाहिए।

(iv) उपर्युक्त निदेश के पैरा 10 के खंड (ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:

"(ii) अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता

बैंक, अपने विवेकानुसार अतिदेय जमाराशि या उसके एक भाग का नवीकरण कर सकता है, बशर्ते अवधि पूर्णता की तारीख से नवीकरण की तारीख तक की अतिदेय अवधि (दोनों दिन मिलाकर) 14 दिन से अधिक नहीं हो और इस प्रकार नवीकृत की जाने वाली जमा की राशि पर देय उपर्युक्त ब्याज दर वह होगी, जो अवधि पूर्णता की तारीख को या जिस तारीख को जमाकर्ता नवीकरण चाहता हो उस तारीख को प्रचलित हो, जो भी कम हो। अतिदेय जमाराशियों के मामले में जहां अतिदेय अवधि 14 दिन से अधिक हो और यदि जमाकर्ता अतिदेय जमा की पूरी राशि या उसका एक भाग नये एनआरई मीयादी जमा के रूप रखता है, तो बैंक नये जमा के रूप में इस प्रकार रखी गयी राशि पर अतिदेय अवधि के लिए अपनी स्वयं की ब्याज दरें निश्चित कर सकते हैं।"

(b) Banks should disclose in advance the schedule of interest rates payable on deposits including deposits on which differential interest will be paid. Interest rates paid by the bank should be as per the schedule and not be subject to negotiation between the depositor and the bank.

Banks should announce the effective date of change in the policy at the earliest".

(iv) Clause (ii) of paragraph 10 of the aforesaid Directive shall be substituted by the following.

"(ii) Non-resident (External) Rupee Account

The bank may, at its discretion, renew an overdue deposit or a portion thereof provided the overdue period from the date of maturity till the date of renewal (both days inclusive) does not exceed 14 days and the rate of interest payable on the amount of the deposit so renewed shall be the appropriate rate of interest for the period of renewal as prevailing on the date of maturity or on the date when the depositor seeks renewal whichever is lower. In the case of overdue deposits where the overdue period exceeds 14 days and if the depositor places the entire amount of overdue deposit or a portion thereof as a fresh NRE term deposit, banks may fix their own interest rates for the overdue period on the amount so placed as a fresh deposit."

(v) उपर्युक्त निदेश का पैरा 11(क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“जब कोई अग्रिम मीयादी जमा पर दिया जाता है और वह निम्नलिखित के नाम रहता है -

- (i) उधारकर्ता के नाम पर अकेले या संयुक्त रूप से
- (ii) भागीदारी फर्म के भागीदारों में से किसी एक भागीदार के नाम पर और अग्रिम उक्त फर्म को स्वीकृत किया जाता है,
- (iii) स्वामित्ववाली संस्था के स्वामी के नाम पर और अग्रिम ऐसी संस्था को स्वीकृत किया गया हो
- (iv) वह आश्रित (वार्ड) जिसका अभिभावक आश्रित की ओर से उधार लेने के लिए सक्षम है और जहां उक्त क्षमता में आश्रित के अभिभावक को अग्रिम स्वीकृत किया गया हो।”

2. समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसम्बर 1985 के निदेश डीबीओडी.सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

(v) Paragraph 11(a) of the aforesaid directive shall be substituted by the following :

"When an advance is granted against a term deposit and the deposit stands in the name of

- (i) the borrower either singly or jointly,
- (ii) one of the partners of a partnership firm and the advance is made to the said firm,
- (iii) the proprietor of a proprietary concern and the advance is made to such a concern,
- (iv) a ward whose guardian is competent to borrow on behalf of the ward and where the advance is made to the guardian of the ward in such capacity, the interest rate chargeable shall be equal to bank's Prime Lending Rate or less".

2. The other provisions of Directive DBOD. No. Dir. BC. 151/C.347-85 dated 27 December 1985, as amended from time to time, shall remain unchanged.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

अनुबंध

जमाराशियों पर ब्याज दें (अनिवासी जमाराशियों को छोड़कर)

खाते की श्रेणी	प्रतिशत वार्षिक
(i) चालू	कुछ नहीं
(ii) बचत	4.5
(iii) मीयादी जमाराशियां 15 दिन और उससे अधिक	मुक्त

ANNEXURE

Rate of interest on deposits (Excluding Non-resident Deposits)

Category of Account	Percent per annum
(i) Current	Nil
(ii) Savings	4.5
(iii) Term deposits 15 days and over	Free

29 अप्रैल 1998
9 वैशाख 1920 (शक)

April 29, 1998
Vaishakha 9, 1920 (Saka)

**विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक)
योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर
ब्याज दरें**

**INTEREST RATES ON DEPOSITS
HELD UNDER FOREIGN CURRENCY
NON-RESIDENT ACCOUNTS
(BANKS) SCHEME**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that :

I. ब्याज दरें

समय-समय पर यथासंशोधित 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 115/13.01.09/93 के वर्तमान पैरा (vi), जो विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अधीन स्वीकृत जमाराशियों से संबंधित है, को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये:

I. Interest Rates

The existing paragraph (vi) of Directive DBOD No. BC. 115/13.01.09/93 dated April 29, 1993 as amended from time to time, relating to deposits accepted under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) Scheme, shall be substituted as under :

- (i) छः महीने और उससे अधिक परन्तु एक वर्ष से कम की जमाराशियों तथा अस्थिर दर वाली जमाराशियों के संदर्भ में ब्याज उस दर पर अदा किया जायेगा जो संबंधित मुद्रा/अवधिपूर्णता के लिए 25 आधार अंक घटाकर लिबोर से अधिक न हो। अस्थिर दर वाली जमाराशियों के लिए ब्याज की

- (i) In respect of deposits of six months and above but less than one year, and floating rate deposits, interest shall be paid at a rate not in excess of LIBOR minus 25 basis points for the respective currency/maturity. For floating rate deposits, the

पुनर्निधारित अवधि छः महीने होगी।

- (ii) एक वर्ष और उससे अधिक की अवधिपूर्णता वाली जमाराशियों के संदर्भ में ब्याज संबंधित मुद्रा/अवधि समाप्ति के लिए 50 आधार अंक जोड़कर विनिमय (स्वैप) दरों की उच्चतम सीमा के भीतर अदा किया जायेगा।
- (iii) पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य दिन विद्यमान लिबोर/स्वैप दरें आगामी सप्ताह दी जाने वाली प्रभावी ब्याज दरों के लिए उच्चतम दरें निर्धारित करने के लिए आधार होंगी।

II. अतिदेय एफसीएनआर जमाराशियों पर ब्याज की अदायगी

समय-समय पर यथासंशोधित 11 सितंबर 1986 के बैंक के निदेश डीबीओडी. सं. डीआईआर. बीसी. 95/सी.347(1)-86 के वर्तमान पैरा 5 को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा:

बैंक अपने विवेकानुसार अतिदेय जमाराशि या उसके एक भाग का नवीकरण कर सकता है, बशर्ते अवधिपूर्णता की तारीख से नवीकरण की तारीख तक की अतिदेय अवधि (दोनों दिन मिलाकर) 14 दिन से अधिक नहीं हो और इस प्रकार नवीकृत की जाने वाली जमा की राशि पर देय उपयुक्त ब्याज दर वह होगी जो अवधिपूर्णता की तारीख को या जिस तारीख को जमाकर्ता

interest reset period shall be six months.

- (ii) In respect of deposits of maturity of one year and above, the interest shall be paid within the ceiling of Swap rates for the respective currency/maturity plus 50 basis points.
- (iii) The LIBOR/Swap rates as on the last working day of the preceding week would form the base for fixing the ceiling rates for the interest rates that would be offered effective the following week.

II. Payment of Interest on overdue FCNR Deposits

The existing paragraph 5 of Bank's Directive DBOD. No. Dir. BC.95/C.347(I)-86 dated September 11, 1986 as amended from time to time, shall be modified as under :

The bank may, at its discretion, renew an overdue deposit or a portion thereof provided the overdue period from the date of maturity till the date of renewal (both days inclusive), does not exceed 14 days and the rate of interest payable on the amount of the deposit so renewed shall be the appropriate rate of interest for the period of renewal

नवीकरण चाहता हो उस तारीख को प्रचलित हो, जो भी कम हो। अतिदेय जमाराशियों के मामले में जहां अतिदेय अवधि 14 दिन से अधिक हो और यदि जमाकर्ता अतिदेय जमा की पूरी राशि या उसका एक भाग नये एफसीएनआर (बी) जमा के रूप रखता है तो बैंक नये जमा के रूप में इस प्रकार रखी गयी राशि पर अतिदेय अवधि के लिए अपनी स्वयं की ब्याज दरें निश्चित कर सकते हैं।

as prevailing on the date of maturity or on the date when the depositor seeks renewal, whichever is lower. In the case of overdue deposits where the overdue period exceeds 14 days and if the depositor places the entire amount of overdue deposit or a portion thereof as a fresh FCNR(B) Deposit, banks may fix their own interest rates for the overdue period on the amount so placed as a fresh term deposit.

2. समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 11 सितंबर 1986 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 95/सी.347(I)-86 तथा दिनांक 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइ.आर. बीसी. 115/13.01.09/93 के अन्य सभी उपलब्ध अपरिवर्तित रहेंगे।

2. All other provisions of Directive DBOD. No. Dir. BC. 95/C.347(I)-86 dated September 11, 1986 and DBOD. No. Dir. BC. 115/13.01.09-93 dated April 29, 1993, as amended from time to time, shall remain unchanged.

3. बैंकों द्वारा ऐसे परिवर्तनों की प्रभावी तारीख यथाशीघ्र घोषित की जायेगी।

3. The effective date on such changes shall be announced by banks as early as possible.

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

(S. Gurumurthy)
Executive Director

20 मई 1998
30 वैशाख 1920 (शक)

May 20, 1998
Vaishakha 30, 1920 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी
निधि अनुपात के अंतर्गत 3 मई 1991
तथा 17 अप्रैल 1992 के बीच जमा
शेषराशियों का निर्मोचन

RELEASE OF BALANCES
IMPOUNDED BETWEEN 3RD MAY
1991 AND 17TH APRIL 1992 UNDER 10
PER CENT INCREMENTAL CRR

कृपया उक्त विषय पर 18 मई 1998 के उप गवर्नर
के परिपत्र एमपीडी. 176/07.01.279/97-98 का
अवलोकन करें।

Please refer to the Deputy Governor's
circular MPD. 176/07.01.279/97-98 dated
18th May 1998 on the captioned subject.

2. इस संबंध में कृपया 8 अक्टूबर 1992 के
हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. बीसी. 38/12.01.001/
92 के पैरा 2(बी) का अवलोकन करें जिसके
अनुसार प्रत्येक बैंक द्वारा 10 प्रतिशत वृद्धिशील
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अंतर्गत रखी गयी
अतिरिक्त नकद शेषराशियों के एक तिहाई हिस्से
को निर्मुक्त किया गया था। अब यह निर्णय लिया
गया है कि 17 अप्रैल 1992 तक की निवल मांग
और मीयादी देयताओं के स्तर के आधार पर प्रत्येक
बैंक द्वारा 10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी
निधि अनुपात के अंतर्गत रखी गयी अतिरिक्त नकद
शेषराशियों के शेष दो तिहाई हिस्से का निर्मोचन
अनुबंध में दी गयी अनुसूची के अनुसार 12 समान
किस्तों में किया जाये। 20 मई 1998 की संबंधित
अधिसूचना बैंपविवि. सं. 43/12.01.001/92 की
एक प्रति संलग्न है।

2. In this connection we invite a
reference of para 2(b) of our circular DBOD.
No. BC. 38/12.01.001/92 dated 8th October
1992 in terms of which one-third of the
additional cash balances maintained under
the 10 per cent incremental CRR by each
bank was released. It has now been decided
to release the remaining two thirds of
additional cash balances maintained under
the 10 per cent incremental CRR by each
bank based on the level of Net Demand and
Time Liabilities upto April 17, 1992 in 12
equal instalments as per the schedule given
in the Annexure. A copy of the relative
notification DBOD. No. BC. 43/12.01.001/
92 dated 20th May 1998 is enclosed.

3. कृपया नोट करें कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1ए) के अंतर्गत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अन्य निर्धारण अगली सूचना तक जारी रहेंगे।

भवदीय

(एन.के. सरकार)
महा प्रबंधक

3. Please note that other prescriptions of incremental Cash Reserve Ratio under section 42(1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934 would continue till further advice.

Yours faithfully

(N. K. Sarkar)
General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी.43/12.01.001/97-98

20 मई 1998
30 वैशाख 1920 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप धारा (1ए) के साथ पठित धारा 42 की उप धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 8 अक्टूबर 1992 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 37/12.01.001/92 के अनुक्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि 17 अप्रैल 1992 के स्तर तक निवल मांग और मीयादी देयताओं के स्तर पर आधारित 10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों

DBOD.No.BC. 43/12.01.001/97-98

May 20, 1998
Vaishakha 30, 1920 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 42 read with sub-section (1A) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934, and in continuation of its Notification DBOD No. BC. 37/12.01.001/92 dated 8th October 1992 Reserve Bank of India hereby specifies that the remaining two-thirds balance of the additional cash balances maintained by Scheduled Commercial Banks under 10 per

द्वारा रखी गयी अतिरिक्त नकद शेषराशियों के शेष दो तिहाई हिस्से का निर्मोचन निम्नानुसार 12 समान किस्तों में किया जाये:

निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ पखवाड़ा	संचयी निर्मोचन
23 मई 1998	एक बटा बारहवां हिस्सा
06 जून 1998	दो बटा बारहवां हिस्सा
04 जुलाई 1998	तीन बटा बारहवां हिस्सा
01 अगस्त 1998	चार बटा बारहवां हिस्सा
29 अगस्त 1998	पांच बटा बारहवां हिस्सा
26 सितंबर 1998	छः बटा बारहवां हिस्सा
24 अक्तूबर 1998	सात बटा बारहवां हिस्सा
21 नवम्बर 1998	आठ बटा बारहवां हिस्सा
19 दिसम्बर 1998	नव बटा बारहवां हिस्सा
16 जनवरी 1999	दस बटा बारहवां हिस्सा
13 फरवरी 1999	ग्यारह बटा बारहवां हिस्सा
13 मार्च 1999	कुल

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

cent incremental Cash Reserve Ratio (CRR) based on the level of Net Demand and Time Liabilities upto the level as on 17th April 1992 be released in 12 equal installments as indicated below.

Fortnight beginning from	Cumulative Release
May 23, 1998	One twelfth
June 06, 1998	Two twelfth
July 04, 1998	Three twelfth
August 01, 1998	Four twelfth
August 29, 1998	Five twelfth
September 26, 1998	Six twelfth
October 24, 1998	Seven twelfth
November 21, 1998	Eight twelfth
December 19, 1998	Nine twelfth
January 16, 1999	Ten twelfth
February 13, 1999	Eleven twelfth
March 13, 1999	Total

(S. Gurumurthy)
Executive Director

अनुबंध

ANNEXURE

3 मई 1991 तथा 17 अप्रैल 1992 के बीच 10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अंतर्गत जमा किये गये शेष संसाधन (दो तिहाई)- निर्मोचन की अनुसूची

Balance Resources (two-thirds) impounded under 10 per cent incremental CRR between May 03, 1991 and April 17, 1992- Schedule of Release

निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ पखवाड़ा	संचयी निर्मोचन
23 मई 1998	एक बटा बारहवां हिस्सा
06 जून 1998	दो बटा बारहवां हिस्सा
04 जुलाई 1998	तीन बटा बारहवां हिस्सा
01 अगस्त 1998	चार बटा बारहवां हिस्सा
29 अगस्त 1998	पांच बटा बारहवां हिस्सा
26 सितंबर 1998	छः बटा बारहवां हिस्सा
24 अक्टूबर 1998	सात बटा बारहवां हिस्सा
21 नवम्बर 1998	आठ बटा बारहवां हिस्सा
19 दिसम्बर 1998	नव बटा बारहवां हिस्सा
16 जनवरी 1999	दस बटा बारहवां हिस्सा
13 फरवरी 1999	ग्यारह बटा बारहवां हिस्सा
13 मार्च 1999	कुल

Fortnight beginning from	Cumulative Release
May 23, 1998	One twelfth
June 06, 1998	Two twelfth
July 04, 1998	Three twelfth
August 01, 1998	Four twelfth
August 29, 1998	Five twelfth
September 26, 1998	Six twelfth
October 24, 1998	Seven twelfth
November 21, 1998	Eight twelfth
December 19, 1998	Nine twelfth
January 16, 1999	Ten twelfth
February 13, 1999	Eleven twelfth
March 13, 1999	Total

15 जून 1998
25 ज्येष्ठ 1920 (शक)

June 15, 1998
Jyestha 25, 1920 (Saka)

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष

The Chairmen of all
Regional Rural Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी ब्याज

**MONETARY AND CREDIT POLICY
MEASURES**

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा “1998-99 की पहली छमाही के लिए मौद्रिक और ऋण नीति” पर जारी विवरण के फलस्वरूप 29 अप्रैल 1998 का निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 34/13.03.00/98 जारी किया गया था, जिसकी प्रति संलग्न है। हम सूचित करते हैं कि नीतिगत उपायों में निम्नलिखित परिवर्तन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू होंगे।

Consequent on the statement released by the Governor, Reserve Bank of India on "Monetary and Credit Policy for the First Half of 1998-99", Directive DBOD No. Dir. BC. 34/13.03.00/98 dated April 29, 1998 was issued, a copy of which is enclosed. We advise that the following changes in policy measures will be applicable to Regional Rural Banks.

1. जमा दरें

(क) देशी मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम अवधिपूर्णता

पहली जुलाई 1996 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 90/13.01.01/96 के अनुसार देशी मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम अवधि 46 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गयी थी। अब इन देशी मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम अवधि को और घटाकर 30 दिन से

1. Deposit Rates

(a) **Minimum period of maturity of domestic term deposits**

In terms of circular DBOD No. Dir. BC. 90/13.01.01/96 dated July 1, 1996 the minimum period of domestic term deposits was reduced from 46 days to 30 days. It has now been decided to further reduce the minimum period of maturity of

15 दिन करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) देशी मीयादी जमाराशियों का अवधिपूर्व आहरण

15 मार्च 1997 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 22/13.01.05/97 के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे मीयादी जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण की अनुमति दें और जमाराशियां जितनी अवधि तक बैंक के पास रहीं उतनी अवधि के लिए लागू दर अथवा संविदा की दर, जो भी कम हो, में से अवधिपूर्व आहरण के लिए एक प्रतिशत का दंड घटाकर ब्याज अदा करें। अब यह निर्णय किया गया है कि देशी मीयादी जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण के लिए अपनी दंडात्मक ब्याज दर तय करने की बैंकों को अनुमति दी जाये। यह छूट नयी जमाराशियों और मौजूदा जमाराशियों के नवीकरण के लिए लागू होगी। परंतु बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जमाकर्ताओं को जमा दर के साथ-साथ लागू दंडात्मक दर की भी जानकारी दी जाये।

(ग) देशी मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें

यह निर्णय किया गया है कि समान अवधिपूर्णता वाली देशी मीयादी

domestic term deposits from 30 days to 15 days.

(b) Premature withdrawal of domestic term deposits

As per our circular DBOD No. Dir. BC. 22/13.01.05/97 dated March 15, 1997 banks are required to allow premature withdrawal of term deposits and pay interest at the rate applicable to the period for which the deposit had remained with the bank or at a contracted rate, whichever is lower, less one per cent penalty for the premature withdrawal. It has now been decided to permit banks to determine their own penal interest rates for premature withdrawal of domestic term deposits. This relaxation will apply to fresh deposits and renewal of existing deposits. Banks shall, however, ensure that the depositors are made aware of the applicable penal rate along with the deposit rate.

(c) Interest rates on domestic term deposits

It has been decided to permit banks at their discretion to offer

जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दरें अपने विवेकानुसार देने की बैंकों को अनुमति दी जाये, जो निम्नलिखित शर्तों पर होगी:

(i) समान अवधिपूर्णता वाली जमाराशियों के लिए ब्याज की भिन्न-भिन्न दरें देने की अनुमति 15 लाख रुपये और उससे अधिक की देशी मीयादी जमाराशियों के लिए लागू होगी। इसलिए बैंक एक ही अवधिपूर्णता वाली 15 लाख रुपये और उससे अधिक की जमाराशियों के लिए चाहें तो समान दर दे सकते हैं अथवा भिन्न-भिन्न ब्याज दरें दे सकते हैं। परंतु 15 लाख रुपये से कम की समान अवधिपूर्णता वाली जमाराशियों के लिए समान दर लागू होगी।

(ii) बैंकों को चाहिए कि जिन जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दरें अदा की जानी हों, उनके सहित जमाराशियों पर देय ब्याज दरों की अनुसूची वे पहले ही बता दें। बैंक द्वारा अदा की जाने वाली ब्याज दरें अनुसूची के अनुसार होनी चाहिए तथा वे जमाकर्ता और बैंक के बीच बातचीत के अधीन नहीं होनी चाहिए।

differential rates of interest on domestic term deposits of the same maturity subject to the following conditions :

i) The permission to offer varying rates of interest for deposits of the same maturity will apply to domestic term deposits of Rs. 15 lakh and above. Banks may, therefore, offer same rate of interest or differential rates of interest for deposits of Rs. 15 lakh and above of the same maturity. For deposits below Rs. 15 lakh the same rate will apply for deposits of the same maturity.

ii) Banks should disclose in advance the schedule of interest rates payable on deposits including deposits on which differential interest will be paid. Interest rates paid by the bank should be as per the schedule and not be subject to negotiation between the depositor and the bank.

(iii) बैंकों के बोर्डों को इस संबंध में नीति निर्धारित करनी चाहिए। बैंकों को नीति में परिवर्तन की प्रभावी तारीख यथाशीघ्र घोषित करनी चाहिए।

iii) The Boards of banks should lay down a policy in this regard. Banks should announce the effective date of change in the policy at the earliest.

2. ब्याज दरें

देशी मीयादी जमाराशियों पर अग्रिम

4 जुलाई 1996 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 98/13.01.04/96 के साथ पढ़े जाने वाले रिज़र्व बैंक के 29 सितंबर 1995 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 109/13.01.09/95 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार, देशी मीयादी जमाराशियों की जमानत पर दिये गये 2 लाख रुपये तक के ऋणों और अग्रिमों पर वसूल की जाने वाली ब्याज दर जमा दरों से दो प्रतिशत अंक अधिक है तथा 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों के लिए वसूल की जाने वाली दर बैंक की अपनी मूल उधार दर से कम नहीं है। 24 अगस्त 1996 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 114/13.07.01/96 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह स्वतंत्रता दी गयी है कि वे अपनी उधार दरें निश्चित करें। अब यह निश्चय किया गया है कि जमाकर्ता को देशी जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम के लिए ब्याज दर उस सामान्य उधार दर से अधिक न हो जो बैंक अपने सबसे अच्छे ऋण खातों पर वसूल कर रहे हैं।

2. Lending rates

Advances against domestic term deposits

As per instructions in RBI Circular DBOD No. Dir. BC. 109/13.01.09/95 dated September 29, 1995 read with Circular DBOD No. Dir. BC 98/13.01.04/96 dated July 4, 1996, interest rates chargeable on loans and advances granted against domestic term deposits upto Rs. 2 lakh is two percentage points above deposit rates and for advances over Rs. 2 lakh the interest rate chargeable is not less than bank's own PLR. In terms of Circular DBOD No. Dir. BC. 114/13.07.01/96 dated August 24, 1996 the RRBs have been given freedom to determine their lending rates. It has now been decided that advances against domestic deposits to the depositor, should be at an interest rate not exceeding the normal lending rate which the bank is charging on its best borrowal accounts.

ऊपर उल्लिखित परिवर्तनों की प्रभावी तारीख बैंकों द्वारा यथाशीघ्र घोषित की जायेगी।

भवदीय

(एम. पी. कोठारी)

महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीसी. 86/12.01.001/98-99

20 अगस्त 1998

29 श्रावण 1920 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
की धारा 42(1) प्रारक्षित नकदी निधि
अनुपात में वृद्धि

कृपया हमारे मौद्रिक नीति विभाग का 20 अगस्त 1998 का परिपत्र सं. एमपीडी/बीसी/180/07.01.279/98-99 देखें। वर्तमान विदेशी मुद्रा और मौद्रिक स्थितियों की समीक्षा करने के पश्चात् अस्थायी उपाय के रूप में नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

2. प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात
(सीआरआर) में वृद्धि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों

The effective date of changes mentioned above shall be announced by banks as early as possible.

Yours faithfully

(M.P. Kothari)

General Manager

DBOD.No.BC.86/12.01.001/98-99

August 20, 1998

Shravana 29, 1920 (Saka)

To All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTION 42(1) OF THE RBI ACT,
1934 - INCREASE IN CASH RESERVE
RATIO

Please refer to the Circular No. MPD/BC/180/07.01.279/98-99 dated August 20, 1998 from our Monetary Policy Department. On a review of the current foreign exchange and monetary conditions, it has been decided to effect an increase in Cash Reserve Ratio (CRR) as detailed below, as a temporary measure.

2. Increase in Cash Reserve Ratio
(CRR)

Under Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 all Scheduled

(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से वर्तमान में यह अपेक्षित है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निवल मांग और मीयादी देयताओं (शून्य प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अंतर्गत आने वाली देयताओं को छोड़कर) का 10.0 प्रतिशत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के रूप में रखें। 29 अगस्त 1998 को प्रारंभ पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रखा जाने वाला प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात निवल मांग और मीयादी देयताओं के 10.0 प्रतिशत से एक प्रतिशत अंक बढ़ाकर 11.0 प्रतिशत किया जा रहा है।

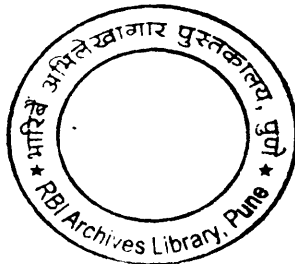
3. यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के रखरखाव संबंधी अन्य सभी निर्धारण बने रहेंगे।

4. 20 अगस्त 1998 की संबंधित अधिसूचना बैंपवि. सं. बीसी. 85/12.01.001/98-99 की एक प्रति संलग्न है।

5. हम यह दुहराते हैं कि विधि के अंतर्गत किये गये प्रावधानों के अनुसार कुछ देयताओं पर शून्य प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के निर्धारण सहित देयताओं की विभिन्न श्रेणियों पर अलग-अलग निर्धारणों को देखते हुए कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखा जाने वाला प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 3 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

भवदीय

(एन.के. सरकार)
महा प्रबंधक



Commercial Banks [excluding Regional Rural Banks (RRBs)] are, at present, required to maintain with the Reserve Bank of India a Cash Reserve Ratio (CRR) of 10.0 per cent of the Net Demand and Time Liabilities (NDTL) (excluding liabilities subject to Zero CRR prescription). Effective from the fortnight beginning August 29, 1998, the CRR to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding RRBs) is being increased by one percentage point from 10.0 percent to 11.0 percent of NDTL.

3. It may be mentioned that all other prescriptions regarding maintenance of incremental CRR under Section 42(1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934 would continue.

4. A copy of the relative notification DBOD No. BC 85/12.01.001/98-99 dated August 20, 1998 is enclosed.

5. We may reiterate that in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities including Zero prescription of CRR on certain liabilities as stipulated under the law, effective CRR maintained by scheduled commercial banks on total Net Demand and Time Liabilities should not be less than 3 percent.

Yours faithfully

(N.K. Sarkar)
General Manager

20 अगस्त 1998
29 श्रावण 1920 (शक)

August 20, 1998
Shravana 29, 1920 (Saka)

अधिसूचना

NOTIFICATION

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 23 मार्च 1998 की अपनी अधिसूचना सं. बैंपविवि. बीसी. 21/12.01.001/97-98 का प्रतिस्थापन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) रखा जाने वाला औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 29 अगस्त 1998 से आरंभ परवाड़े से 11 प्रतिशत होगा।

In exercise of the powers conferred by Proviso to sub-section (1) of Section 42 of the RBI Act, 1934 (2 of 1934) and in supersession of its Notification No. DBOD. BC. 21/12.01.001/97-98 dated March 23, 1998, the Reserve Bank of India hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) shall be 11.00 per cent with effect from the fortnight beginning August 29, 1998.

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

(S. Gurumurthy)
Executive Director

भाग VII
ऋण सूचना

SECTION VII
CREDIT INFORMATION

24 मार्च 1998
3 चैत्र 1920 (शक)

March 24, 1998
Chaitra 3, 1920 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और
वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

The Chairmen/
Chief Executive Officers,
All Scheduled Commercial Banks
and Financial Institutions

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

सूचना का प्रकटीकरण -
मुकदमा दायर खातों की सूची
प्रस्तुत करना

**DISCLOSURE OF INFORMATION -
SUBMISSION OF LIST OF SUIT -
FILED ACCOUNTS**

कृपया दिनांक 24 नवंबर 1995 का हमारा परिपत्र सं.बीसी/सीआइएस(डी) सं.135/20.16.002/95-96 देखें जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया है कि वे उसके अनुबंध-I में दिये गये प्रोफार्मा में 31 मार्च और 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार मुकदमा दायर खातों के बारे में जानकारी हमें प्रस्तुत किया करें। रिपोर्ट भेजने में एकरूपता के लिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे दो प्रतियों में प्रस्तुत किये जाने वाले उक्त विवरण में उधारकर्ताओं के नाम वर्णमाला क्रम से दर्शायें।

Please refer to our Circular BC/CIS (D) No. 135/20.16.002/95-96 dated November 24, 1995 advising the banks and financial institutions to furnish to us the information about the suit - filed accounts in a Statement as on 31st March and 30th September, in the proforma given in Annexure-I thereto. For the sake of uniformity in reporting, banks are advised to arrange the names of the borrowers alphabetically in the said Statement to be submitted to us in duplicate.

2. इसके अलावा, यह पाया गया है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा उक्त विवरण अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत किया जाता है जिसकी वजह से समेकित सूची के प्रकाशन में देरी होती है। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त विवरण हमारे

2. Further, it has been observed that there is inordinate delay in the submission of the above Statement by banks and financial institutions, which, in turn, delays the publication of the consolidated list. It may,

पास विवरण की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाए।

3. तदनुसार, कृपया 31 मार्च 1998 को समाप्त छमाही का विवरण 15 अप्रैल 1998 तक अवश्य प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें।

भवदीय

(ओम प्रकाश अग्रवाल)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.बीसी.डीएल.106/20.16.002/98-99

11 नवंबर 1998
19 कार्तिक 1920 (शक)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/वित्तीय संस्थाएं

फ्लॉपी डिस्कट पर चूककर्ताओं की सूची
और मुकदमा दायर खातों का विवरण
प्रस्तुत करना

आपका ध्यान 6 दिसंबर 1996 के हमारे परिपत्र
बैंपविवि.सं.बीसी.डीएल. 156/20.16.002/96 की

therefore, be ensured that the Statement is submitted to us within 15 days from the date of the Statement.

3. Accordingly, arrangements may, please, be made for submission of the Statement for the Half-year ended 31st March 1998 by 15th April 1998 positively.

Yours faithfully,

(O.P. Agarwal)
General Manager

DBOD.No. BC.DL.106/20.16.002/98-99

November 11, 1998
Kartika 19, 1920 (Saka)

The Chairman & Managing Director/
Chief Executive Officer
All Scheduled Commercial Banks/Fls

**SUBMISSION OF LIST OF
DEFAULTERS ON FLOPPY
DISKETTES AND SUBMISSION OF
STATEMENT OF SUITFILED
ACCOUNTS**

Your attention is invited to our circular
DBOD. No. BC. DL. 156/20-16.002/96

ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे चूककर्ताओं की सूची की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि उसमें दर्शाये गये अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकों/कार्यपालक निदेशकों/निदेशकों आदि के नाम वर्तमान नाम हैं अर्थात् वे भारतीय रिज़र्व बैंक को सूची प्रस्तुत करने की तारीख को ऐसे पद पर थे।

कृपया पुष्टि करें कि 23 अप्रैल 1994 के हमारे परिपत्र बैंपवि. सं.बीसी/सीआइएस 47/20.16.002/94 के अनुसार फ्लोपी डिस्कट पर चूककर्ताओं की सूची तथा 24 नवंबर 1995 के हमारे परिपत्र बैंपवि.सं.135/20.16.002/95 के अनुसार मुकदमा दायर खातों की सूची प्रस्तुत करते समय आपके बैंक/आपकी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

2. इसके अलावा, सरकारी उपक्रमों के मामले में, अध्यक्ष/निदेशकों आदि के नाम देने के बजाय “.....सरकार का उपक्रम” जैसे वाक्यांश मात्र का उल्लेख करने की ही जरूरत है।

3. कृपया सुनिश्चित करें कि उक्त अनुदेशों का सावधानी पूर्वक अनुसरण किया जाता है।

भवदीय

(जे.जी. गुप्ता)
उप महा प्रबंधक

dated 6 December 1996 in terms of which banks and FIs are required to check the list of defaulters to ensure that the names of the Chairmen/Managing Directors/Executive Directors/Directors. etc. indicated therein are current ones i.e. they were holding such position as on the date of submission of the list to Reserve Bank of India.

Please confirm that above instructions are followed by your bank/FI while reporting the list of defaulters on floppy diskettes in terms of our Circular DBOD. No. BC/CIS. 47/20.16.002/94 dated 23 April 1994 as well while submitting the list of suitfiled accounts in terms of our circular DBOD. No. 135/20.16.002/95 dated 24 November 1995.

2. Further, in the case of Government undertakings, instead of giving names of Chairman/Directors, etc., a legend such as "Government of.... Undertaking" only need be mentioned.

3. Please ensure that the above instructions are meticulously followed.

Yours faithfully,

(J.G. Gupta)
Deputy General Manager

18 नवंबर 1998
27 कार्तिक 1920 (शक)

November 18, 1998
Kartika 27, 1920 (Saka)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी
अनुसूचित वाणिज्य बैंक और अधिसूचित
वित्तीय संस्थाएं

The Chairmen/Chief Executive Officers
All Scheduled Commercial Banks and
Notified Financial Institutions

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

**चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना
का प्रकटीकरण - मुकदमा दायर खातों
की सूची का प्रकाशन**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
REGARDING DEFAULTING
BORROWERS - PUBLICATION OF
LIST OF SUIT-FILED ACCOUNTS OF
RS. 1 CRORE AND ABOVE**

कृपया 23 अप्रैल 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.
सं. बीसी/सीआइएस/47/20.16.002/94 का
पैराग्राफ 2(iii) देखें, जिसमें यह उल्लेख किया गया
है कि संगृहीत सूचना के आधार पर, भारतीय रिज़र्व
बैंक प्रति वर्ष मुकदमा दायर खातों की सूची बुकलेट
के रूप में प्रकाशित करेगा तथा प्रत्येक छमाही में
उसे अद्यतन करेगा। इस प्रयोजन के लिए 24 नवंबर
1995 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. बीसी.
सीआइएस (डी) सं. 135/20.16.002/95-96 के
अनुबंध I में एक प्रोफार्मा दिया गया था।

Please refer to paragraph 2(iii) of our circular
letter DBOD No. BC/CIS/47/20.16.002/94
dated 23 April 1994 wherein it is mentioned
that based on the information collected, RBI
will be publishing every year in a booklet
form the list of suit-filed accounts and also
an update of the list half-yearly. For the
purpose, a proforma was given in Annexure
I to our circular DBOD No. BC. CIS (D)
No. 135/20.16.002/95-96 dated 24
November 1995.

2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है
कि हर वर्ष सिर्फ 31 मार्च को भारतीय रिज़र्व बैंक
उक्त सूची प्रकाशित करेगा तथा हर छमाही में उसे

2. On a review, it has since been decided
that RBI will publish only the above list as
on 31 March every year and it will not

अद्यतन नहीं किया जाएगा। तदनुसार, आपको 30 सितंबर को मुकदमा दायर खातों का विवरण हमें प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। तथापि आप उक्त प्रोफार्मा में अपेक्षित पूरी जानकारी देते हुए दो प्रतियों में हर वर्ष 31 मार्च को विवरण प्रस्तुत करना जारी रखें।

भवदीय

(जे.जी. गुप्ता)
उप महा प्रबंधक

prepare half-yearly update. Accordingly, you need not submit to us the statement of suit filed accounts as on 30 September. You may, however, continue to submit the above statement as on 31 March each year, in duplicate, giving complete information as required in the proforma mentioned above.

Yours faithfully,

(J.G. Gupta)
Deputy General Manager

भाग VIII
नियुक्तियाँ/ पारिश्रमिक

SECTION VIII
APPOINTMENTS/REMUNERATION

10 जून 1998
20 ज्येष्ठ 1920 (शक)

June 10, 1998
Jyestha 20, 1920 (Saka)

निजी क्षेत्र के सभी बैंकों के
मुख्य कार्यपालक

The Chief Executives of all
Private Sector Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
की धारा 35-बी-निदेशकों को देय बैठक
शुल्क/अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक
अधिकारियों/प्रबंध निदेशकों/निदेशकों
को देय यात्रा और विराम भत्ता

**SECTION 35B OF THE BANKING
REGULATION ACT 1949 - SITTING
FEES PAYABLE TO THE DIRECTORS/
TRAVELLING AND HALTING
ALLOWANCE PAYABLE TO THE
CHAIRMEN AND CHIEF EXECUTIVE
OFFICERS/MANAGING DIRECTORS/
DIRECTORS**

हमें बैंकों से उनके निदेशकों को देय बैठक शुल्क
में संशोधन के संबंध में अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं।
यह निर्णय लिया गया है कि बैंक अब से अपने बोर्ड
के अनुमोदन से कंपनी अधिनियम, 1956 के
प्रावधानों के अनुपालन के अध्वधीन बैंक के
निदेशकों को देय बैठक शुल्क तथा अध्यक्ष और
मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक और
अन्य निदेशकों को देय यात्रा और विराम भत्ता
निर्धारित कर सकते हैं।

We have been receiving requests from banks
seeking revision in the sitting fees payable
to their directors. It has been decided that
banks may henceforth fix the sitting fees
payable to the directors of the bank with the
approval of their Board subject to
compliance with the provisions of the
Companies Act 1956, as well as the
Travelling and Halting Allowance payable
to the Chairman and Chief Executive
Officer/Managing Director and other
directors.

2. अब से बैंकों को इस संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35-बी के अंतर्गत अनुमोदन के लिए हमसे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चन्द्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

2. Banks need not henceforth approach us for approval under Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949 in this regard.

Yours faithfully

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

भाग IX
विवरणी

SECTION IX
RETURNS

10 जनवरी 1998
20 पौष 1919 (शक)

January 10, 1998
Pausha 20, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
की धारा 26 फार्म IX में विवरण प्रस्तुत
करना - दावा न की गयी जमाराशियाँ

**SECTION 26 OF BANKING
REGULATION ACT. 1949 -
SUBMISSION OF RETURN IN FORM
IX-UNCLAIMED DEPOSITS**

जैसा कि आप जानते हैं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 के अनुसार हर बैंकिंग कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति के बाद तीस दिन के भीतर निर्धारित फार्म (IX) एवं निर्धारित तरीके से भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसे कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार भारत में ऐसे सभी खातों के बारे में जिनका दस वर्ष तक परिचालन नहीं हुआ हो, एक विवरण भेजें।

As you are aware that in terms of Section 26 of Banking Regulation Act, 1949 every banking company is required to submit within thirty days after the close of each calendar year a return in prescribed form (form IX) and manner to the Reserve Bank of India as at the end of such calendar year of all accounts in India, which have not been operated upon for ten years.

2. इस संबंध में, यह पाया गया है कि कई बैंक निर्धारित समय का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके कारण दावा न की गयी जमाराशियों का समेकित विवरण भारत सरकार को देर से प्रस्तुत किया जाता है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को तथा हमारे पास भी यह विवरण निर्धारित समय के अन्दर भेजें।

2. In this connection, it is observed that many banks are not adhering to the prescribed time schedule which results in late submission of consolidated statement of unclaimed deposits to Government of India. You are, therefore advised to submit the return within the stipulated period, to the concerned regional office of this department and to us.

3. हमारे उपर्युक्त अनुदेशों का यदि अनुपालन नहीं किया जाता तो उस पर गंभीर रूख अपनाया जाएगा।

भवदीय

(डी.वी. झवेरी)

महा प्रबंधक

3. Non-compliance of our above instructions in the matter will be viewed seriously.

Yours faithfully

(D.V. Jhaveri)

General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी.15/12.05.005/97-98

24 फरवरी 1998

5 फाल्गुन 1919 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

मुख्य वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्रों से संबंधित
विवरणियों की समीक्षा, युक्तिकरण और
पुनर्रचना

जैसा कि आप जानते हैं, बैंकों का कार्य-भार कम करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के वर्तमान ढांचे की जांच करने के लिए फरवरी 1995 में एक परामर्शक नियुक्त किया था। बैंकों द्वारा बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

DBOD.No.BC.15/12.05.005/97-98

February 24, 1998

Phalgun 5, 1919 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

**REVIEW, RATIONALISATION AND
REDESIGNING OF RETURNS
RELATING TO CORE COMMERCIAL
BANKING AREAS**

As you are aware, with the objective of reducing the workload on banks, Reserve Bank of India had appointed a Consultant in February 1995 to look into the present set up of returns to be submitted by banks to Reserve Bank of India. A review was

को प्रस्तुत की जाने वाली मौजूदा विवरणियों/विवरणों/समीक्षाओं की परामर्शक ने समीक्षा की थी। परामर्शक की सिफारिशों के फलस्वरूप, यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को तत्काल प्रभाव से 16 विवरणियां (अनुबंध में दिये गये ब्यौरे के अनुसार) बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसके आगे, अनुसूचित वाणिज्य बैंक अन्य सभी विवरणियां भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विभागों को प्रस्तुत करते रहें।

भवदीय

(डी.वी. झवेरी)

महा प्रबंधक

undertaken by the Consultant in respect of existing returns / statements / reviews submitted by banks to Department of Banking Operations and Development. Consequent upon the recommendations made by the Consultant, it has been decided that the scheduled commercial banks need not send 16 returns (as detailed in the Annexure) to the Department of Banking Operations and Development with immediate effect. All other returns may continue to be submitted by the scheduled commercial banks to the respective departments of Reserve Bank of India as hitherto.

Yours faithfully

(D.V. Jhaveri)

General Manager

अनुबंध - I
विवरणियां समाप्त करना

क्र.सं. विवरणी/विवरण का नाम	आवधिकता	भा.रि. बैंक में प्राप्तकर्ता विभाग
1. बैंकों के श्रेणीवार अतिदेय अग्रिम	छमाही	बैंपविवि.
2. अधिकारी सेवा विनियमावली का विनियम 19-समीक्षा और अनिवार्य सेवानिवृत्ति	तिमाही	- वही -
3. बैंकों की कार्य-निष्पादकता मूल्यांकन के मानदंड	वार्षिक	- वही -
4. बैंकों के कार्य-निष्पादन बजट	वार्षिक	- वही -
5. सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता का विश्लेषण	वार्षिक	- वही -
6. स्टाफ स्थिति का विवरण	छमाही	- वही -
7. वर्ष के दौरान खोली गयी/बंद की गयी शाखाएं, लंदन कार्यालयों के नाम और पते तथा भारत स्थित समाशोधन गृहों के सदस्य और उप-सदस्य	दो वर्ष में एक बार	- वही -
8. विदेशी बैंकों द्वारा परिसरों का अधिग्रहण	वार्षिक	- वही -
9. जारी किये गये स्टॉक इन्वेस्ट की कुल संख्या और मूल्य दर्शाने वाला विवरण	तिमाही	- वही -
10. पूंजीगत निधियों, जोखिम आस्तियों आदि का विवरण	वार्षिक	- वही -
11. वरिष्ठ कार्यपालकों की सूची दर्शाने वाला विवरण	छमाही	- वही -
12. कंपनी शेयर/डिबेंचर धारिता	छमाही	- वही -
13. दान आदि की समीक्षा	वार्षिक	- वही -
14. बाह्य अलंकरण की समीक्षा	वार्षिक	- वही -
15. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाले निदेशकों का विवरण	छमाही	- वही -
16. 20 अति अवरुद्ध खाते और मुकदमा दायर किये गये 100 शीर्ष खाते	तिमाही	- वही -

ANNEXURE - I
Discontinuance of Returns

Sr. No.	Name of the Return/Statement	Periodicity	Receiving department in RBI
1.	Category-wise overdue advances of banks	Half yearly	DBOD
2.	Regulation 19 of Officers' Service Regulations - Review and Compulsory Retirement	Quarterly	"
3.	Parameters for judging the performance of banks	Annual	"
4.	Performance Budgets of banks	Annual	"
5.	Analysis of profitability of public sector banks	Annual	"
6.	Statement of staff position	Half yearly	"
7.	Branches opened/closed during the year, names and addresses of London Offices and members and sub-members of clearing houses in India	Once in two years	"
8.	Acquisition of premises by foreign banks	Annual	"
9.	Statement indicating total numbers and value of stock invest issued	Quarterly	"
10.	Statement of Capital Funds, Risk Assets etc.	Annual	"
11.	Statement showing list of senior executives	Half yearly	"
12.	Holding of corporate shares/debentures	Half yearly	"
13.	Review of donations	Annual	"
14.	Review on Window-dressing	Annual	"
15.	Statement of Directors belonging to SC/ST	Half yearly	"
16.	Top 20 sticky accounts and Top 100 suit filed accounts	Quarterly	"

24 अगस्त 1998
2 भाद्र 1920 (शक)

August 24, 1998
Bhadra 2, 1920 (Saka)

प्रति, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

To All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
की धारा 42 (2)- फार्म ए में विवरणी

SECTION 42(2) OF RESERVE BANK
OF INDIA ACT, 1934 - RETURN IN
FORM A

कृपया 23 जनवरी 1993 का हमारा परिपत्र
बैंपविवि. सं. 71/12.01.001/93 देखें, जिसके
अनुसार भारत स्थित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों
से अपेक्षा की गयी है कि वे प्रारक्षित नकदी निधि
अनुपात के रखरखाव से छूट प्राप्त श्रेणीवार
जमाराशियों के ब्यौरे फार्म 'ए' के अनुबंध के रूप
में सूचित करें। वित्तीय क्षेत्र के क्रमिक अविनियमन
और बैंकों के तुलनपत्रों पर उसके परिणामी प्रभाव
को देखते हुए वाणिज्य बैंकों की आंकड़ा रिपोर्टिंग
प्रणाली को आशोधित किये जाने की आवश्यकता
है क्योंकि धारा 42(2) संबंधी विवरणियों के मौजूदा
रूप में निम्नलिखित शामिल नहीं हो पाते हैं :

Please refer to our Circular DBOD No. 71/
12.01.001/93 dated January 23, 1993 in
terms of which all the Scheduled
Commercial Banks in India are required to
indicate category wise deposits exempted
from maintenance of Cash Reserve Ratio
(CRR) by way of an Annexure to Form-A.
With gradual deregulation of the financial
sector and the consequential impact on
Balance Sheets of banks, a need has arisen
to modify the data reporting system of
commercial banks, as the Section 42(2)
Returns in the present form do not capture

- (i) वाणिज्यिक क्षेत्र को कुल संसाधन
प्रवाह तथा
- (ii) बैंकिंग प्रणाली द्वारा दिया गया निवल.
विदेशी मुद्रा ऋण ।

- (i) the total resources flow to the
commercial sector and
- (ii) the net foreign currency
exposure of the banking system.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा
डॉ. वाई. वी. रेड्डी, उप गवर्नर की अध्यक्षता में

2. The 'Working Group on Money
Supply : Analytics and Methodology of

गठित 'वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई : अनालिटिक्स एण्ड मेथडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन' ने संस्तुति की है कि मूल फार्म 'ए' में परिवर्तन किये बिना निम्नलिखित को शामिल कर धारा 42(2) संबंधी विवरणियों में उपयुक्त विस्तार किया जाये:

- (i) फार्म 'ए' का एक ज्ञापन, जिसमें प्रदत्त पूंजी, प्रारक्षित निधि, जमा प्रमाणपत्र, तथा मीयादी जमाराशियों की परिपक्वता की संरचना संबंधी आंकड़े शामिल किये गये हों तथा निम्नलिखित दो अनुबंध, अर्थात्
- (ii) अनुबंध 'ए' - इसमें विभिन्न योजनाओं यथा, विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) आदि के रूप में बाह्य देयताओं के अलग-अलग ब्यौरे, विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा विदेशी मुद्रा में भारत में दिये गये बैंक ऋण, और विभेदक/शून्य प्रारक्षित निधि संबंधी निर्धारणों के अंतर्गत आने वाली देशी देयताओं संबंधी आंकड़े शामिल किये गये हों तथा
- (iii) अनुबंध 'बी' - इसमें तीन श्रेणी की प्रतिभूतियों अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों तथा अन्य बाज़ार लिखतों में बैंकों के निवेश संबंधी आंकड़ों के ब्यौरे शामिल किये गये हों।

Compilation' set up by Governor, Reserve Bank of India under the Chairmanship of Dr. Y.V. Reddy, Deputy Governor, has recommended to suitably expand the Section 42(2) Returns without altering the Principal Form A, but by adding

- (i) a Memorandum to Form A, incorporating data on paid up capital, reserves, certificates of deposits, and maturity structure of time deposits and two Annexures, viz
- (ii) Annexure A - incorporating data on break up of external liabilities in terms of various schemes eg., FCNR (B) etc., foreign currency assets and bank credit in India in foreign currency, and domestic liabilities subject to differential/zero reserve prescriptions and
- (iii) Annexure B - incorporating detailed data on banks' investments in three categories of securities viz., government securities, other approved securities, and other market instruments.

3. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सूचना देने के लिए नियत शुक्रवार 09 अक्टूबर 1998 से भारत स्थित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को फार्म 'ए' में विवरणियां प्रस्तुत करने के

3. Accordingly, it has been decided that from the **Reporting Friday October 09, 1998** all the Scheduled Commercial Banks in India should submit Form-A Returns

साथ संलग्न किये गये अनुसार निर्धारित फार्मेट में अनुबंध 'ए' और 'बी' भी प्रस्तुत करना है। अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें।

भवदीय

(एन.के. सरकार)
महा प्रबंधक

along with the Annexure A&B in the prescribed format, as enclosed. We shall be glad if you will please take necessary action urgently in the matter.

Yours faithfully

(N.K. Sarkar)
General Manager

फार्म 'क'

Form A

(जो अनुसूचित बैंक राज्य सहकारी बैंक नहीं है उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

(To be submitted by a scheduled bank which is not a state Central Office-operative bank)

.... शुक्रवार¹ को कारोबार बंद होने की स्थिति का विवरण

Statement of position at the close of business on Friday¹—

(रुपये निकटतम हजार राशि में पूर्णांकित किये जाएं)

(Rupees rounded off to the nearest thousand)

बैंक का नाम : _____

Name of the Bank : _____

I. भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं²

(क) बैंकों से प्राप्त मांग और मीयादी जमाराशियां

(ख) बैंकों से लिये गये उधार³

(ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं⁴

I का जोड़

II. भारत में अन्यो के प्रति देयताएं

(क) सकल जमाराशियां (बैंकों से प्राप्त जमाराशियों को छोड़कर)
(i) मांग

I. Liabilities to the Banking System in India²

(a) Demand and time deposits from Banks

(b) Borrowings from Banks³

(c) Other Demand and Time Liabilities⁴

Total of I

II. Liabilities to Others in India

(a) Aggregate Deposits (Other than from Banks)

(i) Demand

- (ii) मीयादी
- (ख) लिये गये उधार⁵
- (ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं

II का जोड़

I + II का जोड़

III. भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास की आस्तियां

- (क) बैंकों के पास जमाराशियां
 - (i) चालू खातों में
 - (ii) अन्य खातों में
- (ख) मांग और अल्पसूचना पर देय राशि
- (ग) बैंकों को दिये गये अग्रिम अर्थात् बैंकों पर बकाया अग्रिम
- (घ) अन्य आस्तियां

III का जोड़

IV. भारत में नकदी (अर्थात् हाथ में नकदी)

V. भारत में निवेश (बही मूल्य पर)

- (क) खजाना बिलों, खजाना जमा रसीदों, खजाना बचत जमा प्रमाणपत्रों और डाक दायित्वों सहित

- (ii) Time
- (b) Borrowings⁵
- (c) Other demand and time liabilities

Total of II

Total of I + II

III. Assets with the Banking System in India

- (a) Balances with Banks
 - (i) In current account
 - (ii) In other accounts
- (b) Money at call and short notice
- (c) Advances to banks i.e., dues from banks
- (d) Other Assets

Total of III

IV. Cash in India (i.e., cash in hand)

V. Investments in India (at book value)

- (a) Central and State Governments securities including Treasury Bills,

केन्द्रीय और राज्य
सरकार की
प्रतिभूतियां

Treasury Deposits
Receipts, Treasury
Savings Deposit
Certificates and
Postal obligations

(ख) अन्य अनुमोदित
प्रतिभूतियां

(b) Other approved
Securities

V का जोड़

Total of V

VI. भारत में बैंक ऋण
(अंतर-बैंक अग्रिमों को
छोड़कर)
(क) ऋण, नकदी ऋण
और ओवरड्राफ्ट

(ख) खरीदे और भुनाये गये
अंतर्देशीय बिल

(i) खरीदे गये बिल
(ii) भुनाये गये बिल

(ग) खरीदे और भुनाये गये
विदेशी बिल

(i) खरीदे गये बिल
(ii) भुनाये गये बिल

VI. Bank Credit in India
(excluding inter-bank
advances)
(a) Loans, cash
credits and
overdrafts
(b) Inland Bills
purchased and
discounted
(i) Bills Purchased
(ii) Bills
Discounted
(c) Foreign Bills
purchased and
discounted
(i) Bills purchased
(ii) Bills
discounted

VI का जोड़

Total of VI

III + IV + V + VI का जोड़

Total of III + IV + V + VI

अ. भारतीय रिज़र्व बैंक
अधिनियम, 1934 की धारा

A. Net Liabilities for
the purpose of

42 के प्रयोजन के लिए शुद्ध देयताएं = बैंकिंग प्रणाली की शुद्ध देयताएं + भारत में अन्यो के प्रति देयताएं अर्थात् (I - III) + II, यदि (I - II) धन का अंक हो अथवा केवल II, यदि (I-III) ऋण का अंक हो

Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 = Net Liability to the Banking System + Liabilities to Others in India i.e., (I-III) + II, if (I-II) is a plus figure or II only, if (I-III) is a minus figure.

आ. अधिनियम के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे जाने के लिए न्यूनतम जमाराशि (निकट तम रुपये तक पूर्णांकित)

B. Amount of minimum deposit required to be kept with the Reserve Bank of India under the Act (rounded off to the nearest rupee)

इ. बचत बैंक खाता (देखें विनियम 7) भारत में मांग देयताएं भारत में मीयादी देयताएं

C. Savings Bank account (vide Regulation 7)
Demand liabilities in India
Time liabilities in India

स्थान :
तारीख :

Place :
Date :

फार्म 'क' का ज्ञापन

1. प्रदत्त पूंजी

Memorandum to Form A

1. Paid-up Capital

- 1.1 प्रारक्षित निधियां
2. मीयादी देयताएं
- 2.1 अल्पकालिक
- 2.2 दीर्घकालिक

3. जमा प्रमाणपत्र
4. निवल मांग और मीयादी देयताएं (शून्य प्रारक्षित निधि संबंधी निर्धारण के अंतर्गत आनेवाली देयताओं को घटाने के बाद अनुबंध क)
5. प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की चालू दर के अनुसार रखी जानेवाली जमाराशियां
6. अन्य कोई देयताएं जिन पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 और 42(1ए) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव किया जाना है।
7. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 और 42(1ए) के अंतर्गत रखरखाव के लिए अपेक्षित कुल प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)।

¹जहां अनुसूचित बैंक के एक या अधिक कार्यालयों में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अंतर्गत शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश हो, वहां विवरणी में ऐसे कार्यालय या कार्यालयों के संबंध में पिछले कार्यदिवस के आंकड़े दिये जायेंगे,

- 1.1 Reserves
2. Time Deposits
- 2.1 Short-term
- 2.2 Long-term
3. Certificates of Deposits
4. Net Demand and Time Liabilities (after deduction of liabilities under zero reserve prescription, Annexure A)
5. Amount of Deposits required to be maintained as per current rate of CRR
6. Any other liability on which CRR is required to be maintained as per current RBI instructions under section 42 and 42(1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934.
7. Total CRR required to be maintained under Section 42 and 42(1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

¹Where Friday is a public holiday under the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881) for one or more offices of a Schedule Bank, the return shall give the preceding working day's figure in respect of such office or offices,

पर फिर भी उसे उस शुक्रवार से संबंधित माना जायेगा।

²विवरणी में जहां कहीं भी “बैंकिंग प्रणाली” या “बैंक” अभिव्यक्ति आती हो उसका अभिप्राय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(I) के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (घ) के उपखंड (i) से (vi) तक में संदर्भित बैंक और अन्य किसी वित्तीय संस्था से है।

³क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में, प्रवर्तक बैंक को छोड़कर।

⁴यदि I (ग) में II (ग) से अलग आंकड़ा देना संभव न हो, तो उसे II(ग) के सामने दर्शाये गये आंकड़े में शामिल किया जाये। ऐसी स्थिति में बैंकिंग प्रणाली के प्रति निवल देयताओं का आकलन III के जोड़ पर I(क) और I(ख) के जोड़ के अतिरिक्त, यदि कोई हो, के रूप में किया जायेगा।

⁵भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय निर्यात-आयात बैंक को छोड़कर।

but shall nevertheless be deemed to relate to that Friday.

²The expression "Banking System" or "Banks" Wherever it appears in the return means the banks and any other financial institutions referred to in sub-clause (i) to (vi) of clause (d) of the Explanation below Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

³In case of RRBs, apart from the sponsor bank.

⁴If it is not possible to provide the figure against I(c) separately from II(c), the same may be included in the figure against IIc. In such a case, the net liability to the banking system will be worked out as the excess, if any of the aggregate of 1(a) and 1(b) over the aggregate of III.

⁵Other than from Reserve Bank of India, Industrial Development Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development and Export-Import Bank of India.

अनुबंध क

(राशि निकटतम हजार रुपयों में)

बैंक का नाम:

मद (1)	बही मूल्य पर बकाया (2)	पुनर्मूल्यन पर मूल्य (3)	ब्याज (4)
देयताएं			
भारत में दूसरों के प्रति देयताएं I. अनिवासी जमाराशियां (I.1+I.2+I.3+I.4) I.1 अनिवासी बाह्य रुपया खाता (एनआरई) I.2 अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय रुपया खाता (एनआरएनआर) I.3 विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक योजना (एफसीएनआर (बी)) (I.3.1+I.3.2) I.3.1 अल्पावधि ¹ I.3.2 दीर्घावधि ² I.4 अन्य (नामोल्लेख करें)			
II. अन्य जमाराशियां/योजनाएं (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6) II.1 विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा II.2 निवासी विदेशी मुद्रा खाते II.3 भारतीय निर्यातकों के एस्क्रो खाते II.4 पोतलदान से पूर्व ऋण के लिए विदेशी ऋण सुविधा खाता और विदेशी बिलों की पुनर्भुनाई II.5 एसीयू(अम.डॉलर) खाते में जमाशेष II.6 अन्य (नामोल्लेख करें)			
III. भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति विदेशी मुद्रा देयताएं (III.1+III.2)			

(1)	(2)	(3)	(4)
III.1 अंतर बैंक विदेशी मुद्रा जमाराशियां III.2 अंतर बैंक विदेशी मुद्रा ऋण			
IV. विदेशी ऋण ³ आस्तियां			
(I) भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां I.1 विदेशी मुद्रा ऋण I.2 अन्य			
(II) भारत में अन्य के पास आस्तियां II.1 भारत में विदेशी मुद्रा में बैंक ऋण ⁴ II.2 अन्य			
(III) विदेश में विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁵			
V. दूसरों के प्रति बाह्य देयताएं, विभेदक/शून्य सीआरआर निर्धारण के अधीन (I+II)			
VI. बाह्य देयताएं, पूर्णतया सीआरआर निर्धारण के अधीन (IV)			
VII. शुद्ध अंतर बैंक देयताएं (फार्म 'ए' का I-III)			
VIII. कोई अन्य देयता जो शून्य निर्धारण के अंतर्गत आती हो			
IX. देयताएं, शून्य सीआरआर निर्धारण के अधीन (V+VII+VIII)			
ज्ञापन मर्दे 1. एफसीएनआर (बी) रिपोर्टिंग पखवाड़े में शेष 11.04.1997 को शेष 11.04.1997 से वृद्धि			

प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर

1.-----

पदनाम

2.-----

पदनाम

¹एक वर्ष या उससे कम की संविदागत अवधिपूर्णता

²एक वर्ष से अधिक की संविदागत अवधिपूर्णता

³उस अंश से संबंधित जिसे रुपयों में बदला (स्वैप) नहीं गया है।

⁴एफसीएनआर (बी) जमाराशियों में से ऋण

⁵(i) विदेश में रखी गयी शेष राशियां (अर्थात् नोस्ट्रो खाते में नकदी, एसीयू (अमरिकी डालर) में नामे शेष खाता और एसीयू देशों के वाणिज्य बैंकों में जमाशेष (ii) अल्पावधि विदेशी जमाराशियां तथा पात्र प्रतिभूतियों में निवेश (iii) विदेशी मुद्रा बाज़ार लिखत, खजाना बिलों सहित और (iv) विदेशी शेयर और बांड

ANNEXURE A

Name of the Bank :

(Amount in Rupees rounded off to the nearest thousand)

Items	Outstanding at book value	Revaluation value	Interest
1	2	3	4
Liabilities Liabilities to others in India I. Non-Resident Deposits (I.1+I.2+I.3+I.4) I.1 Non-Resident External Rupee Account (NRE) I.2 Non-Resident Non Repatriable Rupee Account (NRNR) I.3 Foreign Currency Non-Resident Banks Scheme [FCNR (B)](I.3.1 + I.3.2) I.3.1 Short-term ¹ I.3.2 Long-term ² I.4 Others (to be specified)			
II. Other Deposits/Schemes (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6) II.1 Exchange Earner's Foreign Currency II.2 Resident Foreign Currency Accounts II.3 ESCROW Accounts by Indian Exporters II.4 Foreign Credit Line for Pre-shipment Credit account and Overseas Rediscounting of Bills II.5 Credit Balances in ACU (US dollar) Account II.6 Others (to be specified)			
III. Foreign Currency Liabilities to the Banking System in India (III.1+III.2) III.1 Inter-bank Foreign Currency Deposits			

1	2	3	4
III.2 Inter-bank Foreign Currency Borrowings			
IV. Overseas Borrowings³ Assets (I) Assets with the banking system in India I.1 Foreign Currency lending I.2 Others (II) Assets with others in India II.1 Bank Credit in India in Foreign Currency ⁴ II.2 Others (III) Overseas foreign currency assets⁵			
V. External Liabilities to Others subject to differential/zero CRR prescription (I+II)			
VI. External Liabilities fully subject to CRR Prescription (IV)			
VII. Net Inter-Bank Liabilities (I-III of Form 'A')			
VIII. Any other liabilities coming within the purview of zero prescription			
IX. Liabilities subject to zero CRR prescription (V+VII+VIII)			
Memo items 1. FCNR(B) Balance as on the Reporting Fortnight Balance as on 11.04.1997 Increase over 11.04.1997			

Signature of Authorised officials

1.-----
Designation

2.-----
Designation

¹Of contractual maturity of one year or less.

²Of contractual maturity of more than one year.

³Pertains to the portion not swapped into Rupees.

⁴Loans out of FCNR(B) deposits.

⁵Include balances held abroad (i.e., cash component of Nostro account, debit balances in ACU (US dollar) account and credit balances in the commercial banks of ACU countries) ii) short term foreign deposits and investments in eligible securities, iii) foreign money market instruments including Treasury Bills, and iv) foreign shares and bonds.

अनुबंध ख

(राशि निकटतम हजार रुपयों में)

बैंक का नाम:

मद	बही मूल्य पर बकाया	पुनर्मूल्यन पर मूल्य
1	2	3
देयताएं		
I. अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश (I.1+I.2) I.1 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश [I.1.1+I.1.2 = फार्म ए की मद V (क)] I.1.1 अल्पावधि¹ I.1.2 दीर्घावधि² I.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश (= फार्म ए की मद V(ख))		
II. गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश (II.1+II.2+II.3+II.4) निम्नलिखित में निवेश II.1 वाणिज्यिक पत्र (कमर्शियल पेपर) II.2 भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा अन्य पारस्परिक निधियों के यूनिट II.3 निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये शेयर II.3.1 सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान II.3.2 निजी कंपनी क्षेत्र II.3.3 सरकारी वित्तीय संस्थान II.4 बांड/डिबेंचर निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये II.4.1 सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान II.4.2 निजी कंपनी क्षेत्र II.4.3 सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थानों		
ज्ञापन मर्दे		
1. प्राथमिक बाज़ार में शेयरों/डिबेंचरों/बांडों में अभिदान 2. निजी तौर पर रखे गये निगमों में अभिदान		

प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर

1.-----

पदनाम

2.-----

पदनाम

¹एक वर्ष या उससे कम की संविदागत अवधिपूर्णता

²एक वर्ष से अधिक की संविदागत अवधिपूर्णता

ANNEXURE B

Name of the Bank :

(Amount in Rupees rounded off to the nearest thousand)

Items	Outstanding at book value	Revaluation value
1	2	3
I. Investments in Approved Securities (I.1 + I.2) I.1 Investments in Government securities (I.1.1+I.1.2 = Item V(a) of Form A) I.1.1 Short Term ¹ I.1.2 Long Term ² I.2 Investments in Other Approved Securities (= Item V(b) of Form A)		
II. Investments in Non-Approved Securities (II.1+II.2+II.3+II.4) Investments in II.1 Commercial Paper II.2 Units of Unit Trust of India and other Mutual Funds II.3 Shares issued by II.3.1 Public Sector Undertakings II.3.2 Private Corporate Sector II.3.3 Public Financial Institutions II.4 Bonds/debentures issued by II.4.1 Public Sector Undertakings II.4.2 Private Corporate Sector II.4.3 Public Financial Institutions		
Memo Items		
1. Subscriptions to shares/debentures/bonds in the Primary market. 2. Subscriptions through Private Placements		

Signature of Authorised Officials

1.-----
(Designation)

2.-----
(Designation)

¹Of contractual maturity of one year or less.

²Of contractual maturity of more than one year.

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.118/24.76.002/98

DBOD.No.FSC.BC.118/24.76.002/98

26 दिसंबर 1998
5 पौष 1920 (शक)

December 26, 1998
Pausha 5, 1920 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/
सहायक संस्थाएं

All Scheduled Commercial Banks/
Subsidiaries

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

संविभाग प्रबंधन सेवाओं के लिए सूचना
प्रणाली

INFORMATION SYSTEM FOR
PORTFOLIO MANAGEMENT
SERVICES (PMS)

उक्त विषय पर 18 अक्टूबर 1993 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 183/27.07.003/93-94 देखें। बैंकिंग सांख्यिकी निर्देशन समिति (कमेटी ऑन डाइरेक्शन ऑफ बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स) की सिफारिशों पर यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों/बैंकों की सहायक संस्थाओं को हमारे सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को तीन विवरणियों (बीएसआर - 8ए बीएसआर - 8 बी, बीएसआर - 8 सी) का सेट तत्काल प्रभाव से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

Please refer to our circular DBOD No. BC. 183/27.07.003/93-94 dated october 18, 1993 on the above subject. On the recommendation of the Committee on Direction of Banking Statistics (CDBS), it has been decided that the banks/bank subsidiaries need not submit with immediate effect the set of three returns (BSR - 8A, BSR - 8B, BSR - 8C) to our Department of Statistical Analysis and Computer Services (DESACS).

भवदीय

Yours faithfully

(अर्णव राय)
उप महा प्रबंधक

(Arnab Roy)
Deputy General Manager

भाग X विविध

- (क) शाखा विस्तार
- (ख) बैंकों द्वारा शुरू किये गये गैर-पारंपरिक कार्य-व्यापारी बैंकिंग,
क्रेडिट कार्ड प्रणाली,
किराया खरीद व्यवसाय, आदि
- (ग) बैंकों में ग्राहक सेवा
- (घ) बैंकों में धोखाधड़ी आदि
- (ङ) अन्य

SECTION X

MISCELLANEOUS

- (a) BRANCH EXPANSION
- (b) NON-TRADITIONAL TYPE OF WORK
TAKEN UP BY BANKS-MERCHANT
BANKING, CREDIT CARD SYSTEM,
HIRE-PURCHASE BUSINESS, ETC.
- (c) CUSTOMER SERVICE IN BANKS
- (d) FRAUDS, ETC. IN BANKS
- (e) OTHERS

29 जुलाई 1998
7 श्रावण 1920 (शक)

July 29, 1998
Shravana 7, 1920 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Indian Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

**बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
की धारा 23-ग्रामीण शाखाओं को
ब्लॉक/सेवा क्षेत्र से बाहर ले जाना और
उन्हें बंद करना**

**SECTION 23 OF THE BANKING
REGULATION ACT, 1949-SHIFTING
OF RURAL BRANCHES OUTSIDE
THE BLOCK/SERVICE AREA AND
CLOSURE OF RURAL BRANCHES**

कृपया आप 20 मई 1992 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 132/22.01.001/92 देखें। उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 3 (I) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना बैंक अपनी ग्रामीण/कस्बाई (अर्ध शहरी) शाखाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु वे ऐसा इस शर्त पर ही कर सकते हैं कि मौजूदा और प्रस्तावित केन्द्र उसी ब्लॉक और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हों और दूसरे स्थान पर शाखा उन गांवों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर सकेगी जो गांव सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण की योजना के अंतर्गत आबंटित किये गये हैं। बैंकों को यह भी विदित है कि ग्रामीण शाखाओं को ब्लॉक/सेवा क्षेत्र के बाहर ले जाने की हमारी अनुमति जिला परामर्शदात्री समिति और राज्य सरकार (संस्थागत वित्त निदेशालय) द्वारा इस तरह के प्रस्तावों के अनुमोदन के आधार पर होती है। हमने इस मामले की समीक्षा की है और अब यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण शाखाओं को ब्लॉक/सेवा क्षेत्र के बाहर ले जाने

Please refer to our Circular DBOD No. BL.BC. 132/22.01.001/92 dated 20th May 1992. In terms of paragraph 3(I) thereof, banks are free to shift their branches at rural/ semi-urban centres without obtaining prior approval of Reserve Bank of India, subject to the conditions that the existing and the proposed centres are within the same Block and Service Area and the relocated branch would be able to cater adequately to the banking needs of the villages allocated under the Scheme of Service Area Approach. Banks are also aware that the shifting of rural branches outside the Block/Service Area is being allowed by us on the basis of approval of such proposals by the District Consultative Committee and the State Government (Directorate of Institutional Finance). The matter has been reviewed by us and it has now been decided that the

की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जिला परामर्शदात्री समिति और राज्य सरकार के अनुमोदन पर जोर दिये बिना दी जाये, जो निम्नलिखित मामलों में होगी :

- (i) जो शाखाएं पांच वर्ष या उससे अधिक समय से हैं और पिछले तीन वर्षों में लगातार घाटा उठा रही हैं।
- (ii) जो शाखाएं ऐसे केन्द्रों पर हैं जहां की समस्यायें बैंकों के नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे कि प्रायः बाढ़, भूस्खलन की आशंका से ग्रस्त अथवा बांध (डैम) के निर्माण के कारण पानी में डूबने की आशंका अथवा भूमिगत अग्नि इत्यादि।
- (iii) कानून और व्यवस्था की समस्या अथवा आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण बैंक की सम्पत्ति/स्टाफ सदस्यों को क्षति की आशंका के कारण शाखा को अन्यत्र ले जाना आवश्यक हो।
- (iv) वे मामले जहां शाखा का परिसर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है अथवा जल गया/नष्ट हो गया है और उस केन्द्र/ब्लॉक/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त परिसर उपलब्ध नहीं है।

2. इसके अतिरिक्त 24 अगस्त 1993 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 152/22.01.001/93 के अनुसार ग्रामीण केन्द्रों पर घाटा उठाने वाली शाखाओं को बंद करने की अनुमति उस स्थिति में नहीं है जब उस केन्द्र पर एक ही वाणिज्य बैंक शाखा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को

shifting of rural branches outside the Block/Service Area may be allowed by Reserve Bank of India without insisting on the approval of DCC and State Government in the following cases :

- (i) Branches which are in existence for five years or more and are incurring losses continuously for the last three years.
- (ii) Branches located at centres suffering from problems beyond control of the banks, such as, prone to floods, land slides or likely to be sub-merged in waters due to construction of dams, or having underground fires, etc.
- (iii) Shifting is necessitated on account of law and order problem or terrorists' activities posing threats to bank property/staff members.
- (iv) Cases where the branch premises are in a dilapidated condition or burnt/destroyed and no suitable premises are available at the centre/Block/Service Area.

2. Further, in terms of Circular DBOD No. BL.BC. 152/22.01.001/93 dated 24th August 1993, closure of loss-making branches at rural centres is not permissible if there is a single commercial bank branch (excluding RRBs) at the centre. However,

छोड़कर) हो। परन्तु जिन ग्रामीण केन्द्रों पर दो या अधिक वाणिज्य बैंक शाखायें (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) हैं वहां किसी एक शाखा को बंद करने का निर्णय संबंधित बैंकों द्वारा परस्पर परामर्श करके लिया जा सकता है और उसके लिए हमारी अनुमति इस शर्त पर होती है कि उस प्रस्ताव का अनुमोदन जिला परामर्शदात्री समिति ने किया हो और वह संबंधित राज्य सरकार (संस्थागत वित्त निदेशालय) के माध्यम से प्राप्त हुआ हो। अब यह निर्णय लिया गया है कि घाटा उठाने वाली ग्रामीण शाखाओं को राज्य सरकार और जिला परामर्शदात्री समिति की संलग्नता के बिना बंद करने की अनुमति दी जाये। परन्तु अन्य मामलों को बैंकों को स्वयं निपटाना होगा, जैसे कि बंद करने के लिए प्रस्तावित शाखा की आस्तियों और देयताओं का उसी बैंक या भिन्न बैंक को अंतरण, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत गांवों का पुनः आबंटन, स्टाफ का पुनः नियोजन आदि।

3. यह भी निर्णय लिया गया है कि घाटा उठाने वाली ग्रामीण शाखाओं को अन्यत्र ले जाने अथवा बंद करने के लिए अनुमति अब भविष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महा प्रबंधक/प्रभारी महाप्रबंधक द्वारा दी जायेगी। तदनुसार बैंकों को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में वे अपने निदेशक मंडल से विधिवत् अनुमोदित अपने प्रस्ताव पूर्व अनुमोदन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें जिसके कार्यक्षेत्र में केन्द्र आता है।

भवदीय

(ओम प्रकाश अग्रवाल)

महा प्रबंधक

at rural centres served by two or more commercial bank branches (excluding RRBs), decision for closure of one of the branches may be taken by the concerned banks by mutual consultation and the same is allowed by us subject to approval of the proposal by the District Consultative Committee and routing of the same through the concerned State Government (DIF). It has now been decided to allow closure of loss-making rural branches without involving State Government and DCC. However, the banks will have to themselves settle the other matters, such as, transfer of assets and liabilities of the branch proposed to be closed, to other branches of the same bank or different bank, re-allocation of villages under Service Area Approach, redeployment of staff, etc.

3. It has also been decided that the permission for shifting and closure of loss-making rural branches will hereafter be given by the Chief General Manager/General Manager-in-Charge of the concerned Regional Office of Reserve Bank of India. Accordingly, banks are advised to submit their proposals in this regard, duly approved by their Boards of Directors, to the concerned Regional Office of Reserve Bank of India under whose jurisdiction the centre falls, for prior approval.

Yours faithfully,

(O.P. Agarwal)

General Manager

2 जून 1998
12 ज्येष्ठ 1920 (शक)

June 2, 1998
Jyestha 12, 1920 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

All Scheduled Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत रिपोर्टें/
समीक्षा

REPORTS/REVIEWS SUBMITTED
BY BANKS TO RBI

हाल ही में हमने बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत विभिन्न विवरणों/रिपोर्टों की समीक्षा की थी। बैंकों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विवरणियों को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता को देखते हुए यह निश्चय किया गया है कि बैंकों को आगे से निम्नलिखित रिपोर्टें/समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

A review of the various Statements/Reports submitted by banks to RBI was undertaken by us recently. Having regard to the need for rationalising the various Returns submitted by banks it has been decided that banks need not henceforth submit to RBI the following Reports/Reviews.

- (i) बैंकों की अनुषंगी कंपनियों तथा वित्तीय सेवाएं प्रदान करनेवाली ऐसी कंपनियों की, जिनमें बैंकों ने संविभाग निवेश किये हैं, कार्यप्रणाली पर समीक्षा रिपोर्टें (19 मार्च 1993 के परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 94/24.01.001/92-93 द्वारा प्रस्तुत की जा रही)।
- (ii) विभागीय आधार पर की जा रही मर्चेंट बैंकिंग और पैरा बैंकिंग गतिविधियों पर समीक्षा रिपोर्टें (16 मई 1988 के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी. 1917/सी. 469-88 द्वारा प्रस्तुत की जा रही)।

- (i) Review Reports on the working of banks' Subsidiaries and of companies offering financial services in which banks have made portfolio investments (being submitted vide Circular DBOD No. FSC. BC. 94/24.01.001/92-93 dated 19 March 1993).
- (ii) Review Reports on merchant banking and para banking activities undertaken Departmentally (being submitted vide Circular DBOD No. BP. 1917/C.469-88 dated 16 May 1988).

(iii) बैंकों द्वारा विभागीय आधार पर किये जा रहे उपस्कर पट्टे पर देने, किराया खरीद, फैक्ट्रिंग आदि कार्यों के संबंध में समीक्षा रिपोर्टें (19 फरवरी 1994 के परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 18/24.01.001/93-94 द्वारा प्रस्तुत की जा रही)।

2. किन्तु बैंकों द्वारा समीक्षा रिपोर्टें (i) के संबंध में छमाही आधार पर तथा (ii) और (iii) के संबंध में वार्षिक आधार पर निदेशक बोर्ड/बोर्ड की प्रबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।

भवदीय

(चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.एफएससी.बीसी.50/24.01.011/98

2 जून 1998
12 ज्येष्ठ 1920 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

देशी क्रेडिट कार्ड कारोबार में बैंकों का प्रवेश

30 जून 1989 के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी. (एफएससी). बीसी. 144/सी.469-89 के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया था कि यदि वे देशी

(iii) Review Reports on equipment leasing, hire purchase, factoring etc. undertaken by banks Departmentally (being submitted vide Circular DBOD. No. FSC. BC. 18/24.01.001/93-94 dated 19 February 1994.)

2. Banks should, however, place Review Reports at (i) on Half-yearly basis and (ii) & (iii) on Annual basis before the Board of Directors/Management Committee of the Board.

Yours faithfully,

(Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

DBOD.No. FSC.BC.50/24.01.011/98

June 2, 1998
Jyestha 12, 1920 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

ENTRY OF BANKS INTO DOMESTIC CREDIT CARD BUSINESS

In terms of Circular DBOD No. BP(FSC) BC. 144/C.469-89 dated 30 June 1989, banks were advised that if they desire to

क्रेडिट कार्ड कारोबार के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वे ऐसे एक बैंक के साथ उपयुक्त समझौता करें जिसने पहले से क्रेडिट कार्ड कारोबार शुरू कर रखा हो तथा ऐसे प्रस्ताव अनुमोदन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजे जाने चाहिए। स्थिति की समीक्षा की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को या तो स्वतंत्र रूप से या कार्ड जारी करनेवाले अन्य बैंकों के साथ समझौता करके क्रेडिट कार्ड का कारोबार करने की अनुमति दी जाये। क्रेडिट कार्ड का कारोबार स्वस्थ आधार पर तथा बैंक के बोर्ड के अनुमोदन से किया जाना चाहिए। अब से बैंकों को ऐसे प्रस्ताव पूर्वानुमोदन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भेजने की जरूरत नहीं है। तथापि, क्रेडिट कार्ड संबंधी कारोबार करने के लिए एक पृथक् सहायक संस्था की स्थापना करने के इच्छुक बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेना होगा।

2. फलस्वरूप, बैंकों को अब से 9 दिसंबर 1997 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 152/24.01.011/97-98 के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट कार्ड कारोबार संबंधी समीक्षा/रिपोर्टें भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित करने की जरूरत नहीं है। तथापि, बैंकों को हमारे 23 सितंबर 1996 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 121/21.03.038/96 में दर्शाये गये अनुसार उनके निदेशक बोर्ड/बोर्ड की प्रबंधन समिति के समक्ष उक्त समीक्षा/रिपोर्ट प्रस्तुत करना जारी रखना चाहिए।

भवदीया

(चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)

महा प्रबंधक

enter domestic credit card business, it would be preferable that they have a suitable tie-up arrangement with one of the banks which might have already introduced credit cards and that such proposals should be forwarded to RBI for approval. The position has been reviewed and it has been decided to allow banks freedom to undertake credit card business either independently or in tie-up arrangement with other card issuing banks. The credit card business should be conducted on sound lines and with the approval of the bank's Board. Banks need not henceforth, forward such proposals to RBI for prior approval. Banks desirous of setting up a separate subsidiary for undertaking credit card business would, however, require RBI's prior approval.

2. Consequently, banks need not henceforth forward to the RBI Reviews/Reports on credit card business as required in terms of our circular DBOD FSC. BC. 152/24.01.011/97-98 dated 9 December 1997. Banks should, however, continue to place the above Review/Report before their Board of Directors/Managing Committee of the Board as indicated in our circular DBOD No. BP. BC. 121/21.03.038/96 dated 23 September 1996.

Yours faithfully,

(Chitra Chandramouliswaran)

General Manager

23 जून 1998
2 आषाढ़ 1920 (शक)

June 23, 1998
Aashadha 2, 1920 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

All Scheduled Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

स्टॉकइनवेस्ट योजना

STOCKINVEST SCHEME

दिनांक 1 फरवरी 1992 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 76/24.47.001/91-92 के अनुसार यह अपेक्षित है कि 'स्टॉकइनवेस्ट योजना' लागू करने वाला बैंक अपनी बनायी गयी विस्तृत योजना हमें औपचारिक रूप से लागू करने के कम से कम एक पखवाड़ा पहले भेजे तथा उसमें किये जाने वाले किसी भी परिवर्तनों की सूचना हमें अग्रिम रूप में दे। यह निश्चय किया गया है कि अब से बैंकों को लागू किये जाने के पहले हमें योजना भेजने की जरूरत नहीं है। योजना उनके बोर्डों के अनुमोदन से तथा समय-समय पर हमारे द्वारा सूचित स्टॉकइनवेस्ट को नियंत्रित करने वाली शर्तों के अधीन लागू की जाये।

In terms of circular DBOD No. BC.76/24.47.001/91-92 dated 1 February 1992, a bank proposing to introduce the Stockinvest Scheme, is required to forward to us the detailed Scheme drawn by it at least a fortnight before its formal introduction, as also bring to our notice any changes made therein well in advance. It has been decided that banks need not henceforth refer the Scheme to us before introduction. The Scheme may be introduced with the approval of their Board and subject to the terms and conditions governing Stockinvests as advised by us from time to time.

2. यह भी निश्चय किया गया है कि स्टॉकइनवेस्ट जारी करने वाले बैंकों को जारी किये गये स्टॉकइनवेस्ट की संख्या तथा निहित राशि दर्शाने वाले विवरण प्रत्येक निमाही के अंत में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि 20 दिसंबर 1993 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 206/24.47.001/93-94 में सूचित किया गया था।

2. It has also been decided that banks issuing stockinvests need not submit to RBI the statements indicating the number of stockinvests issued and the amount involved at the end of each quarter as advised in our circular DBOD No. FSC. BC. 206/24.47.001/93-94 dated 20 December 1993.

भवदीया

Yours faithfully,

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

12 अक्टूबर 1998
20 आश्विन 1920 (शक)

October 12, 1998
Ashwina 20, 1920 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक के अध्यक्ष तथा
प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

The Chairmen & Managing Directors/
Chief Executives of all Scheduled
Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

बूढ़े/बीमार/अक्षम ग्राहकों द्वारा बैंक
खातों का परिचालन

**OPERATION OF BANK ACCOUNTS
BY OLD/SICK/INCAPACITATED
CUSTOMERS**

बूढ़े/बीमार/अक्षम बैंक ग्राहकों को उनके बैंक खाते
आदि के परिचालन के लिए उपयुक्त सुविधा प्रदान
करने के प्रश्न पर कुछ समय से हम विचार कर रहे
थे। अब हमने भारतीय बैंक संघ के साथ परामर्श
करके मामले की जांच की है तथा यह निर्णय लिया
गया है कि पेंशन खातेदारों को प्रदान की गयी
सुविधा ऐसे गैर पेंशन खातेदारों को भी प्रदान की
जाये जो बीमार/बूढ़े/अक्षम हैं तथा संयुक्त खाता
खोलने और उनमें लेनदेन करने के इच्छुक नहीं हैं
(जिससे समस्या का समाधान हो सकता था)।

The question of extending a suitable facility
to old/sick/incapacitated bank customers for
operation of their bank accounts etc. has
been engaging our attention for some time.
We have since examined the issue in
consultation with Indian Banks' Association
and it has been decided to extend the
facilities offered to the pension account
holders to the non-pensioner account holders
also who are sick/old/incapacitated and are
not willing to open and operate joint
accounts (by which the problem could be
solved).

2. बीमार/बूढ़े अक्षम खातेदारों के मामले
निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

2. The cases of sick/old/incapacitated
account holders fall into following
categories :

क) ऐसे खातेदार जो इतने बीमार हैं कि
चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते/
अपने बैंक खाते से रकम निकालने के

a) An account holder who is too ill
to sign a cheque/cannot be
physically present in the bank

लिए बैंक में स्वयं नहीं जा सकते, परंतु चेक/आहरण पर्ची पर अपने अंगूठे के निशान लगा सकते हैं तथा

to withdraw money from his bank account but can put his/her thumb impression on the cheque/withdrawal form and

ख) ऐसे खातेदार जो न सिर्फ बैंक में जाने में असमर्थ है बल्कि कुछ शारीरिक कमी/अक्षमता के कारण चेक/आहरण पर्ची पर अंगूठे के निशान लगाने में भी असमर्थ हैं।

b) An account holder who is not only unable to be physically present in the bank but is also not even able to put his/her thumb impression on the cheque/withdrawal form due to certain physical defect/incapacity.

3. बूढ़े/बीमार खातेदारों को अपने बैंक खातों में लेनदेन करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से बैंक निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करें :

3. With a view to enabling the old/sick account holders to operate their bank accounts, banks may follow the procedure as under :

क) जहां कहीं बीमार/बूढ़े/अक्षम खातेदार के अंगूठे या पैर की उंगली के निशान प्राप्त किये जाते हैं, उसकी पहचान ऐसे दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए जिन्हें बैंक जानता हो तथा जिनमें से एक जिम्मेदार बैंक पदाधिकारी होना चाहिए।

a) Wherever thumb or toe impression of the sick/old/incapacitated account holder is obtained, it should be indentified by two independent witnesses known to the bank, one of whom should be a responsible bank official.

ख) जहां ग्राहक अपने अंगूठे के निशान भी नहीं लगा सकते तथा स्वयं बैंक में उपस्थित नहीं हो सकते, उन मामलों में चेक/आहरण पर्ची पर एक निशान प्राप्त कर लिया जाये, जिसकी पहचान दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए जिनमें

b) Where the customer cannot even put his/her thumb impression and also would not be able to be physically present in the bank, a mark can be obtained on the cheque/withdrawal form which should be identified by

से एक जिम्मेदार बैंक पदाधिकारी होना चाहिए।

4. ग्राहक से बैंक को यह भी सूचित करने के लिए कहा जाये कि उक्त प्रकार से प्राप्त चेक/आहरण पर्ची के आधार पर बैंक से कौन रकम निकालेगा तथा यह कि उस व्यक्ति की पहचान दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए। जो व्यक्ति बैंक से वस्तुतः रकम निकालेगा उससे कहा जाये कि वह बैंक को अपना हस्ताक्षर प्रस्तुत करे।

5. इस संदर्भ में ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके दोनों हाथ नहीं हों तथा जो चेक/आहरण पर्ची पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता हो, बैंक खाता खोलने के प्रश्न पर भारतीय बैंक संघ द्वारा अपने परामर्शदाता से प्राप्त राय अनुबंध में दी गयी है।

भवदीय

(श्रीमती देवकी मुत्तुकृष्णन)
महा प्रबंधक

two independent witnesses, one of whom should be a responsible bank official.

4. The customer may also be asked to indicate to the bank as to who would withdraw the amount from the bank on the basis of cheque/withdrawal form as obtained above and that person should be identified by two independent witnesses. The person who would be actually drawing the money from the bank should be asked to furnish his signature to the bank.

5. In this context, the opinion obtained by the Indian Banks' Association from their consultant on the question of opening of a bank account of a person who had lost both his hands and could not sign the cheque/withdrawal form is given in the Annexure.

Yours faithfully,

(Smt. Devaki Muthukrishnan)
General Manager

जो व्यक्ति अपने दोनों हाथ खो चुका हो तथा हस्ताक्षर नहीं कर सकता हो उसके द्वारा बैंक खाता खोले जाने के बारे में भारतीय बैंक संघ के परामर्शदाता की राय

OPINION OF CONSULTANT OF INDIAN BANKS' ASSOCIATION ON THE QUESTION OF OPENING OF BANK ACCOUNT BY A PERSON WHO HAS LOST BOTH HIS HANDS AND CANNOT SIGN

साधारण खंड अधिनियम के अनुसार अपना नाम लिखने में असमर्थ व्यक्ति के संदर्भ में अपने व्याकरणिक अर्थभेदों और सहार्थी अभिव्यक्तियों सहित “हस्ताक्षर” शब्द में अपने व्याकरणिक अर्थभेदों और सहार्थी अभिव्यक्तियों सहित “चिह्न” शब्द शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने एआइआर 1950 - उच्चतम न्यायालय, 265 में यह निर्णय दिया है कि हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति तथा दस्तावेज पर किये गये हस्ताक्षर या बनाये गये चिह्न के बीच भौतिक संपर्क होना चाहिए। अतः दोनों हाथ खो देने वाले व्यक्ति के मामले में, हस्ताक्षर चिह्न के माध्यम से किया जा सकता है। यह चिह्न उस व्यक्ति द्वारा किसी भी रूप में बनाया जा सकता है। सुझाये गये अनुसार यह पैर की उंगली का निशान भी हो सकता है। यह ऐसे चिह्न से हो सकता है जो कोई भी व्यक्ति हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की ओर से ऐसे उपकरण द्वारा लगा सकता है, जिसका हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क हो।

"In terms of the General Clauses Act, the term "Sign" with its grammatical variations and cognate expressions, shall, with reference to a person who is unable to write his name, include "mark" with its grammatical variations and cognate expressions. The Supreme Court has held in AIR 1950 - Supreme Court, 265 that there must be physical contact between the person who is to sign and the signature or the mark put on the document. Therefore, in the case of the person who has lost both his hands, the signature can be by means of a mark. This mark can be placed by the person in any manner. It could be the toe impression, as suggested. It can be by means of mark which anybody can put on behalf of the person who has to sign, the mark being put by an instrument which has had a physical contact with the person who has to sign."

30 मार्च 1998
9 चैत्र 1920 (शक)

March 30, 1998
Chaitra 9, 1920 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Bank)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

बैंकों में धोखाघड़ी/लाभांश/ब्याज वारंटों तथा धन-वापसी आदेशों के लिए सममूल्य सुविधा की स्वीकृति

FRAUDS IN BANKS/GRANT OF 'AT PAR' FACILITY FOR DIVIDEND/ INTEREST WARRANTS AND REFUND ORDERS

कृपया 30 सितम्बर 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 109/21.01.023/97 देखें, जिसके अनुसार 'सममूल्य' सुविधा प्रदान करने की समग्र योजना बैंकों के विवेक पर छोड़ दी गयी है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से 'सममूल्य' सुविधा के संबंध में नीति निर्धारित करते समय अपने हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया तैयार करें।

Please refer to our Circular DBOD. No. BP. BC. 109/21.01.023/97 dated September 30, 1997, in terms of which, the entire scheme of extending 'at par' facility has been left to the discretion of the banks. Banks have been advised to put in place adequate internal control mechanism to safeguard their interests while determining the policy regarding 'at par' facility with the approval of their respective Boards.

2. हालांकि बैंकों से यह अपेक्षा की गयी थी कि वे अपने कंपनी ग्राहकों को ऐसी सुविधा प्रदान करने के पहले खाते के पूर्व-निधीयन सहित आवश्यक सावधानी बरतें, हमारी जानकारी में ऐसी बात आयी है कि निधीयन संबंधी पर्याप्त व्यवस्थाएं, न होने के कारण कुछ कंपनियों द्वारा जारी लिखते वापस कर दी गयी थीं जिसे इन कंपनियों में निवेशकों का विश्वास टूट गया और फलस्वरूप जनता के बीच कुहराम मच गया। इस संबंध में, 27 मई 1997 के परिपत्र पर्यवि. सं. बीसी. 8/23.08.03/96-97 के

2. Although, banks were required to take necessary care before extending such facility to their corporate clients, including pre-funding of the account, it has come to our notice that instruments issued by some of the companies were returned due to inadequate funding arrangements eroding the investors' confidence in these companies leading to public furore. In this connection, reference is invited to para 3(c) of Circular

पैरा 3(सी) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार बैंकों को हमेशा पार्टी द्वारा खाते का पूर्व-निधीयन किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए तथा नियंत्रक शाखा द्वारा स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए। अतः बैंकों को पुनः सूचित किया जाता है कि वे किसी ग्राहक को 'सममूल्य' सुविधा प्रदान करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि लिखतों से संबंधित भुगतान पूरा करने के लिए पूर्व-निधीयन की उपयुक्त व्यवस्थाएं की गयी हों ताकि भुगतान के लिए प्रस्तुत किये जाने पर निधियों की कमी के कारण लाभांश/ब्याज वारंट नकारे न जाएं। कंपनियों के स्तर पर किये जाने वाले चूक संबंधी दीर्घकालिक मामले कंपनियों के रजिस्ट्रार अथवा वित्त मंत्रालय (कंपनी कार्य विभाग) को सूचित किये जाएं ताकि वे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें।

भवदीय

(सी.आर. मुरलीधरन)

महा प्रबंधक

DoS. No. BC. 8/23.08.03/96-97 dated May 27, 1997, according to which the banks must ensure pre-funding of account by the party at all times and the position is to be reviewed by the controlling branch. Banks are, therefore, again advised to ensure that the pre-funding arrangements to meet the payments on the instruments are suitably tied up before the grant of 'at par' facility to a client so that the dividend/interest warrants are not dishonoured due to lack of funds, when presented for payment. Chronic cases of defaults on the part of companies in meeting their liabilities on the dividend/interest warrants etc. may be communicated to the Registrar of Companies or the Ministry of Finance (Department of Company Affairs), to enable them to take action against such companies under the Companies Act, 1956.

Yours faithfully,

(C.R. Muralidharan)

General Manager

15 जून 1998
25 ज्येष्ठ 1920 (शक)

June 15, 1998
Jyestha 25, 1920 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यपालक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

The Chief Executives of all Commercial
Banks (other than Regional Rural
Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

सेवानिवृत्ति से पूर्व बैंक अधिकारियों की
मंजूरी संबंधी शक्तियां

**SANCTIONING POWER OF BANK
OFFICIALS PRIOR TO RETIREMENT**

कृपया 24 मार्च 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 32/17.04.001/94 का अवलोकन करें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया है कि सेवानिवृत्ति से तीन माह पहले की अवधि में नियंत्रक कार्यालयों में क्षेत्रीय प्रमुखों तथा प्रधान कार्यालय के स्तर पर सहायक/उप महाप्रबंधक और ऊपर के ओहदे वाले वरिष्ठ कार्यपालकों को अपनी मंजूरी संबंधी शक्तियों का प्रयोग अन्य अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से करना चाहिए। यह भी सूचित किया गया था कि सेवानिवृत्ति से 3 माह पहले की अवधि में कार्यपालक निदेशक/अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की शक्तियों का प्रयोग क्रमशः अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंधन समिति द्वारा किया जाना चाहिए।

Please refer to our circular DBOD. No. BC. 32/17.04.001/94 dated March 24, 1994 advising, **inter alia**, that during the period of three months prior to retirement, Regional Heads at Controlling Offices and Senior Executives of the rank of Assistant/Deputy General Manager and above at Head Office level, should exercise their sanctioning powers jointly with other officials. It was also provided that the powers of ED/CMD, during the period of 3 months prior to retirement should be exercised respectively by the CMD/the Management Committee.

2. स्थिति की समीक्षा की गयी है तथा यह निर्णय लिया गया है कि बैंक नियंत्रक कार्यालयों के क्षेत्रीय प्रमुखों, प्रधान कार्यालय स्तर पर वरिष्ठ कार्यपालकों तथा सर्वोच्च कार्यपालकों, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक सहित, को उन्हें प्रत्यायोजित मंजूरी संबंधी शक्तियों का प्रयोग सेवानिवृत्ति से पूर्व की तीन माह की अवधि

2. The position has since been reviewed and it has been decided that banks may permit Regional Heads at Controlling Offices, Senior Executives and Top Executives at Head Office level including CMD and ED to exercise the sanctioning powers delegated to them during the period

में भी करने की अनुमति दे सकते हैं। तथापि, इस अवधि में उनके द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव तत्काल अगले उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष रखे जाने चाहिए।

3. बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है कि सेवानिवृत्ति से तीन माह पूर्व की अवधि में शाखा प्रबंधकों द्वारा दी गयी स्वीकृतियों की सूचना तत्काल अगले उच्चतर प्राधिकारी को दे दी जाये।

भवदीय

(अमलेन्दु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

of three months prior to retirement also. However, the proposals sanctioned by them during the period should be put up immediately to the next higher authority.

3. The Board may prescribe suitable mechanism to ensure that sanctions made by Branch Managers during the period of three months prior to retirement are reported promptly to the next higher authority.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

1 जनवरी 1998

January 1, 1998

स्वर्ण/चांदी आयात करने के लिए नामित
बैंकों के मुख्य कार्यपालकगण

**The Chief Executives of the Banks
nominated to import gold/silver**

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

स्वर्ण/चांदी का आयात

IMPORT OF GOLD/SILVER

आपको यह विदित ही है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 नवंबर 1997 को उन बैंकों की एक बैठक बुलाई थी जिनको स्वर्ण का व्यापार करने की अनुमति दी गयी है। उक्त बैठक में स्वर्ण से संबंधित उत्पाद प्रारंभ करने और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से स्वर्ण-ऋण की व्यवस्था करने सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ था। इस संबंध में बैंकों द्वारा स्वर्ण से संबंधित उत्पाद आरंभ करने के संबंध में कतिपय समाचार हमारी जानकारी में आये हैं। यह ध्यान रखा जाये कि किसी स्वर्ण जमा योजना या स्वर्ण से संबंधित अन्य उत्पादों के आरंभ करने के लिए तथा विदेश से या भारत में स्वर्ण उधार लेने के लिए कोई व्यवस्था करने के लिए भी भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता है।

As you are aware, RBI had convened a meeting of banks which have been allowed to deal in gold, on 25th November 1997, during which various issues including those relating in introduction of gold related products and arranging of gold loan from foreign suppliers were discussed. In this context we have come across certain news reports regarding launching of gold related products by banks. It may be noted that introduction of any gold deposit scheme or other gold related products and also entering into arrangements for borrowing gold from abroad or in India would require prior approval of RBI.

भवदीया

Yours faithfully,

(देवकी मुत्तुकृष्णन)
महा प्रबंधक

(Devaki Muthukrishnan)
General Manager

27 जनवरी 1998
7 माघ 1919 (शक)

January 27, 1998
Magha 7, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

बैंकों का तुलनपत्र-प्रकटीकरण

**BALANCE SHEET OF BANKS -
DISCLOSURES**

हमारे दिनांक 23 अप्रैल 1996 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 57/21.04.018/96 तथा दिनांक 21 मई 1997 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 59/21/04.048/97 में निहित अनुदेशों के अनुसार बैंकों के तुलनपत्र की “लेखा टिप्पणी” में निम्नलिखित सूचनाओं को दर्शाया जाना अपेक्षित है।

In terms of instructions contained in our circulars DBOD. No. BP. BC. 57/21.04.018/96 dated April 23, 1996 and DBOD. No. BP.BC. 59/21.04.048/97 dated May 21, 1997, the following information is required to be disclosed in the 'Notes on Accounts' to the balance sheet of banks.

- i. पूंजी पर्याप्तता अनुपात
- ii. राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत।
- iii. निवल अग्रिमों के प्रति निवल निष्क्रिय आस्तियों का प्रतिशत।
- iv. निष्क्रिय आस्तियों के प्रति किये गये प्रावधानों की राशि, निवेशों के मूल्य में मूल्यहास तथा वर्ष के दौरान आयकर (अन्य प्रावधानों और आकस्मिकताओं के साथ इन तीनों प्रावधानों का मिलान लाभ और हानि खाते में ‘प्रावधान और आकस्मिकताएं’ शीर्ष

- i) Capital Adequacy Ratio
- ii) Percentage of share holding of the Government of India in the nationalised banks.
- iii) Percentage of net NPAs to net advances.
- iv) Amount of provisions made towards NPA, Depreciation in the value of investments and Income-tax during the year (these three provisions along with other provisions and contingencies would tally with the

के तहत धारित कुल राशि से होगा)।

v. स्तर-II पूंजी के रूप में जुटाये गये गौण ऋण की राशि (तुलनपत्रों में व्याख्यात्मक नोटों/टिप्पणियों के रूप में तथा अन्य देयताओं और प्रावधानों से संबंधित अनुसूची 5 में)।

vi. भारत में और भारत के बाहर निवेशों का कुल मूल्य, भारत में और भारत के बाहर किये गये निवेशों पर अलग से मूल्यहास के लिए कुल प्रावधान तथा भारत में और भारत के बाहर निवेशों का निवल मूल्य।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि उक्त प्रकटीकरणों के अलावा 31 मार्च 1998 के तुलनपत्र से 'लेखा टिप्पणी' में निम्नलिखित कारोबार अनुपात भी व्यक्त किये जायें।

- i) पूंजी पर्याप्तता अनुपात - स्तर I पूंजी
- ii) पूंजी पर्याप्तता अनुपात - स्तर II पूंजी
- iii) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय
- iv) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज से इतर आय
- v) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ

aggregate of the amount held under 'Provisions and Contingencies' in the Profit and Loss account).

v) Amount of sub-ordinated debt raised as Tier-II capital (by way of explanatory notes/remarks in the balance sheets as well as in Schedule 5 relating to Other Liabilities and Provisions).

vi) The gross value of investments in India and outside India, the aggregate of Provisions for Depreciation separately on investments in India and outside India and the net value of investments in India and outside India.

2. It has now been decided that in addition to the above disclosures, the following business ratios also should be disclosed in the 'Notes on Accounts' commencing from the Balance Sheet as at 31 March, 1998.

- i) Capital Adequacy Ratio - Tier I capital
- ii) Capital Adequacy Ratio - Tier II capital
- iii) Interest income as a percentage to working funds
- iv) Non-interest income as a percentage to working funds
- v) Operating profit as a percentage to working funds

- vi) आस्तियों पर प्रतिलाभ
- vii) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा राशियां तथा अग्रिम)
- viii) प्रति कर्मचारी लाभ

भवदीय

(अ. घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

- vi) Return on assets
- vii) Business (deposits plus advances) per employee
- viii) Profit per employee

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी.10/09.08.001/97-98

3 फरवरी 1998
14 माघ 1919 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

**कार्य स्थलों में यौन उत्पीड़न-
ऐसे उत्पीड़न को रोकने के लिए उच्चतम
न्यायालय के मार्गदर्शी सिद्धांत - उनका
कार्यान्वयन**

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिये गये एक निर्णय में इस बात की परिभाषा दी गयी है कि कार्य स्थलों में यौन उत्पीड़न से क्या तात्पर्य है तथा न्यायालय ने इस प्रकार के उत्पीड़न को रोकने के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत तय किये हैं

DBOD.No. BC.10/09.08.001/97-98

February 3, 1998
Magha 14, 1919 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

**SEXUAL HARASSMENT IN WORK
PLACES - GUIDELINES BY
SUPREME COURT TO PREVENT
SUCH HARASSMENT -
IMPLEMENTATION THEREOF**

The Hon'ble Supreme Court of India has in a recent judgement defined what constitutes sexual harassment in work places and has laid down certain guidelines (enclosed as Annexure to this circular) to prevent such

जो इस परिपत्र के अनुबंध में दिये गये हैं। केन्द्र सरकार ने भी इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनी सहमति प्रदान की है। उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि कामगार महिलाओं के लैंगिक समानता के अधिकार को परिरक्षित करने और लागू करने के लिए सभी कार्य स्थलों में इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का कड़ाई से पालन किया जाये। जब तक कोई उपयुक्त कानून नहीं बना दिया जाता तब तक न्यायालय के निदेश बाध्यकारी तथा विधिक तौर पर लागू (संविधान का अनुच्छेद 141) रहेंगे।

2. चूंकि मार्गदर्शी सिद्धांतों के कार्यान्वयन का दायित्व अकेले नियोजक पर है, अतः आपसे अनुरोध है कि विशिष्ट तौर पर निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें:

- (i) उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित यौन उत्पीड़न की परिभाषा तथा उसकी स्पष्ट मनाही अपने बैंक में कार्य करने वाले सभी स्टाफ की जानकारी में लायें।
- (ii) कर्मचारियों से संबंधित आचार नियमावलियों को उपयुक्त तौर पर आशोधित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनमें यौन उत्पीड़न की स्पष्ट मनाही तथा अपराधकर्ताओं के खिलाफ उपयुक्त दंड के प्रावधान शामिल है।
- (iii) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायें कि कार्य, अवकाश, स्वास्थ्य और आरोग्य के संबंध में कार्य के लिए उपयुक्त

harassment. These guidelines have the consent of the Union Government. The Supreme Court has directed that the guidelines be strictly observed at all work places for the preservation and enforcement of the right to gender equality of working women. The Direction of the Court would be binding and enforceable in law (Article 141 of the Constitution) until a suitable legislation is enacted.

2. As the onus for implementation of the guidelines lies solely on the employer, we would urge you to initiate immediate action to specifically ensure the following :

- (i) Bring to the notice of those working in your bank the definition of sexual harassment as laid down by the Supreme Court and its express prohibition.
- (ii) Take all necessary action to suitably modify the conduct rules governing the employees to ensure that these include the express prohibition of sexual harassment and provide for appropriate Penalties against the offender.
- (iii) Take all steps necessary to ensure that appropriate work conditions are provided in respect of work, leisure, health

स्थितियां हैं ताकि साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य स्थलों में महिलाओं के प्रति कोई प्रतिकूल माहौल नहीं है तथा किसी भी महिला कर्मचारी के सामने इस बात का विश्वास करने के उचित आधार नहीं हैं कि वह अपने रोजगार के संबंध में अलाभ की स्थिति में है।

- (iv) यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों से निपटने के लिए अपने बैंक में एक प्रक्रिया तैयार करें।

3. भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए की गयी कार्रवाई की जानकारी यथाशीघ्र हमें दी जाये।

भवदीय

(ए. एल. नरसिंहन)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

and hygiene, to further ensure that there is no hostile environment towards women at work places and no woman employee has reasonable grounds to believe that she is disadvantaged in connection with her employment.

- (iv) Set up a mechanism in your bank to deal with complaints of sexual harassment.

3. Action taken for implementation of the guidelines laid down by the Supreme Court of India may please be intimated to us at an early date.

Yours faithfully,

(A.L. Narasimhan)
Additional Chief General Manager

कार्यस्थलों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में एक सार्वजनिक हित वाले मुकदमे में 1992 की रिट याचिका (आपराधिक) सं. 666/70 (विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य) में उच्चतम न्यायालय द्वारा 14 अगस्त 1997 के इसके निर्णय में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांत और मानदंड

इसमें निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांत और मानदंड निम्नानुसार हैं :-

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(घ) में दी गयी 'मानवाधिकार' की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए,

इस तथ्य को नोट करते हुए कि भारत में मौजूदा सिविल और दंडिक कानूनों में कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न से महिलाओं को विशिष्ट संरक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किये गये हैं और यह कि ऐसा कानून बनाने में काफी समय लम्पेगा,

कार्यस्थलों में नियोजकों के लिए तथा अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के लिए यह आवश्यक और समीचीन है कि वे महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करें।

i. कार्यस्थलों तथा अन्य संस्थाओं में नियोजकों या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के कर्तव्य: कार्यस्थलों या अन्य संस्थाओं

GUIDELINES AND NORMS LAID DOWN BY THE HON'BLE SUPREME COURT IN ITS JUDGEMENT DATED 14TH AUGUST, 1997 IN A PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) WRIT PETITION (CRIMINAL) NO. 666/70 OF 1992 (VISHAKA & ORS. VS. STATE OF RAJASTHAN & ORS.) ON THE SUBJECT OF SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN IN THE WORKPLACES.

The GUIDELINES and NORMS prescribed herein are as under :-

HAVING REGARD to the definition of 'human rights' in Section 2(d) of the Protection of Human Rights Act, 1993,

TAKING NOTE of the fact that the present civil and penal laws in India do not adequately provide for specific protection of women from sexual harassment in work places and that enactment of such legislation will take considerable time,

It is necessary and expedient for employers in work places as well as other responsible persons or institutions to observe certain guidelines to ensure the prevention of sexual harassment of women.

i. **Duty of the Employer or other responsible persons in work places and other institutions :** It shall be the

में नियोजक अथवा अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे सभी अपेक्षित कदम उठाकर यौन उत्पीड़न के कार्यों को रोकें या निवारित करें तथा यौन उत्पीड़न के कार्यों के समाधान, निपटान या अभियोजन के लिए प्रक्रियाएं तैयार करें।

ii. परिभाषा: इस प्रयोजन के लिए यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित अप्रिय यौन व्यवहार (प्रत्यक्ष अथवा विवक्षित तौर पर) शामिल है:

- क) शारीरिक संपर्क और अग्रसरता,
- ख) यौन संबंध की मांग या अनुरोध,
- ग) यौन अभिप्राय वाली टिप्पणियां,
- घ) अश्लील साहित्य का प्रदर्शन, तथा
- ड) अन्य कोई अप्रिय शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक यौन स्वरूप का आचरण।

जहां इनमें से कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में किया जाये जिनमें ऐसे आचरण की शिकार महिला को इस बात की उचित आशंका हो कि चाहे वह वेतन या मानदेय ले रही हो या ऐच्छिक कार्य कर रही हो, चाहे वह सरकार, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के उद्यम में हो, उसके रोजगार या कार्य के संबंध में ऐसा आचरण अपमानजनक हो सकता है और उससे स्वास्थ्य और सुरक्षा की समस्या हो सकती है। उदाहरणार्थ, यह भेदभावपूर्ण होगा यदि महिला के लिए इस बात का विश्वास

duty of the employer or other responsible persons in work places or other institutions to prevent or deter the commission of acts of sexual harassment and to provide the procedures for the resolution, settlement or prosecution of acts of sexual harassment by taking all steps required.

ii. **Definition :** For this purpose, sexual harassment includes such unwelcome sexually determined behaviour (whether directly or by implication) as :

- a) physical contact and advances;
- b) a demand or request for sexual favours;
- c) sexually coloured remarks;
- d) showing pornography; and
- e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

Where any of these acts is committed in circumstances whereunder the victim of such conduct has a reasonable apprehension that in relation to the victim's employment or work whether she is drawing salary, or honorarium or voluntary, whether in government, public or private enterprise such conduct can be humiliating and may constitute a health and safety problem. It is

करने के उचित आधार हों कि उसके द्वारा आपत्ति उठाने से भर्ती या पदोन्नति सहित उसके रोजगार या कार्य के संबंध में उसे नुकसान उठाना पड़ेगा अथवा जब इससे कार्य का प्रतिकूल माहौल बन रहा हो। यदि पीड़ित महिला प्रश्नाधीन आचरण के लिए सहमति नहीं दे रही हो अथवा उसके लिए आपत्ति उठा रही हो तो प्रतिकूल परिणाम देखे जा सकते हैं।

- iii. **निवारक उपाय:** सभी नियोजक तथा कार्यस्थल के प्रभारी, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र, यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएँ। इस दायित्व की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वे निम्नलिखित उपाय करें :

- क) उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की व्यक्त मनाही को अधिसूचित, प्रकाशित एवं उचित रूप से परिचालित किया जाना चाहिए;
- ख) सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के आचरण तथा अनुशासन से संबंधित नियमों/विनियमों में यौन उत्पीड़न की मनाही से संबंधित नियम/विनियम शामिल किये जाने चाहिए और इन नियमों में अपराधियों के विरुद्ध उपयुक्त दंड की व्यवस्था होनी चाहिए;

discriminatory for instance when the woman has reasonable grounds to believe that her objection would disadvantage her in connection with her employment or work including recruiting or promotion or when it creates a hostile work environment. Adverse consequences might be visited if the victim does not consent to the conduct in question or raises any objection thereto

- iii. **Preventive Steps :** All employers or persons in charge of work place whether in the public or private sector should take appropriate steps to prevent sexual harassment. Without prejudice to the generality of this obligation they **should take the following steps :**

- a) Express prohibition of sexual harassment as defined above at the work place should be notified, published and circulated in appropriate ways;
- b) The Rules/Regulations of Government and Public Sector bodies relating to conduct and discipline should include rules/regulations prohibiting sexual harassment and provide for appropriate penalties in such rules against the offender;

ग) निधी क्षेत्र के नियोजकों के संबंध में औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत स्थायी आदेशों में उक्त मनाही को सम्मिलित करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए;

घ) कार्य, अवकाश, स्वास्थ्य और आरोग्य के संबंध में कार्य के लिए उपयुक्त माहौल उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यस्थलों में महिलाओं के प्रति कोई प्रतिकूल माहौल नहीं है तथा किसी भी महिला कर्मचारी के सामने इस बात का विश्वास करने के उचित आधार नहीं हैं कि वह अपने रोजगार के संबंध में अलाभ की स्थिति में है।

iv. **दांडिक कार्यवाही :-** जहां इस तरह का आचरण भारतीय दंड संहिता अथवा अन्य किसी कानून के तहत विशिष्ट अपराध की श्रेणी में आता हो, नियोजक उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष शिकायत करके विधि के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ करेगा।

विशेष तौर पर यह सुनिश्चित किया जाये कि यौन उत्पीड़न की शिकायत का निपटान करते समय उसकी शिकार महिलाओं अथवा गवाहों को सताया न जाय अथवा उनके खिलाफ भेदभाव न बरता जाय। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को अपराधकर्ता का स्थानांतरण अथवा अपना स्थानांतरण मांगने का विकल्प होना चाहिए।

c) As regards private employers steps should be taken to include the aforesaid prohibitions in the standing orders under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946; and;

d) Appropriate **work conditions** should be provided in respect of work, leisure, health and hygiene to further ensure that there is no hostile environment towards women at work places and no employee woman should have reasonable grounds to believe that she is disadvantaged in connection with her employment.

iv. **Criminal Proceedings :** Where such conduct amounts to a specific **offence** under the Indian Penal Code or under any other law the employer shall initiate appropriate action in accordance with law by making a complaint with the appropriate authority.

In particular, it should ensure that victims, or witnesses are not victimized or discriminated against while dealing with complaints of sexual harassment. The victims of sexual harassment should have the option to seek transfer of the perpetrator or their own transfer.

v. **अनुशासनिक कार्रवाई:** जहां इस तरह का आचरण सेवा संबंधी नियमों के अंतर्गत कदाचार के रूप में परिभाषित किया गया हो, वहां नियोजक द्वारा उन नियमों के अनुसार उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

vi. **शिकायत की प्रक्रिया :** इस तरह का आचरण विधि के अंतर्गत अपराध हो या नहीं अथवा उससे सेवा नियमों का उल्लंघन हो रहा हो या नहीं, पीड़ित महिलाओं द्वारा की गयी शिकायत के निपटान के लिए नियोजक की संस्था में एक उपयुक्त शिकायत प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसी शिकायत प्रक्रिया द्वारा शिकायतों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

vii. **शिकायत समिति:** उक्त (vi) में उल्लिखित शिकायत प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार एक शिकायत समिति, एक विशेष परामर्शदाता अथवा अन्य समर्थक सेवा, गोपनीयता बरतने सहित, का पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए।

शिकायत समिति की प्रमुख महिला होनी चाहिए और उसके सदस्यों में आधी या उससे अधिक संख्या महिलाओं की होनी चाहिए। इसके अलावा, वरिष्ठ स्तर से होने वाले किसी अनुचित दबाव या प्रभाव की संभावना को रोकने के लिए ऐसी शिकायत समिति में तीसरे पक्ष के रूप में गैर सरकारी संगठन या अन्य संस्था, जो यौन उत्पीड़न के मामले से परिचित हो, शामिल होनी चाहिए।

v. **Disciplinary Action :** Where such conduct amounts to mis-conduct in employment as defined by the relevant service rules, appropriate disciplinary action should be initiated by the employer in accordance with those rules.

vi. **Complaint Mechanism :** Whether or not such conduct constitutes an offence under law or a breach of the service rules, an appropriate complaint mechanism should be created in the employer's organization for redress of the complaint made by the victim. Such complaint mechanism should ensure time-bound treatment of complaints.

vii. **Complaints Committee :** The complaint mechanism, referred to in (vi) above, should be adequate to provide where necessary, a complaints committee, a special counsellor or other support service including the maintenance of confidentiality.

The Complaints Committee should be headed by a woman and not less than half of its members should be women. Further, to prevent the possibility of any undue pressure or influence from senior levels, such Complaints Committee should involve a third party, either NGO or other body who is familiar with the issue of sexual harassment.

शिकायत समिति द्वारा शिकायतों और उनके द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट संबंधित सरकारी विभाग को दी जाये। नियोजक और प्रभारी अधिकारी शिकायत समिति की रिपोर्टों सहित उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन की रिपोर्ट भी सरकारी विभाग को देंगे।

The Complaints Committee must make an annual report to the Government department concerned of the complaints and action taken by them. The employers and person in charge will also report on the compliance with the aforesaid guidelines including on the reports of the Complaints Committee to the Government department.

viii. **कर्मचारियों की पहल:** कर्मचारियों और अन्य उपयुक्त फोरम की बैठक में यौन उत्पीड़न के मामले उठाने की अनुमति कर्मचारियों को होनी चाहिए और नियोजक-कर्मचारी की बैठकों में इस पर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए।

viii. **Workers' Initiative :** Employees should be allowed to raise issues of sexual harassment at workers' meeting and in other appropriate forum and it should be affirmatively discussed in Employer-Employee Meetings.

ix. **जानकारी:** मार्गदर्शी सिद्धांतों (और इस विषय पर कानून बनने के बाद उपयुक्त कानून) को उपयुक्त तरीके से प्रमुख रूप से अधिसूचित करके इस संबंध में महिला कर्मचारियों के अधिकारों की जानकारी उन्हें विशेष तौर पर दी जानी चाहिए।

ix. **Awareness :** Awareness of the rights of female employees in this regard should be created in particular by prominently notifying the guidelines (and appropriate legislation when enacted on the subject) in a suitable manner.

x. **तीसरे पक्ष द्वारा उत्पीड़न:** जहां किसी तीसरे पक्ष या बाहरी व्यक्ति के किसी कार्य या लोप के फलस्वरूप यौन उत्पीड़न हो रहा हो, नियोजक तथा प्रभारी व्यक्ति समर्थक और निवारक कार्रवाई के रूप में प्रभावित व्यक्ति की मदद करने के लिए सभी आवश्यक और उचित कदम उठाएंगे।

x. **Third Party Harassment :** Where sexual harassment occurs as a result of an act or omission by any third party or outsider, the employer and person in charge will take all steps necessary and reasonable to assist the affected person in terms of support and preventive action.

- xi. केन्द्र/राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए विधान सहित उपयुक्त उपाय करने के बारे में विचार करने का अनुरोध किया जाता है कि इस आदेश द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों का निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा भी पालन किया जाये।
- xii. इन मार्गदर्शी सिद्धांतों से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत उपलब्ध किसी अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बैंपविवि.आइबीएस1816/23.67.001/98-99

**4 फरवरी 1999
15 माघ 1920 (शक)**

**अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सोना/चांदी/प्लैटिनम आयात करने के लिए
प्राधिकृत सभी बैंक**

प्रिय महोदय,

**सोना/चांदी/प्लैटिनम की ब्रिकी-नकद
रूप में अदायगी**

कृपया 19 अप्रैल 1991 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 114/सी.469 (81)-91 का संदर्भ लें, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि राजकोषीय कानूनों के उल्लंघन और कर वंचना के लिए बैंक चैनलों के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने की दृष्टि से बैंकों द्वारा रु. 50,000/- और उससे अधिक के मांग ड्राफ्ट, डाक अंतरण, तार अंतरण और यात्री चेक

- xi. The Central/State Governments are requested to consider adopting suitable measures including legislation to ensure that the guidelines laid down by this order are also observed by the employers in Private Sector.
- xii. These guidelines will not prejudice any rights available under the Protection of Human Rights Act, 1993.

DBOD.No. IBS.1816/23.67.001/98-99

**February 4, 1999
Magha 15, 1920 (Saka)**

**The Chairmen/Chief Executives of all
the Banks authorised to import gold/
silver/platinum**

Dear Sir,

**SALE OF GOLD/SILVER/PLATINUM-
PAYMENT IN CASH**

Please refer to our circular DBOD. No. BP. BC. 114/C. 469(81)-91 dated 19 April 1991 which stipulates that in order to curb the misuse of banking channels for violation of fiscal laws and evasion of taxes, Demand Drafts, Mail Transfers, Telegraphic Transfers and Travellers Cheques for Rs.

ग्राहक के खाते में राशि नामे डालकर अथवा खरीदार द्वारा दिये जाने वाले चेकों या अन्य लिखतों के प्रति ही जारी किये जायें, न कि नकद अदायगी पर।

2. सोना/चांदी/प्लैटिनम आयात करने के लिए प्राधिकृत कुछ बैंकों ने हम से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या हमारे उपर्युक्त परिपत्र में निहित अनुदेश प्राधिकृत बैंकों द्वारा की जाने वाली सोने की खुदरा बिक्री पर भी लागू होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अनुदेश सोना/चांदी/प्लैटिनम की बिक्री पर भी लागू हैं। अतः बैंक यह सुनिश्चित करें कि रु. 50,000 और उससे अधिक के मूल्य के सोने/चांदी/प्लैटिनम की बिक्री की अदायगी ग्राहक के खाते में राशि नामे डालकर अथवा खरीदार द्वारा दिये गये चेकों या अन्य लिखतों के माध्यम से ही स्वीकार की जाये, न कि नकद रूप में।

भवदीया

(देवकी मृत्तुकृष्णन)
महाप्रबंधक

50,000/- and above should be issued by banks only by debit to the customer's account or against cheques or other instruments tendered by the purchaser and not against cash payment.

2. Some of the banks authorised to import gold/silver/platinum have sought clarification from us whether the instructions contained in our circular mentioned above are also applicable in the case of retail sale of gold by the authorised banks. It is clarified that the above instructions are applicable to sale of gold/silver/platinum also. Banks should, therefore, ensure that payment towards sale of gold/silver/platinum of the value of Rs. 50,000/- and above is received only by debit to the customer's account or against cheques or other instruments tendered by the purchaser and not in cash.

Yours faithfully,

(Devaki Muthukrishnan)
General Manager

11 फरवरी 1998
22 माघ 1919 (शक)

February 11, 1998
Magha 22, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

आंकड़े प्रस्तुत करना - गोपनीयता संबंधी
दायित्वों का उल्लंघन

FURNISHING OF DATA - VIOLATION
OF SECRECY OBLIGATIONS

जैसा कि बैंकों को विदित है, सरकारी और अन्य एजेंसियों से शैक्षणिक/सैद्धांतिक प्रयोजनों के लिए समय-समय पर उनके व्यवसाय संबंधी कुछ पहलुओं पर आंकड़ों/सूचनाओं के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। ग्राहकों के लेनदेनों के संदर्भ में गोपनीयता बरतने संबंधी बैंकों के दायित्व की पृष्ठभूमि में इस मसले की जांच की गयी। भारत में गोपनीयता कानून की व्याप्ति सामान्यतः अंतर्निहित संविदा पर आधारित विधि के सामान्य सिद्धांतों का अनुसरण करती है। गोपनीयता बरतने संबंधी बैंकों का दायित्व बैंकर और ग्राहक के बीच संविदात्मक संबंध के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, अतः सुस्पष्ट परिस्थितियों को छोड़कर अन्य किसी भी परिस्थिति में तीसरे पक्ष को कोई सूचना नहीं दी जानी चाहिए। उक्त नियम के निम्नलिखित अपवाद अब स्वीकार कर लिये गये हैं -

As the banks are aware, requests for data/information on certain aspects of their business are received from time to time from Government and other agencies for academic/theoretical purposes. This issue was examined in the background of the bankers' obligation to maintain secrecy in respect of customers transactions. The scope of the secrecy law in India has generally followed the common law principles based on implied contract. The bankers' obligation to maintain the secrecy arises out of the contractual relationship between the banker and customer, and as such no information should be divulged to third parties except under circumstances which are well defined. The following exceptions to the said rule are now accepted.

- जहां प्रकटीकरण कानूनी अनिवार्यता हो
- जहां जनता के प्रति कर्तव्य के तौर पर प्रकटीकरण जरूरी हो

- Where disclosure is under compulsion of law
- Where there is a duty to the public to disclose

- जहां बैंक के हित के लिए प्रकटीकरण अपेक्षित हो तथा
- जहां प्रकटीकरण ग्राहक की व्यक्ति या निहित सहमति के साथ किया गया हो।

अतः बैंकों को उक्त पृष्ठभूमि या परिस्थितियों में ऐसी जानकारी देने की उलझनों को समझना चाहिए, जिनके कारण गोपनीयता के प्रावधानों का उल्लंघन होता हो।

2. ऊपर स्पष्ट की गयी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, हम सूचित करते हैं कि जब कभी ऐसे अनुरोध प्राप्त हों तब बैंकों को स्वयं को इस बात से आश्वस्त कर लेना चाहिए कि मांगी गयी सूचना ऐसे स्वरूप की न हो जिससे बैंकिंग लेनदेनों में गोपनीयता संबंधी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हो। उन मामलों में जहां बैंकों को संदेह हो कि सूचना देने से गोपनीयता संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है या नहीं, उन्हें विशिष्ट कानूनी सलाह प्राप्त कर लेनी चाहिए।

भवदीय

(जे.बी. म्हात्रे)
उप महा प्रबंधक

- Where interest of bank requires disclosure and
- Where the disclosure is made with the express or implied consent of the customer.

The banks should therefore, appreciate the implications of furnishing information that would violate the provisions of secrecy in the background or circumstances stated above.

2. In view of the position clarified above, we advise that whenever such requests are received, the banks should satisfy themselves that the information being sought is not of such a nature as will violate the provisions of the laws relating to secrecy in the banking transactions. In cases in which the banks have doubts whether the furnishing of information might violate secrecy provisions, they should get specific legal advice.

Yours faithfully,

(J.B. Mhatre)
Deputy General Manager

27 फरवरी 1998
8 फाल्गुन 1919 (शक)

February 27, 1998
Phalguna 8, 1919 (Saka)

वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
अधिकारी

The Chairmen/Chief Executive Officers
of Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

**इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा
समाशोधन)**

**ELECTRONIC CLEARING SERVICE
(CREDIT CLEARING)**

कृपया 23 जून 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. बीसी. सं. 68/09.07.007/96-97 देखें, जिसके अनुसार चार महानगरों में चलायी जा रही उक्त योजना को 1 जुलाई 1997 से चार और केन्द्रों अर्थात् अहमदाबाद, बंगलूर, हैदराबाद और पुणे में लागू कर दिया गया था। समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) योजना को 1 जुलाई 1998 से आठ और केन्द्रों अर्थात् भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना तथा तिरुवनंतपुरम में भी लागू कर दिया जाये। इसके साथ यह योजना उन सभी केन्द्रों पर लागू हो जाएगी जहां समाशोधन गृहों का प्रबंधन भारतीय रिज़र्व बैंक करता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा) योजना के अंतर्गत लेनदेन की सीमा 1 जुलाई 1998 से वर्तमान रु. 50,000/- से बढ़ाकर रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) करने का निर्णय लिया गया है। बैंकों से अनुरोध है कि वे इसकी जानकारी उन कंपनी ग्राहकों को दें जो काफी संख्या में लाभांश भुगतान आदि करते हैं तथा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) की सुविधा का लाभ उठाने के लिए समझायें।

Please refer to our circular letter DBOD.BC. No. 68/09.07.007/96-97 dated 23rd June 1997 in terms of which the coverage under the above scheme operating at the four metropolitan cities was extended to four more centres viz. Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad and Pune, with effect from 1st July 1997. On a review, it has been decided to extend the ECS (Credit Clearing) Scheme to eight more centres viz. Bhubaneshwar, Chandigarh, Guwahati, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna and Thiruvananthapuram with effect from 1st July 1998. With this the scheme would cover all centres where Reserve Bank of India manages the Clearing Houses. Simultaneously it has been decided to increase the limit on the transaction value under the ECS (Credit) Scheme from the present Rs.50,000/- to Rs. 1,00,000/- (Rs. one lakh only) with effect from 1st July 1998. Banks are requested to please bring this development to the notice of the corporate customers issuing large number

of dividend payments, etc. and impress upon them to avail of the benefit under the ECS (Credit Clearing) facility.

2. उक्त गतिविधि के फलस्वरूप “प्रोसीजरल गाइडलाइन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (क्रेडिट क्लीयरिंग), जून 1997” के , पृष्ठ 6 पर पैराग्राफ 20 में तथा पृष्ठ 7 पर पैराग्राफ 21 (रिकार्ड 3) में और साथ ही पृष्ठ 30 पर परिशिष्ट VII (फार्म सं. ई4) में जिसकी प्रतियां आपको पहले ही उपलब्ध करायी जा चुकी हैं, उपर्युक्त परिवर्तन कर लिये जायें।

भवदीय

(डी.वी. झवेरी)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.17/21.04.048/98

4 मार्च 1998
13 फाल्गुन 1919 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं
प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण
मानदंड-कृषि अग्रिम

कृपया 19 फरवरी 1997 के हमारे परिपत्र
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 14/21.04.048/97 का

2. Consequent to the above development, changes may please be made in paragraph 20 on page 6 and paragraph 21 (record 3) on page 7 and also Appendix VII (form No. E4) on page 30 of the "Procedural Guidelines of Electronic Clearing Service (Credit Clearing), June 1997", copies of which have already been made available to you.

yours faithfully,

(D.V. Jhaveri)
General Manager

DBOD.No. BP.BC.17/21.04.048/98

March 4, 1998
Phalguna 13, 1919 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Bank)

Dear Sir,

PRUDENTIAL NORMS ON INCOME
RECOGNITION, ASSET CLASSIFICATION
AND PROVISIONING - AGRICULTURAL
ADVANCES

Please refer to our circular DBOD No.
BP.BC. 14/21.04.048/97 dated February 19,

अवलोकन करें जिसके द्वारा बैंकों को सूचित किया गया था कि कृषि के प्रयोजनार्थ स्वीकृत अग्रिमों के मामले में यदि अदायगी के लिए देय ब्याज/किस्तों की तारीख से दो तिमाहियों से अधिक समय तक ब्याज/किस्त बकाया हो, तो अग्रिम को अनर्जक आस्ति माना जाये। हमें ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि कृषि की पद्धतियों तथा फसल काटने और उसे बेचने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न कृषि प्रयोजनों के लिए स्वीकृत अग्रिमों के वर्गीकरण के लिए एकसमान तौर पर उक्त मानदंड लागू करना कठिन है। इस मामले पर पुनर्विचार किया गया है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि कृषि के प्रयोजनार्थ स्वीकृत अग्रिमों को अनर्जक आस्ति तभी माना जाये यदि ब्याज और/या मूलधन की किस्त देय होने की तारीख के बाद दो फसल कटाई मौसमों के दौरान परंतु दो छमाहियों से अनधिक समय में अदा नहीं की गयी हो।

2. ये अनुदेश लेखा वर्ष 1997-98 से लागू होंगे।

भवदीय

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

1997 advising banks that in respect of advances granted for agricultural purposes where interest/instalment is in arrears for more than two quarters from the date the interest/instalments are due for repayment, the advance should be treated as NPA. We have been receiving representations that keeping in view the agricultural practices and the time taken for harvesting and marketing of crops, it is difficult to uniformly apply the above norm for classification of advances granted for various agricultural purposes. The matter has been reconsidered and it is clarified that advances granted for agricultural purposes may be treated as NPA if interest and/or instalment of principal remains unpaid, after it has become past due, for two harvest seasons but for a period not exceeding two half years.

2. These instructions will apply from the accounting year 1997-98.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

4 मार्च 1998
13 फाल्गुन 1919 (शक)

March 4, 1998
Phalguna 13, 1919 (Saka)

सोना/चांदी आयात करने के लिए नामित बैंकों
के मुख्य कार्यपालक

The Chief Executives of the Banks
nominated to import gold/silver

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

सोना/चांदी का आयात

IMPORT OF GOLD/SILVER

कृपया उक्त विषय पर 1 जनवरी 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आइबीएस. 1410/23.67.001/97-98 देखें। कुछ बैंकों ने इस बात का स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या उदारीकृत आयात नीति के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें दिये गये प्राधिकार के तहत आयातित सोना सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजनों के लिए पात्र आस्ति माना जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के तहत बैंक द्वारा अपने खाते में रखा गया सोना सांविधिक चलनिधि अनुपात की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए पात्र आस्ति माना जाएगा।

Please refer to our Circular DBOD. No. IBS. 1410/23.67.001/97-98 dated 1 January 1998 on the subject mentioned above. Some of the banks have sought clarification as to whether the gold imported under the authorisation given to them by the RBI under the liberalised import policy, will qualify as an eligible asset for SLR purposes. It is clarified that under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 gold held by a bank on its own account will qualify as an eligible asset for meeting SLR requirements.

2. साथ ही, हम सूचित करते हैं कि सोने में खुली स्थिति रखने से बैंक को मूल्य संबंधी जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। अतः बैंक अपने बोर्डों के अनुमोदन से सोने में खुली स्थिति रखने के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं तथा साथ ही ऐसी सीमाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि सोने में खुली स्थिति रखने वाले बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता संबंधी मौजूदा अपेक्षाओं के अलावा, खुली स्थिति संबंधी सीमा के 5% तक स्तर - I पूंजी भी रखना चाहिए (जैसा कि विदेशी मुद्रा की खुली स्थिति के मामले में होता है।)

2. Further, we advise that taking up an open position in gold can expose a bank to price risk. Therefore, banks may lay down with the approval of their Boards, prudential limits on taking open position in gold and also obtain the specific approval of the RBI for such limits. It is clarified that banks keeping open position in gold should also maintain Tier-I Capital to the extent of 5% of the open position limit (as in the case of forex open position), in addition to the existing Capital Adequacy requirements specified by RBI.

3. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वायदा संविदा विनियमन अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सोने में कोई वायदा सौदा करने की मनाही है।

भवदीया

(देवकी मुथुकृष्णन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी.19/21.01.023/98

10 मार्च 1998
19 फाल्गुन 1919 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध
निदेशक/मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

भारत में विभिन्न संघों/संगठनों द्वारा
विदेशी अभिदान (विनियमन)
अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विदेशी
अभिदान

कृपया आप 16 फरवरी 1996 का हमारा पत्र सं.
बैंपविवि. बीपी. बीसी. 16/21.01.023/96 और
23 मई 1997 का पत्र सं. बैंपविवि. बीपी. 2777/
21.01.023/97 देखें, जिनमें बैंकों से कहा गया है
कि विदेशी अभिदान की राशि संघों (एसोसिएशनों)

3. Banks are advised that entering into any forward deal in gold is prohibited under the Forward Contract Regulation Act, 1952.

Yours faithfully,

(Devaki Muthukrishnan)
General Manager

DBOD.No. BP.BC.19/21.01.023/98

March 10, 1998
Phalguna 19, 1919 (Saka)

The Chairmen and Managing
Directors/ Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

**RECEIPT OF FOREIGN
CONTRIBUTIONS BY VARIOUS
ASSOCIATIONS/ORGANISATIONS
IN INDIA UNDER FOREIGN
CONTRIBUTION (REGULATION)
ACT, 1976**

Please refer to our letters Nos. DBOD.
BP.BC. 16/21.01.023/96 dated 16th
February 1996 & DBOD. BP. 2777/
21.01.023/97 dated 23rd May 1997 advising
banks that foreign contributions should not

/संगठनों के खातों में तब तक जमा न की जाये, जब तक कि विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकरण अथवा पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली गयी हो। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे संगठनों/संघों के खातों में जमा किये गये विदेशी अभिदानों के ब्यौरे की छमाही विवरणी भारत सरकार, गृह मंत्रालय को छमाही समाप्त होने से दो महीने में प्रस्तुत किया करें।

2. भारत सरकार ने हमें जानकारी दी है कि रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को बार-बार अनुदेश दिये जाने के बावजूद कुछ बैंकों ने केंद्र सरकार की आवश्यक अनुमति के बिना संगठनों/संघों के खातों में विदेशी अभिदान जमा किये हैं। अधिकतर बैंक छमाही विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा का भी दृढ़ता से पालन नहीं करते। ये विवरणियां न मिलने के कारण उक्त अधिनियम का उल्लंघन करके विदेशी अभिदानों के आने पर नज़र रखने में सरकार को बहुत कठिनाई होती है।

3. अतएव हम अपने ऊपर उल्लिखित पत्रों में दिये गये अनुदेशों को दोहराते हुए सूचित करते हैं कि बैंक इन अनुदेशों का कुशलता से पालन करें। पंजीकरण करते अथवा पूर्व अनुमोदन देते समय गृह मंत्रालय, भारत सरकार उसकी प्रति बैंक की संबंधित शाखा को अनिवार्यतः परांकित करता है। इसलिए संगठनों/संघों के खाते में विदेशी अभिदान तब तक जमा नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सरकार से शाखा को इस आशय का आदेश प्राप्त

be credited to the Accounts of Associations/ Organisations unless they have obtained registration or prior permission under FC(R) Act, 1976. The banks were also advised to submit a Return furnishing details of the foreign contributions credited to the Accounts of Organisations/Associations on a half-yearly basis to Government of India, Ministry of Home Affairs, within a period of two months from the closure of the half-yearly period.

2. It has been brought to our notice by Government of India that in spite of repeated instructions issued to banks by the RBI, some of the banks have credited the foreign contributions to the Accounts of Organisations/Associations without the requisite permission of the Central Government. Also the requirement of filing half yearly Returns is not being strictly adhered to by most of the banks. In the absence of these Returns, the Government find it very difficult to keep a watch on the inflow of foreign contributions, in violation of the provisions of the said Act.

3. We, therefore, reiterate the instructions contained in our abovementioned letters and advise that the banks should scrupulously follow these instructions. While granting registration or prior permission, the Ministry of Home Affairs, Government of India invariably endorses a copy thereof to the concerned branch of the bank. As such, no credits of

न हो जाये। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष 31 मार्च और 30 सितम्बर की स्थिति की छमाही विवरणियां छमाही की समाप्ति से दो महीने की निर्धारित अवधि में सरकार को अनिवार्य रूप से भेज दी जायें।

4. कृपया यह नोट करें कि इन अनुदेशों का दृढ़ता से पालन न करने और इसके परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन अथवा भारत सरकार को विवरणियां समय पर प्रस्तुत न करने को गंभीरता से लिया जायेगा।

5. इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी कार्यालयों/शाखाओं को तत्काल अनुपालन के लिए अवगत कराया जाये और इस संबंध में शाखाओं को जारी की गयी सूचना की प्रतिलिपि हमारी जानकारी और रिकार्ड के लिए हमें भेजी जाये।

भवदीय

(ए. एल. सिंहमार)

उप महा प्रबंधक

foreign contributions should be allowed in the Accounts of Organisations/Associations unless an order to this effect is received by the branches from the Government. Further, the half yearly Returns as on 31st March & 30th September of every year should invariably be forwarded to Government within the stipulated period of two months of the closure of the half year.

4. It may please be noted that non-adherence to these instructions resulting in violations of the provisions of the said Act or non submission of timely Returns to Government of India would be viewed seriously by us.

5. The contents of this Circular should be brought to the notice of all your offices/branches for immediate compliance and a copy of the advice issued to your branches in this regard may be sent to us for our information and record.

Yours faithfully,

(A.L. Sinhmar)

Deputy General Manager

बैंपविवि.आइबीएस. 1929/23.67.001/97-98

DBOD.No. IBS.1929/23.67.001/97-98

14 मार्च 1998
23 फाल्गुन 1919 (शक)

March 14, 1998
Phalgun 23, 1919 (Saka)

स्वर्ण आयात हेतु प्राधिकृत बैंकों के
मुख्य कार्यपालक

The Chief Executives of the Banks
authorised to Import Gold

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

स्वर्ण का आयात

IMPORT OF GOLD

कृपया आप 6 मार्च 1998 का भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र एडी (जी.पी.सीरीज) परिपत्र सं. 7 देखें। ऊपर उल्लिखित परिपत्र के पैरा 2(1) के अनुसार विदेश से उधार लिया गया स्वर्ण बैंक की मांग और मीयादी देयताओं के भाग के रूप में माना जायेगा और इसलिए वह नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात के अधीन होगा।

Please refer to the RBI circular AD (G.P. Series) Circular No. 7 dated 6.3.1998. Gold borrowed from abroad in terms of para 2(1) of the above mentioned circular will form part of the bank's demand and time liabilities and will therefore be subject to Cash Reserve Ratio and Statutory Liquidity Ratio.

भवदीया

Yours faithfully,

(देवकी मुत्तुकृष्णन)
महा प्रबंधक

(Devaki Muthukrishnan)
General Manager

बैंपविवि.बीसी. सं. 27/12.06.114/98

DBOD.No.BC. 27/12.06.114/98

3 अप्रैल 1998
13 चैत्र 1920 (शक)

April 3, 1998
Chaitra 13, 1920 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

To All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन -
“दि टोरोन्टो-डोमिनियन बैंक”

INCLUSION IN THE SECOND
SCHEDULE TO RESERVE BANK OF
INDIA ACT, 1934 - "THE TORONTO -
DOMINION BANK"

हम सूचित करते हैं कि दि टोरोन्टो डोमिनियन बैंक
का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की
दूसरी अनुसूची में 27 दिसंबर 1997 से अर्थात् 3
दिसंबर 1997 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.
सं. आईबीएस. 1226/23.13.079/97-98 के
भारत के राजपत्र (भाग-III-खंड 4) में प्रकाशित
होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है। बैंक
का पता निम्नलिखित है :

We advise that the name of "The Toronto-
Dominion Bank" has been included in the
Second Schedule to the Reserve Bank of
India Act, 1934 with effect from 27th
December 1997 i.e. the date on which the
relative Notification DBOD. No. IBS. 1226/
23.13.079/97-98 dated 3rd December 1997
was published in the Gazette of India (Part
III-Sec. 4). The address of the bank is as
under :

दि टोरोन्टो डोमिनियन बैंक,
86, फ्री प्रेस हाउस, 8वीं मंज़िल,
फ्री प्रेस जर्नल रोड,
215, नरीमन प्वाइंट,
मुंबई - 400 021.

The Toronto - Dominion Bank,
86, Free Press House, 8th Floor,
Free Press Journal Road,
215, Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

भवदीय

Yours faithfully,

(डी.वी. झवेरी)
महा प्रबंधक

(D.V. Jhaveri)
General Manager

11 अप्रैल 1998
21 चैत्र 1920 (शक)

April 11, 1998
Chaitra 21, 1920 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण,
प्रावधान तथा अन्य संबंधित मामले -
निवेशों का मूल्यन

INCOME RECOGNITION, ASSET
CLASSIFICATION, PROVISIONING
AND OTHER RELATED MATTERS -
VALUATION OF INVESTMENTS

कृपया आप 09 अप्रैल 1997 का परिपत्र सं. बीपी. बीसी. 30/21.04.048/97 देखें, जिसमें 31 मार्च 1997 की स्थिति के तुलनपत्र को अंतिम रूप देते समय बैंकों एवं लेखा-परीक्षकों द्वारा सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों के मूल्यन के लिए अपनायी जाने वाली पद्धति निर्धारित की गयी है। अब यह निर्णय किया गया है कि बैंक 31 मार्च 1998 की स्थिति के तुलनपत्र को अंतिम रूप देते समय संलग्न अनुबंध में बतायी गयी पद्धति अपनायें।

Please refer to our circular DBOD.No.BP.BC. 30/21.04.048/97 dated 9 April 1997 prescribing the method to be adopted by banks and auditors for valuation of Government and other securities while finalising the Balance Sheet as on 31 March 1997. It has now been decided that banks should adopt the method indicated in the Annexure, for the Balance Sheet as on 31 March 1998.

2. हम यह सूचित करते हैं कि अनुबंध में बतायी गयी मूल्यन की पद्धति के कारण प्रतिभूतियों के मूल्य में कोई वृद्धि होती हो तो उसे आय के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि कोई बैंक प्रतिभूतियों के मूल्यन की अब सुझायी जा रही पद्धति से इतर कोई अन्य विवेकपूर्ण पद्धति अपना रहे हों तो वे अब तक अपनायी जा रही प्रथा को जारी रखें।

2. In this connection we advise that if there is any appreciation in the value of securities on account of the method of valuation as indicated in the Annexure, it should **not** be booked as Income. Further, banks which have adopted a more prudent method of valuation of securities than the one now being suggested, may continue the practice hitherto followed by them.

भवदीय

Yours faithfully,

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

(C.R. Muralidharan)
General Manager

अनुबंध

ANNEXURE

निवेश श्रेणी बैंकों द्वारा अपनायी जानेवाली पद्धति

1. स्थायी निवेश (i) जैसा कि रिज़र्व बैंक के 3 अप्रैल 1995 के परिपत्र बीपी. बीसी. 37/21.04.048/95 के पैराग्राफ 7 में बताया गया है, “स्थायी” श्रेणी की प्रतिभूतियों की बिक्री से हुए प्रतिलाभ को पहले लाभ और हानि खाते में लिया जाना चाहिए और उसके बाद इसे “पूँजीगत प्रारक्षित निधि” खाते में विनियोजित किया जा सकता है।
- (ii) जैसा कि रिज़र्व बैंक के 3 अप्रैल 1995 के परिपत्र बीपी. बीसी. 37/21.04.048/95 के पैराग्राफ 1 में बताया गया है, “स्थायी” निवेशों का मूल्यन लागत पर किया जाना चाहिए और यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो तो प्रीमियम को प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए संक्रामित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम हो वहां इस अंतर को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए और उसे संक्रामित

Investment Category Method to be adopted by banks

1. Permanent Investments (i) As indicated in paragraph 7 of RBI Circular BP. BC.37/21.04.048/95 dated 3 April 1995 any gain on sale of securities in the 'Permanent' category should be first taken to the profit and loss account and thereafter it could be appropriated to "Capital Reserve".
- (ii) In terms of paragraph 1 of RBI Circular BP. BC.37/21.04.048/95 dated 3 April 1995, 'Permanent' investments should be valued at cost and in case cost price is higher than the face value, the premium should be amortised over the remaining period of maturity of the security. On the other hand, where the cost price is less than the face value,

अथवा आय खाते में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि उक्त राशि वसूल न किये गये प्रतिलाभ की द्योतक है।

2. चालू निवेश

“चालू” श्रेणी की सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन 31 मार्च 1998 को बाज़ार दरों, जहां उपलब्ध हों, पर किया जाना चाहिए। जहां बाज़ार दरें उपलब्ध न हों वहां सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन निम्नलिखित दर पर किया जाना चाहिए :

31 मार्च 1998 की स्थिति के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां, रिज़र्व बैंक की सूची में ब्रिकी के लिए थीं, उनके मूल्य नीचे दिये गये हैं :

प्रतिभूति का नाम
ब्रिकी मूल्य (रु. पैसे)

6.50% 2000	91.34
5.75% 2001	85.54
6.50% 2001	87.55

2. Current Investments

the difference should be ignored and should not be amortised or taken to income account since the amount represents unrealised gain.

Valuation of Government Securities in the 'Current' category should be done as per market quotations as on 31 March, 1998, wherever available. Where market quotations are **not available**, valuation of the Government Securities should be made on the following basis :

As on 31 March, 1998 the Central Government Securities which were on the RBI list for sale and their prices are given below :

Nomen- clature of security	Sale Price (Rs. Ps.)
6.50% 2000	91.34
5.75% 2001	85.54
6.50% 2001	87.55

12.69%	2002	104.47
11.15%	2002	99.36
5.75%	2003	78.40
6.50%	2004	77.74
8.25%	2005	82.52
6.75%	2006	73.59
13.05%	2007	105.52
7.00%	2009	68.94
11.50%	2010	95.88
9.00%	2013	78.38

6.00 प्रतिशत कैपिटल बांड्स, 2002 से इतर केन्द्र सरकार की अन्य प्रतिभूतियों के संबंध में 31 मार्च 1998 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित प्राप्तियां लागू की जानी चाहिए:

वर्षों की सं.	अवधिपूर्णता पर प्राप्ति (%)
0	9.43
1	10.50
2	10.83
3	11.09
4	11.28
5	11.40
6	11.57
7	11.73
8	11.88
9	12.02
10 और उससे अधिक	12.15

12.69%	2002	104.47
11.15%	2002	99.36
5.75%	2003	78.40
6.50%	2004	77.74
8.25%	2005	82.52
6.75%	2006	73.59
13.05%	2007	105.52
7.00%	2009	68.94
11.50%	2010	95.88
9.00%	2013	78.38

In respect of other Central Government Securities, other than the 6.00 per cent Capital Indexed Bonds 2002, the following yields as on March 31, 1998 may be applied :

No. of years	YTM (%)
0	9.43
1	10.50
2	10.83
3	11.09
4	11.28
5	11.40
6	11.57
7	11.73
8	11.88
9	12.02
10 and beyond	12.15

उपर्युक्त प्रतिफल राज्य सरकार की प्रतिभूतियों तथा सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

6.00 प्रतिशत कैपिटल इंडेक्स बांड्स का “लागत” पर मूल्यन 22 जनवरी 1998 के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीसी. 8/12.02.001/97-98 में दी गयी परिभाषा के अनुसार किया जाना चाहिए।

यह स्पष्ट किया जाता है कि अवधिपूर्णता पर प्राप्ति की उचित दरें तय करने के प्रयोजन हेतु वर्षों की संख्या का हिसाब एक वर्ष से कम की अवधि को निकटतम पूर्ण वर्ष तक लेकर लगाया जाना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कर योग्य बांडों के लिए ऊपर बतायी गयी सरकारी प्रतिभूतियों की अवधिपूर्णता पर प्रतिफल की दरों से एक प्रतिशत अधिक लागू किया जाना चाहिए।

The yields as indicated above should also be applied to the State Government Securities and Government Guaranteed Securities.

The 6.00 per cent Capital Indexed Bonds may be valued at 'Cost' as defined in Circular DBOD. No. BC. 8/12.02.001/97-98 dated January 22, 1998.

It is clarified that the reckoning of number of years for the purpose of deciding upon appropriate YTM Rate be done by rounding off the fractional period of an year to the nearest completed year.

For valuation of taxable PSU bonds, 1% above the YTM rates of Government Securities stated above should be applied.

Sec. X(e)

सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के करमुक्त बांडों के लिए अवधिपूर्णता पर प्रतिफल 10 प्रतिशत माना जाना चाहिए।

For tax free bonds of PSUs the expected 'Yield To Maturity' may be deemed as 10%.

जहां तक दर न दी जाने वाली अन्य प्रतिभूतियों के मूल्यन का संबंध है, बैंकों को चाहिए कि वे दर न दी जाने वाली प्रतिभूतियों का मूल्यन करने के लिए अवधिपूर्णता पर प्रतिफल की एकसमान पद्धति अपनायें।

As regards valuation of other unquoted securities banks should uniformly follow 'Yield To Maturity' method for arriving at valuation of unquoted securities.

3. शेयर

- (i) जहां शेयर बाज़ार की दरें उपलब्ध हों वहां शेयरों का मूल्यन तदनुसार किया जाना चाहिए।
- (ii) जिन शेयरों के मामले में चालू दरें उपलब्ध नहीं हैं अथवा शेयर बाज़ार में शेयर उद्धृत नहीं किये जाते, वहां उसे बही मूल्य पर (पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों, यदि कोई हो, पर विचार किये बिना) हिसाब में लिया जाना चाहिए। बही मूल्य का पता अद्यतन उपलब्ध तुलनपत्र से लगाया जाना चाहिए। यदि अद्यतन तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो शेयर का मूल्य एक रुपया प्रति कंपनी के

3. Shares

- (i) Wherever Stock Exchange quotations are available, the shares should be valued accordingly.
- (ii) In the case of shares for which Current quotations are not available or where the shares are not quoted on the Stock Exchanges, the same should be taken at Book Value (without considering Revaluation Reserves, if any) which is to be ascertained from the latest Balance

हिसाब से लगाया जाना चाहिए।

- (iii) सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के मामले में सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के शेयरों का मूल्यन 31 मार्च 1997 के तुलनपत्र के अनुसार अलग-अलग मूल्य पर किया जाना चाहिए। यदि 31 मार्च 1997 का तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो 31 मार्च 1996 के तुलनपत्र के अनुसार अलग-अलग मूल्य का हिसाब लगाया जाना चाहिए और उसको 20 प्रतिशत घटाया अथवा बढ़ा लगाया जाना चाहिए। यदि 31 मार्च 1996 का तुलनपत्र भी उपलब्ध न हो तो सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान के संबंधित शेयरों का मूल्य एक रुपया प्रति कंपनी लगाया जाना चाहिए, जैसा कि रिज़र्व बैंक के 19 मार्च 1996 के परिपत्र बैपविवि. सं. बीपी.बीसी. 25/21.04.048/96 के पैराग्राफ 5 में बताया गया है।

Sheet. In case latest Balance Sheet is not available, the shares are to be taken at Re. 1 per company.

- (iii) In the case of public sector companies, shares of PSUs should be valued at the break-up value as per the Balance Sheet as on 31 March, 1997. In case the 31 March, 1997 Balance Sheet is not available, the break-up value as per 31 March, 1996 Balance Sheet should be worked out and it should be reduced or discounted by 20%. If 31 March, 1996 Balance Sheet is also not available, the shares of the concerned PSUs should be valued at Re. 1 per company as indicated in paragraph 5 of RBI Circular DBOD. No. BP. BC. 25/21.04.048/96 dated 19 March, 1996.

4. डिबेंचर (1) जहां शेयर बाज़ार की दरें उपलब्ध हों वहां डिबेंचरों का मूल्यन तदनुसार किया जाना चाहिए।

(2) जहां कहीं चालू दर उपलब्ध न हो अथवा जहां डिबेंचर शेयर बाज़ार में उद्धृत न किये जाते हों तो उनका मूल्यन निम्न प्रकार किया जाना चाहिए:

क) कारोबारी (carrying) लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर, यदि ब्याज नियमित चुकाया जाता हो।

ख) जहां ब्याज की चुकौती नियमित नहीं है और इसलिए वह बकाया है तो मूल्यहास उसी तरह किया जाना चाहिए, जैसे कि अग्रिमों को अवमानक, संदिग्ध और हानि के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है।

5. पारस्परिक निधियों के यूनिट

पारस्परिक निधियों के यूनिटों में निवेश का मूल्यन प्रत्येक विशिष्ट योजना के संबंध में पारस्परिक निधि द्वारा घोषित अद्यतन शुद्ध आस्ति मूल्य के आधार पर

4. Debentures (i) Wherever Stock Exchange quotations are available, the debentures should be valued accordingly.

(ii) Wherever Current quotations are not available or where the debentures are not quoted on the Stock Exchanges the same should be valued as follows :

a) At Carrying Cost (i.e. book value), if interest is serviced regularly.

b) Where interest is not serviced regularly and as such, is in arrears, the Depreciation should be made on the same lines as advances classified as sub-standard, doubtful and loss.

5. Mutual Fund Units

Investment in Mutual Fund Units is to be valued based on latest NAV declared by the Mutual Fund in respect

किया जाना चाहिए।
तथापि यदि शेयर बाज़ार
की दरों के अनुसार बाज़ार
दरें उपलब्ध हों तो बाज़ार
दरें लगायी जानी चाहिए।

of each particular
Scheme. However,
if market rates are
available as per
Stock Exchange
quotations, market
rates should be
adopted.

6. सहायक कंपनी
और प्रायोजित
संस्थाओं में
निवेश प्रतिभूति का मूल्यन सतत
आधार पर कारोबारी
लागत (अर्थात् बही मूल्य)
पर किया जाना चाहिए।

6. Investments
in subsidiaries
and sponsored
institutions Security is to be
valued at Carrying
Cost (i.e. book
value) on a consis-
tent basis.

7. खज़ाना बिल
(सभी
अवधिपूर्णतायें) मूल्यन कारोबारी लागत
(अर्थात् बही लागत) पर
आधारित होना चाहिए।

7. Treasury Bills
(All maturities) Valuation may be
based at Carrying
Cost (i.e. book
value).

8. वाणिज्य पत्र वाणिज्य पत्र का मूल्यन
कारोबारी लागत (अर्थात्
बही लागत) पर किया
जाना चाहिए।

8. Commercial
Paper Commercial Paper
to be valued at Car-
rying Cost (i.e.
book value).

9. सामान्य मुद्दे
(i) पूर्णांक तक यह बैंक के विवेकानुसार
लाना (उदाहरणार्थ सतत आधार पर किया
निकटतम हजार जाना चाहिए।
तक)
(ii) निवेश तुलनपत्र के प्रयोजन के
श्रेणियां लिए निवेशों को
निम्नलिखित श्रेणियों में
वर्गीकृत किया गया है :

9. General Issues
(i) Rounding May be done at
off (e.g. to bank's discretion on
nearest 000s) a consistent basis.
(ii) Investment For the purpose of
Categories Balance Sheet, in-
vestments are to be
classified into the
following cate-
gories :

(iii) जोड़ लगाना	(क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिलों, ज़ीरो कूपन बांडों सहित)		(a) Government Se- curities (inclusive of T Bills, Zero Cou- pon bonds)
	(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		(b) Other approved securities
	(ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बांड		(c) Shares
	(ड) सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम (प्रायोजित संस्थाएं)		(d) Debentures and bonds
(iii) जोड़ लगाना	(च) अन्य (वाणिज्य पत्र, पारस्परिक निधियों के यूनिट आदि)		(e) Subsidiaries and Joint Ventures (sponsored institu- tions)
	(iii) जोड़ लगाना	(iii) Aggre- gation	(f) Others (CP, Mu- tual Fund Units, etc.)
	प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यन ऊपर बताये गये अनुसार स्क्रिपवार किया जायेगा और मूल्यहास/मूल्यवृद्धि का जोड़ श्रेणीवार लगाया जायेगा। शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए रिज़र्व बैंक के 19 मार्च 1996 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 25/21.04.048/96 के पैराग्राफ 4 में बताये गये अनुसार प्रावधान किया जायेगा। शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, नज़रअंदाज की जानी चाहिए। किसी एक श्रेणी में शुद्ध मूल्यहास के लिए अपेक्षित प्रावधान हो तो किसी अन्य श्रेणी में		Securities under each category shall be valued scrip-wise as indicated above and Depreciation/ Appreciation shall be aggregated cat- egory-wise. Net de- preciation, if any, shall be provided for as indicated in paragraph 4 of RBI Circular DBOD. No. BP. BC. 25/ 21.04.048/96 dated 19 March, 1996. Net Appreciation, if any, should be ig- nored. Net Depre- ciation required to

शुद्ध मूल्य वृद्धि के कारण उसे घटाया नहीं जाना चाहिए।

10. पुनर्पूजीकरण बांड

जैसा कि रिज़र्व बैंक के 3 अप्रैल 1995 के परिपत्र बीपी. बीसी. 37/21.04.048/95 के पैराग्राफ 5 में बताया गया है, पुनर्पूजीकरण बांड स्थायी अथवा चालू निवेशों के भाग नहीं होंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सरकार से प्राप्त पुनर्पूजीकरण बांडों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं होगा, परन्तु जिस मामले में बैंक दूसरे बैंकों से पुनर्पूजीकरण बांड निवेश प्रयोजनों के लिए प्राप्त करते हैं उनमें अथवा मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जायेगा।

10. Recapitalisation Bonds

be provided for in any one category should not be reduced on account of Net Appreciation in any other category.

As indicated in paragraph 5 of RBI Circular BP.BC. 37/21.04.048/95 dated 3 April 1995, the Recapitalisation Bonds will not form part of 'Permanent' or "Current" investments. It will not be necessary to provide for depreciation on the Recapitalisation Bonds received by the nationalised banks from Government. In case, however, banks acquire recapitalisation bonds of other banks for Investment purposes, the Depreciation, if any, will have to be provided for.

29 अप्रैल 1998
09 वैशाख 1920 (शक)

April 29, 1998
Vaishakha 9, 1920 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

पूँजी पर्याप्तता - तुलना पत्रों में
प्रकटीकरण

CAPITAL ADEQUACY, DISCLOSURES
IN BALANCE SHEETS

- (i) पूँजी पर्याप्तता - निवेशों के संबंध में
जोखिम भारांक
वर्तमान अनुदेशों (22 अप्रैल 1992 के
बैंपविवि. परिपत्र सं.बीपी.बीसी. 117/
21.01.002/92 का पैरा 6ए देखें) के
अंतर्गत सरकारी तथा अन्य न्यासी
प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों को शून्य
जोखिम भारांक तथा अन्य निवेशों को 100
प्रतिशत जोखिम भारांक दिया जाता है।

- (i) Capital Adequacy - Risk Weights in
respect of investments
Under the existing instructions (c.f.
para. 6A of DBOD. Circular No. BP.
BC. 117/21.01.002/92 dated April 22,
1992), investments in government and
other trustee securities carry zero risk
weight and other investments carry
100 per cent risk weight.

यह स्पष्ट किया जाता है कि इंदिरा विकास
पत्र/किसान विकास पत्र में किये गये निवेशों
को तथा उन बांडों और डिबेंचरों में किये गये
निवेशों को भी, जिनमें ब्याज और मूल धन
की अदायगी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा
गारंटीकृत होती है, शून्य जोखिम भारांक
प्राप्त होगा। अन्य सभी निवेशों को 100
प्रतिशत जोखिम भारांक दिया जायेगा।

It is clarified that investments in Indira
Vikas Patra/Kisan Vikas Patra (IVP/
KVP) and investments in Bonds and
Debentures where payment of interest
and principal is guaranteed by Central/
State Government shall also carry zero
risk weight. All other investments
shall carry 100 percent risk weight.

- (ii) तुलनापत्रों में प्रकटीकरण
27 जनवरी 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं.
बीपी. बीसी. 9/21.04.018/98 के पैरा 2
के अनुसार बैंकों से अनुरोध किया गया था

- (ii) Disclosures in Balance Sheets
In terms of paragraph 2 of circular
DBOD. No. BP. BC. 9/21.04.018/98
dated January 27, 1998, banks were

कि वे 31 मार्च 1998 के तुलनपत्र से 'लेखा टिप्पणी' में कुछ कारोबार अनुपात दर्शायें।

इस संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिये जा रहे हैं :

- (क) निम्नलिखित अनुपातों अर्थात् (i) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय, (ii) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय, (iii) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ में 'कार्यशील निधियों' की गणना वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के तहत फार्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित कुल आस्तियों (संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर) के औसत के रूप में की जानी चाहिए। तथापि, 'अस्तियों पर प्रतिलाभ' का अनुपात तुलनपत्र की तारीख को कार्यशील निधियों (अर्थात् संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर कुल आस्तियों) के संदर्भ में होगा।
- (ख) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियां तथा अग्रिम) की गणना के प्रयोजन के लिए अंतरबैंक जमाराशियों को निकाल दिया जाये।

advised to disclose certain business ratios in the 'Notes on accounts' commencing from the Balance Sheet as at 31st March 1998.

In this connection, it is clarified as under :

- (a) In the following ratios viz. (i) interest income as percentage to working funds, (ii) non-interest income as percentage to working funds, (iii) operating profit as percentage to working Funds, 'working funds' should be reckoned as average of total of assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in form X under Section 27 of Banking Regulation Act, 1949 during the 12 months of the financial year. However, the ratio of 'return on assets' would be with reference to working funds (i.e. total of assets excluding accumulated losses, if any) on the balance sheet date.
- (b) For the purpose of computation of the business per employee (deposits plus advances) inter bank deposits may be excluded.

भवदीय,

(सी.आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

Yours faithfully,

(C.R. Muralidharan)
General Manager

19 मई 1998
29 वैशाख 1920 (शक)

May 19, 1998
Vaishakha 29, 1920 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

लेखा मानदंड 11 (संशोधित)

ACCOUNTING STANDARD 11
(REVISED)

कृपया 5 जून 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 68/21.04.018/96 देखें, जो (i) विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं तथा राजस्व मदों के पुनर्मूल्यांकन एवं भारत में किये गये विदेशी मुद्रा लेनदेनों की बुकिंग और (ii) भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की आस्तियों एवं देयताओं के रूपांतरण के प्रयोजन के लिए एस 11 (संशोधित) लागू करने से संबंधित है। हम सूचित करते हैं कि बैंकों में एस 11 (संशोधित) लागू करने के मुद्दे की अभी भी जांच की जा रही है। 31 मार्च 1998 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंकों के तुलनपत्र को अंतिम रूप देने में होने वाले विलंब को टालने के लिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 5 जून 1996 के उक्त परिपत्र में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन लेखा वर्ष 1997-98 के लिए भी करें।

Please refer to our Circular DBOD. No. BP.BC. 68/21.04.018/96 dated June 5, 1996 regarding the applicability of AS 11 (Revised) for (i) revaluing foreign currency assets and liabilities and revenue items and booking of foreign exchange transactions done in India and (ii) for the purpose of translation of assets and liabilities of foreign branches of Indian banks. We advise that the issue of applicability of AS 11 (Revised) to banks is still under examination. With a view to avoiding delay in the finalisation of balance sheets of banks for the financial year ended 31 March, 1998, banks are advised to follow the guidelines prescribed in the above mentioned Circular dated June 5, 1996 for the Accounting Year 1997-98 also.

भवदीय

Yours faithfully,

(सी.आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

(C.R. Muralidharan)
General Manager

30 मई 1998
10 ज्येष्ठ 1920 (शक)

May 30, 1998
Jyestha 10, 1920 (Saka)

निजी क्षेत्र के सभी बैंकों के
अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध
निदेशक

The Chairman and Chief Executive
Officer/Managing Director of all
Private Sector Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक
आधिकारी द्वारा विदेश में आधिकारिक
दौरे

OFFICIAL VISITS ABROAD BY
CHAIRMAN AND CHIEF
EXECUTIVE OFFICER

कृपया 31 अक्टूबर 1992 का हमारा पत्र सं.
435/08.95.004/92 देखें, जिसके अनुसार भारत
के निजी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष और मुख्य
कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य कार्यपालक 10 से
12 दिन तक की अवधि के लिए अपने निदेशक
बोर्ड के अनुमोदन से संपर्कियों के साथ चर्चा करने,
संगोष्ठियों में भाग लेने आदि जैसे व्यावसायिक
प्रयोजनों के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं। यह
भी सूचित किया गया था कि बैंकों को इस विभाग
को एक सारांश रिपोर्ट भेजनी चाहिए जिसमें दौरे की
प्रमुख विशिष्टताएं तथा किये गये दौरे के अनुसरण
में इसके द्वारा शुरू किये गये विशिष्ट अनुवर्ती उपायों
संबंधी ब्यौरे दर्शाये गये हों।

Please refer to our Circular No. 435/
08.95.004/92 dated 31 October 1992 in
terms of which the Chairman and Chief
Executive Officer and other executives of
Indian private sector banks could undertake
visits abroad for business purposes like
holding discussions with correspondents,
participating in seminars etc., with the
approval of their Board of Directors, for a
period not exceeding 10 to 12 days. It was
also advised that the banks should send to
this Department a synopsis containing the
salient features of the visit and the details
regarding specific follow up measures,
initiated by it, in pursuance to the visit
undertaken.

2. हमने अब इस मामले की समीक्षा की है तथा
यह निर्णय लिया गया है कि अब से बैंकों को
अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अन्य
कार्यपालकों द्वारा किये गये विदेशी दौरों से संबंधित
रिपोर्टें प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

2. We have since reviewed the matter and
it has been decided that the banks need not
henceforth submit reports on overseas visits
undertaken by the Chairman and Chief
Executive Officer/other executives.

3. साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि बैंकों को मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक के आधिकारिक दौरे पर होने पर उनकी अनुपस्थिति में की गयी एवजी संबंधी व्यवस्थाओं के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10बी (9) के अंतर्गत हमारे पूर्वानुमोदन की भी आवश्यकता नहीं है। तथापि, किये गये दौरे और एवजी संबंधी व्यवस्थाओं के लिए बैंक के निदेशक बोर्ड का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दौरे तथा एवजी संबंधी की गयी व्यवस्थाओं की जानकारी दी जानी चाहिए।

4. जहां तक ऐसे दौरे के संबंध में विदेशी मुद्रा के निर्मोचन का संबंध है बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण मैनुअल, 1993 के अध्याय 8 के प्रावधानों से दिशा-निर्देश प्राप्त करें।

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चन्द्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

3. It is further advised that banks need not also seek our prior approval under Section 10B(9) of the B.R. Act, 1949 for substitute arrangements made in the absence of the Chief Executive Officer/Managing Director while he is on official tour. The visits and substitute arrangements made should, however, be with the prior approval of the Board of Directors of the bank. The concerned Regional Office of RBI may be kept informed of the visit and substitute arrangements made.

4. As regards release of exchange for such visits banks may be guided by the provisions of Chapter 8 of the Exchange Control Manual 1993.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

10 जुलाई 1998
18 आषाढ़ 1920 (शक)

July 10, 1998
Aashadha 18, 1920 (Saka)

अध्यक्ष,
निजी क्षेत्र के सभी भारतीय वाणिज्य बैंक

The Chairman,
All Indian Commercial Banks in the
Private Sector

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयर जारी करना

ISSUE OF SHARES BY PRIVATE SECTOR BANKS

कृपया उक्त विषयक 17 जून 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 76/16.13.100/94 देखें। परिपत्र के पैरा 4 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार, सभी प्रकार के शेयर अर्थात् सार्वजनिक, अधिमान, अधिकार/कर्मचारियों को विशेष आबंटन तथा बोनस शेयर जारी करने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षित है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करें। इन अनुदेशों की समीक्षा की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में उन बैंकों को, जिनके शेयर शेयर-बाजारों में सूचीबद्ध हैं, बोनस शेयरों को छोड़कर अन्य प्रकार के शेयर जारी करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, बैंकों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के सुसंगत विनियमों का अनुपालन करना चाहिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो, उनका अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

Please refer to our Circular DBOD. No. BC. 76/16.13.100/94 dated June 17, 1994 on the abovementioned subject. In terms of instructions given in paragraph 4 of the Circular, banks in the private sector are required to obtain prior approval of Reserve Bank of India (RBI) for issue of all types of shares viz. public, preferential, rights/special allotment to employees and bonus shares. These instructions have been reviewed and it has been decided that in future, banks **whose shares are listed on the stock exchanges** need not seek prior approval of RBI for issue of shares **except Bonus shares**. The banks should, however, comply with relevant regulations of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and seek their approval, wherever necessary.

2. जब कभी किसी बैंक द्वारा उक्त श्रेणी के शेयर जारी किये जायें, उन्हें निर्गम के पूरे ब्यौरे देते

2. As and when issues of the above categories of shares are made by a bank, it

हुए हमारे पास एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए।

3. जैसा कि ऊपर दर्शाया जा चुका है, बैंकों को बोनस शेयर जारी करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करते रहना चाहिए।

भवदीय

(एल. डिसूजा)

महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.एमसी.02/19.06.02/97-98

20 जुलाई 1998
29 आषाढ़ 1920 (शक)

निजी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष

प्रिय महोदय,

अप्रैल 1998 - मार्च 2000 की अवधि के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों हेतु कार्य योजना

कृपया कार्य योजना बनाने का कार्य जारी रखने और योजना अवधि को अप्रैल 1996 से मार्च 1998 तक बढ़ाने के संबंध में 15 जुलाई 1996 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एमसी. 2/19.06.01/96-97 का अवलोकन करें। जैसा कि आप जानते हैं, बैंक 28 जुलाई 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एमसी. 14/19.06.01/94-95 के साथ परिचालित फॉर्मेट में, जिसमें 4 सितंबर 1996 के हमारे परिपत्र

should submit a report to us giving full details of the issue.

3. As indicated above, banks should continue to obtain prior approval of RBI for issue of Bonus shares.

Yours faithfully,

(L. D'Souza)

General Manager

DBOD.No. MC.02/19.06.02/97-98

July 20, 1998
Ashadha 29, 1920 (Saka)

The Chairmen of Private Sector Banks

Dear Sir,

ACTION PLAN FOR PRIVATE SECTOR BANKS FOR THE PERIOD APRIL 1998 - MARCH 2000

Please refer to our circular letter DBOD. No. MC. 2/19.06.01/96-97 dated 15th July 1996 regarding continuation of the Action Plan exercise and extending the plan period from April 1996 to March 1998. As you are aware, banks have been submitting to us their half yearly progress reports in the format circulated with our circular letter DBOD.

बैंपविवि.सं.एमसी. 15/19.06.01/96-97 के अनुसार बाद में संशोधन किया गया था, अपनी छमाही प्रगति रिपोर्टें भेजते रहे हैं। हम बैंकों के वित्तीय निरीक्षणों से ज्ञात पूंजी पर्याप्तता, वित्तीय स्थिति, अनर्जक आस्तियों में कमी, लाभप्रदता तथा उनके परिलाचनों से संबंधित अन्य प्रमुख पहलुओं एवं कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन में की गयी प्रगति की समीक्षा उनके अध्यक्षों/मुख्य कार्यपालकों के साथ आवधिक चर्चा के दौरान करते रहे हैं।

2. चर्चाओं के महत्व और बैंक की कार्यप्रणाली के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की समीक्षा प्रक्रिया पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि आपके बैंक के लिए कार्य योजना बनाने का कार्य जारी रखा जाये। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप मोटे तौर पर वर्तमान निर्देशों के आधार पर अप्रैल 1998 से मार्च 2000 तक की अवधि के लिए उपयुक्त कार्य योजना तैयार करें, जिसमें पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने, बेहतर ऋण प्रबंधन, अतिदेयों की वसूली, उपयुक्त लक्ष्यों के साथ अनर्जक अग्रिमों में कमी, प्रति कर्मचारी कारोबार के आधार पर बढ़ी हुई उत्पादकता, आय में वृद्धि और समग्र लाभप्रदता में सुधार के लिए व्यय पर नियंत्रण तथा 'वाई'2 के की समस्या के निवारण सहित कंप्यूटरीकरण की दिशा में उठाये गये कदमों के संबंध में बैंक की रणनीति का उल्लेख किया गया हो।

No. MC. 14/19.06.01/94-95 dated 28th July 1994 and subsequent amendments thereto vide our circular letter DBOD. No. MC.15/19.06.01/96-97 dated 4th September 1996. We have also been holding periodical discussions with the Chairmen/Chief Executives of banks reviewing the capital adequacy, financial position, reduction in non-performing assets, profitability and other major aspects relating to the operations of the banks as revealed in their financial inspections as also the progress made in the implementation of Action Plans.

2. Considering the importance of the discussions and review machinery in vital areas of the bank's functioning, it has been decided to continue with the action plan exercise for your bank. You are, therefore, advised to draw suitable action plan for the period from April 1998 to March 2000 broadly on the existing lines spelling out the strategy of the bank for strengthening the capital base, better credit administration, recovery of overdues, reduction of non-performing advances with suitable targets, increased productivity in terms of business per employee, increase in income and control over expenditure for improvement in overall profitability and steps taken towards computerisation (including compliance with Y2K problem). You may like to draw up the plan in the light of the experience gained by the bank as also the problems your bank is likely to encounter during the Action plan period 1998-2000.

आशा है कि आप यह योजना बैंक द्वारा अर्जित अनुभवों तथा कार्य योजना अवधि 1998-2000 के दौरान आपके बैंक के समक्ष आ सकने वाली समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में तैयार करेंगे। यह योजना दस्तावेज़ अगस्त 1998 के अंत तक हमारे उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाये जिसके क्षेत्राधिकार में आपके बैंक का प्रधान कार्यालय आता है तथा उसकी एक प्रतिलिपि हमें भी भेजी जाये। वर्तमान फार्मेट में आकड़े/प्रगति रिपोर्टें मार्च और सितंबर के अंत तक हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को तथा हमें छमाही अंतरालों पर इस प्रकार भेजी जाएं ताकि वे क्रमशः 15 मई और 15 नवंबर तक प्राप्त हो जाएं। बैंक यह सुनिश्चित करें कि ये प्रगति रिपोर्टें भारतीय रिज़र्व बैंक को उपर्युक्त तारीखों से पूर्व निश्चित रूप से प्रस्तुत कर दी जाएं।

भवदीया

(सुधा दामोदर)

सहायक महा प्रबंधक

बैंपविवि.बीपी.बीसी.73/21.04.018/98

27 जुलाई 1998

5 श्रावण 1920 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

अंतर शाखा खाते-पुरानी बकाया जमा प्रविष्टियां

28 फरवरी 1991 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 91/सी. 686-91 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार बैंकों को जमा की स्थिति में 'अन्य

Sec. X(e)

The plan document should be sent by end of August 1998 to our Regional Office under whose jurisdiction your bank's Head Office is functioning. A copy of the same should also be sent to us. The data/progress reports in the **existing format** as at the end of March and September may be submitted to our Regional Office and also to us at half yearly intervals so as to reach us by 15th May and 15th November respectively. The banks should ensure that the progress reports are submitted to RBI positively before the above dates.

Yours faithfully,

(Sudha Damodar)

Assistant General Manager

DBOD.No. BP.BC.73/21.04.018/98

July 27, 1998

Shravana 5, 1920 (Saka)

All Commercial Banks

(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

**INTER-BRANCH ACCOUNTS - OLD
OUTSTANDING CREDIT ENTRIES**

In terms of instructions contained in our circular DBOD. No. BP. BC. 91/C.686-91 dated February 28, 1991 banks are required

देयताएं और प्रावधान' (अनुसूची 5) के अंतर्गत तथा नामे की स्थिति में 'अन्य आस्तियां' (अनुसूची 11) के अंतर्गत अंतर-शाखा खाते में निवल शेषराशि दर्शानी है। ऐसा पाया गया है कि कुछ बैंकों में अंतर-शाखा खातों के समाधान का काफी कार्य बकाया है जो गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मामले की ब्यौरेवार जांच की गयी है तथा यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को पहले अंतर-शाखा खाते में पांच साल से अधिक समय से बकाया जमा प्रविष्टियों को अलग करना चाहिए तथा उन्हें एक पृथक् अवरुद्ध खाते में अंतरित करना चाहिए और तुलनपत्र में इसे 'अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य' (अनुसूची 5) के अंतर्गत दर्शाना चाहिए। अनुसूची 5 अथवा 11, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत शामिल करने के लिए अंतर-शाखा लेनदेनों की निवल राशि का पता लगाते समय अवरुद्ध खाते की कुल राशि निकाल देनी चाहिए तथा सिर्फ शेष जमा प्रविष्टियों संबंधी राशि को नामे प्रविष्टियों के प्रति समायोजित करना चाहिए। अवरुद्ध खाते की शेष राशि की गणना प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात के रखरखाव के प्रयोजन के लिए की जाएगी।

2. साथ ही हम यह भी सूचित करते हैं कि अवरुद्ध खाते से किसी भी समायोजन की अनुमति 2 अधिकारियों द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर ही दी जानी चाहिए जिनमें से एक संबंधित शाखा से बाहर का होना चाहिए, राशि एक लाख रुपये से अधिक होने पर वह अधिमानतः नियंत्रक/प्रधान कार्यालय का होना चाहिए।

भवदीय

(अमलेन्दु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

to show net balance in Inter-branch Account under 'Other Liabilities and Provisions' (Schedule 5) when in credit and under 'Other Assets' (Schedule 11) when in debit. It has been observed that some banks have large arrears in the reconciliation of inter-branch Accounts which is a cause for serious concern. The matter was examined in detail recently and it has been decided that banks should first segregate the credit entries outstanding for more than five years in inter-branch Account and transfer them to a separate Blocked Account and show it under 'Other Liabilities and Provisions - Others' (Schedule 5) in the Balance Sheet. While arriving at the Net amount of Inter-branch transactions for inclusion under Schedule 5 or 11 as the case may be, the aggregate amount of Blocked Account should be excluded and only the amount representing the remaining credit entries should be netted against debit entries. The balance in the Blocked Account will be reckoned for the purpose of maintenance of CRR/SLR.

2. We further advise that any adjustment from the Blocked Account should be permitted only with the authorisation of 2 officials, one of whom should be from outside the Branch concerned, preferably from the Controlling/Head Office if the amount exceeds Rupees one lakh.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

10 सितंबर 1998
19 भाद्र 1920 (शक)

September 10, 1998
Bhadra 19, 1920 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली

ASSET - LIABILITY MANAGEMENT
(ALM) SYSTEM

आपको विदित ही है कि रिज़र्व बैंक ने बैंकों में जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रणालियों के एक भाग के रूप में आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली को ठीक से लागू करने के लिए हम चलनिधि संबंधी जोखिम और ब्याज दर जोखिम को मापने के लिए स्थूल दिशा निर्देश संलग्न कर रहे हैं। इस पत्र के साथ भेजे गये दिशानिर्देशों का उद्देश्य आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली के लिए अपेक्षित आंकड़ों के संग्रह, संकलन और विश्लेषण के लिए उपाय प्रारंभ करने हेतु आदान-प्रदान करना है। आप इन दिशा-निर्देशों का अध्ययन करें और इस प्रणाली के कार्यान्वयन के बारे में अपने सुझाव तथा आनेवाली कठिनाइयां, यदि कोई हों, हमें बतायें।

As you are aware, the RBI has decided to introduce the Asset-Liability Management (ALM) System, as a part of the Risk Management and control Systems in banks. We forward herewith broad Draft guidelines for measurement of liquidity risk and interest rate risk for putting in place the ALM System. The guidelines sent with this letter are intended to form the basis for initiating measures for collection, compilation and analysis of data required to support the ALM System. You may study the guidelines and forward to us your suggestions and difficulties, if any, that may be encountered in implementation of the system.

2. आप देखेंगे कि बैंकों को अपने व्यवहारगत और मौसमी (सीजनल) स्वरूप का अध्ययन करने के लिए भूतकाल के आंकड़ों का विश्लेषण करना होगा और तुलनपत्र से इतर मदों सहित आस्ति और देयताओं के विभिन्न घटकों की अवधिपूर्णता की रूपरेखा तैयार करने के लिए अपेक्षित आधार मानक (बेंचमार्क) तय करने होंगे। ये दिशा-निर्देश उन

2. You will observe that the banks will have to analyse the past data for studying their behavioural and seasonal pattern and fix the benchmarks required for preparing maturity profile of various components of Assets and Liabilities including Off-Balance Sheet Items. The guidelines would serve as

बैंकों के लिए एक आधार के रूप में सहायक होंगे जिनमें औपचारिक आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली नहीं है। जिन बैंकों ने पहले ही अधिक परिष्कृत (सोफिस्टिकेटेड) प्रणालियां अपना ली हैं वे अपनी वर्तमान प्रणालियां जारी रख सकते हैं लेकिन उन्हें अपनी सूचना और रिपोर्टिंग प्रणालियों को अधिक बेहतर बनाना चाहिए। बैंकों को ब्याज दर के घटबढ़ के लिए भी राय बनानी होगी तथा अंतरालों पर विवेकपूर्ण सीमायें निर्धारित करनी होंगी। इस कार्य के लिए निरंतर समीक्षा किये जाने और सूचना अद्यतन किये जाने की जरूरत होगी। अतः हमारा सुझाव है कि बैंक महा प्रबंधक (निधि प्रबंधन/खजाना) के प्रभार के अधीन तत्काल एक छोटा समूह गठित करें जिसमें निवेश, विदेशी मुद्रा ऋण और प्रबंधन सूचना विभागों/क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हों तथा उन्हें आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली के लिए आधार-कार्य तैयार करने का काम सौंपा जायें।

3. निधि प्रबंधन/खजाना (ट्रेजरी) के प्रभारी महा प्रबंधक को 'केन्द्रीय (नोडल) अधिकारी' के रूप में नामित किया जाये, जो प्रस्तावित आस्ति-देयता प्रणाली और दिशा-निर्देशों के संबंध यदि कोई स्पष्टीकरण चाहिए हों तो उसके लिए रिज़र्व बैंक (वर्तमान में श्री सलीम गंगाधरन, उप महाप्रबंधक, केन्द्रीय बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, टेलीफोन नं. 2184936) से संपर्क में रहे। उक्त केन्द्रीय अधिकारी का नाम, पता, टेलीफोन नंबर (साथ टेलेक्स/फैक्स नं. भी) हमें तत्काल बताया जाये।

4. उक्त विषय पर जानकारी प्रदान करने और उसे व्यापक रूप से दूसरों तक पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि बैंकर प्रशिक्षण

a benchmark for those banks which lack a formal ALM System. Banks which have already adopted more sophisticated systems may continue their existing systems but they should fine-tune their Information and Reporting Systems. The banks shall also have to take views on the interest rate movements and fix prudential limits on the Gaps. The exercise will require constant review and updating. We therefore, suggest that banks may immediately set up a small Group under the charge of the General Manager (Funds Management/Treasury) with senior officers drawn from Investments, Foreign Exchange, Credit and Management Information departments/areas and entrust them with the tasks of preparing the ground work for implementation of the ALM System.

3. The General Manager in-charge of Funds Management/Treasury may be designated as the 'Nodal Officer' who should be in touch with the RBI (viz. for the present Shri Salim Gangadharan, Deputy General Manager, Central DBOD - Telephone Number is 2184936) for clarifications, if any, required in regard to the proposed ALM System and guidelines. The name, address and Telephone Number (also Telex/Fax Number) of the Nodal Officer may be advised to us immediately.

4. In order to disseminate and impart knowledge on the subject, it has been decided to hold 2/3 days' seminars in

महाविद्यालय, मुंबई में 2/3 दिन का सेमिनार आयोजित किया जाये, ताकि बैंक प्रारंभिक कठिनाईयों को हल कर सकें और प्रणाली को सहज रूप में कार्यान्वित कर सकें।

5. बैंक प्रस्तावित आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली 1 अप्रैल 1999 से अवश्य लागू कर दें। हमारा अनुरोध है कि आप इस विषय में अपने विचार (फीडबैक) 15 अक्टूबर 1998 तक भेज दें। इस विषय पर एक औपचारिक परिपत्र जनवरी 1999 में जारी किया जायेगा।

6. बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासले समिति द्वारा जारी किये गये आलेख - 'ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के सिद्धांत' और 'चलनिधि मापने और प्रबंधन के लिए एक ढांचा' बैंकों की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए संलग्न है।

भवदीय

(अमर्लेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

Bankers Training College, Mumbai in November 1998 to enable banks to overcome initial difficulties and to implement the system smoothly.

5. Banks should introduce the proposed ALM System positively from April 1, 1999. We shall be glad to receive feed-back from you on the subject before October 15, 1998. A formal Circular will be issued to banks on the subject some time in January 1999.

6. Papers on "Principles for the Management of Interest Rate Risk" and "A Framework for Measuring and Managing Liquidity" issued by the Basle Committee on Banking Supervision, are enclosed for information and guidance of banks.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

बैंकों में आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली- दिशा निर्देश

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय वित्तीय बाजारों में बड़ी तेजी से व्यापक परिवर्तन हुए हैं। आस्तियों और देयताओं सहित कारोबार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा तथा देशी ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा दरों में बढ़ती हुई अस्थिरता से क्रय-विक्रय दरों के बीच अंतर, लाभप्रदता, दीर्घावधि अर्थक्षमता के बीच अच्छा संतुलन बनाये रखने में बैंकों के प्रबंध तंत्र पर दबाव आया है। इन दबावों के कारण विकासगत और व्यापक उपाय किये जाने की जरूरत है न कि केवल तदर्थ कार्रवाई की। बैंकों के प्रबंध तंत्रों को अपने कारोबारी निर्णयों को कंपनी नीति द्वारा संचालित गत्यात्मक और समन्वित जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया पर आधारित करना होगा। अपने कारोबार के दौरान बैंकों के सामने कई बड़े जोखिम आते हैं जैसे - ऋण जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम, इक्विटी/पण्य मूल्य जोखिम, चलनिधि जोखिम तथा परिचालन जोखिम।

2. इस नोट में बैंकों में ब्याज दर और चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, जो आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) कार्य का हिस्सा हैं, के संदर्भ में स्थूल दिशा-निर्देश दिये गये हैं। आस्ति-देयता प्रबंधन कार्य के प्रारंभ में इस बात पर ध्यान देना होगा कि जोखिम प्रबंधन अनुशासन लागू किया जाये, जैसे निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के बाद कारोबार प्रबंध किया जाये। अच्छे जोखिम प्रबंध कार्यक्रमों का उद्देश्य यह होना चाहिए कि ये कार्यक्रम बैंक प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण साधन का काम करें।

ASSET - LIABILITY MANAGEMENT SYSTEM IN BANKS - GUIDELINES

Over the last few years the Indian financial markets have witnessed wide ranging changes at fast pace. Intense competition for business involving both the assets and liabilities, together with increasing volatility in the domestic interest rates as well as foreign exchange rates, has brought pressure on the management of banks to maintain a good balance among spreads, profitability and long-term viability. These pressures call for structured and comprehensive measures and not just ad hoc action. The Management of banks has to base their business decisions on a dynamic and integrated risk management system and process, driven by corporate strategy. Banks are exposed to several major risks in the course of their business - credit risk, interest rate risk, foreign exchange risk, equity/commodity price risk, liquidity risk and operational risks.

2. This note lays down broad guidelines in respect of interest rate and liquidity risks management systems in banks which form part of the Asset-Liability Management (ALM) function. The initial focus of the ALM function would be to enforce the risk management discipline viz. managing business after assessing the risks involved. The objective of good risk management programmes should be that these programmes will evolve into a strategic tool for bank management.



Sec. X(e)

3. आस्ति-देयता प्रबंधन प्रक्रिया तीन स्तंभों पर आधारित है:

- आस्ति देयता प्रबंधन सूचना प्रणाली:
 - ⇒ प्रबंधन सूचना प्रणाली
 - ⇒ सूचना उपलब्धता, सम्यकता, पर्याप्तता और कालोचितता
- आस्ति-देयता प्रबंधन संगठन
 - ⇒ संरचना और जिम्मेदारियां
 - ⇒ सर्वोच्च प्रबंध तंत्र के शामिल होने का स्तर
- आस्ति-देयता प्रबंधन प्रक्रिया
 - ⇒ जोखिम के मानदंड
 - ⇒ जोखिम का पता लगाना
 - ⇒ जोखिम को मापना
 - ⇒ जोखिम प्रबंधन
 - ⇒ जोखिम संबंधी नीतियां और सहन (टालरेंस) स्तर

4. आस्ति-देयता प्रबंधन सूचना प्रणाली सूचना आस्ति-देयता प्रबंधन प्रक्रिया की कुंजी है। शाखाओं के व्यापक जाल तथा आस्ति-देयता प्रबंधन, जिसके अंतर्गत शेष समाप्ति अवधि और प्रवृत्ति के स्वरूप के आधार पर सूचना का विश्लेषण किया जाता है, के लिए अपेक्षित सूचना इकट्ठी करने हेतु पर्याप्त प्रणाली के अभाव को देखते हुए बैंकों को वर्तमान स्थिति में अपेक्षित सूचना प्राप्त करने में समय लगेगा। आस्ति-देयता प्रबंधन की समस्या को एबीसी दृष्टिकोण अपनाकर हल किये जाने की जरूरत है अर्थात् कारोबार के बड़े हिस्सेवाली सर्वोच्च शाखाओं में आस्ति और देयता उत्पादों की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना और फिर विवेकपूर्ण ढंग से यह अनुमान लगाना कि अन्य शाखाओं में आस्तिओं और देयताओं की प्रवृत्ति क्या रहेगी। विदेशी मुद्रा, निवेश संविभाग और मुद्रा बाजार के कार्यकलापों के संदर्भ में, कार्यों के

3. The ALM process rests on three pillars :

- ALM information systems
 - ⇒ Management Information Systems
 - ⇒ Information availability, accuracy, adequacy and expediency
- ALM organisation
 - ⇒ Structure and responsibilities
 - ⇒ Level of top management involvement
- ALM process
 - ⇒ Risk parameters
 - ⇒ Risk identification
 - ⇒ Risk measurement
 - ⇒ Risk management
 - ⇒ Risk policies and tolerance levels.

4. ALM Information systems

Information is the key to the ALM process. Considering the large network of branches and the lack of an adequate system to collect information required for ALM which analyses information on the basis of residual maturity and behavioural pattern it will take time for banks in the present state to get the requisite information. The problem of ALM needs to be addressed by following an ABC approach i.e. analysing the behaviour of asset and liability products in the top branches accounting for significant business and then making rational assumptions about the way in which assets and liabilities would behave in

केन्द्रीकृत स्वरूप को देखते हुए, विश्वसनीय सूचना प्राप्त करना अधिक आसान होगा। आस्ति-देयता प्रबंधन के अंदर कारोबार चलाने का अनुभव प्राप्त करने के बाद बैंक प्रबंध तंत्र कुछ समय बाद आंकड़ों और अनुमानों को परिष्कृत बना सकते हैं। कम्प्यूटरीकरण के विस्तार से बैंकों को आंकड़े प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

5. आस्ति-देयता प्रबंधन संगठन

5.1 (क) जोखिम के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी बोर्ड की होनी चाहिए और उसे बैंक की जोखिम प्रबंधन कार्यनीति निश्चित करनी चाहिए तथा चलनिधि, ब्याज दर एवं विदेशी मुद्रा तथा इक्विटी मूल्य जोखिम के लिए सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए।

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित बैंक के वरिष्ठ प्रबंध तंत्र युक्त आस्ति-देयता समिति बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा बैंक के बजट के अनुरूप (आस्ति और देयता भाग में) बैंक की कारोबारी नीति निश्चित करने एवं जोखिम प्रबंधन के लक्ष्य निश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

other branches. In respect of foreign exchange, investment portfolio and money market operations, in view of the centralised nature of the functions, it would be much easier to collect reliable information. The data and assumptions can then be refined over time as the bank management gain experience of conducting business within an ALM framework. The spread of computerisation will also help banks in accessing data.

5. ALM organisation

5.1 a) The Board should have overall responsibility for management of risks and should decide the risk management policy of the bank and set limits for liquidity, interest rate, foreign exchange and equity price risks.

b) The Asset-Liability Committee (ALCO) consisting of the bank's senior management including CEO should be responsible for ensuring adherence to the limits set by the Board as well as for deciding the business strategy of the bank (on the assets and liabilities sides) in line with the bank's budget and decided risk management objectives.

(ग) परिचालन स्टाफ युक्त आस्ति-देयता प्रबंधन डेस्क जोखिम रूपरेखा का विश्लेषण करने, निगरानी करने और आस्ति-देयता समिति को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। स्टाफ द्वारा तुलनपत्र से संबंधित बाजार की स्थितियों में विभिन्न संभावनाओं के प्रभाव दर्शानेवाले अनुमान (अनुकरण/सिमुलेशन) भी तैयार किये जाने चाहिए तथा बैंक की आंतरिक सीमाओं का पालन करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की सिफारिश की जानी चाहिए।

c) The ALM desk consisting of operating staff should be responsible for analysing, monitoring and reporting the risk profiles to the ALCO. The staff should also prepare forecasts (simulations) showing the effects of various possible changes in market conditions related to the balance sheet and recommend the action needed to adhere to bank's internal limits.

5.2 आस्ति-देयता समिति निर्णय करनेवाली एक ऐसी इकाई है जो ब्याज दर तथा चलनिधि जोखिमों के कुशल प्रबंधन सहित जोखिम-वापसी (रिस्क रिटर्न) दृष्टिकोण से तुलनपत्र आयोजना के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक बैंक को अपनी आस्ति-देयता समिति की भूमिका, उसकी जिम्मेदारियों तथा उसके द्वारा लिये जानेवाले निर्णयों के बारे में निर्णय लेना होगा। बैंक की कारोबार और जोखिम प्रबंधन नीति में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंक बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं/मानदंडों के भीतर कार्य करे। आस्ति-देयता समिति अन्य बातों के साथ-साथ जिन कारोबारी मुद्दों पर विचार करेगी उनमें जमाराशियों और अग्रिमों के लिए उत्पाद मूल्यनिर्धारण, वृद्धिशील आस्तियों और देयताओं की वांछित अवधिपूर्णता रूपरेखा आदि शामिल हैं। बैंक के जोखिम स्तरों की निगरानी करने के अलावा उक्त समिति द्वारा पिछली बैठकों में लिये गये निर्णयों के परिणामों तथा उनके कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा भी की जानी चाहिए। साथ ही उक्त समिति बैंक का चालू ब्याज दर दृष्टिकोण स्पष्ट करेगी और इस दृष्टिकोण के आधार पर भावी कारोबार नीति के लिए अपने निर्णय लेगी। उदाहरण

5.2 The ALCO is a decision making unit responsible for balance sheet planning from risk-return perspective including the strategic management of interest rate and liquidity risks. Each bank will have to decide on the role of its ALCO, its responsibility as also the decisions to be taken by it. the business and risk management strategy of the bank should ensure that the bank operates within the limits/parameters set by the Board. The business issues that an ALCO would consider, inter alia, will include product pricing for both deposits and advances, desired maturity profile of the incremental assets and liabilities, etc. In addition to monitoring the risk levels of the bank, the ALCO should review the results of and progress in implementation of the decisions made in the previous meetings. The ALCO would also articulate the current interest rate view of

के लिए निधीकरण नीति के संदर्भ में इसकी जिम्मेदारी देयताओं के स्रोत तथा देयताओं के रूपों या आस्तियों की बिक्री के संबंध में निर्णय लेना होगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उसे ब्याज दर उतार-चढ़ाव की भावी दिशा के बारे में दृष्टिकोण विकसित करना होगा और नियत बनाम (वर्सेस) अस्थायी दर निधियों, थोक बनाम खुदरा जमा राशियों, मुद्रा बाज़ार बनाम पूंजी बाज़ार निधीकरण, देशी बनाम विदेशी मुद्रा निधीकरण आदि में से निधीकरण के मिले-जुले रूप का निश्चय करना होगा। अलग-अलग बैंक को अपनी आस्ति-देयता समिति की बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता निश्चित करनी होगी।

5.3 आस्ति-देयता समिति का गठन

आस्ति-देयता समिति का आकार (सदस्यों की संख्या) प्रत्येक संस्था के आकार, कारोबार के स्वरूप तथा संगठनात्मक जटिलता पर निर्भर करेगा। सर्वोच्च प्रबंध तंत्र की वचनबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक द्वारा इस समिति की अध्यक्षता की जानी चाहिए। निवेश, ऋण, निधि प्रबंधन/ट्रेजरी (विदेशी मुद्रा और देशी), अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और आर्थिक अनुसंधान विभागों के प्रमुखों को इस समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग के प्रमुख को भी प्रबंध सूचना प्रणाली सुदृढ़ करने तथा संबंधित कंप्यूटरीकरण के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। कुछ बैंकों में उप-समितियां भी हो सकती हैं।

the bank and base its decisions for future business strategy on this view. In respect of the funding policy, for instance, its responsibility would be to decide on source and mix of liabilities or sale of assets. Towards this end, it will have to develop a view on future direction of interest rate movements and decide on a funding mix between fixed vs floating rate funds, wholesale vs retail deposits, money market vs capital market funding, domestic vs foreign currency funding, etc. Individual banks will have to decide the frequency for holding their ALCO meetings.

5.3 Composition of ALCO

The size (number of members) of ALCO would depend on the size of each institution, business mix and organisational complexity. To ensure commitment of the Top Management, the CEO/CMD or ED should head the Committee. The Chiefs of Investment, Credit, Funds Management/Treasury (forex and domestic), International banking and Economic Research can be members of the Committee. In addition the Head of the Information Technology Division should also be an invitee for building up of MIS and related computerisation. Some banks may even have sub-committees.

5.4 निदेशकों की समिति

बैंकों को एक व्यावसायिक प्रबंधकीय और पर्यवेक्षी समिति भी गठित करनी चाहिए जिसमें तीन-चार निदेशक हों जो प्रणाली के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी तथा उसके कार्य की आवधिक समीक्षा करेगी।

5.5 आस्ति-देयता प्रबंधन प्रक्रिया

आस्ति-देयता प्रबंधन के कार्य-क्षेत्र को निम्नप्रकार दर्शाया जा सकता है:

- चलनिधि जोखिम प्रबंधन
- बाज़ार जोखिमों का प्रबंधन (ब्याज दर जोखिम सहित)
- निधीकरण और पूंजी आयोजना
- लाभ आयोजना और वृद्धि प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन)
- व्यापारिक जोखिम प्रबंधन

इस नोट में दिये गये दिशा-निर्देश मुख्य रूप से चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों से संबंधित हैं।

6. चलनिधि जोखिम प्रबंधन

6.1 चलनिधि की आवश्यकताओं को मापना और उनका प्रबंधन वाणिज्य बैंकों की महत्वपूर्ण गतिविधि है। देयताएं देय होते ही उनको पूरा करने की किसी बैंक की क्षमता को सुनिश्चित कर चलनिधि प्रबंधन द्वारा प्रतिकूल स्थिति बनने की संभावना को कम किया जा सकता है। चलनिधि के महत्व को अलग-अलग संस्थाओं से ऊपर उठकर देखना होगा क्योंकि एक संस्था में चलनिधि में कमी का संपूर्ण तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। बैंक प्रबंधनों को निरंतर आधार पर न केवल बैंकों की चलनिधि स्थितियों को मापना चाहिए बल्कि इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि संकट की परिस्थितियों में चलनिधि की अपेक्षाएं क्या रूप

5.4 Committee of Directors

Banks should also constitute a professional managerial and Supervisory Committee consisting of three to four directors which will oversee the implementation of the system and review its functioning periodically.

5.5 ALM process :

The scope of ALM function can be described as follows :

- Liquidity risk management
- Management of market risks (including Interest Rate Risk)
- Funding and capital planning
- Profit planning and growth projection
- Trading risk management

The guidelines given in this note mainly address Liquidity and Interest Rate risks.

6. Liquidity Risk Management

6.1 Measuring and managing liquidity needs are vital activities of commercial banks. By assuring a bank's ability to meet its liabilities as they become due, liquidity management can reduce the probability of an adverse situation developing. The importance of liquidity transcends individual institutions, as liquidity shortfall in one institution can have repercussions on the entire system. bank management should measure not only the liquidity positions of banks on an ongoing basis but also examine how

लेंगी। अनुभव यह दर्शाता है कि आम तौर पर अर्थसुलभ (लिक्विड) समझी जानेवाली आस्तियां, जैसे सरकारी प्रतिभूतियां और अन्य मुद्रा बाजार के लिखत भी उस स्थिति में अर्थसुलभ नहीं रह सकते जब बाजार और उसके संचालक एकदिशी (यूनिडायरेक्शनल) हों। अतः चलनिधि पर अवधिपूर्णता अथवा नकदी प्रवाह की बेमेल स्थितियों के माध्यम से ध्यान रखना होगा। शुद्ध निधीकरण आवश्यकताओं को मापने तथा उनके प्रबंधन के लिए अवधिपूर्णता सोपान और संचयी अधिशेष की गणना अथवा चुनी हुई अवधिपूर्णता तारीखों को निधियों के कोटे के उपयोग को एक मानक साधन के रूप में अपनाया जाता है। संरचनात्मक चलनिधि के विवरण का फॉर्मेट अनुबंध I में दिया गया है।

6.2 परिशिष्ट I में दी गयी अवधिपूर्णता की रूपरेखा का उपयोग विभिन्न कालखंडों में बैंकों के भावी नकदी प्रवाहों को मापने के लिए किया जा सकता है। 14 दिन के सांविधिक प्रारक्षित चक्र को देखते हुए कालखंड को निम्नप्रकार आबंटित किया जा सकता है:

- i) 1 से 14 दिन
- ii) 15 से 28 दिन
- iii) 29 दिन और 3 महीने तक
- iv) 3 महीने से अधिक और 6 महीने तक
- v) 6 महीने से अधिक और 12 महीने तक
- vi) 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक
- vii) 2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक
- viii) 5 वर्ष से अधिक

liquidity requirements are likely to evolve under crisis scenarios. Experience shows that assets commonly considered as liquid like Government securities and other money market instruments could also become illiquid when the market and players are unidirectional. Therefore liquidity has to be tracked through maturity or cash flow mismatches. For measuring and managing net funding requirements, the use of a maturity ladder and calculation of cumulative surplus or deficit of funds at selected maturity dates is adopted as a standard tool. The format of the Statement of Structural Liquidity is given in Annexure I.

6.2 The Maturity Profile as given in Appendix I could be used for measuring the future cash flows of banks in different time buckets. The time buckets given in the Statutory Reserve cycle of 14 days may be distributed as under :

- i) 1 to 14 days
- ii) 15 to 28 days
- iii) 29 days and upto 3 months
- iv) Over 3 months and upto 6 months
- v) Over 6 months and upto 12 months
- vi) Over 1 year and upto 2 years
- vii) Over 2 years and upto 5 years
- viii) Over 5 years

6.3 प्रत्येक कालखंड के भीतर आनेवाली नकदी राशि और जानेवाली नकदी राशि के अनुसार बेमेल स्थितियां हो सकती हैं। जहां एक वर्ष तक की बेमेल स्थितियां संगत हो सकती हैं क्योंकि ये आनेवाली चलनिधि समस्याओं की पूर्व चेतावनी संकेत देती हैं, वहीं मुख्य ध्यान अल्पावधि बेमेल स्थितियों पर होना चाहिए जैसे 1-14 दिन और 15-28 दिन। किंतु बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे बोर्ड/प्रबंध समिति के अनुमोदन से आंतरिक विवेकपूर्ण सीमाएं निश्चित कर सभी कालखंडों में अपनी संचयी बेमेल स्थितियों (जो कुल हो) पर निगरानी रखें। 1-14 दिन और 15-28 दिन के दौरान बेमेल स्थितियां किसी भी हालत में प्रत्येक कालखंड में नकदी प्रवाहों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी बैंक को अपनी आस्ति-देयता रूपरेखा के कारण अधिक सहन-स्तर की जरूरत हो तो ऐसी उच्चतर सीमा की आवश्यकता के संबंध में कारण बताते हुए अपने बोर्ड/प्रबंध समिति द्वारा मंजूर करायी गयी उच्चतर सीमा में कार्य कर सकता है। बोर्ड/प्रबंध समिति द्वारा अनुमोदित नोट की प्रति बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जाये। उच्चतर सहन-स्तर की अनुमति देने का विवेकाधिकार उस अस्थायी अवधि के लिए है जब तक कि प्रणाली सुस्थापित नहीं हो जाती और बैंक अपने आस्ति-देयता स्वरूप का पुनर्विन्यास करने में समर्थ नहीं होता।

6.4 संरचनात्मक चलनिधि (अनुबंध I) का विवरण नकदी प्रवाहों के प्रत्याशित समय के अनुसार अवधिपूर्णता क्रम में आनेवाली और जानेवाली सभी नकदी को रखकर तैयार किया जाये। अवधिपूर्ण हो

6.3 Within each time bucket there could be mismatches depending on cash inflows and outflows. While the mismatches upto one year would be relevant since these provide early warning signals of impending liquidity problems, the main focus should be on the short-term mismatches viz., 1-14 days and 15-28 days. Banks, however, are expected to monitor their cumulative mismatches (running total) across all time buckets by establishing internal prudential limits with the approval of the Board/Management Committee. The mismatch during 1-14 days and 15-28 days should not in any case exceed 20% of the cash outflows in each time bucket. If a bank in view of its asset - liability profile needs higher tolerance level, it could operate with higher limit sanctioned by its Board/Management Committee giving reasons on the need for such higher limit. A copy of the note approved by Board/Management Committee may be forwarded to the Department of Banking Supervision, RBI. The discretion to allow a higher tolerance level is intended for a temporary period, till the system stabilises and the bank is able to restructure its asset-liability pattern.

6.4 The Statement of Structural Liquidity (Annexure I) may be prepared by placing all cash inflows and outflows in the maturity ladder according to the

रही देयता से नकदी जायेगी जबकि अवधिपूर्ण हो रही आस्ति से नकदी आयेगी। तुरंत उपलब्ध विदेशी मुद्रा संसाधनों [(एफसीएनआर (बी) निधियों, आदि)] सहित, जिनका विनियोजन रुपया संसाधनों की वृद्धि के लिए किया जा सकता है, विदेशी मुद्रा संबंधी परिचालनों के कारण रुपये के आने और जाने को हिसाब में लेना आवश्यक होगा। नकदी के आने/जाने की संभावित मात्रा निर्धारित करते हुए बैंकों को अपनी आस्ति-देयता की रूपरेखाओं के अनुसार कई कल्पनाएं करनी होंगी। उदाहरण के लिए, बड़े शाखा नेटवर्क वाले भारतीय बैंक (अपनी जमाराशियों का आधार स्थिर होने पर, क्योंकि अधिकांश जमाराशियां नवीकृत की जाती हैं) असंतुलनों के लिए बड़ी सहन सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं बशर्ते उनकी मीयादी जमाराशियों का आधार काफी अधिक हो। सहन सीमाएं तय करते समय बैंक अपने आस्ति-देयता आधार, कारोबार के स्वरूप, भविष्य की रणनीति आदि पर आधारित सभी सुसंगत कारकों को हिसाब में ले सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करने में दिलचस्पी रखता है कि सभी आवश्यक कारकों को ध्यान में रखते हुए सहन सीमाएं निर्धारित की जायें तथा चलनिधि प्रबंधन के अनुभवों के आधार पर उन्हें और परिशोधित किया जाये।

6.5 1-90 दिनों की समय सीमा में गतिशील आधार पर अपनी अल्पकालिक चलनिधि पर निगरानी रखने में बैंकों को समर्थ बनाने हेतु, बैंक कारोबार संबंधी प्रक्षेपणों और अन्य वचनबद्धताओं के आधार पर अपनी अल्पकालिक चलनिधि की रूपरेखाओं का अनुमान ले सकते हैं। अल्पकालिक गतिशील

expected timing of cash flows. A maturing liability will be a cash outflow while a maturing asset will be a cash inflow. It would be necessary to take into account the rupee inflows and outflows on account of forex operations including the readily available forex resources [FCNR (B) funds, etc.] which can be deployed for augmenting rupee resources. While determining the likely cash inflows/outflows, banks have to make a number of assumptions according to their asset - liability profiles. For instance, Indian banks with large branch network can (on the stability of their deposit base as most deposits are renewed) afford to have larger tolerance levels in mismatches if their term deposit base is quite high. While determining the tolerance levels the banks may take into account all relevant factors based on their asset-liability base, nature of business, future strategy etc. The RBI is interested in ensuring that the tolerance levels are determined keeping all necessary factors in view and further refined with experience gained in Liquidity Management.

6.5 In order to enable the banks to monitor their short-term liquidity on a dynamic basis over a time horizon spanning from 1-90 days, banks may estimate their short-term liquidity profiles on the basis of business projections and

चलनिधि का अनुमान लगाने के लिए एक संकेतात्मक फार्मेट (अनुबंध III) संलग्न है।

7. मुद्रा संबंधी जोखिम

7.1 चल मुद्रा दर व्यवस्था के फलस्वरूप एक घोषित अस्थिरता आयी है, जिसने बैंकों के तुलनपत्रों की जोखिम संबंधी रूपरेखा में नया आयाम जोड़ दिया है। अविनियमन के बाद मुक्त अर्थव्यवस्थाओं के बीच पूंजी प्रवाह बढ़ने से लेनदेनों की मात्रा में वृद्धि हुई है। अस्थिरता के साथ बड़े अंतर-देशीय प्रवाहों के कारण बैंकों के तुलनपत्रों में विनिमय दर में घटबढ़ की जोखिम शामिल हो गयी है।

7.2 विभिन्न मुद्राओं में लेनदेन करने से अवसरों के साथ जोखिम भी सामने आते हैं। यदि किसी मुद्रा की आस्तियों के स्तर की तुलना में उसकी देयताएं अधिक हों, तो मुद्रा के असंतुलन से मूल्य में वृद्धि या कमी आ सकती है जो मुद्रा के घट-बढ़ पर निर्भर होगा। मुद्रा जोखिम को टालने का सरलतम उपाय यह सुनिश्चित करना है कि असंतुलनों को, यदि कोई हो, कम करके उन्हें शून्य या शून्य के आसपास लाया जाये। बैंक जमाराशियां स्वीकार करने, ऋण और अग्रिम देने तथा विदेशी मुद्रा लेनदेनों के लिए भाव उद्धृत करने जैसे विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन करते हैं। चाहे कोई भी रणनीति क्यों न अपनायी जाये, मुद्रा संबंधी असंतुलनों को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा, सजग कारोबारी रणनीति के रूप में कुछ संस्थाएं स्वामिगत व्यापारी स्थितियां अपना सकती हैं।

other commitments. An indicative format (Annexure III) for estimating Short-term dynamic liquidity is enclosed.

7. Currency Risk

7.1 Floating exchange rate arrangement has brought in its wake pronounced volatility adding a new dimension to the risk profile of banks' balance sheets. The increased capital flows across free economies following deregulation have contributed to increase in the volume of transactions. Large cross border flows together with the volatility has rendered the banks' balance sheets vulnerable to exchange rate movements.

7.2 Dealing in different currencies brings opportunities as also risks. If the liabilities in one currency exceed the level of assets in the same currency, then the currency mismatch can add value or erode value depending upon the currency movements. The simplest way to avoid currency risk is to ensure that mismatches, if any, are reduced to zero or near zero. Banks undertake operations in foreign exchange like accepting deposits, making loans and advances and quoting prices for foreign exchange transactions. Irrespective of the strategies adopted, it may not be possible to eliminate currency mismatches altogether. Besides, some of the institutions may take proprietary trading positions as a conscious business strategy.

7.3 मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करना आस्ति-देयता प्रबंधन का एक और आयाम है। मुद्रा की स्थिति में असंतुलन होने पर तुलनपत्र में विनिमय दर में घट-बढ़ के जोखिम के अलावा देश संबंधी जोखिम और निपटान जोखिम भी आ जाते हैं। जब से भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग) ने 1978 में दिन के अंत में लगभग सम स्थिति की संकल्पना लागू की है, तब से बैंक एक दिवसीय सीमाएं निर्धारित कर रहे हैं तथा चयनात्मक रूप में सक्रिय दिन के समय के लेनदेन कर रहे हैं। 1981 में “विदेशी मुद्रा कारोबार में आंतरिक नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश” लागू किये जाने के बाद, अवधिपूर्णता संबंधी असंतुलन (अंतराल) भी नियंत्रण के अधीन हैं। भारत में विदेशी मुद्रा बाज़ार पर विशेषज्ञ दल (सोडानी समिति) की सिफारिशों के अनुसरण में विदेशी मुद्रा की स्थिति की गणना को पुनः परिभाषित किया गया है तथा बैंकों को 5 प्रतिशत की खुली स्थिति सीमा तक एक दिवसीय सीमाएं तय करने का विवेकाधिकार दिया गया है जो अतिरिक्त स्तर I पूंजी के रखरखाव से संबद्ध है।

7.4 वर्तमान में, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से अंतराल सीमाएं निर्धारित करने के लिए भी स्वतंत्र हैं परन्तु वायदा लेनदेनों से संबद्ध जोखिम की माप करने के लिए उन्हें जोखिम पर मूल्य (वीएआर) दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। इस प्रकार अंतराल सीमाओं के साथ खुली स्थिति सीमाएं विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेनों के प्रति जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण निर्धारित करती हैं। ऐसे जोखिमों के प्रबंधन के लिए बैंकों को विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग द्वारा जारी 27 दिसंबर 1997 के परिपत्र

7.3 Managing Currency Risk is one more dimension of Asset - Liability Management. Mismatched currency position besides exposing the balance sheet to movements in exchange rate also exposes it to country risk and settlement risk. Ever since the RBI (Exchange Control Department) introduced the concept of end of the day near square position in 1978, banks have been setting up overnight limits and selectively undertaking active day time trading. Following the introduction of "Guidelines for Internal Control over Foreign Exchange Business" in 1981, maturity mismatches (gaps) are also subject to control. Following the recommendations of Expert Group on Foreign Exchange Markets in India (Sodhani Committee) the calculation of exchange position has been redefined and banks have been given the discretion to set up overnight limits linked to maintenance of additional Tier I capital to the extent of 5 per cent of open position limit.

7.4 Presently, the banks are also free to set gap limits with RBI's approval but are required to adopt Value at Risk (VaR) approach to measure the risk associated with forward exposures. Thus the open position limits together with the gap limits form the risk management approach to forex operations. For monitoring such risks banks should follow the instructions contained in

ए.डी. (एम.ए. श्रृंखला) सं. 52 में दिये गये अनुदेशों का अनुपालन करना चाहिए।

8. ब्याज दर जोखिम

8.1 ब्याज दरों को कई चरणों में अविनियमित करने तथा अधिकांश आस्तियों और देयताओं के मूल्य निर्धारण में बैंकों को दिये गये परिचालनात्मक लचीलेपन के कारण बैंकिंग प्रणाली में ब्याज दर जोखिम आ गया है। ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है जिसमें बाजार में ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तनों का बैंक की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन वर्तमान आय (आय परिप्रेक्ष्य) तथा बैंक की निवल मालियत (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) दोनों को प्रभावित करते हैं। आय परिप्रेक्ष्य संबंधी जोखिम को निवल ब्याज आय अथवा निवल ब्याज मार्जिन में परिवर्तन के रूप में मापा जा सकता है। एमआइएस की खराब स्थिति, बैंकों में कंप्यूटरीकरण की मंद रफ्तार तथा पूर्ण अविनियमन के अभाव को देखते हुए परंपरागत 'गैप' विश्लेषण को ब्याज दर जोखिम मापने की उपयुक्त पद्धति माना गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक का इरादा है कि वह बाद में, जब बैंकों के पास एमआइएस में पर्याप्त विशेषज्ञता और कुशलता हासिल हो जाये, अवधि अंतराल विश्लेषण, अनुरूपण (सिम्यूलेशन) तथा जोखिम पर मूल्य जैसे ब्याज दर जोखिम की माप के आधुनिक तकनीकों की ओर अग्रसर होगा। अंतराल या बेमेल जोखिम की माप एक नियत तारीख को विभिन्न समय अंतरालों पर मौजूद अंतरों की गणना करके की जा सकती है। 'गैप' विश्लेषण में दर संवेदनशील देयताओं और दर संवेदनशील आस्तियों (तुलनपत्र बाह्य स्थितियों को शामिल

Circular A.D (M.A. Series) No. 52 dated December 27, 1997 issued by the Exchange Control Department.

8. Interest Rate Risk (IRR)

8.1 The phased deregulation of interest rates and the operational flexibility given to banks in pricing most of the assets and liabilities have exposed the banking system to Interest Rate Risk. Interest Rate Risk is the risk where changes in market interest rates might adversely affect a bank's financial condition. Changes in interest rates affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the bank (economic value perspective). The risk from the earnings perspective can be measured as changes in the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin (NIM). In the context of poor MIS, slow pace of computerisation in banks and the absence of total deregulation, the traditional Gap analysis is considered as a suitable method to measure the Interest Rate Risk. It is the intention of RBI to move over to modern techniques of Interest Rate Risk measurement like Duration Gap Analysis, simulation and Value at Risk at a later date when banks acquire sufficient expertise and sophistication in MIS. The Gap or Mismatch risk can be measured by calculating Gaps over different time intervals as at a given date. Gap analysis measures mismatches between rate sensitive liabilities and rate sensitive

करते हुए) के बीच मौजूद असंतुलनों की माप की जाती है। किसी आस्ति या देयता को सामान्य तौर पर दर संवेदनशील तब माना जाता है जब -

- (i) विचाराधीन समय अंतराल के भीतर, नकदी प्रवाह हो,
- (ii) अंतराल के दौरान, ब्याज दर पुनर्निर्धारित/पुनर्मूल्यित होती हो,
- (iii) जिन मामलों में ब्याज दरें प्रशासित होती हैं, उनमें (अर्थात् बचत बैंक जमा राशियों, रु. 2 लाख तक के अग्रिमों, विभेदक ब्याज दर अग्रिमों, निर्यात ऋण पुनर्वित्त, प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात शेष, आदि में) भारतीय रिज़र्व बैंक ब्याज दरों में परिवर्तन करता हो, तथा
- (iv) संविदा के अनुसार उसे उल्लिखित अवधिपूर्णता के पहले अदा या आहरित किया जा सकता हो।

8.2 दर संवेदनशील देयताओं, आस्तियों और तुलनपत्र बाह्य स्थितियों को शेष अवधिपूर्णता अथवा अगली पुनर्मूल्यन अवधि, जो भी पहले हो, के अनुसार कालखंड समूहित करके 'गैप' रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। 'गैप' विश्लेषण में दर संवेदनशीलता निर्धारित करना एक कठिन कार्य है। सभी निवेश, अग्रिम, जमा राशियां, उधार राशियां, खरीदी गयी निधियां आदि, जो एक निर्धारित कालखंड में अवधिपूर्ण/पुनर्मूल्यित होती हैं, ब्याज दर के प्रति संवेदनशील हैं। इसी तरह, यदि बैंक ऋण की मूल चुकौती को समय सीमा के भीतर प्राप्त करने की आशा रखे तो वह भी (ब्याज) दर के प्रति संवेदनशील है। इसमें मूल राशि की अंतिम चुकौती तथा अंतरिम किस्तें शामिल हैं। कुछ आस्तियों और देयताओं पर ऐसी (ब्याज) दरें प्राप्त/अदा की जाती हैं, जो संदर्भ दर के साथ परिवर्तित होती हैं। इन आस्तियों और देयताओं को पूर्व निर्धारित अंतरालों

assets (including off-balance sheet positions). An asset or liability is normally classified as rate sensitive if :

- i) within the time interval under consideration, there is a cash flow;
- ii) the interest rate resets/reprices contractually during the interval;
- iii) RBI changes the interest rates (i.e. interest rates on Savings Bank Deposits, advances upto Rs. 2 lakhs, DRI advances, Export credit, Refinance, CRR balance, etc.) in cases where interest rates are administered; and
- iv) it is contractually pre-payable or withdrawable before the stated maturities.

8.2 The Gap Report should be generated by grouping rate sensitive liabilities, assets and off-balance sheet positions into time buckets according to residual maturity or next repricing period, whichever is earlier. The difficult task in Gap analysis is determining rate sensitivity. All investments, advances, deposits, borrowings, purchased funds etc. that mature/reprice within a specified timeframe are interest rate sensitive. Similarly, any principal repayment of loan is also rate sensitive if the bank expects to receive it within the time horizon. This includes final principal payment and interim instalments. Certain assets and liabilities receive/pay rates that

पर पुनर्मूल्यित किया जाता है तथा ये पुनर्मूल्यन के समय दर के प्रति संवेदनशील हैं। जहां मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें उनके चालू रहने के दौरान निश्चित होती हैं, वहीं बैंकिंग तंत्र का अग्रिम संविभाग मूलतः अस्थायी रहता है। मूल उधार दर में परिवर्तनों के अनुरूप अग्रिमों पर ब्याज दरों का पुनर्मूल्यन कितनी भी बार किया जा सकता है। निम्नलिखित कालखंडों में अंतरालों की पहचान की जा सकती है :

- i) 1 महीने तक
- ii) एक महीने से अधिक तथा 3 महीनों तक
- iii) 3 महीनों से अधिक तथा 6 महीनों तक
- iv) 6 महीनों से अधिक तथा 12 महीनों तक
- v) 1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्षों तक
- vi) 3 वर्षों से अधिक तथा 5 वर्षों तक
- vii) 5 वर्षों से अधिक
- viii) गैर-संवेदनशील

तुलनपत्र में ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील आस्तियों और देयताओं की विभिन्न मदों का वर्गीकरण परिशिष्ट II में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार किया जाना है तथा ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील आस्तियों और देयताओं का रिपोर्टिंग फॉर्मेट अनुबंध II में दिया गया है।

8.3 अंतराल प्रत्येक समयावधि के लिए दर संवेदनशील आस्तियों और दर संवेदनशील देयताओं के बीच का अंतर है। धनात्मक अंतराल यह सूचित करता है कि इसमें दर संवेदनशील देयताओं की तुलना में दर संवेदनशील आस्तियां अधिक हैं, जबकि ऋणात्मक अंतराल यह सूचित करता है कि इसमें दर संवेदनशील देयताएं अधिक हैं। अंतराल रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि संस्था धनात्मक अंतराल (दर संवेदनशील आस्ति > दर संवेदनशील

vary with a reference rate. These assets and liabilities are repriced at pre-determined intervals and are rate sensitive at the time of repricing. While the interest rates on term deposits are fixed during their currency, the advances portfolio of the banking system is basically floating. The interest rates on advances could be repriced any number of occasions, corresponding to the changes in PLR. The Gaps may be identified in the following time buckets :

- i) upto 1 month
- ii) Over one month and upto 3 months
- iii) Over 3 months and upto 6 months
- iv) Over 6 months and upto 12 months
- v) Over 1 year and upto 3 years
- vi) Over 3 years and upto 5 years
- vii) Over 5 years
- viii) Non-sensitive

The various items of rate sensitive assets and liabilities in the Balance Sheet may be classified as explained in Appendix-II and the Reporting Format for interest rate sensitive assets and liabilities is given in Annexure II.

8.3 The Gap is the difference between Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate Sensitive Liabilities (RSL) for each time bucket. The positive Gap indicates that it has more RSAs than RSLs whereas the negative Gap indicates that it has more RSLs. The Gap reports indicate whether the institution is in a position to benefit from rising interest rates by having a

देयता) के जरिये बढ़ती ब्याज दरों का लाभ उठाने की स्थिति में है अथवा वह ऋणानात्मक अंतराल (दर संवेदनशील देयता > दर संवेदनशील आस्ति) द्वारा घटती हुई ब्याज दरों से लाभ उठाने की स्थिति में है। अतः अंतराल का उपयोग ब्याज दर संवेदनशीलता के माप के रूप में किया जा सकता है।

8.4 प्रत्येक बैंक को चाहिए कि वह बोर्ड/प्रबंधन समिति के अनुमोदन से अलग-अलग अंतरालों पर विवेकपूर्ण सीमाएं तय करे। विवेकपूर्ण सीमाओं का असर कुल आस्तियों, अर्जक आस्तियों या इक्विटी पर पड़ना चाहिए। बैंक ब्याज दर संबंधी घट-बढ़ पर अपने दृष्टिकोण के आधार पर जोखिम पर आय का आकलन कर सकते हैं तथा बोर्ड/प्रबंधन समिति के अनुमोदन से विवेकपूर्ण स्तर निर्धारित कर सकते हैं।

8.5 भारतीय रिज़र्व बैंक उचित समय पर बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी पर्याप्तता की शुरुआत भी करेगा।

9. अंतराल (गैप) रिपोर्टें (चलनिधि तथा ब्याज दर संवेदनशीलता) तैयार करने के लिए विभिन्न कालखंडों में आस्तियों और देयताओं के विभिन्न घटकों का वर्गीकरण, जैसा कि परिशिष्ट I और II में सूचित किया गया है, आधार-मानक है। जो बैंक पिछले आंकड़ों/अनुभूत अध्ययनों के आधार पर आस्तियों और देयताओं के विभिन्न घटकों के व्यवहारगत स्वरूप, निहित विकल्पों, 'रोल्स-इन' और 'रोल्स-आउट' का उचित अनुमान लगाने में बेहतर रूप में तैयार हों, वे आस्ति देयता समिति/बोर्ड के अनुमोदन उपयुक्त समयावधियों में उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। आस्ति देयता समिति/बोर्ड द्वारा अनुमोदित नोट की एक प्रति बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को प्रेषित की जाये।

positive Gap ($RSA > RSL$) or whether it is in a position to benefit from declining interest rates by a negative Gap ($RSL > RSA$). The Gap can, therefore, be used as a measure of interest rate sensitivity.

8.4 Each bank should set prudential limits on individual Gaps with the approval of the Board/Management Committee. The prudential limits should have a bearing on the total assets, earning assets or equity. The banks may work out earnings at risk, based on their views on interest rate movements and fix a prudent level with the approval of the Board/Management Committee.

8.5 RBI will also introduce capital adequacy for market risks in due course.

9. The classification of various components of assets and liabilities into different time buckets for preparation of Gap reports (Liquidity and Interest Rate Sensitivity) as indicated in Appendices I & II is the benchmark. Banks which are better equipped to reasonably estimate the behavioural pattern, embedded options, rolls-in and rolls-out, etc. of various components of assets and liabilities on the basis of past data/empirical studies could classify them in the appropriate time buckets, subject to approval from the ALCO/Board. A copy of the note approved by the ALCO/Board may be sent to the Department of Banking Supervision.

अवधिपूर्णता रूपरेखा - चलनिधि

लेखा शीर्ष	कालखंडों में वर्गीकरण

अ. निधियों का जाना

1. पूंजी, प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	5 वर्षों के कालखंड में
2. मांग जमा राशियां (चालू और बचत बैंक जमाराशियां)	मांग जमा राशियों को अस्थिर और प्रमुख हिस्सों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्यतः जमाराशियों का 25% मांग पर आहरण योग्य रहता है। इस हिस्से को अस्थिर माना जा सकता है। अस्थिर हिस्से को पहले कालखंड अर्थात् 1 से 14 दिन में रखा जा सकता है और प्रमुख भाग को 1-2 वर्षों के कालखंड में रखा जा सकता है।
3. सावधि जमा राशियां	संबंधित अवधिपूर्णता कालखंड
4. जमा प्रमाणपत्र, उधार और बाण्ड (अनुषंगी ऋण सहित)	संबंधित अवधिपूर्णता कालखंड
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	
i) देय बिल	i) 1-14 दिनों का कालखंड
ii) अंतर-कार्यालय समायोजन	ii) प्रवृत्ति विश्लेषण के अनुसार। नकद अदायगियों का प्रतिनिधित्व न करनेवाली मदों को 5 वर्षों से अधिक के कालखंड में रखा जा सकता है।
iii) निष्क्रिय आस्तियों के लिए प्रावधान	iii)
क) अवमानक	क) 2-5 वर्ष का कालखंड
ख) संदिग्ध और हानिवाली	ख) 5 वर्ष से अधिक का कालखंड
iv) निवेशों में मूल्यहास के लिए प्रावधान	iv) 5 वर्ष से अधिक का कालखंड

- v) निवेशों में निष्क्रिय आस्तियों के लिए प्रावधान
 - क) अवमानक
 - ख) संदिग्ध और हानिवाली
- vi) अन्य प्रयोजनों हेतु ऋण
- vii) अन्य देयताएं

- v)
 - क) 2-5 वर्ष का कालखंड
 - ख) 5 वर्षों से अधिक का कालखंड
- vi) प्रयोजन आधारित संबंधित कालखंड
- vii) संबंधित अवधिपूर्णता कालखंड। नकद अदायगियों का प्रतिनिधित्व न करनेवाली मदों (अर्थात् अग्रिम रूप से प्राप्त आय आदि) को 5 वर्षों से अधिक के कालखंड में रखा जा सकता है।

आ. निधियों का आना

1. नकद

1-14 दिनों का कालखंड

2. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष

अपेक्षित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात के ऊपर अतिरिक्त शेष 1-14 दिनों के कालखंड के अंतर्गत दर्शाया जाये तथा सांविधिक शेषों को 14 दिनों की समयपश्चता के साथ मांग और मीयादी देयताओं के संबंधित परिपक्वता स्वरूप के अनुसार विभिन्न कालखंडों के बीच बांट दिया जाये।

3. अन्य बैंकों के पास शेष

(i) चालू खाता

- (i) न्यूनतम शेषों की शर्तों के कारण आहरित न किये जाने योग्य भाग को 1-2 वर्षों के कालखंड के अंतर्गत दर्शाया जाये और बाकी शेष 1-14 दिनों के कालखंड के अंतर्गत दर्शाया जाये।

(ii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि, मीयादी जमाराशियां तथा रखी गई अन्य राशियां

- (ii) संबंधित अवधिपूर्णता कालखंड।

4. निवेश

(i) अनुमोदित प्रतिभूतियां

(ii) कंपनी डिबेंचर और बांड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाण्ड, जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पत्र, प्रतिदेय अधिमान शेयर, पारस्परिक निधियों की यूनितें (सीमित अवधि), आदि

(iii) शेयर/पारस्परिक निधियों (असीमित अवधि) की यूनितें

(iv) सहायक संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों में निवेश

(i) विभिन्न कालखंडों में मांग और मीयादी देयताओं के अनुसार सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखने के लिए पुनर्निवेश किये जाने हेतु अपेक्षित राशि को छोड़कर संबंधित अवधिपूर्णता कालखंड।

(ii) संबंधित अवधिपूर्णता कालखंड। निष्क्रिय आस्तियों के रूप में वर्गीकृत निवेशों को 2-5 वर्षों के कालखंड (अवमानक) में अथवा 5 वर्षों के कालखंड (संदिग्ध और हानिवाली) में दर्शाया जाना चाहिए।

(iii) 5 वर्षों से अधिक कालखंड में

(iv) 5 वर्षों से अधिक कालखंड में

5. अग्रिम (अर्जक)

(i) खरीदे और भुनाये गये बिल (डीयूपीएन के अधीन आनेवाले बिलों सहित)

(ii) नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट (अस्थायी ओवरड्राफ्ट सहित) तथा कार्यशील पूंजी का मांग ऋण घटक

(iii) मीयादी ऋण

(i) संबंधित अवधिपूर्णता कालखंड

(ii) बैंकों को बकायों के आधार पर लिये अग्रिमों के व्यावहारिक तथा मौसमी स्वरूप (पैटर्न) का अध्ययन करना चाहिए तथा प्रमुख और अस्थिर हिस्से की पहचान की जानी चाहिए। जहां अस्थिर हिस्से को संबंधित अवधिपूर्णता कालखंडों में दर्शाया जाना चाहिए, वहीं प्रमुख हिस्से को 1-2 वर्षों के कालखंड में दर्शाया जाये।

(iii) अंतरिम नकदी प्रवाह संबंधित अवधिपूर्णता कालखंड के अंतर्गत दर्शाया जाये।

6. अनर्जक आस्तियां

- (i) अवमानक
- (ii) संदिग्ध और हानिवाली

- (i) 2-5 वर्षों का कालखंड
- (ii) 5 वर्षों से अधिक का कालखंड

7. अचल आस्तियां

5 वर्षों से अधिक का कालखंड

8. अन्य आस्तियां

- (i) अंतर-कार्यालय समायोजन

- (i) प्रवृत्ति विश्लेषण के अनुसार। अमूर्त मदों या नकद प्राप्य राशियों की द्योतक मदों से भिन्न मदों को 5 वर्ष से अधिक के कालखंड के अंतर्गत दर्शाया जाये।

- (ii) अन्य

- (ii) संबंधित अवधिपूर्णता कालखंड। अमूर्त आस्तियों और नकद प्राप्य राशियों की द्योतक आस्तियों से भिन्न आस्तियों को 5 वर्ष से अधिक के कालखंड के अंतर्गत दर्शाया जाये।

इ. आकस्मिक देयताएं/वादा की गई/उपलब्ध स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमाएं और अन्य आनेवाली/जानेवाली राशियां

- 1. (i) संस्थाओं को वादा की गई स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमाएं (जानेवाली राशि)

- (i) 1-14 दिनों का कालखंड

- (ii) नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट/कार्यकारी पूंजी सीमाओं के मांग ऋण घटक का उपयोग न किया गया भाग

- (ii) खातों से ली गयी मोटी रकमों के उधारों के व्यावहारिक और मौसमी स्वरूप (पैटर्न) का अध्ययन करें और इस प्रकार पता लगायी गई राशियों को 12 महीने तक की संबंधित अवधिपूर्णता कालखंडों के अंतर्गत रखें।

2. साख-पत्र/गारण्टियां (जानेवाली राशि)	गतिविधियों के संबंध में ऐतिहासिक प्रवृत्ति विश्लेषण किया जाना चाहिए और साख-पत्रों/गारण्टियों (शुद्ध मार्जिन) से संबंधित इस प्रकार निकली राशि को विभिन्न कालखंडों में रखा जाना चाहिए।
3. रिपो/पुनः भुनाये गये बिल (डीयूपीएन)/स्वैप आईएनआर/यूएसडी, अवधिपूर्ण होनेवाली विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं आदि	संबंधित अवधिपूर्णता कालखण्ड
4. देय/प्राप्य ब्याज (जानेवाली/आनेवाली राशि)	संबंधित अवधिपूर्णता कालखण्ड

टिप्पणी:

- i) किसी अन्य आकस्मिकता के कारण देयता को संबंधित अवधिपूर्णता कालखण्डों के अंतर्गत दर्शाया जाये।
- ii) सभी अतिदेय देयताओं को 1-14 दिनों के कालखण्ड में रखा जाये।
- iii) अग्रिमों और निवेशों से जो ब्याज और किस्तें एक महीने से कम के लिए अतिदेय हैं उन्हें 3-6 महीनों के कालखंडों में रखा जाये। इसके अलावा यदि पहले की प्राप्य राशियां वसूल न हुई हों तो देय ब्याज और किस्तें (अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किये जाने से पूर्व) एक महीने की छूट अवधि दिये बिना 6-12 महीनों के कालखंड में रखी जायें।

ई. अंतराल का वित्तपोषण:

यदि ऋणात्मक अंतराल जानेवाली राशियों की 20% की विवेकपूर्ण सीमा से अधिक हो जाता है तो बैंक एक फुटनोट के जरिये यह दर्शाये कि वह इस अंतराल को किस प्रकार वित्तपोषित करेगा ताकि इस बेमेल स्थिति को निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर लाया जा सके। इस अंतराल को बाजार से उधारों (मांग/मीयादी), बिल पुनर्भुनाई, भारिबैं/अन्य से पुनर्वित्त, रिपो और रुपयों में परिवर्तन के बाद विदेशी मुद्रा संसाधनों के विनियोजन (बिना स्वैप वाली विदेशी मुद्रा निधियों) आदि से वित्तपोषित किया जा सकता है।

Maturity profile - Liquidity

Heads of Accounts	Classification into time buckets
A. Outflows	
1. Capital, Reserves and Surplus	Over 5 years bucket.
2. Demand Deposits (Current and Savings Bank Deposits)	Demand Deposits may be classified into volatile and core portions. 25% of deposits are generally withdrawable on demand. This portion may be treated as volatile. While volatile portion can be placed in the first time bucket i.e., 1-14 days, the core portion may be placed in 1-2 years bucket.
3. Term Deposits	Respective maturity buckets.
4. Certificates of Deposit, Borrowings and Bonds (including Sub-Ordinated Debt)	Respective maturity buckets.
5. Other Liabilities and Provisions	
(i) Bills Payable	(i) 1-14 days bucket.
(ii) Inter-office Adjustment	(ii) As per trend analysis. Items not representing cash payables may be placed in over 5 years bucket.
(iii) Provisions for NPAs	(iii)
a) Sub-standard	a) 2-5 years bucket.
b) Doubtful and Loss	b) Over 5 years bucket
(iv) Provisions for depreciation in investments	(iv) Over 5 years bucket.

Heads of Accounts	Classification into time buckets
(v) Provisions for NPAs in investments	v)
a) Sub-standard	a) 2-5 years bucket.
b) Doubtful and Loss	b) Over 5 years bucket.
(vi) Provisions for other purposes	(vi) Respective buckets depending on the purpose.
(vii) Other Liabilities	(vii) Respective maturity buckets. Items not representing cash payables (i.e. income received in advance etc.) may be placed in over 5 years bucket.

B. Inflows

1. Cash

1-14 days bucket

2. Balance with RBI

While the excess balance over the required CRR/SLR may be shown under 1-14 days bucket, the Statutory Balances may be distributed amongst various time buckets corresponding to the maturity profile of DTL with a time-lag of 14 days.

3. Balances with other Banks

(i) Current Account

(i) Non-withdrawable portion on account of stipulations of minimum balances may be shown under 1-2 years bucket and the remaining balances may be shown under 1-14 days bucket.

(ii) Money at Call and Short Notice, Term Deposits and other placements

(ii) Respective maturity buckets.

4. Investments

(i) Approved securities

(i) Respective maturity buckets excluding the amount required to be reinvested to maintain SLR corresponding to the DTL profile in various time buckets.

(ii) Corporate debentures and bonds, PSU bonds, CDs and CPs, Redeemable preference shares, Units of Mutual Funds (close ended), etc.

(ii) Respective maturity buckets. Investments classified as NPAs should be shown under 2-5 years bucket (sub-standard) or over 5 years bucket (doubtful and loss).

(iii) Shares/Units of Mutual Funds (open ended)

(iii) Over 5 years bucket.

(iv) Investments in Subsidiaries/Joint Ventures

(iv) Over 5 years bucket.

5. Advances (Performing)

(i) Bills Purchased and Discounted (including bills under DUPN)

(i) Respective maturity buckets.

(ii) Cash Credit/Overdraft (including TOD) and Demand Loan component of Working Capital.

(ii) Banks should undertake a study of behavioural and seasonal pattern of availments based on outstandings and the core and volatile portion should be identified. While the volatile portion could be shown in the respective maturity buckets, the core portion may be shown under 1-2 years bucket.

(iii) Term Loans

(iii) Interim cash flows may be shown under respective maturity buckets.

Heads of Accounts	Classification into time buckets

6. NPAs

(i) Sub-standard	(i) 2-5 years bucket.
(ii) Doubtful and Loss	(ii) Over 5 years bucket.

7. Fixed Assets

Over 5 years bucket

8. Other Assets

(i) Inter-office Adjustment	(i) As per trend analysis. Intangible items or items not representing cash receivables may be shown in over 5 years bucket.
(ii) Others	(ii) Respective maturity buckets. Intangible assets and assets not representing cash receivables may be shown in over 5 years bucket.

C. Contingent Liabilities/Lines of Credit committed/available and other Inflows/Outflows

1. (i) Lines of Credit committed to Institutions (outflow)	(i) 1-14 days bucket.
(ii) Unavailed portion of Cash Credit/Overdraft/Demand loan component of Working Capital limits (outflow)	(ii) Banks should undertake a study of the behavioural and seasonal pattern of potential availments from the accounts and the amounts so arrived at may be shown under relevant maturity buckets upto 12 months.

Heads of Accounts	Classification into time buckets
2. Letters of Credit/Guarantees (out-flow)	Historical trend analysis ought to be conducted on the devolvments and the amounts so arrived at in respect of outstanding Letters of Credit/Guarantees (net of margins) should be distributed amongst various time buckets.
3. Repos/Bills Rediscounted (DUPN)/ Swaps INR/USD, maturing forex forward contracts, etc.	Respective maturity buckets.
4. Interest payable/receivable (outflow/inflow)	Respective maturity buckets.

Note :

- i) Liability on account of any other contingency may be shown under respective maturity buckets.
- ii) All overdue liabilities may be placed in the 1-14 days bucket.
- iii) Interest and instalments from advances and investments, which are overdue for less than one month may be placed in the 3-6 months, bucket. Further, interest and instalments due (before classification as NPAs) may be placed in the 6-12 months bucket without the grace period of one month if the earlier receivables remain uncollected.

D. Financing of Gap :

In case the negative gap exceeds the prudential limit of 20% of outflows, the bank may show by way of a foot note as to how it proposes to finance the gap to bring the mismatch within the prescribed limits. The gap can be financed from market borrowings (call/term), Bills Rediscounting, Refinance from RBI/others, Repos and deployment of foreign currency resources after conversion into rupees (unswapped foreign currency funds) etc.

ब्याज दर संवेदनशीलता

लेखा शीर्ष	दर, संवेदनशीलता और कालखंड
देयताएं	
1. पूंजी, प्रारक्षित निधि और अधिशेष	असंवेदनशील
2. चालू जमाराशियां	असंवेदनशील
3. बचत बैंक जमाराशियां	उस सीमा तक संवेदनशील, जितने अंश (कोर) पर ब्याज अदा किया जाना है। इसे 3-6 महीने वाले कालखंड में शामिल किया जा सकता है। जिस अंश पर ब्याज नहीं दिया जाना है, उसे असंवेदनशील कालखंड में दर्शाया जाये।
4. मीयादी जमाराशियां और जमा प्रमाणपत्र	संवेदनशील और अवधिपूर्णता पर पुनः मूल्य लगाया जाता है। इस राशि को शेष अवधि के आधार पर विभिन्न कालखंडों में वितरित किया जा सकता है। परंतु अस्थिर सावधि जमाराशियों के मामले में राशियों को कालखंड के अंतर्गत तब रखा जाये जब जमाराशियों का संविदा रूप में पुनः मूल्यन किया जाना हो।
5. उधार राशियां - नियत	संवेदनशील और अवधिपूर्णता पर पुनः मूल्य लगाया जाता है। इस राशि को शेष अवधि के आधार पर विभिन्न कालखंडों में वितरित किया जा सकता है।
6. उधार राशियां - अस्थिर	संवेदनशील और ब्याज दर पुनः तय करते समय पुनः मूल्य लगाया जाता है। जमाराशियों को उस उचित कालखंड में वितरित किया जाना चाहिए, जो पुनः मूल्य लगाने की तारीख से संबंधित हो।
7. उधार राशियां - ज़ीरो कूपन	संवेदनशील और अवधिपूर्णता पर ब्याज लगाया जाता है। इस राशि को संबंधित अवधिपूर्णतावाले कालखंड को वितरित किया जाना चाहिए।

देयताएं

8. रिज़र्व बैंक से उधार

एक महीने तक का कालखंड।

9. अन्य एजेंसियों से पुनर्वित्त

(क) नियत दर : संबंधित अवधिपूर्णता के अनुसार
(ख) अस्थिर दर : पुनः मूल्य लगाना, जब ब्याज दर पुनः तय की जाती है।

10. अन्य देयताएं और प्रावधान

- (i) भुगतान योग्य बिल
- (ii) अंतर-कार्यालय समायोजन
- (iii) प्रावधान
- (iv) अन्य

- i) असंवेदनशील
- ii) असंवेदनशील
- iii) असंवेदनशील
- iv) असंवेदनशील

11. रिपो/पुनः भुनाये गये बिल
(डीयूपीएन), स्वैप (खरीद/बिक्री)
आदि

पुनः मूल्य लगाने का काम केवल अवधि पूर्ण होने पर किया जाये और संबंधित अवधिपूर्णता के कालखंड को वितरित किया जाना चाहिए।

आस्तियां

1. नकदी

असंवेदनशील

2. रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि

ब्याजवाले अंश को 3-6 महीने के कालखंड में दिखाया जाना चाहिए। शेष राशि असंवेदनशील है।

3. रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि

- (i) चालू खाता
- (ii) मांग और अल्प सूचना पर राशि, मीयादी जमाराशियां तथा अन्य के पास राशि

- (i) असंवेदनशील
- (ii) अवधिपूर्णता पर संवेदनशील। राशि को संबंधित अवधिपूर्णता के कालखंडों में वितरित किया जाये।

4. निवेश (सक्रिय)

- (i) नियत दर/जीरो कूपन
- (ii) अस्थिर दर

- (i) अवधिपूर्णता पर संवेदनशील
- (ii) अगले पुनर्मूल्यन की तारीख को संवेदनशील

आस्तियां

5. शेयर/पारस्परिक निधियों के यूनिट

असंवेदनशील

6. अग्रिम (अर्जक)

- (i) खरीदे और भुनाये गये बिल (डीयूपीएन के अंतर्गत आनेवाले बिलों सहित)
- (ii) नकदी ऋण ओवरड्राफ्ट (टीओडी) मांग पर चुकौती योग्य ऋण और सावधि ऋणों सहित)

(i) अवधिपूर्णता पर संवेदनशील

(ii) केवल तभी संवेदनशील जब मूल ऋण दर/जोखिम प्रीमियम बदले। हाल ही में मूल ऋण दर में जल्दी-जल्दी परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार, प्रत्येक बैंक को देखना चाहिए कि ब्याज दर में परिवर्तन की दिशा क्या है और राशि को उस कालखंड में रखना चाहिए, जिस समय तक मूल ऋण दर संशोधित होनी हो।

7. निष्क्रिय आस्तियां (अग्रिम और निवेश)*

- (i) अवमानक
- (ii) संदिग्ध और हानिवाली

(i) 2-5 वर्षीय कालखंड

(ii) 5 वर्ष से अधिक का कालखंड

8. अचल आस्तियां

असंवेदनशील

9. अन्य आस्तियां

- (i) अंतर-कार्यालय समायोजन
- (ii) अन्य

(i) असंवेदनशील

(ii) असंवेदनशील

10. प्रतिवर्ती रिपो, स्वैप (बिक्री/खरीद) और पुनः भुनाये गये बिल (डीयूपीएन)

अवधिपूर्णता पर संवेदनशील

11. अन्य उत्पाद (ब्याज दर)

- (i) स्वैप
- (ii) अन्य व्युत्पन्न

(i) संवेदनशील और अवधिपूर्णता के संदर्भ में विभिन्न कालखंडों में वितरित किया जाना है।

(ii) जब कभी लागू हो तब उपयुक्त वर्गीकरण किया जाना चाहिए।

* प्रावधानों की राशि घटाकर शुद्ध राशि दिखायी जानी चाहिए।

Interest Rate Sensitivity

Heads of Accounts	Rate sensitivity and time bucket
Liabilities	
1. Capital, Reserves and Surplus	Non-sensitive.
2. Current Deposits	Non-sensitive.
3. Savings Bank Deposits	Sensitive to the extent of interest paying (core) portion. This may be included in the 3-6 months bucket. The non-interest paying portion may be shown in non-sensitive bucket.
4. Term Deposits and Certificates of Deposit	Sensitive and reprices on maturity. The amounts should be distributed to different buckets on the basis of remaining maturity. However, in case of floating term deposits, the amounts may be shown under the time bucket when deposits contractually become due for repricing.
5. Borrowings - Fixed	Sensitive and reprices on maturity. The amounts should be distributed to different buckets on the basis of remaining maturity.
6. Borrowings - Floating	Sensitive and reprices when interest rate is reset. The amounts should be distributed to the appropriate bucket which refers to the repricing date.
7. Borrowings - Zero Coupon	Sensitive and reprices on maturity. The amounts should be distributed to the respective maturity buckets.

Heads of Accounts	Rate sensitivity and time bucket

8. Borrowings from RBI	Upto 1 month bucket.
9. Refinances from other agencies	(a) Fixed rate: As per respective maturity (b) Floating rate: Reprices when interest rate is reset.
10. Other Liabilities and Provisions	
(i) Bills Payable	(i) Non-sensitive.
(ii) Inter-office Adjustment	(ii) Non-sensitive.
(iii) Provisions	(iii) Non-sensitive.
(iv) Others	(iv) Non-sensitive.
11. Repos/Bills Re-discounted (DUPN), Swaps (Buy/Sell) etc.	Reprices only on maturity and should be distributed to the respective maturity buckets.

Assets

1. Cash	Non-sensitives.
2. Balances with RBI	Interest earning portion may be shown in 3-6 months bucket. The balance amount is non-sensitive.
3. Balances with other Banks	
(i) Current Account	(i) Non-sensitive.
(ii) Money at Call and Short Notice, Term Deposits and other placements	(ii) Sensitive on maturity. The amounts should be distributed to the respective maturity buckets.
4. Investments (Performing)	
(i) Fixed Rate/Zero Coupon	(i) Sensitive on maturity.

Heads of Accounts	Rate sensitivity and time bucket
(ii) Floating Rate	(ii) Sensitive at the next repricing date
5. Shares/Units of Mutual Funds	Non-sensitive.
6. Advances (Performing)	
(i) Bills Purchased and Discounted (including bills under DUPN)	(i) Sensitive on maturity.
(ii) Cash Credits/Overdrafts (including TODs)/Loans repayable on demand and Term Loans	(ii) Sensitive only when PLR/risk premium is changed. Of late, frequent changes in PLR have been noticed. Thus, each bank should foresee the direction of interest rate movements and capture the amounts in the respective maturity buckets by which time PLR would be revised.
7. NPAs (Advances and Investments)*	
(i) Sub-Standard	(i) 2-5 years bucket.
(ii) Doubtful and Loss	(ii) Over 5 years bucket.
8. Fixed Assets	Non-sensitive.
9. Other Assets	
(i) Inter-office Adjustment	(i) Non-sensitive.
(ii) Others	(ii) Non-sensitive.
10. Reverse Repos, Swaps (Sell/Buy) and Bills Rediscounted (DUPN)	Sensitive on maturity.
11. Other products (Interest Rate)	
(i) Swaps	(i) Sensitive and should be distributed under different buckets with reference to maturity.
(ii) Other Derivatives	(ii) Should be suitably classified as and when introduced.

* Amounts to be shown net of provisions.

अनुबंध - I

बैंक का नाम.....

संरचनात्मक चलनिधि का विवरण.....को

(राशि करोड़ रुपये में)

शेष अवधिपूर्णता									
जानेवाली राशि	1-14 दिन	15-28 दिन	29 दिन से 3 महीने	3-6 महीने	6-12 महीने	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	जोड़
1. पूंजी									
2. प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष									
3. जमाराशियां	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) चालू जमाराशियां (ii) बचत बैंक जमाराशियां (iii) मीयादी जमाराशियां (iv) जमा प्रमाणपत्र									
4. उधार	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) मांग और अल्प सूचना (ii) अंतर-बैंक (मीयादी) (iii) पुनर्वित्त (iv) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) देय बिल (ii) अंतर-कार्यालय समायोजन (iii) प्रावधान (iv) अन्य									
6. निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध अधिकतम ऋण सीमा	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) संस्थाएं (ii) ग्राहक									

7. नकदी ऋण का अप्रयुक्त अंश/ओवरड्राफ्ट/कार्यकारी पूंजी का मांग ऋण घटक									
8. साख पत्र/गारंटियां									
9. रिपो									
10. पुनः भुनाये गये बिल (डीयूपीएन)									
11. स्वैप (क्रय/विक्रय)/अवधिपूर्ण होनेवाले वायदे									
12. देय ब्याज									
13. अन्य (निर्दिष्ट करें)									
क. जानेवाली कुल राशि									

आनेवाली राशि	1-14 दिन	15-28 दिन	29 दिन से 3 महीने	3-6 महीने	6-12 महीने	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	जोड़
1. नकदी									
2. भा.रि.बैं. के पास जमा शेष									
3. अन्य बैंकों के पास जमा शेष	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) चालू खाता (ii) मांग और अल्प सूचना पर राशि, मीयादी जमाराशियां तथा अन्य के पास राशि									
4. निवेश (रिपो के अंतर्गत आनेवाले सहित परंतु प्रतिवर्ती रिपो रहित)									
5. अग्रिम (अर्जक)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) बिल - खरीदे और भुनाये गये (डीयूपीएन के अधीन आनेवाले बिलों सहित) (ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण (iii) मीयादी ऋण									
6. अनर्जक आस्तियां (अग्रिम और निवेश)									
7. अचल आस्तियां									
8. अन्य आस्तियां	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) अंतर-कार्यालय समायोजन (ii) अन्य									
9. प्रतिवर्ती रिपो									
10. स्वैप (विक्रय/क्रय)/ अवधिपूर्ण वायदे									
11. पुनः भुनाये गये बिल (डीयूपीएन)									
12. प्राप्य ब्याज									
13. प्रतिबद्ध अधिकतम ऋण सीमाएं									
14. अन्य (निर्दिष्ट करें)									
ख. आनेवाली कुल राशि									
ग. बेमेल स्थिति (ख-क)									
घ. संचयी बेमेल स्थिति									
ड. क के % के रूप में ग									

ANNEXURE - I

NAME OF THE BANK.....

Statement of Structural Liquidity as on

(Amounts in Crores of Rupees)

RESIDUAL MATURITY									
OUTFLOWS	1-14 days	15-28 days	29 days to 3 months	3-6 months	6-12 months	1-2 years	2-5 years	Over 5 years	Total
1. Capital									
2. Reserves & Surplus									
3. Deposits	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) Current Deposits									
(ii) Savings Bank Deposits									
(iii) Term Deposits									
(iv) Certificates of Deposits									
4. Borrowings	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) Call and Short Notice									
(ii) Inter-Bank (Term)									
(iii) Refinances									
(iv) Others (specify)									
5. Other Liabilities & Provisions	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) Bills Payable									
(ii) Inter-office Adjustment									
(iii) Provisions									
(iv) Others									
6. Lines of Credit committed to	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) Institutions									
(ii) Customers									

7. Unavailed portion of Cash Credit/Overdraft/ Demand Loan component of Working Capital									
8. Letter of Credit/ Guarantees									
9. Repos									
10. Bills Rediscounted (DUPN)									
11. Swaps (Buy/Sell) maturing forwards									
12. Interest payable									
13. Others (specify)									
A. TOTAL OUTFLOWS									

INFLOWS	1-14 days	15-28 days	29 days to 3 months	3-6 months	6-12 months	1-2 years	2-5 years	Over 5 years	Total
1. Cash									
2. Balances with RBI									
3. Balances with other Banks	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) Current Account									
(ii) Money at Call and Short Notice, Term Deposits and other placements									
4. Investments (including those under Repos but excluding Reverse Repos)									
5. Advances (Performing)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) Bills Purchased and Discounted (including bills under DUPN)									
(ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand									
(iii) Term Loans									
6. NPAs (Advances and Investments)									
7. Fixed Assets									
8. Other Assets	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) Inter-office Adjustment									
(ii) Others									
9. Reverse Repos									
10. Swaps (Sell/Buy)/maturing forwards									
11. Bills Rediscounted (DUPN)									
12. Interest receivable									
13. Committed Lines of Credit									
14. Others (specify)									
B. TOTAL INFLOWS									
C. MISMATCH (B-A)									
D. CUMULATIVE MISMATCH									
E. C as % To A									

अनुबंध - II

बैंक का नाम.....

ब्याज दर संवेदनशीलता का विवरण.....को

(राशि करोड़ रुपये में)

ब्याज दर संवेदनशीलता									
देयताएं	1 महीने तक	1-3 महीने	3-6 महीने	6-12 महीने	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	गैर- संवेदन- शील	जोड़
1. पूंजी									
2. प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष									
3. जमाराशियां	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) चालू जमाराशियां									
(ii) बचत बैंक जमाराशियां									
(iii) मीयादी जमाराशियां									
(iv) जमा प्रमाणपत्र									
4. उधार	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) मांग और अल्प सूचना									
(ii) अंतर-बैंक (मीयादी)									
(iii) पुनर्वित्त									
(iv) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) देय बिल									
(ii) अंतर-कार्यालय समायोजन									
(iii) प्रावधान*									
(iv) अन्य									
6. रिपो									
7. पुनः भुनाये गये बिल (डीयूपीएन)									
8. स्वैप (क्रय/विक्रय)									
9. अन्य (निर्दिष्ट करें)									
क. कुल देयताएं									

* अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधानों को छोड़कर

आस्तियां									
1. नकद									
2. भा.रि.बैं. के पास जमा शेष									
3. अन्य बैंकों के पास जमा शेष	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) चालू खाता									
(ii) मांग और अल्प सूचना पर देय धन, मीयादी जमाराशियां तथा अन्य के पास राशि									
4. निवेश (रिपो के अंतर्गत आनेवाले सहित परंतु प्रतिवर्ती रिपो रहित)									
5. अग्रिम (अर्जक)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) खरीदे और भुनाये गये (डीयूपीएन के अधीन आनेवाले बिलों सहित)									
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण									
(iv) मीयादी ऋण									
6. अनर्जक आस्तियां (अग्रिम और निवेश)*									
7. अचल आस्तियां									
8. अन्य आस्तियां	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) अंतर-कार्यालय समायोजन									
(ii) अन्य									
9. प्रतिवर्ती रिपो									
10. स्वैप (विक्रय/क्रय)									
11. पुनः भुनाये गये बिल (डीयूपीएन)									
12. अन्य (निर्दिष्ट करें)									
ख. कुल आस्तियां									
ग. गैप (ख - क)									
अन्य उत्पाद (ब्याज दर)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) एफआरए									
(ii) स्वैप									
(iii) वायदे (फ्यूचर्स),									
(iv) विकल्प									
(v) अन्य									
घ. कुल अन्य उत्पाद									
ड. शुद्ध गैप (ग-घ)									
च. संचयी गैप									
छ. ख के % के रूप में ड									

* राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शायी जाये

ANNEXURE - II

NAME OF THE BANK.....

Statement of Interest Rate Sensitivity as on

(Amounts in Crores of Rupees)

INTEREST RATE SENSITIVITY									
LIABILITIES	upto 1 month	1-3 months	3-6 months	6-12 months	1-3 years	3-5 years	over 5 years	Non- sensi- tive	Total
1. Capital									
2. Reserves & Surplus									
3. Deposits	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) Current Deposits									
(ii) Savings Bank Deposits									
(iii) Term Deposits									
(iv) Certificates of Deposit									
4. Borrowings	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) Call and Short Notice									
(ii) Inter-Bank (Term)									
(iii) Refinances									
(iv) Others (specify)									
5. Other Liabilities & Provisions	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) Bills Payable									
(ii) Inter-office Adjustment									
(iii) Provisions*									
(iv) Others									
6. Repos									
7. Bills Rediscounted (DUPN)									
8. Swaps (Buy/Sell)									
9. Others (specify)									
A. TOTAL LIABILITIES									

*excluding provisions for non-performing advances and investments.

ASSETS									
1. Cash									
2. Balance with RBI									
3. Balance with other Bank	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) Current Account (ii) Money at Call and Short Notice, Term Deposits and other placement									
4. Investments (including those under Repos but excluding Reverse Repos)									
5. Advance (Performing)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) Bills Purchased and Discounted (including bills under DUPN) (ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand (iii) Term Loans									
6. NPAs (Advances and Investments)*									
7. Fixed Asses									
8. Other Assets	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) Inter-office Adjustment (ii) Others									
9. Reverse Repos									
10. Swaps (Sell/Buy)									
11. Bills Rediscounted (DUPN)									
12. Others (specify)									
B. TOTAL ASSETS									
C. GAP (B-A)									
OTHER PRODUCTS (INTEREST RATE)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
(i) FRAs (ii) Swaps (iii) Futures (iv) Options (v) Others									
D. TOTAL OTHER PRODUCTS									
E. NET GAP (C-D)									
F. CUMULATIVE GAP									
G. E. AS % TO B									

*Amounts to be shown net of provisions.

अनुबंध - III

बैंक का नाम.....
अल्पावधि गत्यात्मक चलनिधि का विवरण.....को

(राशि करोड़ रुपये में)

क. जानेवाली राशि			
	1-14 दिन	15-28 दिन	29-90 दिन
1. ऋणों और अग्रिमों में शुद्ध वृद्धि			
2. निवेशों में शुद्ध वृद्धि : (i) अनुमोदित प्रतिभूतियां (ii) मुद्रा बाजार के लिखत (खजाना बिलों से भिन्न) (iii) बांड/डिबेंचर/शेयर (iv) अन्य			
3. अंतर-बैंक दायित्व			
4. तुलन-पत्र से बाहर की मदें (रिपो, स्वैप, भुनाये गये बिल आदि)			
5. अन्य			
जानेवाली कुल राशि			
ख. आनेवाली राशि			
1. शुद्ध नकदी स्थिति			
2. जमाराशियों में शुद्ध वृद्धि (नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात दायित्व घटाकर			
3. निवेशों पर ब्याज			
4. अंतर-बैंक दावे			
5. पुनर्वित्त पात्रताएँ (निर्यात ऋण)			
6. तुलन-पत्र के बाहर की मदें (प्रतिवर्ती रिपो, स्वैप, भुनाये गये बिल आदि)			
7. अन्य			
आनेवाली कुल राशि			
ग. बेमेल स्थिति (ख - क)			
घ. संचयी बेमेल स्थिति			
ड. कुल जानेवाली राशि के % के रूप में ग			

ANNEXURE - III

Name of the Bank.....

statement of short-term Dynamic Liquidity as on

(Amounts in Crores of Rupees)

A. Outflows			
	1-14 days	15-28 days	29-90 days
1. Net increase in loans and advances			
2. Net increase in investments :			
(i) Approved securities			
(ii) Money market instruments (other than Treasury Bills)			
(iii) Bonds/Debentures/Shares			
(iv) Others			
3. Inter-bank obligations			
4. Off-balance sheet items (Repos, swaps, bills discounted, etc.)			
5. Others			
TOTAL OUTFLOWS			
B. Inflows			
1. Net cash position			
2. Net increase in deposits (less CRR obligations)			
3. Interest on investments			
4. Inter-bank claims			
5. Refinance eligibility (Export credit)			
6. Off-balance sheet items (Reverse repos, swaps, bills discounted, etc.)			
7. Others			
TOTAL INFLOWS			
C. Mismatch (B-A)			
D. Cumulative mismatch			
E. C as a % to total outflows			

Principles for the Management of Interest Rate Risk

SUMMARY

1. As part of its on-going efforts to address international bank supervisory issues, the Basle Committee on Banking Supervision¹ is issuing the attached paper on the management of interest rate risk. In this, as many other areas, sound controls are of crucial importance. It is essential that banks have a comprehensive risk management process in place that effectively identifies, measures, monitors and controls interest rate risk exposures, and that is subject to appropriate board and senior management oversight. The attached paper describes each of these elements, drawing upon experience in member countries and principles established in earlier publications by the Committee. The objective of the paper is to outline a number of principles for use by supervisory authorities when evaluating banks' interest rate risk management .

2. The supervisory capital requirements established by the Basle Committee will, as from the end of 1997, cover interest rate risk

in the trading activities of banks.² This paper is intended to set out principles of more general application for the management of interest rate risk, independent of whether the positions are part of the trading book or reflects banks' non-trading activities. It refers to an interest rate risk management process, which includes the development of a business strategy, the assumption of assets and liabilities in banking and trading activities, as well as a system of internal controls. In particular, the paper addresses the need for effective interest rate risk management, monitoring and control functions within the interest rate risk management process.

3. In developing these principles, the Committee has drawn not only on supervisory guidance in member countries but also on the comments of the banking industry on the Committee's earlier paper, issued for consultation in April 1993³ as well as comments received on the draft of this paper issued for consultation in January 1997. In addition, the present paper incorporates many of the principles contained in the guidance issued by the committee for derivatives activities,⁴ which

¹The Basle Committee on Banking Supervision is a Committee of banking supervisory authorities which was established by the central-bank Governors of the Group of Ten countries in 1975. It consists of senior representatives of bank supervisory authorities and central banks from Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, Sweden, Switzerland, United Kingdom and the United States. It usually meets at the Bank for International Settlements in Basle, Where its permanent Secretariat is located.

²Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks, January 1996.

³Measurement of Bank's Exposure to Interest Rate Risk, Consultative proposal by the Basle Committee on Banking Supervision, April 1993.

⁴Risk Management Guidelines for Derivatives, July 1994.

are reflected in the qualitative parameters for model-users in the recently published capital standards for market risk.

4. These principles are intended to be of general application, based as they are on practices currently used by many international banks, even though their specific application will depend to some extent on the complexity and range of activities undertaken by individual banks. Supervisory authorities should, therefore, use them to reassess their own supervisory methods and procedures for monitoring how bank control interest rate risk. While the exact approach chosen by individual supervisors will depend upon a host of factors, including their on-site and off-site supervisory techniques and the degree to which external auditors are also used in the supervisory function, **all members of the Basle Committee agree that the principles set out here should be used in evaluating the adequacy and effectiveness of a bank's interest rate risk management.**

5. The basle Committee is also distributing this paper to supervisory authorities world wide in the belief that the principles presented will provide a useful framework for prudent supervision of interest rate risk. More generally, the Committee wishes to emphasize that sound

risk management practices are essential to the prudent operation of banks and to promoting stability in the financial system as a whole.

6. This paper also provides supervisory authorities with a framework for obtaining information on interest rate risk. It broadly describes the types of basic information that should be available to supervisory authorities to help them in evaluating banks' interest rate risk exposures. This information can be used in a variety of ways by supervisory authorities to provide quantitative assessments of the interest rate risk faced by banks.

7. After careful consideration of the comments received, the Committee has set out principles for sound interest rate risk management, rather than establishing a more standardized measures for interest rate risk. The Committee will, however, keep the need for such more standardized measures under review and may, at a later stage, revisit its approach in this area. In that context, the Committee is aware that industry techniques for measuring and managing interest rate risk are continuing to evolve, particularly for products with uncertain cash flows or repricing dates, such as many mortgage-related products and retail deposits.

8. Even though the Committee is not currently proposing capital charges specifically for interest rate risk, all banks

should have enough capital to support the risks they incur, including those arising from interest rate risk. Individual supervisors may, of course, decide to apply capital charges to their banking system in general or to individual banks that are more extensively exposed to interest rate risk, or whose risk management processes are unsatisfactory.

9. The Committee stipulates in the five sections III to VII of the paper the following eleven principles for banking supervisory authorities to apply in assessing bank's management of interest rate risk:

The role of the board and senior management

Principle 1:

In order to carry out its responsibilities, the board of directors in a bank should approve strategies and policies with respect to interest rate risk management and ensure that senior management takes the steps necessary to monitor and control these risks. The board of directors should be informed regularly of the interest rate risk exposure of the bank in order to assess the monitoring and controlling of such risk.

Principle 2:

Senior management must ensure that the structure of the bank's business and the level of interest rate risk it assumes are effectively managed, that appropriate policies and procedures are established to

control and limit these risks, and that resources are available for evaluating and controlling interest rate risk.

Principle 3:

Banks should clearly define the individuals and/or committee responsible for managing interest rate risk and should ensure that there is adequate separation of duties in key elements of the risk management process to avoid conflicts of interest. Banks should have risk measurement, monitoring and control functions with clearly defined duties that are sufficiently independent from position-taking functions of the bank and which report risk exposures directly to senior management and the board of directors. Larger or more complex banks should have a designated independent unit responsible for the design and administration of the bank's interest rate risk measurement, monitoring and control functions.

Policies and procedures

Principle 4:

It is essential that bank's interest rate risk policies and procedures be clearly defined and consistent with the nature and complexity of their activities. These policies should be applied on a consolidated basis and, as appropriate, at the level of individual affiliates, especially when recognising legal distinctions and possible obstacles to cash movements among affiliates.

Principle 5:

It is important that banks identify the risks inherent in new products and activities and ensure these are subject to adequate procedures and controls before being introduced or undertaken. Major or risk management initiatives should be approved in advance by the board or its appropriate delegated committee.

Measurement and monitoring system**Principle 6:**

It is essential that banks have interest rate risk measurement system that capture all material sources of interest rate risk and that assess the effect of interest rate changes in ways that are consistent with the scope of their activities. The assumptions underlying the system should be clearly understood by risk managers and bank management.

Principle 7:

Banks must establish and enforce operating limits and other practices that maintain exposures within levels consistent with internal policies.

Principle 8:

Banks should measure their vulnerability to loss under stressful market conditions - including the breakdown of key assumptions - and consider those results when establishing and reviewing their policies and limits for interest rate risk.

Principle 9:

Banks must have adequate information systems for measuring, monitoring, controlling and reporting interest rate exposures. Reports must be provided on a timely basis to the bank's board of directors, senior management and, where appropriate, individual business line managers.

Internal controls**Principle 10:**

Banks must have adequate system of internal controls over their interest rate risk management process. A fundamental component of the internal control system involves regular independent reviews and evaluations of the effectiveness of the system and, where necessary, ensuring that appropriate revisions or enhancements to internal controls are made. The results of such reviews should be available to the relevant supervisory authorities.

Information for supervisory authorities**Principle 11:**

Supervisory authorities should obtain from bank's sufficient and timely information with which to evaluate their level of interest rate risk. This information should take appropriate account of the range of maturities and currencies in each bank's portfolio, including off-balance sheet items, as well as other relevant factors, such as the

distinction between trading and non-trading activities.

I. SOURCES AND EFFECTS OF INTEREST RATE RISK

1. Interest rate risk is the exposure of a bank's financial condition to adverse movements in interest rates. Accepting this risk is a normal part of banking and can be an important source of profitability and shareholder value. However, excessive interest rate risk can pose a significant threat to a bank's earnings and capital base. Changes in interest rates affect a bank's earnings by changing its net interest income and the level of other interest-sensitive income and operating expenses. Changes in interest rates also affect the underlying value of the bank's assets, liabilities and off-balance sheet instruments because the present value of future cash flows (and in some cases, the cash flows themselves) change when interest rates change. Accordingly, an effective risk management process that maintains interest rate risk within prudent levels is essential to the safety and soundness of banks.

2. Before setting out some principles for interest rate risk management, a brief introduction to the sources and effects of interest rate risk might be helpful. Thus, the following sections describe the primary forms of interest rate risk to which banks are typically exposed. These include

repricing risk, yield curve risk, basis risk and optionality, each of which is discussed in greater detail below. These sections also describe the two most common perspectives for assessing a bank's interest rate risk exposure: the earnings perspective and the economic value perspective. As the names suggest, the earnings perspective focuses on the impact of interest rate changes on a bank's near-term earnings, while the economic value perspective focuses on the value of a bank's net cash flows.

A. Sources of Interest Rate Risk

1. *Repricing risk:* As financial intermediaries, banks encounter interest rate risk in several ways. The primary and most often discussed form of interest rate arises from timing differences in the maturity (for fixed rate) and repricing (for floating rate) of bank assets, liabilities and off-balance-sheet (OBS) positions. While such repricing mismatches are fundamental to the business of banking, they can expose a bank's income and underlying economic value to unanticipated fluctuations as interest rates vary. For instance, a bank that funded a long-term fixed rate loan with a short-term deposit could face a decline in both the future income arising from the position and its underlying value if interest rates increase. These declines arise because the cash flows on the loan are fixed over its lifetime, while the interest paid on the funding is variable,

and increases after the short-term deposit matures.

2. *Yield curve risk:* Repricing mismatches can also expose a bank to changes in the slope and shape of the yield curve. Yield curve risk arises when unanticipated shifts of the yield curve has adverse effects on a bank's income or underlying economic value. For instance, the underlying economic value of a long position in 10-year government bonds hedged by a short position in 5-year government notes could decline sharply if the yield curve steepens, even if the position is hedged against parallel movements in the yield curve.

3. *Basis risk:* Another important source of interest rate risk (commonly referred to as basis risk) arises from imperfect correlation in the adjustment of the rates earned and paid on different instruments with otherwise similar repricing characteristics. When interest rates change, these differences can give rise to unexpected changes in the cash flows and earnings spread between assets, liabilities and OBS instruments of similar maturities or repricing frequencies. For example, a strategy of funding a one year loan that reprices monthly based on the one month U.S. Treasury Bill rate, with a one-year deposit that reprices monthly based on one month Libor, exposes the institution to the risk that the spread between the two index rates may change unexpectedly.

4. *Optionality:* An additional and increasingly important sources of interest rate risk arises from the options embedded in many bank assets, liabilities and OBS portfolios. Formally, an option provides the holder the right, but not the obligation, to buy, sell, or in some manner alter the cash flow of an instrument of financial contract. Options may be stand alone instruments such as exchange-traded options and over-the-counter (OTC) contracts, or they may be embedded within otherwise standard instruments. While banks use exchange-traded and OTC-options in both trading and non-trading accounts, instruments with embedded options are generally most important in non-trading activities. They include various types of bonds and notes with call or put provision, loans which give borrowers the right to prepay balances, and various types of non-maturity deposit instruments which give depositors the right to withdraw funds at any time, often without any penalties. If not adequately managed, the asymmetrical payoff characteristics of instruments with optionality features can pose significant risk particularly to those who sell them, since the options held, both explicit and embedded, are generally exercised to the advantage of the holder and the disadvantage of the seller. Moreover, an increasing array of options can involve significant leverage which can magnify the influences (both negative and positive) of options positions on the financial conditions of the firm.

B. Effects of Interest Rate Risk

1. As the discussion above suggests, changes in interest rates can have adverse effects both on a bank's earnings and its economic value. This has given rise to two separate, but complementary, perspectives for assessing a bank's interest rate risk exposure.

2. **Earnings perspective:** In the earnings perspective, the focus of analysis is the impact of changes in interest rates on accrual or reported earnings. This is the traditional approach to interest rate risk assessment taken by many banks. Variation in earnings is an important focal point for interest rate risk analysis because reduced earnings or outright losses can threaten the financial stability of an institution by undermining its capital adequacy and by reducing market confidence.

3. In this regard, the component of earnings that had traditionally received the most attention is net interest income (i.e. the difference between total interest income and total interest expenses). This focus reflects both the importance of net interest income in banks' overall earnings and its direct and easily understood link to changes in interest rates. However, as banks have expanded increasingly into activities that generate fee-based and other non-interest income, a broader focus on overall net income - incorporating both interest and non-interest

income and expenses - has become more common. The non-interest income arising from many activities, such as loan servicing and various asset securitisation programs, can be highly sensitive to market interest rates. For example, some banks provide the servicing and loan administration function for mortgage loan pools in return for a fee based on the volume of assets it administers. When interest rates fall, the servicing bank may experience a decline in its fee income as the underlying mortgages prepay. In addition, even traditional sources of non-interest income such as transaction processing fees are becoming more interest rate sensitive. This increased sensitivity has led both bank management and supervisors to take a broader view of the potential effects of changes in market interest rates on bank earnings and to factor these broader effects into their estimated earnings under different interest rate environments.

4. **Economic value perspective:** Variation in market interest rates can also affect the economic value of a bank's assets, liabilities and OBS positions. Thus, the sensitivity of a bank's economic value to fluctuations in interest rates is a particularly important consideration of shareholders, management and supervisors alike. The economic value of an instrument represents an assessment of the present value of its expected net flows, discounted to reflect market rates. By extension, the economic value of a bank can be viewed as the present value of bank's

expected net cash flows, defined as the expected cash flows on assets minus the expected cash flows on liabilities plus the expected net cash flows on OBS positions. In this sense, the economic value perspective reflects one view of the sensitivity of the net worth of the bank to fluctuations in interest rates.

5. Since the economic value perspective considers the potential impact of interest rate changes on the present value of all future cash flows, it provides a more comprehensive view of the potential long-term effects of changes in interest rates than is offered by the earnings perspective. This comprehensive view is important since changes in near-term earnings - the typical focus of the earnings perspective - may not provide an accurate indication of the impact of interest rate movements on the bank's overall positions.

6. Embedded losses: The earnings and economic value perspectives discussed thus far focus on how future changes in interest rates may affect a bank's financial performance. When evaluating the level of interest rate risk it is willing and able to assume, a bank should also consider the impact the past interest rates may have on future performance. In particular, instruments that are not marked to market may already contain embedded gains or losses due to past rate movements. These gains or losses may be reflected over time

in the bank's earnings. For example, a long term fixed rate loan entered into when interest rates were low and refunded more recently with liabilities bearing a higher rate of interest will, over its remaining life, represent a drain on the bank's resources.

II. SOUND INTEREST RATE RISK MANAGEMENT PRACTICES

1. Sound interest rate risk management involves the application of four basic elements in the management of assets, liabilities and off-balance-sheet instruments:

- Appropriate board and senior management oversight;
- Adequate risk management policies and procedures;
- Appropriate risk measurement, monitoring and control functions; and
- Comprehensive internal controls and independent audits.

2. The specific manner in which a bank applies these elements in managing its interest rate risk will depend upon the complexity and nature of its holdings and activities as well as on the level of interest rate risk exposure. What constitutes adequate interest rate risk management practices can therefore vary considerably. For example, less complex banks whose senior managers are actively involved in the details of day-to-day operations may be able to rely on relatively basic interest rate risk

management processes. However, other organisations that have more complex and wide-ranging activities are likely to require more elaborate and formal interest rate risk management processes, to address their broad range of financial activities and to provide senior management with the information they need to monitor and direct day-to-day activities. Moreover, the more complex interest rate risk management processes employed at such banks require adequate internal controls that include audits or other appropriate oversight mechanisms to ensure the integrity of the information used by senior officials in overseeing compliance with policies and limits. The duties of the individuals involved in the risk measurement, monitoring and control functions must be sufficiently separate and independent from the business decision makers and position takers to ensure the avoidance of conflicts of interest.

3. As with other risk factor categories, the Committee believes that interest rate risk should be monitored on a consolidated, comprehensive basis, to include interest rate exposures in subsidiaries. At the same time, however, institutions should fully recognise any legal distinctions and possible obstacles to cash flow movements among affiliates and

adjust their risk management process accordingly. While consolidation may provide a comprehensive measure in respect of interest rate risk, it may also underestimate risk when positions in one affiliate are used to offset positions in another affiliate. This is because a conventional accounting consolidation may allow theoretical offsets between such positions from which a bank may not in practice be able to benefit because of legal or operational constraints. Management should recognise the potential for consolidated measures to undertake risks in such circumstances.

III. BOARD AND SENIOR MANAGEMENT OVERSIGHT OF INTEREST RATE RISK⁵

Effective oversight by a bank's board of directors and senior management is critical to a sound interest rate risk management process. It is essential that these individuals are aware of their responsibilities with regard to interest rate risk management and that they adequately perform their roles in overseeing and managing interest rate risk.

⁵This section refers to a management structure composed of a board of directors and senior management. The Committee is aware that there are significant differences in legislative and regulatory frameworks across countries as regards the functions of the board of directors and senior management. In some countries, the board has the main, if not exclusive, function of supervising the executive body (senior management, general management) so as to ensure that the latter fulfils its tasks. For this reason, in some cases, it is known as a supervisory board. This means that the board has not executive functions. In other countries, by contrast, the board has a broader competence in that it lays down the general framework for the management of the bank. Owing to these differences, the notions of the board of directors and the senior management are used in this paper not to identify legal constructs but rather to label two decision-making within a bank.

A. Board of Director

Principle 1:

In order to carry out its responsibilities, the board of directors in a bank should approve strategies and policies with respect to interest rate risk management and ensure that senior management takes the steps necessary to monitor and control these risks. The board of directors should be informed regularly of the interest rate risk exposure of the bank in order to assess the monitoring and controlling of such risk.

1. The board of directors has the ultimate responsibility for understanding the nature and the level of interest rate risk taken by the bank. The board should approve broad business strategies and policies that govern or influence the interest rate risk of the bank. It should review the overall objectives of the bank with respect to interest rate risk and should ensure the provision of clear guidance regarding the level of interest rate risk acceptable to the bank. The board should also approve policies that identify lines of authority and responsibility for managing interest rate risk exposures.

2. Accordingly, the board of directors is responsible for approving the overall policies of the bank with respect to interest rate risk and for ensuring that management takes the steps necessary to identify, measure, monitor, and control these risks.

The board or a specific committee of the board should periodically review information that is sufficient in detail and timeliness to allow it to understand and assess the performance of senior management in monitoring and controlling these risks in compliance with the bank's board-approved policies . Such reviews should be conducted regularly, being carried out more frequently where the bank holds significant positions in complex instruments. In addition, the board or one of its committees should periodically re-evaluate significant interest rate risk management policies as well as overall business strategies that affect the interest rate risk exposure of the bank.

3. The board of directors should encourage discussions between its members and senior management - as well as between senior management and others in the bank - regarding the bank's interest rate risk exposures and management process. Board members need not have detailed technical knowledge of complex financial instruments, legal issues, or of sophisticated risk management techniques. They have the responsibility, however, to ensure that the senior management has a full understanding of the risk incurred by the bank and that the bank has personnel available who have the necessary technical skills to evaluate and control these risks.

B. Senior Management

Principle 2:

Senior management must ensure that the structure of the bank's business and the level of interest rate risk it assumes are effectively managed, that appropriate policies and procedures are established to control and limit these risks, and that resources are available for evaluating and controlling interest rate risk.

1. Senior management is responsible for ensuring that the bank has adequate policies and procedures for managing interest rate risk on both a long-term and day-to-day basis and that it maintains clear lines of authorities and responsibility for managing and controlling this risk. Management is also responsible for maintaining:

- appropriate limits on risk taking;
- adequate systems and standards for measuring risk;
- standards for valuing positions and measuring performance;
- a comprehensive interest rate risk reporting and interest rate risk management review process; and
- effective internal controls.

2. Interest rate risk reports to senior management should provide aggregate information as well as sufficient supporting detail to enable management to assess the

sensitivity of the institution or changes in market conditions and other important risk factors. Senior management should also review periodically the organisation's interest rate risk management policies and procedures to ensure that they remain appropriate and sound. Senior management should also encourage and participate in discussions with members of the board and, where appropriate to the size and complexity of the bank, with risk management staff regarding risk measurement, reporting and management procedures.

3. Management should ensure that analysis and risk management activities related to interest rate risk are conducted by competent staff with technical knowledge and experience consistent with the nature and scope of the bank's activities. There should be sufficient depth in staff resources to manage these activities and to accommodate the temporary absence of key personnel.

C. Lines of Responsibility and Authority for Managing Interest Rate Risk

Principle 3:

Banks should clearly define the individuals and/or committees responsible for managing interest rate risk and should ensure that there is adequate separation of duties in key elements of the risk management process

to avoid potential conflicts of interest. Banks should have risk measurement, monitoring and control functions with clearly defined duties that are sufficiently independent from position-taking functions of the bank and which report risk exposures directly to senior management and the board of directors. Larger or more complex banks should have a designated independent unit responsible for the design and administration of the bank's interest rate risk measurement, monitoring and control functions.

1. Banks should clearly identify the individuals and/or committees responsible for conducting all of the various elements of interest rate risk management. Senior management should define lines of authority and responsibility for developing strategies, implementing tactics and conducting the risk measurement and reporting functions of the interest rate risk management process. Senior management should also provide reasonable assurance that all activities and all aspects of interest rate risk are covered by a bank's risk management process.

2. Care should be taken to ensure that there is adequate conflicts of interest. Management elements of the risk management process to avoid potential conflicts of interest. Management should ensure that sufficient safeguards exist to minimise the potential that individuals

initiating risk-taking positions may inappropriately influence key control functions of the risk management process such as the development and enforcement of policies and procedures, the reporting of risks to senior management, and the conduct of back-office functions. The nature and scope of such safeguards should be in accordance with the size and structure of the bank. They should also be commensurate with the volume and complexity of interest rate risk incurred by the banks and the complexity of its transactions and commitments. Larger or more complex banks should have a designed independent unit responsible for the design and administration of the bank's interest rate risk measurement, monitoring and control functions. The control functions carried out by this unit, such as administering the risk limits, are part of the overall internal control system.

3. The personnel charged with measuring, monitoring and controlling interest rate risk should have a well-founded understanding of all types of interest rate risk faced throughout the bank.

IV. ADEQUATE RISK MANAGEMENT POLICIES AND PROCEDURES

Principle 4:

It is essential that banks interest rate risk policies and procedures be clearly defined and consistent with the

nature and complexity of their activities. These policies should be applied on a consolidated basis and, as appropriate, at the level of individual affiliates, especially when recognising legal distinctions and possible obstacles to cash movements among affiliates.

1. Banks should have clearly defined policies and procedures for limiting and controlling interest rate risk. These policies should be applied on a consolidated basis and, as appropriate, at specific affiliates or other units of the bank. Such policies and procedures should delineate lines of responsibility and accountability over interest rate risk management decisions and should clearly define authorised instruments, hedging strategies and position-taking opportunities. Interest rate risk policies should also identify quantitative parameters that define the level of interest rate risk acceptable for the bank. Where appropriate, such limits should be further specified for certain types of instruments, portfolios, and activities. All interest rate risk policies should be reviewed periodically and revised as needed. Management should define the specific procedures and approval necessary for exceptions to policies, limits and authorisations.

2. A policy statement identifying the types of instruments and activities that the bank may employ or conduct is one means whereby management can communicate

their tolerance of risk on a consolidated basis and at different legal entities. If such a statement is prepared, it should clearly identify permissible instruments, either specifically or by their characteristics, and should also describe the purposes of objectives for which they may be used. The statement should also delineate a clear set of institutional procedures for acquiring specific instruments, managing portfolios, and controlling the bank's aggregate interest rate risk exposure.

Principle 5:

It is important that banks identify the interest rate risks inherent in new products and activities and ensure these are subject to adequate procedure and controls before being introduced or undertaken. Major hedging or risk management initiatives should be approved in advance by the board or its appropriate delegated committee.

3. Products and activities that are new to the bank should undergo a careful pre-acquisition review to ensure that the bank understands their interest rate risk characteristics and can incorporate them into its risk management process. When analysing whether or not a product or activity introduces a new element of interest rate risk exposure, the bank should be aware that changes to a instrument's maturity, repricing or repayment terms can materially affect the product's interest rate risk

characteristics. To take a simple example, a decision to buy and hold a 30 year treasury bond would represent a significantly different interest rate risk strategy for a bank that had previously limited its investment maturities to less than 3 years. Similarly, a bank specialising in fixed-rate short-term commercial loans that then engages in residential fixed-rate mortgage lending should be aware of the optionality features of the risk embedded in many mortgage products that allow the borrower to prepay the loan at any time with little, if any, penalty.

4. Prior to introducing a new product, hedging, or position-taking strategy, management should ensure that adequate operational procedures and risk control system are in place. The board or its appropriate delegated committee should also approve major hedging or risk management initiatives in advance of their implementation. Proposals to undertake new instrument or new strategies should contain these features:

- a description of the relevant product or strategy;
- an identification of the resources required to establish sound and effective interest rate risk management of the product or activity;
- an analysis of the reasonableness of

the proposed activities in relation to the bank's overall financial condition and capital levels; and

- the procedures to be used to measure, monitor and control the risks of the proposed product or activity.

V. RISK MEASUREMENT, MONITORING AND CONTROL FUNCTIONS

A. Interest Rate Risk Measurement

Principle 6:

It is essential that banks have interest rate risk measurement system that capture all material sources of interest rate risk and that assess the effect of interest rate changes in ways that are consistent with the scope of their activities. The assumptions underlying the system should be clearly understood by risk managers and bank management.

In general, but depending on the complexity and range of activities of the individual bank, banks should have interest rate risk measurement systems that assess the effects of rate changes on both earnings and economic value. These system should provide meaningful measures of a bank's current levels of interest rate risk exposure, and should be capable of identifying any excessive exposures that might arise.

1. Measurement system should:

- assess all material interest rate risk associated with a bank's assets, liabilities, and OBS positions;
- utilise generally accepted financial concepts and risk measurement techniques; and
- have well documented assumptions and parameters.

2. As a general rule, it is desirable for any measurement system to incorporate interest rate risk exposures arising from the full scope of a bank's activities, including both trading and non-trading sources. This does not preclude different measurement systems and risk management approaches being used for different activities; however, management should have an integrated view of interest rate risk across products and business lines.

3. A bank's interest rate risk measurement system should address all material sources of interest rate risk including repricing, yield curve, basis and option risk exposures. In many cases, the interest rate characteristics of a bank's largest holdings will dominate its aggregate risk profile. While all of a bank's holdings should receive appropriate treatment, measurement systems should evaluate such concentrations with particular rigour. Interest rate risk measurement systems should also provide rigorous treatment of those instruments

which might significantly affect a bank's aggregate position, even if they do not represent a major concentration. Instruments with significant embedded or explicit option characteristics should receive special attention.

4. A number of techniques are available for measuring the interest rate risk exposure of both earnings and economic value. Their complexity ranges from simple calculations to static simulations using current holdings to highly sophisticated dynamic modelling techniques that reflect potential future business and business decisions.

5. The simplest techniques for measuring a bank's rate risk exposure begin with a maturity/repricing schedule that distributes interest-sensitive assets, liabilities and OBS positions into "time bands" according to their maturity (if fixed rate) or time remaining to their next repricing (if floating rate). These schedules can be used to generate simple indicators of the interest rate risk sensitivity of both earnings and economic value to changing interest rates. When this approach is used to assess the interest rate risk of current earnings, it is typically referred to as **gap analysis**. The size of the gap for a given time band - that is, assets minus liabilities plus OBS exposures that reprice or mature within that time band - gives an indication of the bank's repricing risk exposure.

6. A maturity/repricing schedule can also be used to evaluate the effects of changing interest rates on a bank's economic value by applying sensitivity weights to each time band. Typically, such weights are based on estimates of the **duration** of the assets and liabilities that fall into each time-band, where duration is a measure of the percent change in the economic value of a position that will occur given a small change in the level of interest rates. Duration-based weights can be used in combination with a maturity/repricing schedule to provide a rough approximation of the change in a bank's economic value that would occur given a particular set of changes in market interest rates.

7. Many banks (especially those using complex financial instruments or otherwise having complex risk profile) employ more sophisticated interest rate risk measurement systems than those based on simply maturity/repricing schedules. These **simulation techniques** typically involve detailed assessments of the potential effects of changes in interest rates on earnings and economic value by simulating the future path of interest rates and their impact on cash flows. In **static simulations**, the cash flows arising solely from the bank's current on- and off-balance sheet positions are assessed. In a **dynamic simulation** approach, the simulation builds in more detailed assumptions about the future course of interest rates and expected changes in a

bank's business activity over that time. These more sophisticated techniques allow for dynamic interaction of payments streams and interest rates, and better capture the effect of embedded or explicit options.

8. Regardless of the measurement system, the usefulness of each technique depends on the validity of the underlying assumptions and the accuracy of the basic methodologies used to model interest rate risk exposure. In designing interest rate risk measurement systems, banks should ensure that the degree of detail about the nature of their interest-sensitive positions is commensurate with the complexity and risk inherent in those positions. For instance, using gap analysis, the precision of interest rate risk measurement depends in part on the number of time bands into which positions are aggregated. Clearly, aggregation of positions/cash flows into broad time bands implies some loss of precision. In practice, the bank must assess the significance of the potential loss of precision in determining the extent of aggregation and simplification to be built into the measurement approach.

9. Estimates of interest rate risk exposure, whether linked to earnings or economic value, utilise, in some form, forecasts of the potential course of future interest rates. For risk management purposes, banks should incorporate a change in interest rates that is sufficiently large to

encompass the risks attendant to their holdings. Banks should consider the use of multiple scenarios, including potential effects in changes in the relationships among interest rates (i.e. yield curve risk and basis risk) as well as changes in the general level of interest rates. For determining probable changes in interest rates, simulation techniques could, for example, be used. Statistical analysis can also play an important role in evaluating correlation assumptions with respect to basis or yield curve risk.

10. The integrity and timeliness of data on current positions is also a key component of the risk measurement process. A bank should ensure that all material positions and cash flows, whether stemming from on- or off-balance-sheet positions, are incorporated into the measurement system of a timely basis. Where applicable, these data should include information on the coupon rates or cash flows of associated instruments and contracts. Any manual adjustments to underlying data should be clearly documented, and the nature and reasons for the adjustments should be clearly understood. In particular, any adjustments to expected cash flows for expected prepayments or early redemptions should be well reasoned and such adjustments should be available for review.

11. In assessing the results of interest rate risk measurement system, it is important that

the assumptions underlying the system be clearly understood by risk managers and banks management. In particular, techniques using sophisticated simulations should be used carefully so that they do not become "black boxes", producing numbers that have the appearance of precision, but that in fact are not very accurate when their specific assumptions and parameters are revealed. Key assumptions should be recognised by senior management and risk managers and should be re-evaluated at least annually. They should also be clearly documented and their significance understood. Assumptions used in assessing the interest rate sensitivity of complex instruments and instruments with uncertain maturities should be subject to particularly rigorous documentation and review.

12. When measuring interest rate risk exposure, two further aspects call for more specific comment: the treatment of those positions where behavioural maturity differs from contractual maturity and the treatment of positions denominated in different currencies. Positions such as savings and sight deposits may have contractual maturities or may be open-ended, but in either case, depositors generally have the option to make withdrawals at any time. In addition, banks often choose not to move rates paid on these deposits in line with changes in market rates. These factors complicate the measurement of interest rate risk exposure, since not only the value of

the positions but also the timing of their cash flows can change when interest rates vary. With respect to banks' asset, prepayment features of mortgages and mortgage related instruments also introduce uncertainty about the timing of cash flows on these positions. These issues are described in more detail in Annex A, which forms an integral part of this text.

13. Banks with positions denominated in different currencies can expose themselves to interest rate risk in each of these currencies. Since yield curves vary from currency to currency, banks generally need to assess exposures in each. Banks with the necessary skills and sophistication, and with material multi-currency exposures, may choose to include in their risk measurement process methods to aggregate their exposure in different currencies using assumptions about the correlation between interest rates in different currencies. A bank that uses correlation assumptions to aggregate its risk should periodically review the stability and accuracy of those assumptions. The bank also should evaluate what its potential risk exposure would be in the event that such correlations break down.

B. Limits

Principle 7:

Banks must establish and enforce operating limits and practices that maintain and exposures within levels

consistent with their internal policies.

1. The goal of interest rate risk management is to maintain a bank's interest rate risk exposure within self-imposed parameters over a range of possible changes in interest rates. A system of interest rate risk limits and risk taking guidelines provide the means for achieving that goal. Such a system should set boundaries for the level of interest rate risk for the bank and, where appropriate, should also provide the capability to allocate limits to individual portfolios, activities or business units. Limit systems should also ensure that positions that exceed certain predetermined levels receive prompt management attention. An appropriate limit system should enable management to control interest rate risk exposures, initiate discussion about opportunities and risks, and monitor actual risk taking against predetermined risk tolerances.

2. A bank's limits should be consistent with its overall approach to measuring interest rate risk. Aggregate interest rate risk limits clearly articulating the amount of interest rate risk acceptable to the bank should be approved by the board of directors and re-evaluated periodically. Such limits should be appropriate to the size, complexity and capital adequacy of the bank as well as its ability to measure and manage its risk. Depending on the nature of a bank's holdings and its general sophistication, limits can also

be identified with individual business units, portfolios, instrument types or specific instruments. The level of detail of risk limits should reflect the characteristics of the bank's holdings including the various sources of interest rate risk to which the bank is exposed.

3. Limit exceptions should be made known to appropriate senior management without delay. There should be a clear policy as to how senior management will be informed and what action should be taken by management in such cases. Particularly important is whether limits are absolute in the sense that they should never be exceeded or whether, under specific circumstances, which should be clearly described, breaches of limits can be tolerated for a short period of time. In that context, the relative conservation of the chosen limits may be an important factor.

4. Regardless of their level of aggregation, limits should be consistent with the bank's overall approach to measuring interest rate risk and should address the potential impact of changes in market interest rates on reported earnings and the bank's economic value of equity. From an earnings perspective, banks should explore limits on the variability of net income as well as net interest income in order to fully assess the contribution of non-interest income to the interest rate risk exposure of the bank. Such limits usually specify acceptable levels

of earnings volatility under specified interest rate scenarios.

5. The form of limits for addressing the effect of rates on a bank's economic value of equity should be appropriate for the size and complexity of its underlying positions. For banks engaged in traditional banking activities and with few holdings of long-term instruments, options, instruments with embedded options, or other instruments whose value may be substantially altered given changes in market rates, relatively simple limits on the extent of such holdings may suffice. For more complex banks, however, more detailed, limit systems on acceptable changes in the estimated economic value of equity of the bank may be needed.

6. Interest rate risk limits may be keyed to specific scenarios of movements in market interest rates such as an increase or decrease of a particular magnitude. The rate movements used in developing these limits should represent meaningful stress situations taking into account historic rate volatility and the time required for management to address exposures. Limits may also be based on measures derived from the underlying statistical distribution of interest rates, such as earnings at risk or economic value at risk techniques. Moreover, specified scenarios should take account of the full range of possible sources of interest rate risk to the bank including mismatch, yield curve, basis

and option risks. Simple scenarios using parallel shifts in interest rates may be insufficient to identify such risks.

C. Stress Testing

Principle 8:

Banks should measure their vulnerability to loss under stressful market conditions - including the breakdown of key assumptions - and consider those results when establishing and reviewing their policies and limits for interest rate risk.

The risk measurement system should also support a meaningful evaluation of the effect of stressful market conditions on the bank. Stress testing should be designed to provide information on the kinds of conditions under which the bank's strategies or positions would be most vulnerable, and thus may be tailored to the risk characteristics of the bank. Possible stress scenarios might include abrupt changes in the general level of interest rates, changes in the relationships among key market rates (i.e. basis risk), changes in the slope and the shape of the yield curve (i.e. yield curve risk), changes in the liquidity of key financial markets or changes in the volatility of market rates. In addition, stress scenarios should include conditions under which key business assumptions and parameters break down. The stress testing of assumptions used for illiquid instruments and instruments with

uncertain contractual maturities is particularly critical to achieving an understanding of the bank's risk profile. In conducting stress tests, special consideration should be given to instruments or markets where concentration exists as such positions may be more difficult to liquidate or offset in stressful situations. Banks should consider "worst case" scenarios in addition to more probable events. Management and the board of directors should periodically review both the design and the results of such stress tests, and ensure that appropriate contingency plans are in place.

D. Interest Rate Risk Monitoring and Reporting

Principle 9:

Banks must have adequate information system for measuring, monitoring, controlling and reporting interest rate exposures. Reports must be provided on a timely basis to the bank's board of directors, senior management and, where appropriate, individual business line managers.

1. An accurate, informative, and timely management information system is essential for managing interest rate risk exposure, both to inform management and to support compliance with board policy. Reporting of risk measures should be regular and should clearly compare current exposure to policy limits. In addition, past forecasts or risk

estimates should be compared with actual results to identify any modelling shortcomings.

2. Reports detailing the interest rate risk exposure or the bank should be reviewed by the board on a regular basis. While the types of reports prepared for the board and for various levels of management will vary based on the bank's interest rate risk profile, they should, at a minimum include the following:

- summaries of the bank's aggregate exposures;
- reports demonstrating the bank's compliance with policies and limits;
- results of stress tests including those assessing breakdowns in key assumptions and parameters; and

summaries of the findings of reviews of interest rate risk policies, procedures, and the adequacy of the interest rate risk measurement systems, including any findings of internal auditors and retained consultants.

VI. INTERNAL CONTROLS

Principle 10:

Banks must have an adequate system of internal controls over their interest rate risk management process. A fundamental component of the internal

control system involves regular independent reviews and evaluations of the effectiveness of the system and, where necessary, ensuring that appropriate revisions or enhancements to internal controls are made. The results of such reviews should be available to relevant supervisory authorities.

1. Banks should have adequate internal controls to ensure the integrity of their interest rate risk management process. These internal controls should be an integral part of the institution's overall system of internal control. They should promote effective and efficient operations, reliable financial and regularly reporting, and compliance with relevant laws, regulations and institutional policies. An effective system of internal control for interest rate risk includes:

- a strong control environment;
- an adequate process for identifying and evaluating risk;
- the establishment of control activities such as policies, procedures and methodologies;
- adequate information systems; and,
- continual review of adherence to established policies and procedures.

With regard to control policies and procedures, attention should be given to appropriate approval processes, exposure limits, reconciliations, reviews and other mechanisms designed to provide a

reasonable assurance that the institution's interest rate risk management objectives are achieved. Many attributes of a sound risk management process, including risk measurement, monitoring and control functions, are key aspects of an effective system of internal control. Banks should ensure that all aspects of an effective system are effective, including those aspects that are not directly part of the risk management process.

2. In addition, an important element of a bank's internal control system over its interest rate risk management process is regular evaluation and review. This includes ensuring that personnel are following established policies and procedures, as well as ensuring that the procedures that were established actually accomplish the intended objectives. Such reviews and evaluations should also address any significant change that may impact the effectiveness of control, such as changes in market conditions, personnel, technology, and structures of compliance with interest rate risk exposure limits, and ensure that appropriate follow-up with management has occurred for any limits that were exceeded. Management should ensure that all such reviews and evaluations are conducted regularly by individuals who are independent of the function they are assigned to review. When revision or enhancements to internal controls are warranted, there should be a mechanism in

place to ensure that these are implemented in a timely manner.

3. Reviews of the interest rate risk measurement system should include assessments of the assumptions, parameters, and methodologies used. Such reviews should seek to understand, test, and document the current measurement process, evaluate the system's accuracy, and recommend solutions to any identified weaknesses. If the measurement system incorporates one or more subsidiary systems or processes, the review should include testing aimed at ensuring that the subsidiary systems are well-integrated and consistent with each other in all critical respects. The results of this review, along with any recommendations for improvement, should be reported to senior management and/or the board and acted upon in a timely manner.

4. The frequency and extent to which a bank should re-evaluate its risk measurement methodologies and models depends, in part, on the particular interest rate risk exposures created by holdings and activities, the pace and nature of market interest rate changes, and the pace and complexity of innovation with respect to measuring and managing interest rate risk.

5. Banks, particularly those with complex risk exposure, should have their measurement, monitoring and control functions reviewed on a regular basis by an

independent party (such as an internal or external auditor). In such cases, reports written by external auditors or other outside parties should be available to relevant supervisory authorities. It is essential that any independent reviewer ensure that the bank's risk measurement system is sufficient to capture all material elements of interest rate risk, whether arising from on-or off-balance sheet activities. Such a reviewer should consider the following factors in making the risk assessment:

- the quantity of interest rate risk , e.g.
 - the volume and price sensitivity of various products;
 - the vulnerability of earnings and capital under differing rate changes including yield curve twists;
 - the exposure of earnings and economic value to various other forms of interest rate risk, including basis and optionality risk.
- the quality of interest rate risk management, e.g.
 - whether the bank's internal measurement system is appropriate to the nature, scope, and complexities of the bank and its activities;
 - whether the bank has an independent risk control unit responsible for the design and

administration of the risk measurement, monitoring and control functions;

- whether the board of directors and senior management is actively involved in the risk control process;
- whether internal policies, controls and procedures concerning interest rate risk are well documented and complied with;
- whether the assumptions of the risk measurement system are well documented, data accurately processed, and data aggregation is proper and reliable;
- whether the organisation has adequate staffing to conduct a sound risk management process.

6. In those instances where the independent review is conducted by internal auditors, banks are encouraged to have the risk measurement, monitoring and control functions periodically reviewed by external auditors.

VII. MONITORING OF INTEREST RATE RISK BY SUPERVISORY AUTHORITIES

Principle 11:

Supervisory authorities should obtain from banks sufficient and timely

information with which to evaluate their level of interest rate risk. This information should take appropriate account the range of maturities and currencies in each bank's portfolio, including off-balance-sheet items, as well as relevant factors, such as the distinction between trading and non-trading activities.

1. Supervisory authorities should, on a regular basis, obtain sufficient information to assess individual bank's interest rate risk exposures. In order to minimise reporting burden, this information could be obtained through standardised reports that are submitted by banks, through on-site examinations, or by other means, such as internal management reports. The precise information obtained could differ among supervisors, but should enable the supervisor to assess the level and direction of a bank's interest rate exposure. Such information may be generated from the bank's internal measures or from more standardised reports. As a minimum, supervisors should have enough information to identify and monitor banks that have significant repricing mismatches. Information contained in internal management reports, such as maturity/repricing gaps, earnings and economic value simulation estimates, and the results of stress tests can be particularly useful in this regard.

2. A supervisory reporting framework that collects information on a bank's

positions by remaining maturity or time to next repricing is one method that supervisors may use for this purpose. Under such an approach, a bank would categorise its interest-sensitive assets, liabilities and OBS positions into a series of repricing time bands or maturity categories. In addition, the information should identify the balances by specific types of instruments that differ significantly in their cash flow characteristics.

3. Supervisors may want to collect additional information on those positions where the behavioural maturity is different from the contractual maturity. Reviewing the results of a bank's internal model, perhaps under a variety of different assumptions, scenarios and stress tests, can also be highly informative.

4. Banks operating in different currencies can expose themselves to interest rate risk in each of these currencies. Supervisory authorities, therefore, may want banks to analyse their exposures in different currencies separately, at least when exposure in different currencies are material.

5. Another question is the extent to which interest rate risk should be viewed on a whole bank basis or whether the trading book, which is marked to market, and the banking book, which is often not, should be treated separately. As general rule, it is desirable for any measurement system to

incorporate interest rate risk exposures arising from the full scope of a bank's activities, including both trading and non-trading sources. This does not preclude different measurement systems and risk management approaches being used for different activities; however, management should have an integrated view of interest rate risk across products and business lines. Supervisors may want to obtain more specific information on how trading and non-trading activities are measured and incorporated into a single measurement system. They should also ensure that interest rate risk in both trading and non-trading activities is properly managed and controlled.

6. A meaningful analysis of interest rate risk is only possible if the supervisor receives the relevant information regularly and on a timely basis. Since the risk profile in the traditional banking business changes less rapidly than in the trading business, quarterly or semi-annual reporting of the former may be sufficient for many banks. Some of the factors that supervisors may wish to consider when designing a specific reporting framework are described in greater detail in Annex B, which forms an integral part of this text.

ANNEX - A

INTEREST RATE RISK MEASUREMENT TECHNIQUES

1. This annex provides a brief overview of the various technique used by banks to measure the exposure of earnings and of economic value to changes in interest rates. The variety of the techniques ranges from calculations that rely on simply maturity and repricing tables, to static simulations based on current on-and off-balance sheet positions, to highly sophisticated dynamic modelling techniques that incorporate assumptions about the behaviour of the bank and its customers in response to changes in the interest rate environment. Some of these general approaches can be used to measures interest rate risk exposure from both an earnings and an economic value perspective, while others are more typically associated with only one of these two perspectives. In addition, the methods vary in their ability to capture the different forms of interest rate exposure: the simplest methods are intended primarily to capture the risks arising from maturity and repricing mismatches, while the more sophisticated methods can more easily capture the full range of risk exposures.

2. As this discussion suggests, the various measurement approaches described below have their strength and weakness in terms of providing accurate and reasonable

measures of interest rate risk exposure. Ideally, a bank's interest rate risk measurement system would take into account the specific characteristics of each individual interest-sensitive position, and would capture in detail the full range of potential movements in interest rates. In practice, however, measurement systems embody simplifications that move away from this ideal. For instance, in some approaches, positions may be aggregated into broad categories, rather than interest rate sensitivity. Similarly, the nature of interest rate movements that each approach can incorporate may be limited: in some cases, only a parallel shift of the yield curve may be assumed or less than perfect correlations between interest rates may not be taken into account. Finally, the various approaches differ in their ability to capture the optionally inherent in many positions and instrument. The discussion in the following sections will highlight the areas of simplification that typically characterise each of the major interest rate risk measurement techniques.

A. Repricing Schedules

1. The simplest techniques for measuring a bank's interest rate risk exposure begin with a maturity/repricing schedule that distributes interest-sensitive assets, liabilities and off-balance sheet positions into a certain number of predefined

time bands according to their maturity (if fixed rate) or time remaining to their next repricing (if floating rate). Those assets and liabilities lacking definitive repricing intervals (e.g. sight deposits or savings accounts) or actual maturities that could vary from contractual maturities (e.g. mortgages with an option for early repayment) are assigned to repricing time bands according to the judgement and past experience of the bank.

2. **Gap analysis:** Simple maturity/ repricing schedules can be used to generate simple indicators of the interest rate risk sensitivity of both earnings and economic value to changing interest rates. When this approach is used to assess the interest rate risk of current earnings, it is typically referred to as gap analysis. Gap analysis was one of the first methods developed to measure a bank's interest rate risk exposure, and continues to be widely used by banks. To evaluate earnings exposure, interest rate sensitive liabilities in each time band are subtracted from the corresponding interest rate sensitive assets to produce a repricing "gap" for that time band. This gap can be multiplied by an assumed change in interest rates to yield an approximation of the change in net interest rate movement used in the analysis can be based on a variety of factors, including historical experience, simulation of potential future interest rate movements, and the judgement of bank management.

3. A negative, or liability-sensitive, gap occurs when liabilities exceed assets (including off-balance sheet position) in a given time band. This means that an increase in market interest rates could cause a decline in net interest income. Conversely, a positive, or asset-sensitive, gap implies that the bank's net interest income could decline as a result of a decrease in the level of interest rates.

4. These simple gap calculations can be augmented by information on the average coupon on assets and liabilities in each time band. This information can be used to place the results of the gap calculations in context. For instance, information on the average coupon rate could be used to calculate estimates of the level of net interest income arising from positions maturing or repricing within a given time band, which would then provide a "scale" to assess the changes in income implied by the gap analysis.

5. Although gap analysis is a very commonly used approach to assessing interest rate risk exposure, it has a number of shortcomings. First, gap analysis does not take account of variation in the characteristics of different positions within a time band. In particular, all positions within a given time band are assumed to mature or reprice simultaneously, a simplification that is likely to have greater impact on the precision of the estimates as the degree of aggregation within a time band increases.

Moreover, gap analysis ignores differences in spreads between interest rates that could arise as the level of market interest rates changes (basis risk). In addition, it does not take into account any changes in the timing of payments that might occur as a result of changes in the interest rate environment. Thus, it fails to account for differences in the sensitivity of income that may arise from option-related positions. For these reasons, gap analysis provides only a rough approximation to the actual change in net interest income which would result from the chosen change in the pattern of interest rates. Finally most gap analyses fail to capture variability in non-interest revenue and expenses, a potentially important source of risk to current income.

6. **Duration:** A maturity/repricing schedule can also be used to evaluate the effects of changing interest rates on a bank's economic value by applying sensitive weights to each time band. Typically, such weights are based on estimates of the duration of the assets and liabilities that fall into each time band. Duration is a measure of the percent change in the economic value of a position that will occur given a small change in the level of interest rates⁶. It

reflects the timing and size of cash flows that occur before the instrument's contractual maturity. Generally, the longer the maturity or next repricing date of the instrument and the smaller the payments that occur before maturity (e.g. coupon payments), the higher the duration (in absolute value). Higher duration implies that a given change in the level of interest rates will have a larger impact on economic value.

7. Duration-based weights can be used in combination with a maturity/repricing schedule to provide a rough approximation of the change in a bank's economic value that would occur given a particular change in the level of market interest rates. Specifically, an "average" duration is assumed for the positions that fall into each time band. The average durations are then multiplied by an assumed change in interest rates to construct a weight for each time band. In some cases, different weights are used for different positions that fall within a time band, reflecting broad differences in the coupon rates and maturities (for instance, one weight for assets, and another for liabilities). In addition, different interest rate changes are sometimes used for different time bands, generally to reflect differences

⁶In its simplest form, duration measures changes in economic value resulting from a percentage change of interest rates under the simplifying assumptions that changes in value are proportional to changes in the level of interest rates and that the timing of payments is fixed. Two important modifications of simple duration are commonly used that relax one or both of these assumptions. The first case is so called modified duration. Modified duration - which is standard duration divided by $1 + r$, where r is the level of market interest rates - is an elasticity. As such, it reflects the percentage change in the economic value of the instrument for a given percentage in $1 + r$. As with simple duration, it assumes a linear relationship between percentage changes in value and percentage changes in interest rates. The second form of duration relaxes this assumption, as well as the assumption that the timing of payments is fixed. Effective duration is the percentage change in the price of the relevant instrument for a basis point change in yield.

in the volatility of interest rates along the yield curve. The weighted gaps are aggregated across time bands to produce an estimate of the change in economic value of the bank that would result from the assumed changes in interest rates.

8. Alternatively, an institution could estimate the effect of changing market rates by calculating the precise duration of each asset, liability and off-balance sheet position and then deriving the net position for the bank based on these more accurate measures, rather than by applying an estimated average duration weight to all positions in a given time band. This would eliminate potential errors occurring when aggregating positions/cash flows. As another variation, risk weights could also be designed for each time band on the basis of actual percent changes in market values of hypothetical instruments that would result from a specific scenario of changing market rates. That approach - which is sometimes referred to as effective duration - would better capture the non-linearity of price movements arising from significant changes in market interest rates and, thereby, would avoid an important limitation of duration.

9. Estimates derived from a standard duration approach may provide an acceptable approximation of bank's exposure to changes in economic value for relatively non-complex banks. Such estimates, however, generally focus on just

one form of interest rate risk exposure - repricing risk. As a result, they may not reflect interest rate risk arising - for instance - from changes in the relationship among interest rates within a time band (basis risk). In addition, because such approaches typically use an average duration for each time band, the estimates will not reflect differences in the actual sensitivity of positions that can arise from differences in coupon rates and the timing of payments. Finally, the simplifying assumptions that underlie the calculation of standard duration means that the risk of options may not be well-captured.

B. Simulation Approaches

1. Many banks (especially those using complex financial instruments or otherwise having complex risk profile) employ more sophisticated interest rate risk measurement systems than those based on simple maturity/repricing schedules. These simulation techniques typically involve detailed assessments of the potential effects of changes in interest rates on earnings and economic value by simulating the future path of interest rate and their impact on cash flows.

2. In some sense, simulation technique can be seen as an extension and refinement of the simple analysis based on maturity/repricing schedule. However, simulation approaches typically involve a more detailed

breakdown of various categories of on-and off-balance sheet positions, so that specific assumptions about the interest and principal payments and non-interest income and expense arising from each type of position can be incorporated. In addition, simulation techniques can incorporate more varied and refined changes in the interest rate environment, ranging from changes in the slope and shape of the yield curve to interest rate scenarios derived from Monte Carlo simulations.

3. In **static simulations**, the cash flows arising solely from the bank's current on-and off-balance sheet positions are assessed. For assessing the exposure of earnings, simulations estimating the cash flows and resulting earnings streams over a specific period are conducted based on one or more assumed interest rate scenarios. Typically, although not always, these simulations entail relatively straightforward shift or tilts of the yield curve, or changes of spreads between different interest rates. When the resulting cash flows are simulated over the entire expected lives of the bank's holdings and discounted back to their values, an estimate of the change in the bank's economic value can be calculated.⁷

4. In a **dynamic simulation** approach, the simulation builds in more detailed assumptions about the future course of interest rates and the expected changes in a

bank's business activity over that time. For instance, the simulation could involve assumptions about a bank's strategy for changing administered interest rates (on savings deposits, for example), about the behaviour of the bank's customers (e.g. withdrawals from sight and savings deposits) and/or about the future stream of business (new loans or other transactions) that the bank will encounter. Such simulations use these assumptions about future activities and reinvestment strategies to project expected cash flows and estimate dynamic earnings and economic value outcomes. These more sophisticated techniques allow for dynamic interaction of payments stream and interest rates, and better capture the effect of embedded or explicit options.

5. As with other approaches, the usefulness of simulation-based interest rate risk measurement techniques depends on the validity of the underlying assumptions and the accuracy of the basic methodology. The output of sophisticated simulations must be assessed largely in the light of the validity of the simulation's assumptions about future interest rates and the behaviour of the bank and its customers. One of the primary concerns that arises is that such simulations do not become "black boxes" that lead to false confidence in the precision of the estimates.

⁷The duration analysis described in the previous section can be viewed as a very simple form of static simulation.

C. Additional Issues

1. One of the most difficult tasks when measuring interest rate risk is how to deal with those positions where behavioural maturity differs from contractual maturity (or where there is no stated contractual maturity). On the asset side of the balance sheet, such positions may include mortgages and mortgage-related securities, which can be subject to prepayment. In some countries, borrowers have the discretion to prepay their mortgages with little or no penalty, a situation that creates uncertainty about the timing of the cash flows associated with these instruments. Although there is always some volatility in prepayments resulting from demographic factors (such as death, divorce, or job transfers) and macroeconomic conditions, most of the uncertainty surrounding prepayments arises from the response of borrowers to movements in interest rates. In general, decline in interest rates result in increasing levels of prepayments, as borrowers refinance their loans at lower yields. In contrast, when interest rates rise unexpectedly, prepayment rates tend to slow, leaving the bank with a larger than anticipated volume of mortgages paying below current market rates.

2. On the liability side, such positions include so-called non-maturity deposits such as sight deposits and savings deposits, which can be withdrawn, often without penalty, at

the discretion of the depositor. The treatment of such deposits is further complicated by the fact that the rates received by depositors tend not to move in close correlation with changes in the general level of market interest rates. In fact, banks can and do administer the rates on the accounts with the specific intentions of managing the volume of deposits retained.

3. The treatment of positions with embedded options is an issue of special concern in measuring the exposure of both current earnings and economic value to interest rate changes. In addition, the issue arises across the full spectrum of approaches to interest rate measurement, from simple gap analysis to the most sophisticated simulation techniques. In the maturity/repricing schedule framework, banks typically make assumptions about the likely timing of payments and withdrawals on these positions and "spread" the balances across time bands accordingly. For instance, it might be assumed that certain percentages of a pool of 30 year mortgages prepay in given years during the life of the mortgages. As a result, a large share of the mortgage balances that would have been assigned to the time band containing 30 year instruments would be spread among nearer term time bands. In the simulation framework, more sophisticated behavioural assumptions could be employed, such as the use of option-adjusted pricing models to better estimate the timing and magnitude of cash flows

under different interest rate environments. In addition, the simulations can incorporate the bank's assumptions about its likely future treatment of administered interest rates on non-maturity deposits.

4. As with other elements of interest rate risk measurement, the quality of the estimates of interest rate risk exposure depends on the quality of the assumptions about the future cash flows on the positions with uncertain maturities. Banks typically look to the past behaviour of such positions for guidance about these assumptions. For instance, econometric or statistical analysis can be used to analyse the behaviour of a bank's holdings in response to past interest rate movements. Such analysis is particularly useful to assess the likely behaviour of non-maturity deposits, which can be influenced by bank-specific factors such as the nature of the bank's customers and local or regional market conditions. In the same vein, banks may use statistical prepayment models - either models developed internally by the bank or models purchased from outside developers - to generate expectations about mortgage-related cash flows. Finally, input from managerial and business units within the bank could have an important influence, since these areas may be aware of planned changes to business or repricing strategies that could affect the behaviour of the future cash flows of positions with uncertain maturities.

ANNEX - B

MONITORING OF INTEREST RATE RISK BY SUPERVISORY AUTHORITIES

1. This annex provides a brief overview of some of the factors that supervisory authorities might consider in obtaining and analysing information on individual banks' exposures to interest rate risk. As discussed in Section VII of the text, supervisory authorities should obtain information sufficient to assess banks' exposures to interest rate risk in a timely fashion. Such information may be obtained through on-site examinations, through reports that are submitted by banks on a regular basis, or through other means.

2. While the precise information that is obtained will differ across supervisory authorities, one approach that some may adopt is a reporting framework that collects information on a bank's positions by remaining maturity or time to next repricing. Under such an approach, a bank would categorise its interest-sensitive assets, liabilities and off-balance sheet positions into a series of repricing time bands or maturity categories. The two sections that follow discuss the considerations that a supervisor should take into account in specifying the number of time bands and the grouping of positions in the reporting framework. The final section of this annex

describes some general approaches that supervisory authorities may wish to consider in analysing the information that is obtained through such a reporting framework.

A. Time Bands

1. If a reporting framework is used which information is collected by time to next repricing, the number and specific categories of time bands chosen should be sufficient to provide supervisors with a reasonable basis for identifying potentially significant repricing mismatches. The bands, however, could vary materially across countries, both in number and in range, depending on the lending and investing practices and experiences of banks in individual markets.

2. The usefulness of supervisory analysis crucially depends on the precision with which maturities of the positions and cash flows are recorded in the system. In analysing interest rate sensitivities, it is not enough to know when an instrument matures. Rather, the critical factor is when the instrument reprices. Therefore, the emphasis of this section is on repricing rather than maturity. For cash flows whose repricing is unambiguous, the most precise approach is to use the exact repricing date. Any aggregation of positions/cash flows in time bands or zones necessarily implies a loss of information and a lower degree of precision. For this reason, the number of time bands

in a repricing ladder framework always reflects a decision regarding the necessary level of precision and the cost of pursuing greater accuracy. Supervisory authorities could use the repricing ladder in the standardised approach of the Amendment to the Capital Accord as a starting point when developing a reporting framework that meets their particular needs. The breakdown can, of course, be modified by supervisors either in a general way or in a specific way for banks where the nature of business activities warrants or justifies a different reporting form.

B. Item

1. As with the time bands, the breakdown of assets and liabilities could differ among supervisors. A reporting system should include information for all rate sensitive assets, liabilities and OBS positions, and should also identify balances, by specific types of instruments, when those instruments have or may have materially different cash flow characteristics, specific attention should be given to items whose behavioural repricings differ from contractual maturities such as savings deposits and in some countries mortgage related instruments. Further information on these issues is provided in Annex A. If the volume of these positions is significant, they should be reported separately so as to facilitate an assessment of the underlying options risk in the bank balance sheet structure.

2. The analysis of interest rate risk may be more difficult if a bank is engaged in trading activities. As a general rule, it is desirable for any measurement system to incorporate interest rate risk exposures arising from the full scope of a bank's activities, including both trading and non-trading sources. This does not preclude different measurement systems and risk management approaches being used for different activities; however, management should have an integrated view of interest rate risk across products and business lines. Supervisors may wish to permit banks that manage their interest rate risk exposures on an integrated basis to aggregate trading and non-trading positions in the overall reporting framework. However, it is important to recognise that in many countries different accounting rules may apply to the trading book and the traditional banking book. Under these accounting rules, losses in the trading book may not always be offset by profits in the banking book if the latter are unrealised. Furthermore, unlike the banking book, the composition of the trading portfolio changes significantly from week to week or even day to day because it is managed separately and according to a different (shorter) risk horizon than the banking book. This means that a hedge that is present on a given day may disappear a few days later. Supervisors should, therefore, review the risk management practices and information system of banks that conduct material trading activities and should obtain the

information necessary to ensure that interest rate risk in both trading and non-trading activities is properly managed and controlled.

C. Supervisory Analysis

1. A reporting framework designed along these lines may provide supervisors with a flexible tool for analysing interest rate risk. Supervisors can use this basic information to perform their own assessments of a bank's exposure and risk profile.

2. Such assessments may provide insights regarding an institution's exposure to parallel shifts, a flattening or steepening of the yield curve or its inversion with rate changes or different magnitude either based on statistical probabilities or a worst case analysis. For banks with important exposures in foreign currencies, analysis investigating different assumptions on correlations between interest rates in different currencies can be useful. With respect to instrument with behavioural maturities, supervisors may wish to assess alternative assumptions than those used by the institution.

3. The focus of supervisor's quantitative analysis can either be the impact of interest rate changes on current earnings or on the economic value of the banks' portfolio. In conducting their analysis information about

average yields on assets and liabilities in each time band may be useful and supervisors may wish to collect such information in addition to pure position data.

4. Depending on their overall approach, supervisors may conduct their analysis of interest rate risk either on a case by case basis or as part of a broader system designed to identify outliers with apparently excessive risk-taking.

5. By conducting an assessment of interest rate risk using the proposed framework, supervisors may gain more insight into an institution's risk profile than with a reporting system that reduces the complexity of interest rate risk to a single number. In doing so, supervisors can become more familiar with the sensitivity of risk measures to changes in the underlying assumptions, and the evaluation process may produce as many insights as the quantitative result itself.

6. Regardless of the extent of a supervisor's own independent quantitative analysis, a bank's own interest rate risk measure, whether reported as part of a basic supervisory reporting system or reviewing as part of an individual assessment of a bank's risk management, is an important consideration in the supervisory process. Reviewing the results of a bank's internal model can be highly informative, but can also be a difficult process because of the

multitude of assumptions and modelling techniques that are important, but which need to be made transparent to supervisors. To be most useful, the information received should indicate the contribution of principal elements of a bank's portfolio to the risk profile under different assumptions with respect to interest rate changes and the market response. Finally, any quantitative analysis should be supplemented by a review of internal management reports in order to gain greater insights into management's evaluation and management of risks, its methods for measuring exposures, and factors not reflected in the information available in the limited reporting to supervisors.

A FRAMEWORK FOR MEASURING AND MANAGING LIQUIDITY (September 1992)

In its work on the supervision of liquidity, the Basle Committee has focused on developing a greater understanding of the way in which international banks manage their liquidity on a global basis, on the premise that supervision of liquidity is particularly effective if based on a dialogue between bank and supervisor. This paper brings together practice and techniques currently employed by major international banks in a single analytical framework. While no bank may follow this framework precisely, it is a model which is believed to be an example of current sound management practice and which could provide useful guidance to all banks.

The seventh ICBS provides an opportunity for other supervisory authorities to contribute to this work and it is the Committee's intention to prepare revised version of this paper taking account of comments made at Cannes which could then be circulated to supervisory authorities worldwide with the possibility of it being made available through them to commercial banks.

I. Purpose of the analysis

Measuring and managing liquidity are among the most vital activities of

commercial banks. By assuring a bank's ability to meet its liabilities as they come due, liquidity management can reduce the probability of an irreversible adverse situation developing. Even in cases where as crisis develops because of a problem elsewhere at a bank, such as a severe deterioration in asset quality or the uncovering of fraud, or where a crisis reflects a generalised loss of confidence in financial institutions, the time available to a bank to address the problem will be determined by its liquidity. Indeed, the importance of liquidity transcends the individual institution, since a liquidity shortfall at a single institution can have system-wide repercussions. For this reason, the analysis of liquidity requires bank managements to measure not only the liquidity positions of banks on an ongoing basis but also to examine how funding requirements are likely to evolve under crisis scenarios.

This paper sets out in general terms the main elements of a model liquidity measurement and management framework. The framework strikes a balance between quantitative and qualitative factors used to assess liquidity, and provides a methodology for analysing balance sheet and off-balance-sheet activities consistently.

While this paper focuses on the use of the framework by large banks, the approach it describes appears to have broad

applicability to bank liquidity measurement and control, even for small, strictly domestic banks. In particular, good management information systems, central liquidity control, analysis of net funding requirements under alternative scenarios, diversification of funding sources, and contingency planning are crucial elements of strong liquidity management at a bank of any size or scope of operations. The information systems and analysis needed to implement the approach, however, can probably absorb fewer resources and be much less complex at a smaller institution or one that is active in fewer markets than the large, internationally, active banks contemplated in this paper.

II. Policy issues

A. Information and reporting arrangements

Virtually every financial transactions or commitment has implications for a bank's liquidity. Moreover, the transformation of illiquid into more liquid ones is a key activity of banks. Thus, a bank's liquidity policies and liquidity management approach should form key elements of a bank's general business strategy. Understanding the context of liquidity management involves examining a bank's **managerial approach** to funding and liquidity operations and its **liquidity planning under alternative scenarios**.

In particular, all banks should have an **articulated and specific liquidity policy** setting out the general importance management places on liquidity. Such a policy should also enunciate specific policies on particular aspects of liquidity management, such as the relative reliance on the use of certain financial instruments and the encouragement of closer relationships with supervisors. The general policy should be approved by a bank's board of directors.

An important element in such a policy will be a **liquidity reporting structure** designed to provide senior management with timely information and to be flexible enough to deal with various contingencies that may arise during crises. Banks that stress the importance of liquidity assign **ultimate responsibility** for setting liquidity policy and reviewing liquidity decisions to the bank's highest level of management, and their decisions need to be reviewed periodically by the board of directors.

A bank's **investment in information systems** designed to gather and analyse detailed information on assets and liabilities may need to be substantial. Because market conditions and a bank's own liquidity needs change constantly, extensive computer systems are often necessary to provide management with relevant information on an accurate and up-to-date basis. Such systems can also be helpful in projecting the

bank's liquidity positions under a variety of conditions. Sometimes these systems are integrated into information systems monitoring other activities of risk exposures of the bank.

Finally, a schedule of frequent routine **liquidity reviews** and less frequent, but more in-depth reviews should be provided for. These reviews provide the opportunity to re-examine and refine a bank's liquidity policies and practices in the light of a bank's liquidity experience and developments in its business.

B. Treatment of foreign currencies

For banks with an international presence, the treatment of assets and liabilities in multiple currencies adds a layer of complexity to liquidity management for two reasons. First, banks are often less well known to liability holders in foreign currency markets. In the event of market concerns, especially if they relate to a bank's domestic operating environment, these liability holders may not be able to distinguish rumour from fact as well or as quickly as domestic currency customers. Second, in the event of a disturbance, a bank may not always be able to mobilise domestic liquidity to meet foreign currency funding requirements.

Hence, when a bank conducts its business in multiple currencies, its

management must make two key decisions. The first concerns **management structure**. A bank with funding requirements in foreign currencies will generally use one of three approaches. It may completely centralise liquidity management (the head office managing liquidity for the whole bank in every currency). Alternatively, it may decentralise by assigning operating divisions responsibility for their own liquidity, but subject to limits imposed by the head office or frequent, routine reporting to the head office. For example, a non-European bank might assign its London office responsibility for the liquidity management for its European operations in all currencies. As a third approach, a bank may assign responsibility for liquidity in the home currency and for overall coordination to the home office, and responsibility for the bank's global liquidity in each major foreign currency to the management of the foreign office in the country issuing that currency. For example, the treasurer in the Tokyo office of a non-Japanese bank could be responsible for the bank's global liquidity needs in yen. All of these approaches, however, provide head office management with the opportunity to monitor and control worldwide liquidity.

The second decision concerns the **liquidity strategy in each currency**. In the ordinary course of business, a bank must decide how foreign currency funding needs will be met. To what extent, for example, will a bank fund foreign currency needs in

domestic currency and convert the proceeds to foreign currency through the foreign exchange market or currency swaps ? How will a bank manage the associated risk that exchange markets will cease to be available? A bank's assessment will depend on the size of its funding needs, its access to foreign currency funding market, and its capacity to rely on off-balance-sheet instruments (e.g. standby lines of credit, swap facilities, etc.).

A bank must also develop a back-up liquidity strategy for circumstances in which its normal approach to funding foreign currency operations is disrupted. Such a strategy will call for drawing either on home currency sources and converting them to foreign currency through the exchange markets or drawing on back-up sources in particular foreign currencies. For example, back-up liquidity for all currencies may be provided by the head office using the home currency, based on an assessment of the bank's access to the foreign exchange market and the derivative markets under the conditions in which the original liquidity disturbance is likely to occur. Alternatively, a bank's management may decide that certain foreign currencies make up a sufficient part of its liquidity needs to warrant separate liquidity back-up. In that case, either the home office or the regional treasurer for each specific currency would develop a contingency strategy and negotiate liquidity backstop facilities for those currencies.

III. A framework for measuring and managing liquidity

The framework for assessing and managing bank liquidity presented here has three major dimensions: **(A) measuring and managing net funding requirements, (B) Managing market access, and (C) contingency planning.**

A. Measuring and managing net funding requirements

The analysis of net funding requirements involves the construction of a maturity ladder and the calculation of a cumulative net excess or deficit of funds at selected maturity dates. A bank's net funding requirements are determined by analysing its future cash flows based on assumptions of the future behaviour or assets, liabilities and off-balance-sheet items, and then calculating the cumulative net excess over the time frame for the liquidity assessment.

(i) The maturity ladder

A maturity ladder should be used to compare a bank's future cash inflows to its future cash outflows over a series of specified time periods. Cash inflows arise from maturing assets, saleable non-maturing assets and established credit lines that can be tapped. Cash outflows include liabilities falling due and contingent liabilities, especially committed lines

of credit that can be drawn down. In Table 1, the maturity ladder is represented by placing sources and amounts of cash inflows on one side of the page and sources and amounts of outflows on the other.

In constructing the maturity ladder, a bank has to allocate each cash inflow or outflow to a given calendar date from a starting point, usually the next day. (A bank must be clear about the clearing and settlement conventions it is using to determine its initial point.) As a preliminary step to constructing the maturity ladder, cash inflows can be ranked by the date on which assets mature or a conservative estimate of when credit lines can be drawn down. Similarly, cash outflows can be ranked by the date on which liabilities fall due, the earliest date a liability holder could exercise an early repayment option, or the earliest date contingencies can be called. Significant interest and other cash flows should also be included. The difference between cash inflows and cash outflows in each period, the excess or deficit of funds, becomes a starting-point for a measure of a bank's future liquidity excess or shortfall at a series of points in time.

It is this net funding requirement that requires management. Typically, a

bank may find substantial funding gaps in distant periods and will endeavour to fill these gaps by influencing the maturity of transactions so as to offset the gap. For example, if there is a significant funding requirement 30 days hence, a bank may choose to acquire an asset maturing on that day, or seek to renew or roll over a liability. The closer a large gap gets, the more difficult it is to offset. Thus, banks will typically collect data on relatively distant periods so as to maximise the opportunities to close the gap before it gets too close. Most banks would regard it as important that any remaining borrowing requirement should be limited to an amount which experience suggests is comfortably within the bank's capacity to fund in the market.

(ii) Alternative scenarios

Evaluating whether a bank has sufficient liquid depends in large measure on the behaviour of cash flows under different conditions. Analysing liquidity thus entails laying out "what if" scenarios. Three scenarios provide useful benchmarks: a bank's "going-concern" condition, a bank-specific crisis, and a general market crisis. Under each scenario, a bank should try to account for any significant

positive or negative liquidity swings that could occur.

- (a) The **going-concern** scenario establishes a benchmark for the "normal" behaviour of balance sheet-related cash flows in the ordinary course of business at a bank. This scenario is useful in managing a bank's use of deposit and other debt markets. By establishing such a benchmark, a bank can manage its net funding requirements so that it is not faced with very large needs on any given day, so avoiding the impact of temporary constraints on its ability to roll over liabilities because of market disruptions or concerns about its condition.
- (b) Assessing liquidity under the second scenario, a **liquidity crisis at an individual bank** that remains confined to that bank, provides one type of "worst-case" benchmark. The key underlying assumption in this scenario is that many of the bank's liabilities could not be rolled over or replaced and would have to be repaid at maturity so that the bank would have to wind down its books to some degree. This is the

scenario implicit in many existing bank supervisory liquidity measures. While a severe liquidity crisis at an individual bank usually stems from a fundamental, bank-specific problem not related to its liquidity, a bank's ability to honour its deposit maturities under such conditions can provide the time that the bank would need to address the underlying problem. If a bank can weather such a "worst-case" scenario, it can almost certainly survive less drastic firm-specific problems.

- (c) The last scenario is some form of **general market crisis** where liquidity is affected at all banks in one or more markets. The key underlying assumption that banks need to make in this scenario is that severe tiering by perceived credit quality would occur, so that differences in funding access among banks or among classes of financial institutions would widen, benefiting some and harming others. Although some banks may believe that central banks would ensure that key markets would continue to function in some form, severe market

disruption would not necessarily be prevented. For bank management, this represents a second type of "worst-case" scenario that a bank would wish to weather. A supervisor or central bank may find this scenario to be of particular interest when surveying the liquidity profile of the entire banking sector. The collective results would suggest the size of the total liquidity buffer in the banking system and the likely distribution of liquidity problems among large institutions if the banking system as a whole experiences a shortage of liquidity.

A bank will need to assign the timing of cash flows for each type of asset and liability by assessing the probability of the behaviour of those cash flows in the scenario being examined. These decision about the specific timing and the size of cash flows are an integral part of the construction of the maturity ladder under each maturing senario. For each funding source, for example, a bank would have to decide whether the liability would be: (1) repaid in full at maturity;

(2) gradually run off over the next few weeks; or (3) virtually certain to be rolled over or available if tapped. The bank's historical experience of the pattern of flows and a knowledge of market conventions could guide a bank's decisions, but judgement often plays a large role, especially in crisis scenarios. Uncertainty is an inevitable element in choosing between possible behaviour pattern, and that dectates a conservation approach that would bias a bank toward assigning later dates to cash inflows and earlier dates to cash outflows.

Hence, the timing of cash inflows and outflows on the maturity ladder can differ between the going-concern, approach and the two crisis scenarios, as shown in Table 2. In constructing the **going-concern** maturity ladder, conservative assumptions need to be made about the behaviour of cash flows that can replace the contractual cash flows. For example, many maturing loans would be rolled over in the normal course of business and some proportion of transactions

and savings deposits would also be rolled over or could be easily replaced.

In a **bank-specific crisis** scenario it is assumed that a bank will be unable to roll over or replaced many or most of its liabilities, and that it may have to wind down its books to some degree. The assumptions under the third scenario, a **general market crisis**, may differ quite sharply from the assumptions made for a bank-specific crisis. For example, a bank may believe, based upon its historical experience, that its ability to control the level and timing of future cash flows from a stock of saleable assets in a bank-specific funding crisis would deteriorate little from normal conditions. However, in a general market crisis, this capacity may fall off sharply if few institutions are willing or able to make cash purchase of less liquid assets. On the other hand, a bank that has a high reputation in the market may actually benefit from a flight to quality as potential depositors seek out the safest home for their funds. Banks may also anticipate that central banks

would ensure that key markets continue to function but not necessarily without significant disruption.

(iii) **Measuring liquidity over the chosen time-frame**

The evolution of a bank's liquidity profile under one or more scenarios can be tabulated or portrayed graphically, by cumulating the balance of expected cash inflows and cash outflows at several time points. A stylised liquidity graph can be constructed enabling the evolution of the cumulative net excess or deficit of funds to be compared under the three scenarios in order to provide further insights into a bank's liquidity and to check how consistent and realistic the assumptions are for the individual bank. For example, a high-quality institution may look very liquid in a going-concern scenario, marginally liquid in a bank-specific crisis and quite liquid in a general market crisis. In contrast, a weaker institution might be far less liquid in the general crisis than it would in a bank-specific crisis.

It is important to note that the relevant time-frame for active liquidity management is short, generally extending out to more than a few weeks. While most banks would not actively manage their net funding

requirements over a period much longer than four or five weeks, management may consider information on requirements beyond that time frame to be useful. Clearly, banks active in markets for longer-term assets and liabilities will need to use a longer time-frame than banks which are active in short-term money markets and which are in a better position to fill funding gaps at short notice. However, even this latter category of banks may find it worthwhile to tailor the maturity of new transactions to offset gaps some time off.

A longer time horizon may also generate useful information on which to base more strategic decisions on the extent to which a bank may rely on particular markets.

(iv) Assumptions used in determining cash flows

Since a bank's future liquidity position will be affected by factors that cannot always be forecast with precision, assumptions need to be reviewed frequently to determine their continuing validity, especially given the rapidity of change in banking markets. The total number of major assumptions to be made, however, is fairly limited. This section attempts to catalogue the liquidity assumptions

under four broad categories: (a) assets, (b) liabilities, (c) off-balance-sheet activities, and (d) others.

(a) Assets

Assumptions about a bank's future stock of assets include their potential marketability and use as collateral of existing assets which could increase cash inflows, and the extent to which maturing assets will be renewed, and new assets acquired, thus reducing contractual cash inflows.

Determining the level of a bank's **potential assets** involves answering three questions:

- what proportion of maturing assets will a bank be able and willing to **roll over** or renew ?
- what is the expected **level of new loan requests** that will be **accepted** ?
- what is the expected **level of draw-downs of commitments to lend** that a banks will need to fund? These commitments may take the form of committed commercial lines without material adverse change

(MAC) clause, which a bank may not be legally able to turn away even if the borrower's financial condition has deteriorated; committed commercial lines with MAC clause which some customers could draw down in crisis scenarios; and other commercial and consumer credit lines.

In estimating its normal funding needs, some banks use historical patterns of roll-overs, draw-downs and new requests for loans; others conduct a statistical analysis taking account of seasonal and other effects believed to determine loan demand (e.g. for consumer loans). Alternatively, a bank make judgemental business projections, or undertake a customer-by-customer assessment for its larger customer and apply historical relationship to the remainder.

Roll-overs, draw-downs and new loan requests all represent potential cash drains for a bank. Nevertheless, a bank has some leeway to control many of these

items depending on the assumed scenario. In a crisis situation, for example, a bank might decide to risk damaging some business relationships by refusing to roll over loans that it would make under normal conditions, or it might refuse to honour lending commitments that are not binding.

In determining the **marketability of assets**, the approach segregates the assets into three categories by their degree of relative liquidity:

- the most liquid category includes components such as cash, securities, and interbank loans. Some of these assets may be immediate convertible into cash at prevailing market values under almost any scenario (either by outright sale, or for sale and repurchase, or as collateral for secured financing), while others, such as interbank loans or some securities, may lose liquidity in a general crisis;
- a less liquid category comprises a bank's

saleable loan portfolio. The task here is to develop assumptions about a reasonable schedule for the disposal of a bank's assets. Some assets, while marketable, may be viewed as unsaleable within the time frame of the liquidity analysis;

- the least liquid category includes essentially unmarketable assets such as loans not capable of being readily sold, bank premises and investments in subsidiaries, as well as, possibly, severely trouble credits;
- assets pledged to third parties are deducted from each category.

The view underlying the classification process is that different banks could assign the same asset to different categories on the maturity ladder because of differences in their internal asset-liability management. For example, a loan categorised by one bank as a moderately liquid asset-saleable only late in the liquidity analysis time-frame - may be considered a candidate for fairly

quick and certain liquidation at a bank that operates in a market where loans are frequently transferred, that routinely include loan-sale clauses in all loan documentation and that has developed a network of customers with whom it has concluded loan-purchase agreement.

In categorising assets, a bank would also have to decide how an asset's liquidity would be affected under different scenarios. Some assets that may be very liquid during times of normal business conditions may be less so during a time of crisis. Consequently, a bank may place an asset in different categories depending on the type of scenario it is forecasting.

(b) Liabilities

To evaluate the cash flows arising from a bank's liabilities, a bank would first examine the behaviour of its liabilities under normal business conditions. This would include establishing:

- the normal level of roll-overs of deposits and other liabilities;
- the effective maturity of deposits with non-contractual maturities, such as demand

- deposits and many types of savings account;
- the normal growth in new deposit accounts.

As in assessing roll-overs and new requests for loans, a bank could use several possible techniques to establish the effective maturities of its liabilities, such as using historical patterns of deposit behaviour. For sight deposits, whether of individuals or business, many banks conduct a statistical analysis that takes account of seasonal factors, interest rate sensitivities, and other macroeconomic factors. For some large wholesale depositors, a bank may undertake a customer-by-customer assessment of the probability of roll-over.

In examining the cash flows arising from a bank's liabilities in the two crisis scenarios, a bank would examine four basic questions :

- which sources of funding are likely to stay with a bank under any circumstances, and can these be increased?
- which sources of funding can be expected to run off gradually if problems arise and at what rate? Is deposit pricing a means of controlling the rate of run off?

- which maturing liabilities or liabilities with non-contractual maturities can be expected to run off immediately at the first sign of trouble? Are these liabilities with early withdrawal options that are likely to be exercised?
- does the bank have back-up facilities that it can draw down?

The first two categories represent cash-flows developments that tend to reduce the cash outflows project directly from contractual maturities. In addition to the liabilities identified above, a bank's capital and term liabilities not maturing within the horizon of the liquidity analysis provide a liquidity buffer.

The liabilities that make up the first category may be thought to stay with a bank, even under a "worse-case" projection. Some core deposits generally stay with a bank because retail and small business depositors may rely on the public-sector safety net to shield them from loss, or because the cost of switching banks, especially for some business services such as transactions accounts, is prohibitive in the very short run.

The second category, liabilities that are likely to stay with a bank during

periods of mild difficulties and to run off relatively slowly in a crisis, include core deposits that are not already included in the first category. In addition to core deposits, in some countries. Some level of particular types of interbank and government funding may remain with a bank during such periods, although interbank and government deposits are often viewed as volatile. A bank's own liability roll-over experience as well as the experiences of other troubled institutions should help in developing a timetable for these cash flows.

The third category comprises the remainder of the maturing liabilities, including some without contractual maturities, such as wholesale deposits. Under each scenario, this approach adopts a conservative stance and assumes that these remaining liabilities are repaid at the earliest possible maturity, especially in crisis scenario, because such money may flow to government securities and other safe havens. Factors such as diversification and relationship building are seen as especially important in evaluating the extent of liability run-off and a bank's capacity to replace funds. Nevertheless, in a general market crisis, some high-quality institutions may find that they receive larger-than-usual wholesale

deposit inflows, even as funding inflows dry up for other market participations.

Some banks, for example, smaller banks in regional markets, may also have credit lines that they can draw down to offset cash outflows. While these sorts of facility are somewhat rare among larger banks, the possible use of such lines could be addressed with a bank's liability assumptions. Where such facilities are subject to material adverse change clauses, of course they may be of limited value, especially in a bank specific crisis.

(c) Off-balance-sheet activities

A bank should also examine the potential for substantial cash flows from its off-balance-sheet activities (other than the loan commitments already considered), even if such cash flows are not always a part of bank's current liquidity analysis.

Contingent liabilities, such as letters of credit and financial guarantees, represent potentially significant cash drains for a bank, but are usually not dependent on a bank's condition. A bank may be able to ascertain a "normal" level of cash outflows on an ongoing concern basis, and then estimate the scope for an increase in

these flows during periods of stress. However, a general market crisis may trigger a substantial increase in the amount of draw-downs of letters of credit because of an increase in defaults and bankruptcies in the market.

Other potential sources of cash outflows include **swaps, written over-the-counter (OTC) options, and other interest rate and forward foreign rate contracts**. If a bank has a large swap book, for example, then it would want to consider the circumstances under which the bank could become a net payer, and whether or not the potential net payout is significant. For example, if a bank is a swap market-maker, the possibility exists that in a bank-specific or general market crisis, customers with in-the-money swaps (or a net in-the-money swap position) would seek to reduce their credit exposure to the bank by asking the bank to buy outstanding warrants, together with any hedges against these positions, since certain types of crisis may simulate an increase in early exercises (for American-style options) or requests that the bank repurchase options. These exercises and repurchase requests could result in an unforeseen cash drain, if hedges either be quickly liquidated to generate cash or provide insufficient cash.

(d) **Other assumptions**

The discussion has centred so far on assumptions concerning the behaviour of specific instruments under various scenarios. Looking solely at instruments, however, may ignore some factors that may significantly impact a bank's cash flows.

Besides the liquidity needs arising from business activities, banks also require excess funds to support other operations. For example, many large banks provide clearing services to correspondent banks and financial institutions that generate significant and not always easily predictable cash inflows and outflows, the amounts of which depend on the clearing column, of the correspondent banks. Unforeseen fluctuations in these volumes can deplete a bank of needed funds.

Net overhead expenses, such as rent and salary, although generally not significant enough to be considered in banks' liquidity analyses, can in some cases also be sources of cash outflows.

B. Managing market access

Some liquidity management techniques are viewed not only for their influence on the assumptions used in constructing maturity ladders, but also for

their direct contribution to enhancing a bank's liquidity. Thus, it is important for a bank to review periodically its efforts to maintain the **diversification of liabilities**, to establish **relationships with liability-holders** and to develop **asset-sales markets**.

As a check for adequate diversification of liabilities, a bank needs to examine the level of reliance on individual funding sources, by **instrument type**, **nature of the provider of funds**, and **geographic market**. In addition, a bank should strive to understand and evaluate the use of intercompany financing for its individual business offices.

Building strong relationships with some providers of funding can provide a line of defence in a liquidity problem and form an integral part of a bank's liquidity management. The frequency of contact and the frequency of use of a funding source are two possible indicators of the strength of a funding relationship.

Developing markets for asset sales or exploring arrangements under which a bank can borrow against assets is the third element of managing market access. The inclusion of loan-sale clauses in loan documentation and the frequency of use of some asset-sales markets are two possible indicators of a bank's ability to execute asset sales under adverse scenarios.

C. Contingency planning

A bank's ability to withstand a net funding requirement in a bank specific or general market liquidity crisis can also depend on the calibre of its formal contingency plans. Effective contingency plans should address two major questions :

- does management have a strategy for handling a crisis?
- does management have procedures in place for accessing cash in emergency?

The degree to which a bank has addressed these questions realistically, provides management with additional insight as to how a bank may fare in a crisis.

(i) Strategy

A game plan for dealing with a crisis should consist of several components. Most important are those that involve managerial coordination. A contingency plan needs to spell out procedures to ensure that **information flows** remain timely and uninterrupted, and that the information flows provide senior management with the precise information it needs in order to make quick decisions. A clear **division of responsibility** must be set out so that all personnel understand

what is expected of them during a crisis. Confusion in this area can waste resources on certain issues and omit coverage on others.

Another major element in the plan should be a strategy for taking certain **actions to alter asset and liability behaviours**. While assumptions can be made as to how an asset or liability will behave under certain conditions (as discussed above), a bank may have the ability to change these characteristics. For example, a bank may conclude that it will suffer a liquidity deficit in a crisis based on its assumptions regarding the amount of future cash inflows from saleable assets and outflows from deposit run-offs. During such a crisis however, a bank may be able to market assets more aggressively, or sell assets that it would not have sold under normal conditions and thus augment its cash inflows from asset sales. Alternatively, it may try to reduce cash outflows by raising its deposit rates to retain deposits that might otherwise have moved elsewhere.

Other components of the game plan involve **maintaining customer relationships** with borrowers, trading and off-balance-sheet counterparties, and liability-holders. As the intensity of a crisis increases, banks must often trade off relationships with some customers for liquidity in order to survive. By classifying borrowers and trading customers according to their importance to the bank, a bank can determine which relationships it may need to forgo at different points in a crisis. At the same time, relationships with lenders become more important in a crisis. If a bank's strategy requires liability managers to maintain strong ongoing links with lenders and large liability-holders during periods of relative calm, the bank will be better positioned to secure sources of funds during emergencies.

An additional, pragmatic element that may be important is how a bank **deals with the press and broadcast media**. Astute public relations management can help a bank

avoid the spread of public rumours that can result in significant run-offs by retail depositors and institutional investors.

(ii) Back-up liquidity

Contingency plans should also include procedures for making up cash flow shortfalls in emergency situations. Banks have available to them several sources of such funds, including previously unused credit facilities and the domestic central bank. Depending on the severity of a crisis, a bank may choose - or be forced - to use one or more of these sources. The plan should spell out as clearly as possible the amount of funds a bank has available from these sources, and under what scenarios a bank could use them.

TABLE 1
The maturity ladder based on contractual maturities

DAY 1 :				
Cash Inflows		Cash Outflows		Excess/(Shortfall)
Maturing assets	100	Maturing liabilities with contractual maturities	50	
Interest receivable	20	Interest payable	10	
Asset sales	50	Other deposit runoffs	30	
Drawdowns on Com. Lines	10	Drawdowns on Com. Lines	10	
Total	180	Total	140	40
DAY 2 :				
Cash Inflows		Cash Outflows		Excess/(Shortfall)
Maturing assets	100	Maturing liabilities with contractual maturities	70	
Interest receivable	25	Interest payable	20	
Asset sales	55	Other deposit runoffs	40	
Drawdowns on Com. Lines	10	Drawdowns on Com. Lines	50	
Total	190	Total	180	10
DAY 3-DAY 15 :				
Cash Inflows		Cash Outflows		Excess/(Shortfall)
Maturing assets	130	Maturing liabilities with contractual maturities	90	
Interest receivable	50	Interest payable	30	
Asset sales	60	Other deposit runoffs	40	
Drawdowns on Com. Lines	20	Drawdowns on Com. Lines	60	
Total	260	Total	220	40
DAY 16-DAY 30 :				
Cash Inflows		Cash Outflows		Excess/(Shortfall)
Maturing assets	160	Maturing liabilities with contractual maturities	130	
Interest receivable	80	Interest payable	60	
Asset sales	90	Other deposit runoffs	80	
Drawdowns on Com. Lines	40	Drawdowns on Com. Lines	80	
Total	370	Total	350	20

TABLE 2
Day 1 of the maturity ladder under alternative scenarios

Cash inflows	Normal business conditions (1)	Institution-specific crisis (3)	General market crisis (2)
Maturing assets	100	100	90
Interest receivable	20	20	10
Asset sales	50	60	0
Drawdowns	10	0	5
Total	180	180	105
Cash outflows			
Maturing liabilities	50	50	50
Interest payable	10	10	10
Deposit runoffs	30	100	60
Drawdowns on lending commitments	50	60	75
Total	140	220	195
Liquidity Excess/(Shortfall)	40	(40)	(90)

24 सितंबर 1998

September 24, 1998

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंधक निदेशक
सरकारी क्षेत्र के बैंक

**The Chairmen and Managing
Directors/Managing Directors
Public Sector Banks**

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

**ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) की
कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए
कार्यदल - सिफारिशें**

**WORKING GROUP TO REVIEW THE
FUNCTIONING OF DEBTS
RECOVERY TRIBUNALS (DRTs) -
RECOMMENDATIONS**

आप यह जानते हैं कि ऋण वसूली अधिकरणों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और ऋणवसूली अधिकरणों (डीआरटी) के कारगर रूप से कार्य करने हेतु उपाय सुझाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने विधि परामर्शदाता श्री एन.वी. देशपांडे की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया था। उक्त कार्यदल ने 31 अगस्त 1998 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

You are aware that the Reserve Bank of India had constituted a Working Group under the Chairmanship of its Legal Adviser, Shri N.V. Deshpande, to review the functioning of Debts Recovery Tribunals (DRTs) and to suggest measures for the effective functioning of DRTs. The Working Group has since submitted its final report to the Reserve Bank of India on 31st August, 1998.

कार्यदल ने अन्य बातों के साथ ही अपनी रिपोर्ट के परिच्छेद 2.14, 2.30 और 3.12 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित प्रेक्षण/सिफारिशें की हैं :

The Working Group has made, inter alia, the following observations/recommendations in paragraphs 2.14, 2.30 and 3.12 of its report regarding banks and financial institutions :

(क) चूंकि बैंक और वित्तीय संस्थान संबद्ध पक्ष होते हैं, इसलिए यह उनकी जिम्मेदारी और अनिवार्यता होनी चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रतिवादियों को समुचित रूप से नोटिस भेजा जाता है और ऐसा

a) Banks and financial institutions being the interested parties, it should be their responsibility and obligation to ensure that the notices to the defendants are properly served and the matter is not

मामला मात्र संबंधित पक्षों को सम्मन न दिये जाने के कारण अधिक दिनों तक लंबित नहीं रहता है ।

(ख) बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रबंधतंत्रों को चाहिए कि वे वसूली कार्यवाही में तेजी लाने के लिए यूनियनों/फेडरेशंस के साथ परस्पर सक्रिय रूप से विचारविमर्श करते रहें ।

(ग) अपने स्वयं के हित में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को चाहिए कि वे अपने अधिकारियों और स्टाफ पर इस बात के लिए दबाव डालें कि वे वसूली कार्यवाही में गहन रुचि लें ताकि बिना किसी कठिनाई के राशियों की वसूली हो जाये और ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित त्वरित वसूली क्रियाविधि को सफल बनाया जा सके ।

सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त सिफारिशों के तत्काल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करें । ऋण वसूली प्राधिकरणों के पास लंबित/दायर किये गये मामलों के निपटारे हेतु बैंक एक पृथक कक्ष का गठन करने पर भी विचार कर सकते हैं ।

भवदीया

(श्रीमती देवकी मुत्तुकृष्णन)
महाप्रबंधक

prolonged merely on account of non-service of summons on the parties.

b) The Managements of the banks and financial institutions should actively interact with the Unions/Federations for the expeditious recovery proceedings.

c) The banks and financial institutions in their own interest should impress upon the officers and staff to take keen interest in the proceedings so that the amounts can be recovered without any difficulty making the expeditious recovery procedure prescribed under the DRT Act a success.

All the banks are advised to take necessary steps for the implementation of the above recommendations immediately. The banks may also consider constituting a separate cell for dealing with cases pending/filed with Debts Recovery Tribunals.

Yours faithfully,

(Smt. Devaki Muthukrishnan)
General Manager

9 अक्टूबर 1998
17 आश्विन 1920 (शक)

October 9, 1998
Ashwina 17, 1920 (Saka)

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के मुख्य
कार्यपालक

The Chief Executives of Foreign Banks
operating in India

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा
लाभ का प्रेषण

REMITTANCE OF PROFITS BY
FOREIGN BANKS OPERATING IN
INDIA

कृपया 4 जून 1998 का एडी (एमए श्रृंखला) परिपत्र सं. 15 देखें, जिसके अनुसार विदेशी बैंकों को भारतीय परिचालनों के फलस्वरूप सामान्य कारोबार के दौरान अर्जित निवल लाभ/अधिशेष (कर को छोड़कर) को अपने प्रधान कार्यालयों को भेजने के लिए पूर्व अनुमोदन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी निदेशों का अनुपालन कर रहे हों।

Please refer to AD (MA Series) Circular No. 15 dated 4th June 1998 in terms of which foreign banks need not approach RBI for prior approval for remittance of net profit/surplus (net of tax) earned in the normal course of business arising out of their Indian operations, to their Head Offices provided they comply with the provisions of Banking Regulation Act, 1949 and directions issued by RBI in this regard.

2. इस संबंध में, विदेशी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे राशि प्रेषित करने के तत्काल बाद उक्त परिपत्र के अनुसार किये गये प्रेषणों के पूरे ब्यौरे विवरण के रूप में (प्रोफार्मा संलग्न) इस विभाग को प्रस्तुत कर दें। यदि किसी वर्ष में कोई राशि प्रेषित न की गयी हो, तो भी अन्य ब्यौरे देते हुए यह विवरण प्रस्तुत किया जाना है।

2. In this connection, foreign banks are advised to submit to this Department, full details of remittances made in terms of the abovementioned Circular, in the form of a Statement (proforma enclosed), immediately after the remittance is made. Even in case no remittance is made in any year, this Statement is to be submitted giving other particulars.

3. विवरण की एक प्रति मुख्य महा प्रबंधक,

3. A copy of the Statement may also be

बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, केन्द्र I, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, मुंबई - 400 005 को तथा मुख्य महा प्रबंधक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय भवन, मुंबई - 400 001 को भी प्रेषित की जाये ।

भवदीया

(देवकी मुत्तुकृष्णन)
महा प्रबंधक

submitted to the Chief General Manager, Department of Banking Supervision, Reserve Bank of India, Central Office, Centre I, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai 400 005 and the Chief General Manager, Exchange Control Department, Reserve Bank of India, Central Office, Central Office Building, Mumbai 400 001.

Yours faithfully,

(Devaki Muthukrishnan)
General Manager

प्रधान कार्यालय को लाभ का प्रेषण

बैंक का नाम

- i) किस वर्ष के लिए लाभ/अधिशेष प्रेषित किया गया :
- ii) लाभ और हानि खाते के अनुसार निवल लाभ :
- iii) वर्ष के दौरान बैंक की आय :
- iv) भारत में व्यय (प्र.का. के व्ययों के प्रावधान को छोड़कर) :
- v) लाभ और हानि खाता में प्रभारित प्रधान कार्यालय के व्यय :
- vi) आलोच्य वर्ष में किस दर पर आय/ब्याज कर देय है :

Remittance of profit to Head Office

Name of the bank

- i) The year for which profits/surplus was remitted :
- ii) Net profit as per the Profit & Loss Account :
- iii) Income of the bank during the year
- iv) Expenditure in India (without provision for H.O. Expenses) :
- v) H.O. expenses charged to P & L Account :
- vi) Rate at which income/interest tax is payable for the year in question :

- vii) अधिशेष की पूरी राशि पर पूर्ण दर पर गणना किये गये कर के लिए प्रावधान [अर्थात् मद (iii) - (iv) + (v)] :
- viii) किये गये विभिन्न प्रावधानों के ब्यौरे :
 - (क) कर के लिए किये गये वास्तविक प्रावधान
 - (ख) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए
 - (ग) स्टाफ के अंतिम लाभ
 - (घ) अन्य प्रावधान, यदि कोई हों,
- ix) प्रारक्षित निधियों में अंतरित राशि (ब्यौरे दें):
- x) पिछले वर्षों की कर देयताएं, यदि कोई हों, जिन्हें नहीं चुकाया गया है :
- xi) सीआरएआर संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए भारत में प्रतिधारित राशि, यदि कोई हो :
- xii) प्रधान कार्यालय को प्रेषित लाभ/अधिशेष की राशि और लागू की गयी विनिमय दर :
- xiii) प्रेषण की तारीख :
- xiv) प्रेषण की तारीख को पूंजीगत निधियां :
- xv) प्रेषण की तारीख को सीआरएआर :

प्रमाणित किया जाता है कि -

- i) वर्ष के लिए खातों में शामिल बैंक की संपूर्ण आय भारतीय स्रोतों से प्राप्त हुई तथा इस संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों का अनुपालन किया गया है। (यदि आय का कोई भाग भारत के बाहर से प्राप्त हुआ है तो प्रमाणपत्र में यह स्पष्ट दर्शाया जाये कि उसकी राशि वसूल होने पर तत्काल भारत को प्रेषित कर दी गयी थी)

- vii) Provision for tax calculated at full rate on the entire amount of surplus [i.e. item (iii) - (iv) + (v)] :
- viii) Details of various provisions made :
 - (a) Actual provision made for tax
 - (b) For bad and doubtful debts
 - (c) Terminal benefits of the staff
 - (d) Other provisions, if any
- ix) Amount transferred to reserves (give details) :
- x) Tax liabilities of previous years if any, remaining unpaid :
- xi) Amount, if any, retained in India for meeting CRAR requirements :
- xii) Amount of profit/surplus remitted to Head Office and the rate of exchange applied :
- xiii) Date of remittance :
- xiv) Capital funds on the date of remittance :
- xv) CRAR on the date of remittance :

Certified that -

- i) The entire income of the bank included in the accounts for the year had accrued from sources in India and the provisions of B.R. Act 1949 and the directions issued by RBI in this regard have been complied with. [In case a part of the income had accrued outside India, the certificate should clearly indicate that the amount thereof was repatriated to India immediately on realisation].

ii) कर के प्रावधान के लिए अलग रखी गयी राशि आलोच्य वर्ष में बैंक की भारत स्थित शाखा(ओं) की कर देयताओं को कवर करने के लिए पर्याप्त है ।

ii) The amount set aside as provision for tax is adequate to cover the tax liabilities of branch(es) in India of the bank for the year in question.

बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Chief Executive Officer of the bank

(हस्ताक्षरकर्ता का नाम और मुहर)

(Name of the signatory and stamp)

बैंक के लेखापरीक्षक

Auditors of the bank

(हस्ताक्षरकर्ता का नाम और मुहर)

(Name of the signatory and stamp)

टिप्पणी - यदि प्रेषण पिछले वर्षों के न भेजे गये ऐसे लाभों से संबंधित हो, जिन्हें पूंजी पर्याप्तता के लिए प्रतिधारित न किया गया हो परंतु विदेश में प्रेषित करने के लिए रखा गया हो तो वर्षवार पूरे ब्यौरे प्रस्तुत किये जायें ।

Note - If the remittance relates to unremitted profits of earlier years which have not been retained for capital adequacy but are held for remittance abroad, full details, year-wise, may be furnished.

15 अक्तूबर 1998
23 आश्विन 1920 (शक)

October 15, 1998
Ashwina 23, 1920 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

तार अंतरण भुनाई सुविधा - नवीकरण

**T.T. DISCOUNTING FACILITY -
RENEWAL**

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 4 अक्तूबर 1997
का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. 110/12.04.002/
97-98 देखें।

Please refer to our circular letter DBOD. No.
110/12.04.002/97-98 dated October 4, 1997
on the captioned subject.

2. यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित
वाणिज्य बैंकों को स्वीकृत भारतीय रिज़र्व बैंक से
तार अंतरण के अंतर्गत सीमाएं प्राप्त करने से
संबंधित अवधि को और एक वर्ष के लिए अर्थात्
1 नवंबर 1998 से 31 अक्तूबर 1999 तक बढ़ा
दिया जाये।

2. It has been decided to extend the
period for availing of the limits under
telegraphic transfers with the Reserve Bank
of India sanctioned to scheduled commercial
banks for a further period of one year i.e.
from 1st November 1998 to 31st October
1999.

भवदीय

Yours faithfully,

(के. एस. छाबड़ा)
उप महा प्रबंधक

(K.S. Chhabra)
Deputy General Manager

31 अक्टूबर 1998
09 कार्तिक 1920 (शक)

October 31, 1998
Kartika 9, 1920 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय

MONETARY AND CREDIT POLICY MEASURES

कृपया आप गवर्नर महोदय का 30 अक्टूबर 1998 का पत्र सं. एमपीडी. बीसी. 181/07.01.279/98-99 देखें, जिसके साथ “1998-99 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा” संबंधी विवरण की प्रति संलग्न की गयी है। उसमें बताये गये नीतिगत परिवर्तनों के संबंध में दिशा-निर्देश नीचे दिये गये हैं :

Please refer to Governor's letter No. MPD. BC. 181/07.01.279/98-99 dated October 30, 1998, enclosing a copy of the statement on "Mid-Term Review of Monetary and Credit Policy for 1998-99". The guidelines in regard to the Policy changes indicated therein, are given below :

विवेकपूर्ण मानदंडों को सुदृढ़ करना

Strengthening of Prudential Norms

1. पूंजी पर्याप्तता:

- (i) पूंजी पर्याप्तता अनुपात में वृद्धि : 22 अप्रैल 1992 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 117/21.01.002/92 के अनुसार बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूंजी और जोखिम आस्ति का न्यूनतम अनुपात 8 प्रतिशत रखेंगे। सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसरण में निर्णय किया गया है कि बैंकों के लिए पूंजी और जोखिम आस्ति का न्यूनतम अनुपात (सीआरएआर) वर्तमान के 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 मार्च 2000 को

1. Capital Adequacy :

- (i) **Enhancement of Capital Adequacy Ratio :**

In terms of Circular DBOD. No. BP.BC. 117/21.01.002/92 dated April 22, 1992, banks are required to maintain a minimum Capital to Risk Asset Ratio (CRAR) of 8 per cent. In line with the international best practices, it has been decided that the minimum Capital to Risk Asset Ratio for banks

समाप्त वर्ष से 9 प्रतिशत कर दिया जाये ।

should be enhanced from the existing 8 per cent to 9 per cent with effect from the year ending March 31, 2000.

2. सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों पर जोखिम भार

(क) 22 अप्रैल 1992 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 117/21.01.002/92 के अनुसार सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों पर सीआरएआर की गणना के प्रयोजन हेतु शून्य जोखिम भार होता है । बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित नरसिंहम समिति की सिफारिशों के अनुरूप तथा मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण इस प्रकार की प्रतिभूतियों में निहित बाज़ार जोखिम के लिए प्रावधान करने हेतु सरकारी/ अनुमोदित प्रतिभूतियों के लिए जोखिम भार लागू किया जा रहा है । तदनुसार सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों को बाज़ार जोखिम के लिए 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष से 2.5 प्रतिशत का जोखिम भार लगाया जाना चाहिए । नरसिंहम समिति द्वारा सिफारिश किये गये 5 प्रतिशत के मानदंड को पूरा करने के लिए शेष 2.5 प्रतिशत के बारे में बाद में घोषणा की जायेगी ।

(ख) यह भी निर्णय लिया गया है कि सरकारी प्रतिष्ठानों की सरकार द्वारा

2. Risk Weights on Government and other approved securities

- (a) In terms of Circular DBOD. BP. BC. 117/21.01.002/92 dated April 22, 1992, investments in Government and other approved securities carry zero risk-weight for calculation of CRAR. Consistent with the recommendations of Narasimham Committee on Banking Sector Reforms and in order to provide for the market risk in valuation of such securities due to fluctuations in prices, the risk weight for Government and other approved securities is being introduced. Accordingly, investments in government and other approved securities should be assigned a risk weight of 2.5 per cent for market risk, with effect from the year ending March 31, 2000. The balance of 2.5 per cent to reach the norm of 5 per cent, as recommended by the Narasimham Committee, will be announced at a later date.
- (b) It has been further decided that a risk weight of 20 per cent on

गारंटीकृत जो प्रतिभूतियां बाज़ार से ऋण लेने के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं, उनमें निवेश पर भी 20 प्रतिशत का जोखिम भार वित्तीय वर्ष 2000-2001 से लागू किया जाना चाहिए। इस प्रावधान का पालन करने के लिए पर्याप्त समय देने की दृष्टि से बैंकों को अनुमति दी जाती है कि बैंकों के निवेश संविभाग में ऐसी प्रतिभूतियों के 31 मार्च 2000 को बकाया स्टॉक पर जोखिम भार दस-दस प्रतिशत के दो चरणों में अर्थात् 2001-2002 और 2002-2003 में लागू किया जाये।

- (ग) वर्तमान में कुछ सरकारी वित्तीय संस्थाओं के बांडों/प्रतिभूतियों में निवेशों पर शून्य जोखिम भार है, क्योंकि उन्हें शासित करने वाले विशेष विधान के अंतर्गत उन्हें “अनुमोदित प्रतिभूतियों” का दर्जा दिया गया है। कतिपय अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं के बांडों/ऋणपत्रों (डिबेंचरों) में निवेश पर 100 प्रतिशत जोखिम भार है, क्योंकि संबंधित अधिनियम/विधान में अनुमोदित प्रतिभूतियों का दर्जा नहीं दिया गया है। इस विसंगति को दूर करने की दृष्टि से, जैसा कि गवर्नर के परिपत्र में बताया गया है, सरकारी वित्तीय संस्थाओं (संलग्न सूची के अनुसार) के बांडों/ऋणपत्रों में निवेशों पर जोखिम भार तत्काल

investments in the Government guaranteed securities of Government undertakings which **do not** form part of the approved market borrowing programme should be introduced from the financial year 2000-2001. In order to provide sufficient time to comply with this provision, banks are permitted to account for the risk weight on the outstanding stock of such securities in the portfolio of banks as on March 31, 2000 in two phases of 10 per cent each in 2001-2002 and 2002-2003.

- (c) Presently, while investments in the bonds/securities of some of the Public Financial Institutions (PFIs) carry zero risk-weight due to their status as 'Approved Securities', under the special Statutes governing them, investments in bonds/debentures of certain other PFIs carry 100 per cent risk-weight as the relevant Act/Statute does not confer the status of an 'Approved Security'. With a view to removing this anomaly, as indicated in the Governor's Circular, the risk weights on investments in bonds/debentures of PFIs are being

प्रभाव से एकसमान रूप से 20 प्रतिशत किया जा रहा है। सरकारी वित्तीय संस्थाओं की सूची अनुबंध I में दी गयी है।

(घ) सीआरएआर की गणना के लिए जोखिम भार निम्नलिखित रूप में संशोधित माने जायेंगे :

given uniform risk weight of 20 per cent with immediate effect. The list of PFIs is given in Annexure I.

(d) The risk weights on calculation of CRAR would stand modified as under :

क्रमांक	आस्ति का स्वरूप	जोखिम भार (प्रतिशत)	
		मौजूदा	प्रस्तावित
1.	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	0	2.5
2.	केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	0	2.5
3.	उन अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज की अदायगी और मूलधन की चुकौती की गारंटी केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी है	0	2.5
4.	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश, जहां ब्याज की अदायगी और मूलधन की चुकौती की गारंटी राज्य सरकारों ने दी है। (राज्य सरकार द्वारा ब्याज/मूलधन की चुकौती में चूक की स्थिति में बैंक संबंधित राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेशों पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार लगायें)	0	2.5
5.	उन अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश,	0	20

Sr. No.	Nature of Asset	Risk-weight (%)	
		Existing	Revised
1.	Investments in Government Securities	0	2.5
2.	Investments in other Approved Securities guaranteed by Central/ State Government	0	2.5
3.	Investments in other securities where payment of interest and repayment of principal are guaranteed by Central Government	0	2.5
4.	Investments in other securities where payment of interest and repayment of principal are guaranteed by State Governments (In case of a default in interest/principal by State Government, banks should assign 100 per cent risk weight on investments in securities of the concerned State Government)	0	2.5
5.	Investments in other Approved Securities where	0	20

क्रमांक	आस्ति का स्वरूप	जोखिम भार (प्रतिशत)		Sr. No.	Nature of Asset	Risk-weight (%)	
		मौजूदा	प्रस्तावित			Existing	Revised
	जहां ब्याज की अदायगी और मूलधन की चुकौती की गारंटी केंद्र/राज्य सरकार ने नहीं दी है				payment of interest and repayment of principal are not guaranteed by Central/State Government		
6.	सरकारी प्रतिष्ठानों की सरकार द्वारा गारंटीकृत उन प्रतिभूतियों में निवेश, जो अनुमोदित बाजार से ऋण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है।	0	20	6.	Investments in Government Guaranteed Securities of Govt. undertakings which do not form part of the approved market borrowing programme.	0	20
7.	अन्य बैंकों में चालू खाते में जमा शेष	20	20	7.	Balances in current account with other banks	20	20
8.	बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं (संलग्न सूची के अनुसार) पर दावे	20	20	8.	Claims on banks and Public Financial Institutions (as per list attached)	20	20
9.	अन्य बैंकों/सूची के अनुसार सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये बांडों में निवेश (संलग्न सूची के अनुसार)	100	20	9.	Investments in bonds issued by other banks/PFIs (as per list attached)	100	20
10.	ब्याज की अदायगी और मूलधन की चुकौती के लिए बैंकों अथवा सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा (संलग्न सूची के अनुसार) गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश	100	20	10.	Investments in securities which are guaranteed by banks or PFIs (as per list attached) as to payment of interest and repayment of principal	100	20
11.	अन्य बैंकों/सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये स्तर - 2 के पूंजी बांडों	100	100	11.	Investments in subordinated debt in the form of Tier 2 Capital Bonds	100	100

क्रमांक	आस्ति का स्वरूप	जोखिम भार (प्रतिशत)	
		मौजूदा	प्रस्तावित

	के रूप में अधीनस्थ ऋण में निवेश		
12.	अन्य सभी निवेश	100	100

3. सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के लिए जोखिम भार

22 अप्रैल 1992 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 117/21.01.002/92 के अनुसार भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत ऋणों और अग्रिमों के लिए शून्य जोखिम भार है। परन्तु जिन मामलों में गारंटी लागू की गयी है और संबंधित राज्य सरकार 31 मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार चूक में है वहां इस प्रकार के अग्रिमों पर 20 प्रतिशत का जोखिम भार दिया जाना चाहिए। जो राज्य सरकारें इस प्रकार लागू की गारंटियों के संबंध में 31 मार्च 2001 के बाद भी चूक कर रही हों, उनके मामले में 100 प्रतिशत का जोखिम भार दिया जाना चाहिए।

4. विदेशी मुद्रा/स्वर्ण-खुली स्थितियां

विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग के 6 अक्टूबर 1995 के एडी (एमए श्रृंखला) परिपत्र सं. 25 के अनुसार खुले विदेशी मुद्रा ऋण पर बाजार जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षा रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित स्थिति सीमा की 5 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी मुद्रा खुली स्थिति

Sr. No.	Nature of Asset	Risk-weight (%)	
		Existing	Revised

	issued by other banks/ PFI's		
12.	All other investments	100	100

3. Risk weight for Government guaranteed advances

In terms of circular DBOD. No. BP. BC. 117/21.01.002/92 dated April 22, 1992, loans and advances guaranteed by Government of India and State Governments carry zero risk weight. However, in cases in which the guarantee has been invoked and the concerned State Government has remained in default as on March 31, 2000, a risk weight of 20 per cent on such advances should be assigned. State Governments who continue to be in default in respect of such invoked guarantees even after March 31, 2001, a risk weight of 100 per cent should be assigned.

4. Foreign exchange/Gold open positions

In terms of our Exchange Control Department AD (MA Series) Circular No. 25 dated October 6, 1995, capital requirement for market risk on open foreign currency exposure has been prescribed at 5 per cent of the position limit approved by the Reserve Bank.

सीमा पर जोखिम भार 31 मार्च 1999 से 100 प्रतिशत होना चाहिए।

4 मार्च 1998 के हमारे परिपत्र सं. बैंपविवि. आइबीएस. बीसी. 18/23.67.001/97-98 के अनुसार स्वर्ण में खुली स्थिति रखने वाले बैंकों को खुली स्थिति सीमा के 5 प्रतिशत के बराबर स्तर-I की पूंजी बनाये रखनी चाहिए। यह निर्णय लिया गया है कि स्वर्ण में खुली स्थिति सीमा पर जोखिम भार 31 मार्च 1999 से 100 प्रतिशत होना चाहिए।

मौजूदा प्रथा के अनुसार विदेशी मुद्रा और स्वर्ण की खुली स्थिति सीमा के लिए सीआरएआर की अलग-अलग गणना की जाती है और उसे स्तर-I की पूंजी में से घटा दिया जाता है। यह सूचित किया जाता है कि पूंजी और जोखिम आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की गणना करते समय विदेशी मुद्रा और स्वर्ण की खुली स्थिति सीमा दोनों के संबंध में अन्य जोखिम भारित आस्तियों को जोड़ दिया जाना चाहिए।

5. प्रावधान संबंधी मानदंड

(क) अवमानक आस्तियों के लिए निर्धारित समय में कटौती

27 अप्रैल 1992 के हमारे परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी. 129/21.04.043/92 के अनुसार यदि कोई आस्ति अधिकतम दो वर्ष के लिए अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत की गयी है, तो उसे

It has been decided that foreign exchange open position limit should carry 100 per cent risk weight with effect from March 31, 1999.

In terms of our Circular No. DBOD. IBS. BC. 18/23.67.001/97-98 dated March 4, 1998, banks keeping open position in gold should also maintain Tier I Capital to the extent of 5 per cent of the open position limit. It has been decided that open position limit in gold should also carry 100 per cent risk weight with effect from March 31, 1999.

As per the existing practice, CRAR is calculated separately for open position limits in foreign exchange and gold and deducted from Tier-I Capital. It is advised that risk weights both in respect of foreign exchange and gold open position limits should be added to the other risk weighted assets for calculation of CRAR.

5. Provisioning Norms

(a) **Reduction in the time frame for sub-standard assets**

In terms of our Circular No. DBOD. BP. BC. 129/21.04.043/92 dated April 27, 1992, an asset is required to be treated as sub-standard if it has been classified as NPA for a period not

अवमानक माना जाना चाहिए। प्रावधान करने से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं से निकटता लाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2001 से किसी आस्ति को उस स्थिति में संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए यदि वह वर्तमान के 24 महीने के बजाय 18 महीने के लिए अवमानक की श्रेणी में रहे। बैंकों को निम्न प्रकार से चरणों में अतिरिक्त प्रावधान करने के लिए इन मानदंडों को पूरा करने की अनुमति है :

31 मार्च 2001 की स्थिति : नये मानदंडों के कारण जो आस्तियां संदिग्ध हो गयी है उन पर कम से कम 50 प्रतिशत का प्रावधान करना।

31 मार्च 2002 की स्थिति : जो प्रावधान पिछले वर्ष में नहीं किये गये हैं उन शेष आवश्यक प्रावधानों के लिए 31 मार्च 2002।

(ख) सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के संबंध में आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान करने आदि से संबंधित मानदंड

वर्तमान में, प्रावधान करने के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों को, जिनके संदर्भ में गारंटी लागू की गयी है, मानक आस्तियों के रूप में उस स्थिति में भी माना जाता है जब इस प्रकार की आस्तियों पर आय को लाभ और हानि खाते में

exceeding two years. With a view to moving closer to international practices in regard to provisioning norms, it has been decided that an asset should be classified as doubtful, if it has remained in the sub-standard category for 18 months instead of 24 months, as at present, by March 31, 2001. Banks are permitted to achieve these norm for additional provisioning, in phases, as under :

As on March 31, 2001 : Provisioning of not less than 50 per cent on the assets which have become doubtful on account of the new norm.

As on March 31, 2002 : Balance of the provisions not made during the previous year, in addition to the provisions needed, as on March 31, 2002.

(b) Asset Classification and Provisioning Norm in respect of Government Guaranteed Advances

Presently, State Government guaranteed advances in respect of which guarantee has been invoked are treated as standard assets for provisioning purposes though income on such asset is not permitted to be taken to

लेने की अनुमति नहीं होती। कुछ बैंकों ने अभिवेदन किया है कि कुछ राज्य सरकारें गारंटी लागू करने के बाद गारंटीकृत ऋणों के अंतर्गत अपनी वचनबद्धता को निभाने में विलम्ब कर रही हैं। इस प्रकार की प्राप्य राशियों को शीघ्र वसूल करने में बैंकों के प्रयासों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से और साथ ही संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार की प्रथाओं को निरुत्साहित करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया है कि एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के संबंध में जहां गारंटी लागू की गयी हो और दो तिमाहियों से अधिक चूक की स्थिति बनी रही हो, वहां प्रावधान करने से संबंधित मानदंड लागू किया जाये। यह उपाय राज्य सरकारों द्वारा गारंटी पर दिये गये अग्रिमों के संबंध में 1 अप्रैल 2000 से लागू होगा। जहां तक राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत उन अग्रिमों के लिए प्रावधान करने का संबंध है जो 31 मार्च 2000 को लागू थे, 31 मार्च 2000 से 31 मार्च 2003 को समाप्त वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कम से कम 25 प्रतिशत का प्रावधान करके आवश्यक प्रावधान किया जाना चाहिए।

Profit and Loss Account. Some banks have represented that a few State Governments are delaying in honouring their commitments under the guaranteed advances after the guarantee has been invoked. In order to strengthen the banks' efforts to recover such dues expeditiously as well as to discourage such practices by the concerned State Governments, it has been decided, as a prudent measure, to introduce provisioning norm in respect of advances guaranteed by State Governments where guarantee has been invoked and has remained in default for more than two quarters. This measure would be effective in respect of advances sanctioned against State Government guarantee with effect from April 1, 2000. As regards provisioning requirement for advances guaranteed by State Governments which stood invoked as on March 31, 2000, necessary provision should be made during the financial years ending March 31, 2000 to March 31, 2003 with a minimum of 25 per cent each year.

6. **मानक आस्तियों पर प्रावधान**
प्रारंभ में बैंक 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष से मानक आस्तियों पर न्यूनतम 0.25 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान करें।
7. **निवेश-जोखिम (एक्सपोजर) संबंधी मानदंड**
वर्तमान में किसी सरकारी वित्तीय संस्था द्वारा गारंटी के माध्यम से किसी कंपनी के बांडों में बैंक के निवेश को जोखिम संबंधी मानदंडों के प्रयोजन हेतु कंपनी संबंधी जोखिम के रूप में माना जाता है। जैसा कि गवर्नर के परिपत्र में बताया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि जोखिम-मानदंडों की गणना के प्रयोजन हेतु किसी सरकारी वित्तीय संस्था द्वारा (संलग्न सूची के अनुसार) गारंटीकृत कंपनियों के बांडों और ऋणपत्रों (डिबेंचरों) में निवेश को बैंक द्वारा सरकारी वित्तीय संस्था पर जोखिम-राशि माना जायेगा, न कि वर्तमान प्रथा के अनुसार कंपनी पर। कंपनियों के बांडों के लिए सरकारी वित्तीय संस्था द्वारा जारी की गयी गारंटियों को सरकारी वित्तीय संस्था द्वारा गैर-निधिक सुविधा होने के नाते 50 प्रतिशत तक कंपनियों पर जोखिम-राशि (एक्सपोजर) माना जायेगा, जबकि कंपनी को गारंटी देनेवाली सरकारी वित्तीय संस्था पर बैंक की जोखिम-राशि 100 प्रतिशत होगी। किन्तु बांडों/डिबेंचरों की गारंटी देने वाली सरकारी वित्तीय संस्था गारंटी देने के पूर्व वित्तीय प्रणाली के प्रति गारंटीकृत यूनिट की समग्र जोखिम-राशि को हिसाब में लें।
8. **अन्य उपाय**
जैसा कि गवर्नर के परिपत्र में बताया गया है,

6. **Provision on standard assets**
To start with, banks should make a general provision on standard assets of a minimum of 0.25 per cent from the year ending March 31, 2000.
7. **Exposure Norm**
Presently, the exposure of a bank investing in the bonds of a corporate though guaranteed by a PFI, is treated for the purpose of exposure norm, as an exposure on the corporate. As indicated in the Governor's Circular, it has been decided that for the purpose of calculation of exposure norm, investments made by the banks in bonds and debentures of corporates which are guaranteed by a PFI (as per list attached) will be treated as an exposure by the bank on the PFI and not on the corporate as is the practice at present. Guarantees issued by the PFI to the bonds of corporates will be treated as an exposure by the PFI to the corporates to the extent of 50 per cent being a non-fund facility, whereas the exposure of the bank on the PFI guaranteeing the corporate bond will be 100 per cent. The PFI before guaranteeing the bonds/debentures should, however, take into account the overall exposure of the guaranteed unit to the financial system.
8. **Other Measures**
As indicated in the Governor's letter,

भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार संबंधी समिति (अध्यक्ष: एम. नरसिम्हम) द्वारा की गयी अनेक सिफारिशों को लागू किया जाये। इन्हें अनुबंध II में दिया गया है। बैंक इनका कार्यान्वयन करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें और अनुपालन की सूचना रिज़र्व बैंक को 31 मार्च 1999 तक दें।

9. बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे यह परिपत्र अपने निदेशक मंडल की जानकारी में लाएं और इसके कार्यान्वयन की अपनी योजना तथा विवेकपूर्ण उपायों से पड़ने वाले प्रभाव से हमें 31 मार्च 1999 तक अवगत करायें।

भवदीय

(अमलेन्दु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

it has been decided in consultation with Government of India, to implement a number of recommendations made by the Committee on Banking Sector Reforms (Chairman: Shri M. Narasimham). These are given in the Annexure II.

9. The banks are advised to bring this circular to the notice of their Board of Directors and intimate to us their plan of implementation as also the impact of the prudential measures by March 31, 1999.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

अनुबंध - I

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सूची
जिनके बांड/डिबेंचर पूंजी पर्याप्तता अनुपात के
लिए 20 प्रतिशत के भार हेतु पात्र होंगे

1. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि.,
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि.,
3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
4. भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.,
5. भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि.,
6. जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि.,
7. भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और सूचना कंपनी लि.,
8. विद्युत वित्त निगम लि.,
9. राष्ट्रीय आवास बैंक,
10. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
11. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.,
12. भारतीय रेल वित्त निगम लि.,
13. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,
14. भारतीय निर्यात-आयात बैंक,
15. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कं. लि.,

ANNEXURE I

**List of All-India Financial Institutions
whose bonds/debentures would qualify
for 20 per cent risk weight for Capital
Adequacy Ratio**

1. Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.,
2. Industrial Finance Corporation of India Ltd.,
3. Industrial Development Bank of India.
4. Industrial Investment Bank of India Ltd.,
5. Tourism Finance Corporation of India Ltd.
6. Risk Capital and Technology Finance Corporation Ltd.
7. Technology Development and Information Company of India Ltd.
8. Power Finance Corporation Ltd.
9. National Housing Bank.
10. Small Industries Development Bank of India.
11. Rural Electrification Corporation Ltd.
12. Indian Railways Finance Corporation Ltd.
13. National Bank for Agriculture and Rural Development.
14. Export Import Bank of India.
15. Infrastructure Development Finance Co. Ltd.

अनुबंध - II

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार संबंधी समिति की सिफारिशें

सिफारिशें

- i) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को हमेशा अच्छी स्थिति दिखाने की प्रथा से बचना चाहिए। (पैरा सं. 3.22)
- ii) वित्तीय पुनर्विन्यास का कोई भी प्रयास परिचालनगत पुनर्विन्यास के साथ-साथ चलना चाहिए। तुलन-पत्र को ठीक-ठाक रखने के साथ ही साथ नयी अनर्जक आस्तियों को पुनः बनने से रोकने/सीमित करने के लिए कदम उठाये जायें। (पैरा सं. 3.27)
- iii) कठिनाई वाले बैंकों को स्तर-II की पूंजी के लिए बांड जारी करने में समर्थ बनाना। सरकार को इन लिखतों के लिए गारंटी देने की जरूरत होगी, जिससे ये निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए पात्र हो जायेंगे। (पैरा सं. 3.29)
- iv) आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता-स्वरूप, विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं, प्रावधान खातों में घट-बढ़ तथा अनर्जक आस्तियों को चरणबद्ध रूप में प्रकट करने की जरूरत है। (पैरा सं. 3.38)

किये गये निर्णय

रिज़र्व बैंक यह बात दोहराता है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान करने आदि से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड अपनाने चाहिए और हमेशा अच्छी स्थिति दिखाने की प्रथा से बचना चाहिए।

बैंकों को सूचित किया जाता है कि अनर्जक आस्तियों को कम करने के लिए कारगर कदम उठायें तथा जोखिम प्रबंध प्रणालियों और नयी अनर्जक आस्तियां पुनः बनने से रोकने की प्रथाओं को भी ठीक करें।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी स्तर-II की पूंजी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। इन लिखतों के लिए सरकारी गारंटी उपयुक्त प्रतीत नहीं होती।

बैंकों को पहले ही सूचित किया जा चुका है कि वे 1 अप्रैल 1999 से औपचारिक आस्ति-देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली शुरू करें। अधिक प्रकटीकरण के बारे में अनुदेश यथासमय जारी किये जायेंगे।

सिफारिशें

- v) किसी खास औद्योगिक क्षेत्र को बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण तथा आस्ति के मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में, जैसे स्टॉक मार्केट तथा अचल संपत्ति के संदर्भ में संकेन्द्रण अनुपात का उल्लेख करना होगा। ऋण प्रदान करने के इन मानदंडों पर सावधानी से निगरानी रखने की जरूरत है। (पैरा सं. 3.40)
- vi) बैंकों को परिचालन संबंधी संशोधित नियम-पुस्तिकाएं तैयार करनी चाहिए और उन्हें नियमित रूप से अद्यतन करते रहना चाहिए। (पैरा सं. 4.3)
- vii) कारोबारी लेनदेनों की आधार-कार्यालयों (बैंक ऑफिसों) द्वारा रिपोर्टिंग एवं जांच पर बैंक विशेष ध्यान दें। (पैरा सं. 4.8)
- viii) विशेष रूप से बड़े उधार खातों के लिए स्वतंत्र ऋण समीक्षा तंत्र गठित किये जाने और संभाव्य अनर्जक आस्तियों की पहचान करने की जरूरत है। (पैरा सं. 4.12-4.16)
- ix) बदलती हुई प्रशिक्षण जरूरतों की बैंक समीक्षा करें। (पैरा सं. 4.32)

किये गये निर्णय

बैंकों को सूचित किया जाता है कि जो अनुदेश पहले से हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाये।

नियमित रूप से अद्यतन बनाने के लिए व्यवस्था की जाये। अनुपालन की सूचना रिज़र्व बैंक को 30 अप्रैल 1999 तक दी जानी है।

चूंकि यह प्रणाली पहले ही शुरू की जा चुकी है, अतः बैंकों को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को मज़बूत बनाने के लिए इसकी प्रभावपूर्ण ढंग से निगरानी करनी होगी। आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को और मज़बूत करने के लिए जोखिम प्रबंध-प्रणालियों पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे।

बैंकों को बड़े अग्रिमों को मंजूर करने के तुरंत बाद उनके लिए ऋण समीक्षा तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए और खातों में आ रही कमज़ोरियों पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए, ताकि समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

ऋण प्रबंधन, खज़ाना प्रबंधन, व्युत्पन्न उत्पादों, आस्ति-देयता प्रबंध प्रणाली तथा जोखिम प्रबंधन, भुगतान और निपटान प्रणालियों एवं सूचना टेक्नोलॉजी पर अधिक ध्यान दिया जाये।

ANNEXURE II

Recommendations of the Committee on Banking Sector Reforms

Recommendations

- i) Banks and Financial Institutions should avoid the practice of evergreening. (Para No. 3.22)
- ii) Any effort at financial restructuring must go hand in hand with operational restructuring. With the cleaning up of the Balance Sheet, simultaneously steps to be taken to prevent/limit re-emergence of new NPAs. (Para No. 3.27)
- iii) To enable banks in difficulties to issue bonds for Tier II capital, Government will need to guarantee these instruments which would then make them eligible for SLR investment. (Para No. 3.29)
- iv) There is a need for disclosure in a phased manner of the maturity pattern of assets and liabilities, foreign currency assets and liabilities, movements in provision account and NPAs. (Para No. 3.38)

Decisions taken

The Reserve Bank reiterates that banks and financial institutions should adhere to the prudential norms on asset classification, provisioning, etc., and avoid the practice of "evergreening".

The banks are advised to take effective steps for reduction of NPAs and also put in place risk management systems and practices to prevent re-emergence of fresh NPAs.

Public Sector Banks are encouraged to raise their Tier II capital. Government guarantee to these instruments does not seem appropriate.

Banks have already been advised to put in place a formal Asset-Liability Management (ALM) system with effect from April 1, 1999. Instructions on further disclosures will be issued in due course.

Recommendations

- v) Concentration ratios need to be indicated in respect of bank's exposure to any particular industrial sector as also to sectors sensitive to asset price fluctuations such as stock market and real estate. These exposure norms need to be carefully monitored. (Para No. 3.40)
- vi) Banks should bring out revised operational manuals and update them regularly. (Para No. 4.3)
- vii) Banks to pay special attention to reporting and checking by the back offices of trading transactions. (Para No. 4.8)
- viii) There is need to institute an independent loan review mechanism especially for large borrowal accounts and to identify potential NPAs. (Para No. 4.12-4.16)
- ix) Banks to review the changing training needs. (Para No. 4.32)

Decisions taken

Banks are advised to strictly comply with instructions which are already in place.

Arrangements should be put in place for regular updating. Compliance has to be reported to RBI by April 30, 1999.

While the system is already in place, banks are required to monitor this vigorously to strengthen their internal control systems. Detailed guidelines on risk management systems will be issued to further strengthen the internal control systems.

Banks should ensure a loan review mechanism for larger advances soon after its sanction and continuously monitor the weaknesses developing in the accounts for initiating corrective measures in time.

More focus needs to be given on Credit Management, Treasury Management, Derivative Products, ALM system and Risks Management, Payment and Settlement Systems and Information Technology.

11 नवंबर 1998
20 कार्तिक 1920 (शक)

November 11, 1998
Kartika 20, 1920 (Saka)

सभी भारतीय वाणिज्य बैंक

All Indian Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

वाणिज्य बैंकों द्वारा उनके उपयोग के लिए (अर्थात् कार्यालय और स्टाफ के निवास के लिए) पट्टा/किराया के आधार पर आवास का अर्जन

ACQUISITION OF ACCOMMODATION ON LEASE/RENTAL BASIS BY COMMERCIAL BANKS FOR THEIR USE (i.e. FOR OFFICE AND RESIDENCE OF STAFF)

वाणिज्य बैंकों द्वारा उनके उपयोग के लिए (अर्थात् कार्यालय और स्टाफ के निवास के लिए) पट्टा/किराये के आधार पर आवास अर्जित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्ड और प्रक्रियाएं कई वर्षों से लागू हैं तथा इससे बैंकों को परिसर प्राप्त करने के प्रस्तावों की जांच के लिए उचित प्रणाली विकसित करने तथा संबंधित शर्तों का वास्तविक आकलन करने के प्रति ध्यान केन्द्रित करने में मदद मिली है। चूंकि अब प्रक्रियाओं में स्थिरता आ गयी है अतः समीक्षा करके यह निर्णय लिया गया है कि अब से अनुसरण किये जाने वाले मानदण्ड और प्रक्रियाएं बैंक स्वयं निर्धारित करेंगे। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि परिसर किराये पर लेने, भाड़ा, जमा, परिसर के मालिकों को ऋण, आदि संबंधी शक्तियां बैंकों को प्रत्यायोजित कर दी जायें।

The norms and procedures laid down by Reserve Bank of India (RBI) for acquisition of accommodation on lease/rental basis by commercial banks for their use (i.e. for office and for residence of staff) have been in operation for a number of years and have enabled banks to focus on evolving a proper system for examining proposals for securing premises and making a realistic assessment of the attendant terms and conditions. As the procedures have now stabilised, on a review, it has been decided that the norms and procedures to be followed should be henceforth left to be determined by the banks themselves. Accordingly, it has been decided to delegate to banks powers relating to hiring of premises, rentals, deposit, loans to the premises owners, etc.

2. उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम निम्नानुसार सूचित करते हैं :

2. In view of the position stated above, we advise as under :

- i) बैंकों के निदेशक मंडल को नीति निर्धारित करनी चाहिए तथा उनके उपयोग के लिए पट्टा/किराया के आधार पर परिसर अर्जित करने के संबंध में सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए ब्यौरेवार परिचालनात्मक दिशानिर्देश विभिन्न स्तरों पर शक्तियों के प्रत्यायोजन सहित, तैयार करने चाहिए। इन दिशानिर्देशों में महानगरीय, शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में अलग-अलग मानदण्ड निर्धारित किये जाने चाहिए। इन दिशानिर्देशों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संविदागत दायित्वों का अनुपालन किया जाये और परिसर किराये पर लेने/खाली करने संबंधी निर्णय भेदभावपूर्ण न हों। शक्तियां प्रत्यायोजित करते समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण केन्द्रों से भिन्न केन्द्रों के परिसर अभ्यर्पित करने या बदलने संबंधी निर्णय वरिष्ठ कार्यपालकों की एक समिति द्वारा केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर लिये जायें।
- ii) बैंकों के निदेशक मंडल परिसर संबंधी ऋणों पर तिमाही अंतरालों पर देय ब्याज की दर भी निर्धारित करें। इस प्रयोजन के लिए निदेशक मंडलों को चाहिए के वे पट्टा/किराया के आधार पर परिसर प्रदान करने वाले मकान मालिकों को स्वीकृत ऋणों के बारे में अलग नीति निर्धारित करें।

- i) Boards of Directors of the banks should lay down policy and formulate detailed operational guidelines covering all areas in respect of acquiring premises on lease/rental basis for their use including delegation of powers at various levels. The guidelines should prescribe norms separately in respect of metropolitan, urban, semi-urban and rural areas. The guidelines should ensure that the contractual obligations are complied with and the decisions taken for hiring/de-hiring of premises are non-discriminatory. While delegating powers banks may ensure that decisions for surrender or shifting of premises other than at rural centres are taken at Central Office level by a Committee of senior executives.
- ii) The banks' Boards may also determine the rate of interest on Quarterly rests on premises loans. For this purpose the Boards should lay down a separate policy in respect of loans granted to landlords who provide to them premises on lease/rental basis.

3. सभी सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए मकान मालिकों की वास्तविक शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए बैंक ऐसी शिकायतों के निपटान हेतु एक उपयुक्त प्रक्रिया तैयार करें।

4. सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया जाता है कि किराये के संबंध में बातचीत से तय संविदाओं (पट्टा/किराया के आधार पर बैंकों द्वारा लिये गये परिसरों के संबंध में रु. 25 लाख और अधिक की जमाराशियों तथा करों आदि सहित) की सूचना वर्तमान सरकारी अनुदेशों (देखें 25 अगस्त 1975 का वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग का पत्र सं. 30/22/वीआइजी/75) के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया जाना जारी रहेगा। निजी क्षेत्र के बैंकों से ऐसा अपेक्षित नहीं है।

5. कृपया इस परिपत्र को निदेशक मंडल के समक्ष सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए रखें। दिशानिर्देश यथाशीघ्र तैयार किये जायें।

6. बैंक परिसर किराये पर लेने और खाली करने के संबंध में नीति की समीक्षा के प्रयोजन के लिए गठित कार्य दल की रिपोर्ट की एक प्रति आपके मार्गदर्शन के लिए संलग्न है।

भवदीय

(राधेश्याम)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

3. In order to ensure that genuine grievances of the landlords are dealt with expeditiously keeping in view all relevant factors, banks may evolve a suitable machinery for dealing with such grievances.

4. Public Sector banks are advised that negotiated contracts in respect of rentals (including taxes etc. and deposits of Rs. 25 lakhs and above in respect of premises taken by banks on lease/rental basis will continue to be reported to Central Bureau of Investigation as per extant Government instructions {cf. Ministry of Finance, Banking Department letter No. 30/22/Vig/75 dated 25 August 1975}). This requirement is not applicable to banks in the private sector.

5. This Circular may please be placed before the Board of Directors for information and necessary action. The Guidelines may be formulated at the earliest.

6. A copy of the Report of the Working Group constituted for the purpose of reviewing the policy on hiring and de-hiring the bank premises is enclosed for your guidance.

Yours faithfully,

(Radhe Shyam)

Additional Chief General Manager

बैंक परिसर किराये पर लेने/किरायेदारी छोड़ने के संबंध में नीति की समीक्षा के लिए दल

बैंक - परिसर किराये पर लेने/किरायेदारी संबंधी नीति की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा एक कार्यकारी दल गठित किया गया था, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

1. श्री डी.आर.एस. चौधरी,
संयुक्त सचिव, बैंकिंग प्रभाग ...अध्यक्ष
2. श्री डी.टी. पै, कार्यपालक निदेशक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ...सदस्य
3. श्रीमती श्यामला गोपीनाथ,
अपर मुख्य महा प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक ...सदस्य

उक्त कार्यकारी दल ने परिसर किराये पर लेने, मकान मालिकों को अग्रिम देने, किराये संबंधी जमाराशि रखने तथा अन्य संबंधित मामलों के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों को देखा। दल ने किराये की राशि और परिसरों को लौटाने के मामलों में मकान मालिकों से आम तौर पर प्राप्त होनेवाली शिकायतों/कठिनाइयों पर भी ध्यान दिया। यह दल भारतीय बैंक संघ के सचिव तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के एक नये बैंक के अधिकारियों से भी मिला।

2. परिसर किराये पर लेने के क्षेत्र में रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप और दिशा-निर्देश जारी करने का कारण बैंकों के अपने उपयोग के लिए पट्टे/किराये के आधार पर परिसर प्राप्त करने के लिए समझौता करते समय बैंकों के बीच अस्वस्थ प्रतियोगिता से बचना था और साथ ही प्रस्तावित शर्तों के संबंध में

GROUP TO REVIEW POLICY ON HIRING/DE-HIRING OF BANK PREMISES

A Group to review the policy on hiring/de-hiring of bank premises was constituted by Government with the following Members :

- 1) Shri D.R.S. Chaudhary,
Joint Secretary, Banking Division
... Chairman
- 2) Shri D.T. Pai, Executive Director
Union Bank of India ... Member
- 3) Smt. Shyamala Gopinath, ACGM,
Reserve Bank of India ... Member

The Group looked into all guidelines issued by Reserve Bank of India relating to hiring of premises, advances to landlords, rental deposits and allied matters. It also took note of the common complaints/grievances generally received from landlords in the matter of rentals and surrender of premises. The Group also met with Secretary, Indian Banks' Association and officials of a few public sector banks and a new private sector bank.

2. The genesis to RBI intervention in the area of hiring of premises and issuing guidelines was to avoid unhealthy competition among banks while conducting negotiations for acquisition of premises on lease/rental basis for their use and to bring

अधिक एकरूपता लाना भी कारण था। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों पर लागू हैं। इसके पूरक के रूप में भारतीय बैंक संघ ने परिसर किराये और पट्टे पर लेने के संबंध में जांच सूची जारी की है।

3. रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र हैं :

- i) मकान मालिकों को अग्रिम
- ii) किराये के संबंध में उच्चतम सीमा
- iii) कर और सेवा प्रभार
- iv) पट्टे की अवधि
- v) ब्याजमुक्त जमाराशि
- vi) लेनदेनों की रिपोर्ट केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को देना
- vii) परिसर लौटाना और बदलना

4. रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों में लचीलापन है, क्योंकि निर्धारित लेनदेनों से हटकर किये गये किसी कार्य को निदेशक मंडल की समिति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। इन दिशा-निर्देशों के लिए रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और न ही कोई रिपोर्ट देने की अपेक्षा तय की गयी है।

5. परन्तु बैंकों ने परिसर किराये पर लेने/किरायेदारी छोड़ने की क्रियाविधि और प्रणालियां कमोवेश रूप में सुव्यवस्थित कर ली हैं। परंतु सरकार को पट्टे के करार के नवीकरण और परिसर खाली कराने के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ बहुत-से व्यक्तियों से शिकायत मिलती रही है। उक्त समस्याओं को निम्नप्रकार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है :

about greater uniformity on terms offered. The guidelines issued by Reserve Bank of India are applicable to public sector banks and private sector commercial banks. This was supplemented by India Banks' Association bringing out a Check-list on hiring and leasing of premises.

3. The guidelines issued by RBI cover the following major areas :

- i) Advances to Landlords
- ii) Rental ceilings
- iii) Taxes and Service charges
- iv) Period of lease
- v) Deposit free of interest
- vi) Reporting of transactions to CBI
- vii) Surrender and shifting of premises.

4. The guidelines issued by RBI have built-in flexibility as any deviation from the norms prescribed can be approved by the Committee of the Board. The guidelines do not require any approval of RBI and no reporting requirements have been prescribed.

5. However, while banks have by and large streamlined the procedures and systems for hiring/de-hiring of premises, Government has been receiving complaints from a number of individuals against public sector banks regarding renewal of lease agreement and vacation of premises by the banks. The problems can be categorised as under :

- i) पट्टे की अवधि समाप्त होने पर किराये में वृद्धि
- ii) पट्टे के जारी रहने की अवधि में करों में वृद्धि पर मकान मालिकों को क्षतिपूर्ति
- iii) पट्टे के करार का नवीकरण करने में विलम्ब
- iv) क्षेत्र की माप
- v) पट्टा विलेख का पंजीकरण
- vi) परिसर लौटाना

6. रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों से उपयोगी प्रयोजन सिद्ध हुआ है, विशेष रूप से उस समय जब बैंक शाखा लाइसेंसिकरण की नीति के अनुसार प्रति वर्ष भारी संख्या में शाखाएँ खोल रहे थे। इन दिशा-निर्देशों से मंजूरी की शर्तों में एकरूपता लाने, लागत कम करने, मकान मालिकों द्वारा की गयी अनुचित मांगों, अवांछनीय प्रथाओं का प्रतिरोध करने में सहायता मिली है। वास्तव में उक्त दल सरकारी क्षेत्र के बैंकों से चर्चा के दौरान कुछ दिशा-निर्देशों को जारी रखने के पक्ष में था, विशेष रूप से उन दिशा-निर्देशों को जो पट्टे की अवधि, अग्रिम किराया छः महीने के किराये तक के लिए सीमित करने, ऋण की मात्रा और पट्टे की अवधि में ही उसकी वसूली से संबंधित थे।

7. इस दल का यह विचार है कि अब स्थिति बदल गयी है। बैंकों ने स्वयं क्रियाविधि सुव्यवस्थित कर ली है। बैंकों को बदलते परिदृश्य में ऋणों और किराये की उच्चतम सीमा के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं का दृढ़ता से पालन करने में कठिनाइयाँ भी अनुभव हो रही हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रबंधन समिति को प्रस्तुत मामले बढ़ रहे हैं। इन शर्तों से हटने में कोई बड़े निर्णय निहित नहीं होते हैं और इससे प्रबंधन समिति पर काम का

- i) Enhancement in the rent on expiry of lease
- ii) Compensation to landlord of increase in taxes during the currency of the lease
- iii) Delay in renewing lease agreements
- iv) Measurement of area
- v) Registration of Lease Deed
- vi) Surrender of premises

6. The RBI guidelines have served a useful purpose particularly at the time when the Banks were opening a large number of branches every year in accordance with its branch licensing policy. These guidelines helped in bringing about uniformity in terms of sanction, reducing costs, resisting unreasonable demands made by landlords and undesirable practices. In fact, during the interaction the Group had with the public sector banks, they were in favour of continuation of some of the guidelines, particularly those relating to the period of lease, advance rent being limited to six months' rent, quantum of loans and recovery within lease period.

7. The Group is of the view that the situation has now changed. Banks have themselves streamlined procedures. Banks are also experiencing operational difficulties in adhering to the limits prescribed by RBI in regard to loans and rental ceilings in the changing scenario, resulting in increasing references to the Management Committee. The deviations do not involve any major

बोझ जरूर बढ़ता है और साथ ही निर्णय लेने में विलम्ब भी होता है।

सिफारिशों का सारांश

8. उक्त दल ने सूक्ष्म प्रबंधन से दूर रहने और परिचालनगत मामलों में निर्णय लेने में बैंकों को पूरी छूट देने की रिज़र्व बैंक की वर्तमान नीति सहित सभी प्रासंगिक बातों पर ध्यान दिया है। इस दल के विचार से परिसर किराये पर लेना/किरायेदारी छोड़ना पूरी तरह से एक ऐसा प्रबंधन कार्य है जिसे बैंकों के निदेशक मंडलों पर छोड़ देना ही सर्वोत्तम होगा। दल ने सिफारिश की है कि :-

- (क) विस्तृत परिचालनगत दिशा-निर्देशों के संबंध में बैंकों के निदेशक मंडल स्वयं अपनी नीति निर्धारित करें। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों में शामिल क्षेत्रों और इन दिशा-निर्देशों के संबंध में उक्त दल की सिफारिशें अनुबंध I में दी गयी हैं।
- (ख) निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित मानदंडों से हटकर किये गये किसी कार्य को प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- (ग) यदि परिसर किराये पर लेने के सभी प्रस्तावों की जांच बैंक के कार्यपालकों की आंतरिक समिति द्वारा की जाये और उनकी सिफारिशें प्रत्यायोजित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायें तो उचित होगा।

decision making and has instead resulted in increase in burden on the Management Committee and also delay in decision making.

Summary of Recommendations

8. The Group took stock of all relevant factors including RBI's present policy to move away from micro-management and give full freedom to the banks to decide on operational issues. In the view of the Group hiring/de-hiring of premises is purely a managerial function best left to the Boards of the Banks, it is recommended that :-

- (a) Boards of Banks should lay down their own policy in this regard with detailed operational guidelines. List of areas covered by guidelines issued by RBI and Recommendations of the Group regarding these guidelines are given in **Annexure I**.
- (b) Any deviation from norms laid down by the Board should be approved by Management Committee.
- (c) It will be advisable if all proposals on hiring of premises are examined by an Internal Committee of the bank's executives and their recommendations are submitted to the delegated authority.

9. यह भी मानना चाहिए कि बैंक वाणिज्यिक संगठन हैं। इस नाते परिसर का किराया बढ़ाने अथवा उसे लौटाने का निर्णय लेते समय उन्हें वाणिज्यिक पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। इन मामलों में निहित संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए दल की यह सिफारिश है कि शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में परिसर को लौटाने के मामले की जांच अनिवार्य रूप से कार्यपालकों की आंतरिक समिति द्वारा की जाये। यह समिति अपनी सिफारिशें प्रबंधन समिति को भेजेगी।

10. मकान मालिकों की सामान्य शिकायतों के क्षेत्र अनुबंध II में दिये गये हैं।

मकान मालिकों के अनुरोध पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाये। यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सभी प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक कठिनाइयों पर कार्रवाई के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करना चाहिए।

11. उक्त दल ने यह भी नोट किया है कि मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे 25 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि वाले परिसरों के संबंध में की गयी संविदाओं के सभी मामलों की रिपोर्ट केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दें। दल की सिफारिश है कि ये अनुदेश वापस ले लिये जायें, क्योंकि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को ऐसे मामलों में स्वयं ही जानकारी मिल जाती है।

(डी.आर.एस. चौधरी) (डी.टी. पै)
(श्यामला गोपीनाथ)

9. It has also to be recognised that banks being commercial organisations have to take commercial aspects into account while deciding increases in rents or surrender of premises. Keeping in view the sensitivities involved in these matters, the Group recommends that surrender of premises in urban/metropolitan areas should invariably be examined by an Internal Committee of Executives who will send their recommendations to the Management Committee.

10. The areas covering normal grievances of landlords are given in the **Annexure-2**.

In order to ensure that requests from landlords are dealt with expeditiously, keeping in view all relevant factors banks have to evolve suitable machinery for dealing with the genuine grievances.

11. The Group also noted that as per existing instructions Public Sector Banks are required to report to Central Bureau of Investigations [CBI] all negotiated contracts relating to premises involving amounts of Rs. 25 lakhs and over. The Group recommends that these instructions may be withdrawn as CBI itself gets information on such matters as and when situation so warrants.

(D.R.S. Chaudhary) (D.T. Pai)
(S. Gopinath)

अनुबंध 1 - वे क्षेत्र, जिन पर दल ने विचार किया

मौजूदा दिशा-निर्देश	सिफारिशें
1. मकान मालिकों को अग्रिम रिज़र्व बैंक के 17.5.94 के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीएल. बीसी. 60/22.01.003/94 के अनुसार मकान मालिकों को अग्रिमों के लिए तय की गयी केन्द्रवार उच्चतम सीमा निम्नप्रकार है :- ● महानगर 25.00 लाख रुपये ● शहरी केन्द्र 12.50 लाख रुपय ● अन्य केन्द्र 5.00 लाख रुपये	मकान मालिकों को ऋण देने के लिए बैंक का निदेशक मंडल अपनी नीति तय कर सकता है। इस नीति में कम से कम न्यूनतम मार्जिन, किराये आदि से वसूली की अवधि अवश्य शामिल हो। इसके परिणामस्वरूप इस संबंध में रिज़र्व बैंक के अनुदेश वापस ले लिये जाने चाहिए।
2. किराया संबंधी उच्चतम सीमा रिज़र्व बैंक के 17.5.94 के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीएल. बीसी. 60/22.01.003/94 के अनुसार तय की गयी किराये की केन्द्रवार उच्चतम सीमा निम्नप्रकार है : ● महानगर 5.00 लाख रुपये वार्षिक ● शहरी केन्द्र 2.50 लाख रुपय वार्षिक ● अन्य केन्द्र 1.00 लाख रुपये वार्षिक	यह उच्चतम सीमा हटा दी जानी चाहिए और प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए किराये की उच्चतम सीमा तय करने की बैंक को अनुमति होनी चाहिए।
3. कर और सेवा प्रभार रिज़र्व बैंक के 17.5.94 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 60/22.01.003/94 के अनुसार ऊपर उल्लिखित किराये की उच्चतम सीमा में कर और सेवा प्रभार शामिल हैं।	खरखाव और सेवा प्रभार जैसे अन्य मासिक खर्चों और करों की अदायगी के लिए अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। चूंकि स्थानीय प्राधिकारी करों में बढ़ोतरी करते हैं इसलिए अधिकतर मकान मालिक यह मांग करते हैं कि इस प्रकार के करों को बैंक वहन करें। इस क्षेत्र में बैंकों को मकान मालिकों से समझौता करने में कठिनाई होती है। इसलिए करों तथा अन्य मासिक खर्चों की बात अलग-अलग बैंक के विवेकाधिकार पर छोड़ दी जानी चाहिए। मकान मालिकों को सेवा प्रभार का भुगतान प्रदान की गयी अन्य सुविधाओं से संबद्ध होना चाहिए।

मौजूदा दिशा-निर्देश	सिफारिशें
4. पट्टे की अवधि रिज़र्व बैंक के 17.5.94 के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीएल. बीसी. 60/22.01.003/94 के अनुसार पट्टे की अवधि कम से कम 5 वर्ष हो और किराये में उचित बढ़ोतरी करके बैंक के पक्ष में आगे और 5 वर्ष का विकल्प होना चाहिए। पट्टे के करार में बैंक और मकान मालिक की पारस्परिक सहमति से आगे नवीकरण करने का खंड भी शामिल होना चाहिए।	वाणिज्यिक परिसरों से संबंधित मौजूदा मानदंड संतोषजनक ढंग से काम रहे हैं। फिर भी आवासीय परिसरों के संबंध में पट्टे की 5 वर्ष की निर्धारित अवधि लम्बी है, क्योंकि इस अवधि के लिए परिसर उपलब्ध नहीं होते। चूंकि ये परिचालनगत मुद्दे हैं, अतः इसे निदेशक मंडल पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह नीति निर्धारित करे।
5. ब्याजमुक्त जमाराशि रिज़र्व बैंक के 17 अक्टूबर 1983 के परिपत्र सं. बीएल. बीसी. 82/सी.168(61)83 के अनुसार बैंकों को अनुमति है कि वे छः महीने के किराये के बराबर राशि मकान मालिकों के पास जमा रख सकते हैं।	रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को छः महीने तक का अग्रिम किराया देने की अनुमति है। यह व्यवस्था ठीक से काम कर रही है। बैंक प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर मकान मालिकों को दिये जाने वाले अग्रिम की मात्रा तय कर सकते हैं।
6. परिसर लौटाना और बदलना रिज़र्व बैंक के 17 अक्टूबर 1983 के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीएल. बीसी. 82/सी.168(61)-83 और 17 मई 1994 के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीएल.बीसी. 60/22.01.003/94 के द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक किराया तय करने अथवा किरायेदारी कानून के अंतर्गत सुरक्षा लेने के मामले में प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।	दल ने यह नोट किया कि यह प्राथमिक चिन्ता का क्षेत्र है, क्योंकि बैंक इस संबंध में न केवल समस्या का सामना कर रहे हैं, बल्कि परिसर खाली करने/लौटाने के बारे में बैंकों/रिज़र्व बैंक/सरकार को बहुत-सी शिकायतें मिल रही हैं। दल ने यह अनुभव किया कि बैंकों को प्रचलित कानून के अनुसार किरायेदारी संरक्षा का भाग लेने का हक होना चाहिए परन्तु बैंकों को मकान मालिक की अत्यधिक कठिनाई के मामलों में आवासीय परिसर लौटाने पर विचार करना चाहिए।

मौजूदा दिशा-निर्देश	सिफारिशें
परिसर लौटाना और बदलना (जारी...)	जहां तक वाणिज्यिक परिसरों का संबंध है, दीर्घकालिक आवश्यकताओं को देखते हुए इस प्रकार परिसर खाली करना आम तौर पर आवश्यक नहीं है। इसलिए बैंक इस संबंध में प्रचलित कानूनों का लाभ लेते हुए बेदखली से अपने बचाव के लिए सक्रिय कार्रवाई कर सकते हैं। परन्तु दल ने यह भी अनुभव किया कि बैंक के लिए यह विवेकपूर्ण होगा कि पट्टे के करार को समय रहते बढ़ाया जाये, ताकि मकान मालिकों को इस बात की कठिनाई न हो कि बैंक इस प्रकार के परिसरों को लम्बी अवधि तक अपने पास रखे रहें। क्योंकि वाणिज्यिक सम्पत्ति का स्थान विशेष के अनुसार काफी मूल्य होता है इसलिए दल का यह विचार है कि इस प्रकार की वाणिज्यिक सम्पत्ति को खाली करने का बैंक यदि निर्णय ले तो बैंक चाहे तो, मकान मालिक से क्षतिपूर्ति की संभावनाओं पर विचार कर सकता है। जहां तक परिसर बदलने/लौटाने के निर्णय का संबंध है, यह महसूस किया गया है कि यह एक संवेदनशील मामला है और ग्रामीण/कस्बाई शाखाओं के मामले में मंजूर करने वाले प्राधिकारी से ऊपर के स्तर पर आवश्यक निर्णय लिया जाना चाहिए। परन्तु शहरी/महानगरीय केन्द्रों में स्थान के उच्च मूल्य की दृष्टि से निम्नलिखित स्तरों पर अनुमोदन किया जाना चाहिए:- i) शहरी केन्द्र : परिसर समिति की सिफारिश पर कार्यपालक निदेशक/अध्यक्ष ii) महानगरीय केन्द्र : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक और कम से कम दो महाप्रबंधकों की आंतरिक कार्यपालक समिति की सिफारिश पर प्रबंधन समिति

मौजूदा दिशा-निर्देश	सिफारिशें
7. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को लेनदेनों की रिपोर्ट देना रिज़र्व बैंक के 17.10.83 के परिपत्र डीबीओडी.सं. बीएल. बीसी. 82/सी/168(01)/83 के पैराग्राफ 3 के अनुसार पट्टे/किराये पर बैंक द्वारा लिये गये परिसर के मकान मालिक को अग्रिम देने और किराये को जमाराशि के रूप में रखने के 25 लाख रुपये और उससे ऊपर के सभी लेनदेनों की रिपोर्ट केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की दी जानी चाहिए जैसा कि उपर्युक्त अनुदेशों में अपेक्षित है।	चूंकि यदि स्थिति के अनुसार अपेक्षित हो तो जानकारी प्राप्त करने का केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को हर हालत में अधिकार है, इसलिए इस अपेक्षा को समाप्त कर देना चाहिए।
8. रिज़र्व बैंक के 17 अक्टूबर 1983 के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीएल. बीसी. 82/सी.168(61)-83 के अनुसार किसी भी केन्द्र पर आम तौर पर ऐसा अग्रिम नहीं दिया जाना चाहिए जिससे पट्टाकर्ता को किरायेदारी और परिसर को पट्टे पर देने का अधिकार मिल सके अथवा जिससे वर्तमान रहनेवाली पार्टी अपने उपयोग के लिए वैकल्पिक स्थान खरीद ले जिससे कि वह उस परिसर को पट्टे पर दे जिसमें वह रह रहा है।	इस मामले को अलग अलग बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।
9. रिज़र्व बैंक के 7 मार्च 1986 के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीएल. बीसी. 30/सी.168(61)-86 के अनुसार बैंक के उपयोग के लिए परिसर ग्रहण करने हेतु मकान मालिकों को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में बैंकों द्वारा लगाये जानेवाले ब्याज की दरों के संबंध में मामले पर पुनर्विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि इस प्रकार के अग्रिमों को मीयादी ऋण माना जाये और उन पर तदनुसार ब्याज लगाया जाये, जो उस समय 15 प्रतिशत था।	सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि ब्याज साधारण दर पर लगाया जाये। केनरा बैंक ने इस निर्णय के विरुद्ध समीक्षा याचिका दायर की है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि दर बाज़ार-दरों पर तय की जाती है और ऋणों पर ब्याज वाणिज्यिक दर पर लगाया जाता है, इसलिए इन दोनों मामलों को पृथक् रखा जाये और बैंक, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये ऋण संबंधी अनुदेशों के अनुसार ब्याज दर लगायें जो 2 लाख रुपये से ऊपर के ऋणों के लिए न्यूनतम मूल ऋण-दर के अनुसार हो।

अनुबंध 2 - सामान्य शिकायतें और उनके संबंध में दल के अभिमत

शिकायत	अभिमत
1. पट्टा समाप्त होने पर किराये में वृद्धि	इस संबंध में रिज़र्व बैंक ने कोई दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किया है सिवाय इसके कि वृद्धि तर्कसंगत होनी चाहिए। तथापि बैंक आम तौर पर प्रति 5 वर्ष के लिए किराये में 25 प्रतिशत वृद्धि करते हैं, जो कमोवेश ठीक से चल रहा है, हालांकि नयी दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय के कारण कतिपय महानगरों में उच्चतम किराये की मांग की जाती है। बैंक स्थान की स्थिति, करोबार आदि के आधार पर उच्चतर किराया दे रहे हैं। प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर बैंकों को किराये में वृद्धि जारी रखने की अनुमति दी जाये।
2. पट्टा चालू रहने की अवधि में करों में वृद्धि के कारण मकान मालिक को क्षतिपूर्ति शहरी और महानगरी केन्द्रों को छोड़कर अन्यत्र मकान मालिक से इस आशय का सहमति पत्र प्राप्त करने की सामान्य प्रथा है कि मकान मालिक सभी करों को वहन करेगा। कभी-कभी स्थानीय प्राधिकारी करों में काफी वृद्धि कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मकान मालिक किराये के रूप में बहुत ही कम पाते हैं। कुछ मामलों में वे दिये गये ऋणों की चुकौती करने की स्थिति में ही होते हैं।	जहां करों में वृद्धि बहुत अधिक हो वहां यदि इस प्रकार का अनुरोध उचित समझा जाये तो, बैंक पट्टे के चालू रहने की अवधि में करों के बढ़े हुए अंश को वहन करें।
3. पट्टा करार के नवीकरण में विलम्ब हालांकि बैंक पट्टे के करार के नवीकरण की कोशिश करते हैं, परन्तु बैंकों का यह अनुभव है कि मकान मालिक हमेशा बाज़ार से सम्बद्ध अधिक किराये की मांग करते हैं और पट्टा विलेख के नवीकरण में विलम्ब का एक कारण होता है।	बैंक पट्टे की समाप्ति से काफी पहले परस्पर सहमत शर्तों के अनुसार करार के नवीकरण के उपाय करें।

शिकायत	अभिमत
4. क्षेत्र की माप भारतीय बैंक संघ की जांच सूची के अनुसार चटाई क्षेत्र (कार्पेट एरिया)/ किराया क्षेत्र की अभिकल्पना लागू की गयी है, परन्तु पुराने मकान मालिक पुराने करार के अनुसार गणना किये गये क्षेत्र के अनुसार किराये के भुगतान का आग्रह करते हैं।	जिन मामलों में बैंक ने चटाई क्षेत्र को विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट नहीं किया है ऐसे मौजूदा परिसरों के संबंध में बैंक को मूल करार/सहमति पत्र में किये गये निर्देश के अनुसार किराया अदा करना जारी रखना होगा अथवा सही सही चटाई क्षेत्र को नापते हुए और समानुपातिक रूप से किराये में वृद्धि करके मकान मालिक को लाभ देना होगा, ताकि माप की नयी पद्धति के परिणामस्वरूप किराये में कमी न हो। नये परिसरों के लिए बैंक चटाई क्षेत्र के आधार पर किराया तय करने की प्रथा जारी रखें।
5. पट्टे का पंजीकरण किराये और पट्टे पर परिसर लेने के संबंध में भारतीय बैंक संघ जांच की सूची के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि पट्टा विलेख का पंजीकरण करना वांछनीय होगा। इस पर होने वाले व्यय को बैंक और मकान मालिक, अधिमानतः 50 : 50 के आधार पर बांट लें।	सहमति पत्र लेने अथवा स्टाम्प लगा करार करने की बैंकों में प्रथा है। यदि मकान मालिक पट्टा विलेख को पंजीकृत करवाने को तैयार न हों, तो बैंकों को विकल्प है कि या तो पट्टा करार पर स्टाम्प लगवा लें या पट्टा विलेख का पंजीकरण अपने खर्च से करवायें। इसे हर मामले के गुणदोष के आधार पर निर्णय हेतु बैंकों पर छोड़ दिया जाना चाहिए और जहां मौजूदा पट्टा करारों के संबंध में पंजीकरण के लिए मकान मालिक तैयार न हों वहां वे लागत वहन करें।

ANNEXURE 1 – AREAS COVERED BY THE GROUP

EXISTING GUIDELINE	RECOMMENDATIONS
1. Advances to Landlords In terms of RBI Circular DBOD No. BL.BC.60/22.01.003/ 94 dated 17.5.94, centrewise ceiling has been fixed for advances to Landlords as under - ● Metropolitan towns Rs. 25.00 lakhs ● Urban centres Rs. 12.50 lakhs ● Other centres Rs. 5.00 lakhs	Bank's Board may lay down their own policy for grant of loans to the landlords. This policy should at the minimum include minimum margin, period of recovery from rentals etc. Consequently RBI instructions in this regard may be withdrawn.
2. Rental Ceilings In terms of RBI Circular DBOD No. BL.BC.60/22.01.003/ 94 dated 17.5.94, centrewise rental ceiling has been stipulated as under :- ● Metropolitan towns Rs. 5.00 lakh p.a. ● Urban centres Rs. 2.50 lakhs p.a. ● Other centres Rs. 1.00 lakhs p.a.	The ceiling be removed and bank be permitted to fix rental ceiling taking all relevant factors into consideration. RBI's instructions may be withdrawn.
3. Taxes and Service charges In terms of RBI Circular DBOD. NO. BL.BC.60/22.01.003/ 94 dated 17.5.94, the rental ceiling includes taxes and Service charges, as mentioned above.	No separate provision has been made for payment of taxes and other monthly outgoings such as Maintenance/Service charges etc. As the local authorities make upward revision of taxes, landlords mostly demand bearing such taxes by Bank only. This is the area where the Bank is facing difficulty with the landlords for negotiation. Hence taxes and other monthly outgoings can be left to the discretion of the individual Bank. Payment of Service Charges to the landlords should be linked to the additional facilities provided

EXISTING GUIDELINES	RECOMMENDATIONS
4. Period of Lease In terms of RBI Circular DBOD. No. BL.BC.60/22.01.003/94 dated 17.5.94, the period of lease may be for a minimum of 5 years with option for further 5 years in favour of the Banks with reasonable increase in the rental. The lease agreement may also provide for a clause for further renewal of the period by mutual consent of the Banks and the landlords.	The existing norms relating to commercial premises is working satisfactorily. However, with regard to residential premises the period of lease prescribed of 5 years is too long as premises are not available for this period. In view of the fact that these are operational issues we may leave it to the Board to lay down the policy.
5. Deposit free of interest In terms of RBI Circular DBOD No. BL.BC.82/C.168/(61)83 dated 17th October 1983, Banks are permitted to keep with the landlords an amount equivalent to six months' rent.	As per the existing RBI guidelines Banks are permitted to give advance rent upto six months which is working well. Banks may decide the quantum of advance to be given to the landlords on merits of each case.
6. Surrender and shifting of premises In terms of guidelines issued by RBI vide Circular DBOD No. BL.BC.82/C. 168(61)-83 dated 17th October 1983 and DBOD No. BL.BC.60/22.01.003-94 dated 17th May 1994 the matter of fixation of standard rents or taking protection under tenancy laws, each case will have to be considered on merits depending upon the circumstances of each case.	The Group noted that this was an area of primary concern since not only were the banks facing problem in this regard, a number of complaints on vacation/surrender of premises were being received by banks/RBI/Government. The Group felt that though the banks should be entitled to avail of tenancy protection as per extant laws, Banks may consider surrender of residential premises in cases of extreme hardship of landlords.

EXISTING GUIDELINES	RECOMMENDATIONS
6. Surrender and shifting of premises (contd.....)	As far as commercial premises are concerned, keeping in view the long-term requirements, such vacation is not generally called for, the bank may actively seek to protect themselves from eviction by taking advantage of extant laws in this regard. However, the Group also felt that it would be prudent on the part of the bank to ensure that lease agreements are extended well in time so that landlords do not have a grievance that despite termination of lease agreement, banks continue to keep such premises for a long period. Since a commercial property has great site value, the Group was of the view that if the bank decides to vacate such commercial property, it could explore, if it wishes, the possibilities of availing 'compensation' from the landlord. As regards the decision for shifting/surrender of premises it is felt that this is a sensitive issue and should be decided at one level above the sanctioning authority in cases of rural/semi-urban branches. However, in view of high site value in urban/metropolitan centres, approval should be taken at the following levels :- i) Urban centres: ED/Chairman at the recommendation of Premises Committee. ii) Metropolitan: Management Committee at the recommendation of internal committee of executives comprising of CMD/ED and at least two GMs.

EXISTING GUIDELINES	RECOMMENDATIONS
7. Reporting of transactions to CBI In terms of RBI Circular DBOD. No. BL.BC.82/C.168(01)/83 dated 17.10.83, para 3, all transactions of Rs. 25 lacs and over involving grant of advances to and keeping of rental deposits with landlords of premises taken by banks on lease/rental basis should be reported to the Central Bureau of Investigation as required under the aforesaid instructions.	This be dispensed with since CBI in any case is entitled to obtain such information if situation warrants.
8. In terms of RBI Circular DBOD No. BL.BC. 82/C. 168(61)-83 dated 17th October 1983; in any centre, in general no advance should be granted either to enable the Lessor to obtain tenancy rights and to lease the premises or to enable the existing occupants to purchase alternative accommodation for their use so as to enable them to lease out the premises occupied by them.	The matter may be left to the discretion of the individual banks.
9. In terms of RBI Circular DBOD. No. BL.BC.30/C. 168(61)-86 dated 7th March 1986; regarding the rates of interest to be charged by the Banks on advances granted by the Banks to landlords for purpose of acquisition of premises for its use, the matter has been reviewed by us and it has been decided that such advances should be treated as Term Loans and charge interest accordingly which is at present 15% per annum.	The Supreme Court has ruled that interest should be charged at simple rate. Canara Bank has filed a review petition against this judgement, which is pending in the Court. As the rent is fixed on the basis of market rates and interest charged on loans is at commercial rate, these two issues may be delinked and banks may decide interest rate to be charged as per the lending directives issued by RBI with minimum PLR for the loans above Rs. 2 lacs.

ANNEXURE 2 – COMMON GRIEVANCES AND COMMENTS OF THE GROUP

GRIEVANCE	COMMENTS
1. Enhancement in the rent on expiry of lease	There are no guidelines laid down by RBI in this regard except that the enhancement should be reasonable. However, normally Banks are permitting enhancement in rent of 25% for every five years which is by and large working well although in certain metropolis there is demand for higher rent because of the recent Supreme Court judgment in N. Delhi. Banks are permitting higher rent depending upon the strategic locations, business volume etc. banks may be permitted to continue giving enhancement in rent, depending on merits of each case.
2. Compensation to landlord of increase in taxes during the currency of the lease. It is a normal practice excepting urban and metropolitan centres to obtain a consent letter from landlords that all taxes will be borne by the landlord. Sometimes, the local authorities enhance taxes substantially, as a result the landlords hardly get the amount as rent. In some cases, they are in a position to service the loans given to them.	Where enhancements of taxes are sizeable, Banks may bear the enhanced portion of taxes during the currency of lease, if such a request is considered reasonable.
3. Delay in renewing lease agreements Although the Banks are trying to get lease agreement renewed, it is experience of the Banks that landlords always demand more rent related to market and this is one of the reasons the renewal of lease deed gets delayed.	Bank should take steps well in advance of the expiry of lease to renew the Agreement on mutually agreed terms.

GRIEVANCE	COMMENTS
4. Measurement of area In terms of IBA Checklist the concept of Carpet Area/ Rent Area has been introduced. However, the old landlords insist on payment of rent according to area computed as per old agreement.	In respect of existing premises, where the Bank has not specified the areas specifically as carpet areas, bank will have to continue paying the rent as specified in the original agreement/consent letter or give the benefit to landlord, measuring exact carpet area and proportionately increasing the rent so that as a result of new method of measurement it does not reduce the rentals. For new premises, Banks may continue the practice of fixing rent on carpet area.
5. Registration of Lease In terms of Checklist on Hiring and Leasing of premises, of IBA, it has been stipulated that it is desirable to get the Lease Deed registered. The expenses on account of this be shared between the Bank and the landlord, preferably on 50:50 basis.	It is a practice in the Banks to obtain a Consent letter or stamped agreement. If the landlords are not prepared to have the lease deeds registered, option for the Banks is available either to continue the stamped lease agreement or get the deed registered at its own cost. This may be left to the Bank to decide depending upon case to case and bear the cost where landlords are not prepared for registration in respect of existing lease agreements.

बैंपविवि.सं.बी.पी.बीसी.108/21.01.023/98

DBOD.No. BP.BC.108/21.01.023/98

17 नवंबर 1998
26 कार्तिक 1920 (शक)

November 17, 1998
Kartika 26, 1920 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(except Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

विदेशी अंशदान (विनियमन)
अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विदेशी
अंशदानों की स्वीकृति

ACCEPTANCE OF FOREIGN
CONTRIBUTIONS UNDER FOREIGN
CONTRIBUTION (REGULATION)
ACT, 1976

उक्त विषय पर कृपया 22 अप्रैल 1997 का हमारा
पत्र सं. बैंपविवि. बीपी. 2573/21.01.023/97
देखें।

Please refer to our letter No. DBOD. BP.
2573/21.01.023/97 dated 22nd April 1997
on the above subject.

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976
की धारा 10 (क) के प्रावधानों के अनुसार, अनेक
संघों/संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से
मना किया गया है। भारत सरकार से प्राप्त ऐसे 39
संगठनों/संघों की सूची आपकी जानकारी के लिए
प्रेषित की जा रही है। साथ ही, अधिनियम की
धारा 5 के अंतर्गत कई संगठनों को राजनीतिक
स्वरूप के संगठन घोषित किया गया है, जो
राजनीतिक दल नहीं हैं। ऐसे 129 संगठनों की एक
सूची भी इसके साथ प्रेषित की जा रही है।

In accordance with the provisions of Section
10(a) of Foreign Contribution (Regulation)
Act, 1976; a number of Associations/
Organisations have been prohibited from
receiving foreign contribution. A list of 39
such Organisations/Associations received
from Government of India, is forwarded
herewith for your information. Further, a
number of Organisations have been declared
as being Organisations of a political nature,
not being a political party, under Section 5
of the Act, A list of 129 such Organisations
is also forwarded herewith.

आपसे अनुरोध है कि अपनी सभी शाखाओं को यह
अनुदेश दें कि वे इन संघों/संगठनों के खातों पर
विशेष निगरानी रखें तथा उक्त संघों/संगठनों द्वारा

Your are advised to instruct all your branches
to keep a special watch on the accounts of
these Associations/Organisations and bring

अधिनियम के प्रावधानों के किसी प्रकार के उल्लंघन को गृह मंत्रालय की जानकारी में लायें। इस संबंध में जारी किये गये अनुदेशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जाना चाहिए तथा हमारी जानकारी में आये किसी भी उल्लंघन को गंभीरतापूर्वक लिया जायेगा।

भवदीय

(ए. एल. सिंहमार)

उप महा प्रबंधक

to the notice of the Ministry of Home Affairs any violation of the provisions of the Act by the above mentioned associations/ organisations. The instructions issued in this regard should be followed scrupulously and any violations coming to our notice will be viewed by us seriously.

Yours faithfully,

(A.L. Sinhmar)

Deputy General Manager

List of association, not specified in Section 4 of the Foreign Contribution (Regulation) Act 76 which have been prohibited under Section 10 (a) from accepting foreign contribution.

No.	Name & Address of the association/persons	No. & date of order
1.	2.	3.
1.	Rural Action in Development, Distt. Cuddapah, (AP)	52(19)-FCRA (MU-III) dated 12-5-1986
2.	Jamiatul-Hidaya, P.O. Box 2 Manpur, Sarva Ramgarh Road, Jaipur, Rajasthan.	6(99) 84-FC-I dated 18-11-85
3.	Bhopal Technical Vocational Trg. Centre, Arera Colony, Bhopal, M.P.	66(387) 85-FC (MU - II) dated 26-8-86
4.	Shri R. Kamalanathan, Trichi, T.N.	8 (14) 83-FC-I dated 27-6-85
5.	Beracah Christian Mission, Trichi, Tamil Nadu.	-do-
6.	Smt. Helen Rebeca, Trichi, T.N.	-do-
7.	Siloam Christian Aid Mission P (Ltd.) Trichi, Tamil Nadu.	-do-
8.	Action for Peoples Participation and Environment Care, A-62, Ashoka Marine Drive, Ernakulam, Kochin, Kerala.	8 (16) / 87-FC-I dated 2-6-87
9.	Social Action Movement of Idukki, Palianimala, Distt., Idukki, Kerala.	8 (17) / 87-FC-I dated 2-6-87
10.	High Ranga Integrated Development, Society for the Social Amity, AP Vill, 124, Moozhikatt Building Annexe, Ayyapancoil, P.O., Idukki, Kerala.	8 (19) / 87-FC-I dated 2-6-87
11.	Society for Action with the Poor H. No. 126, Ward No. V, Mangavath, Parvirizha, Puthonamthitta P.O., Adoor, Kerala.	8 (20) / 87 - FC - I dated 2 - 6 - 87

No.	Name & Address of the association/persons	No. & date of order
1.	2.	3.
12.	Shri Krishvardan Behari Lal, Hingwale, 17 Koregaon, Pune	8(2) / 88-FC 103(1) / 87-(MU) dated 8-1-1988
13.	Shri Surendra Mohan Singh, Flat No. 103, yegi park, 12 A, Koregaon, Pune.	-do-
14.	Shri Narain Dass, c/o Shri R.K. Aggarwal, Yok and Yeti Appts., Bund Garden Road, Pune.	8(2) 88 / FCRA 103(1) / 87-FC (MU) dated 8-1-88
15.	Shri Lal Prassad Singh, 99/2, Yerawada, Pune.	8(2) / 88-FC-I 103(1) / 87-FC (MU) dated 8-1-88
16.	Mrs. Hemlata Das Boziers, 33, Koregoan park, Pune.	-do-
17.	Jaspal Singh, 32, Koregoan park, Pune, Maharashtra.	-do-
18.	Ashok Kumar Bhaskar, C-2, Sparter Luxury Decan College Road,	-do-
19.	Shri Devendra Singh Bewal, 17, Koregoan Park, Pune.	-do-
20.	Shri Vishwabandhu Shukla 352/9, Boat Club Road, Pune.	-do-
21.	Shri. Mukesh K. Barde Satyam Flat, No. 405 - B, Simpti Road, Boriwali (W), Mumbai - 92.	-do-
22.	Narender Kumar Gulab Chand Jain, 32, Koregoan Park, Pune.	-do-
23.	Islamiya College, Kutiyadi, Calicut Distt. Kerala.	8(5) / 88-FC-I dated 3-3-88
24.	Community Service Society, 5/83, Keelaperuvalla, Asaripallam, Nagarcoil, Kanyakumari, T.N.	8(21) / 88-FC-I dated 8 / 11-7-88

No.	Name & Address of the association/persons	No. & date of order
1.	2.	3.
	Changed Address: 52-D, New Colony, Tuticorin - 8, T.N.	
25.	Society for Peoples Action for Development, 11- 4- 5 Donica Road, Chenchupet, Tenali, Guntur, A.P.	8(33) / 88-FC-I dated 8-12-88
26.	Konkani Project Awaj Datta Prasad Building, M.G. Road, Panaji, Goa.	10(3) / 89-FC-I dated 29-6-89
27.	Vikas parishad, Ganghi Nagar, Koraput, Orissa.	8(1) / 90-FC-I 52(20) / 89-FC-II dated 27-3-90
28.	Children's Development Communities India, 134, Banerjee Road, Calcutta.	8(6) / 92-FC-I dated 14-5-92
29.	Madras Church of Christ, 11, Shenoy Road, Nangamalekam, Madras, T.N.	8(9) / 93-FC-I dated 19-4-93
30.	New Life Community Development Society, Jaipur, Rajasthan.	8(17) / 93-FC-I dated 29-10-93
31.	Tibetan Culture & Education Foundation, Bangalore, C-10, Devatha Plaza, Residency Road, Bangalore, Karnataka.	8(5) / 94-FC-I dated 3-8-94
32.	J&K Muslim Conference, Wazirabag, H.N. 114, Sadar Manzil, Srinagar, J&K.	9(14) / 95-FC-I dated 20-8-96
33.	Falah-E-Aam, C/O C.M. Butt, Village Lathishah, Sapore, Baramula, J&K.	-do-
34.	Alamdard Trust, C/O Muslim Auquf Trust, Mujahid Manzil, J&K.	-do-

No.	Name & Address of the association/persons	No. & date of order
1.	2.	3.
35.	Public Relief Trust, C/O Prof. Yunus-Al-Umar, Islamic Study Circle, Auqaf Building, Badshah Chawk, Srinagar, J&K.	9(14)/95-FC-I dated 20-8-96
36.	Anjumane Hullamia Educational Association, Hussamia Building, Panjishah, Hyderabad.	8(23) / 96-FC-I dated 19-12-96
37.	Asian Aid Organisation Welfare Trust, 55 Kodandarama Gardan, 3rd Stages, Cox Town, Bangalore.	8(24) / 96-FC-I dated 9-01-97
38.	Christ's Helping Hand Children's Home, Alcot Garden, Near BGR High School, Rajamundry, A.P.	8(2) / 98-FC-I dated 31-03-98
39.	St. Joseph's Region (Province) C.S.T. Fathers, Aluva - 683 101, Kerala.	8(4) / 98-FC-I dated 20-04-98

**List of organisations of Political nature (not being a political party) Notified
under Section 5(1) of the Foreign Contribution (Regulation)
Act 76 (As on may 98)**

Sl. No.	Name of the Organisation	Notification No. Date of Notification S.I. No. in Notification
1.	2.	3.
		SO No. 177 (E) dated 18.2.1977
1.	All India Kisan Sabha (AIKS/CPI), 4, Windsar place, New Delhi.	(1)
2.	Bhartiya Khet Mazdoor Union, 4, Windsar Place, New Delhi.	(2)

Sl. No.	Name of the Organisation	Notification No. Date of Notification S.I. No. in Notification
1.	2.	3.
3.	All India Trade Union Congress, New Delhi.	(3)
4.	All India Kisan Sabha (AIKS/NPM) 4, Ashoka Road, New Delhi.	(4)
5.	Centre for Indian Trade Unions, 15, Talkatora Road, New Delhi.	(5)
6.	Bhartiya Mazdoor Sangh, Ram Naresh Bhawan, Pahargunj, New Delhi - 55.	(6)
7.	Indian National Trade Union Congress 4, Bhai Veer Singh Marg, New Delhi.	(8)
8.	United Trade Union Congress, Calcutta.	(9)
9.	National Front Indian Trade Unions 10, Government Palace East Ezra Mansion, Calcutta.	(12)
10.	All India Federation of University & College Teachers Organisations Calcutta.	(13)
11.	All India LIC Employees Federation, Bombay.	(14)
12.	All India Bank Employees Federation, Delhi.	(15)
13.	All India Defence Employees Federation, Pune.	(16)
14.	All India State Government Employees Federation, Hyderabad.	(17)
15.	All India Railwaymen's Federation, New Delhi.	(18)
16.	All India Railway Worker's Federation, New Delhi.	(19)

Sl. No.	Name of the Organisation	Notification No. Date of Notification S.I. No. in Notification
1.	2.	3.
17.	Bharatiya Railway Mazdoor Sangh, Mumbai.	(20)
18.	All Indi Loco Running Staff Association, Lumding, Assam.	(21)
19.	All India Federation of Electricity Employees, Residency Road, Sadar, Nagpur.	(23)
20.	National Federation of Post & Telegraph Employees (K.L. Moja Group), New Delhi.	(24)
21.	Trade Union Co-ordination Centre, 28, Gurudwara, Rakabganj Road, New Delhi.	(25)
22.	Progressive Labour Union, Durgapur, West Bengal.	(26)
23.	Keral Trade Union Front, Chettiangadi, Trichur.	(27)
24.	Swatantra Thozilali Union, State Muslim League Office, Calicut.	(28)
25.	Swathantra Thozhilali Union, Mavoor, Calicut.	(29)
26.	Labour Progressive Federation, Arivagam, Rayapuram, madras.	(30)
27.	Anna Thozhir Sangha Paravani, Madras.	(31)
28.	State Central Labour Union, Srinagar.	(32)
29.	Sarva Shramik Sangh, Mumbai.	(33)
30.	Bhartiya Kamagar Sena, Mumbai.	(34)

Sl. No.	Name of the Organisation	Notification No. Date of Notification S.I. No. in Notification
1.	2.	3.
31.	National Labour Co-ordination Council, Calcutta.	(35)
32.	United Trade Union Congress Calcutta.	(36)
33.	National Labour Organisation, Ahmedabad.	(37)
34.	All India Student Federation, New Delhi.	(38)
35.	All India Youth Federation, New Delhi.	(39)
36.	Student Federation of India, 11, Windsor Place, New Delhi.	(40)
37.	Democratic Youth Federation of India (CPM), 11, Windsor Place, New Delhi.	(41)
38.	Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad, Mumbai.	(43)
39.	All India Democratic Student Organisation, 48, Lenin Sarani, Calcutta.	(46)
40.	Comsomal, Calcutta.	(47)
41.	Revelutionary Youth Front, 124/C, Lenin Sarani, Calcutta.	(48)
42.	Progressive Student Union, Calcutta.	(49)
43.	progressive Democratic Students Union, Hyderabad.	(50)
44.	Radical Student Union, Hyderabad.	(51)
45.	Punjab Student Union.	(52)
46.	All India Sikh Students Federation, Amritsar.	(54)

Sl. No.	Name of the Organisation	Notification No. Date of Notification S.I. No. in Notification
1.	2.	3.
47.	West Benagal Chhatra Parishad Calcutta.	(61)
48.	National Federation of Indian Women, New Delhi.	(63)
49.	Nikhil Banga Mahila Sangha, Calcutta.	(67)
50.	Islamic Study Circle, Red Cross Road, Opp. Hazi Masjid, Maisuma, Srinagar.	(72)
51.	Awami Action Committee, J&K.	(73)
52.	J&K People's League, Srinagar.	(76)
53.	Tribal Front, Agartala.	(82)
54.	All India Muslim Masjis -e- Mushwarat, E 3, Abdul Fazal Enclave Okhla, New Delhi.	(85)
55.	Tabligh Jammat, Bangle Wali Masjid, Nizammudin Basti, New Delhi.	(86)
56.	Citizens for Democracy, New Delhi.	(89)
57.	Nag Vidharbha Andolan Samiti Nagpur.	(92)
58.	Marathwada janata Vikas Parishad Saraswati Bhavan, Sikshan Prasarak Mandal College, Aurangpura, Aurangabad.	(94)
59.	Maharashtra Ekikaran Samiti, Sahar Samiti karyalya, Jalti Math, Near Kapil theatre, Kirloskar Road, Bangalore.	(95)
60.	The Kannada Paksha, 31, Nanje Gowds Road, Mavalli, Bangalore.	(96)

Sl. No.	Name of the Organisation	Notification No. Date of Notification S.I. No. in Notification
1.	2.	3.
61.	Dravida Kazhagam, Periyyar Tahaidal, 50, EVK, Sampath Road, Madras - 7.	(98)
62.	Tamil Nadu Toilers Progressive Party, Madras.	(100)
63.	The Neelchakra, Dolamundai, Cuttack.	(103)
64.	Dalit Panthars, Wadala, Bombay.	(104)
65.	Dalit Panthara, Bhawani Path, Pune.	(105)
66.	People Union for Civil Liberties, 8, Sahayog Apartments, Mayur Vihar, Phase 1, New Delhi.	(106)
67.	People Union for Democratic Right, Qr. No.4, IP.College, Delhi University, New Delhi.	(106)

SO No. 792 (E)
date 16-09-80

68.	All India Insurance Employees' Association, Calcutta.	(1)
69.	All India National Life Insurance Employees' Federation, Bombay.	(2)
70.	National Federation of Indian Railwaymen, New Delhi.	(3)
71.	Institute of Indian Labour, Calcutta.	(4)
72.	National Federation of Posts & Telegraph (Shahi Bhushan Group), New Delhi.	(5)

Sl. No.	Name of the Organisation	Notification No. Date of Notification S.I. No. in Notification
1.	2.	3.
73.	Indian National Plantation Workers Federation Dibrugarh, Assam.	(6)
74.	Anand Marg, Calcutta.	(7)
75.	Protutist Universal, New Delhi.	(9)
76.	Volunteer Social Service, Allahbad.	(10)
77.	Seva Dharam Mission, Varanasi, U.P.	(11)
78.	Education Relief and Welfare Sector, Panditya Road, Calcutta.	(12)
79.	Anand marg Universal Relief Team, Calcutta.	(13)
80.	Universal Proutists Student Federation, New Delhi.	(14)
81.	jamat -e- Islami Hind, Dawat Nagar Abdul Fazal Enclave, Okhala, New Delhi.	(15)
82.	Rashtriya Swayam Sewak Sangh, Hedgewar Bhavan, Nagpur.	(16)
83.	Shiromani Gurudwara Prabhandak Committee, Golden Temple, Amritsar.	(17)
84.	Delhi Gurudwara Prabhandak Committee, Mata Sundri Lane, New Delhi.	(18)
85.	Anjuman Nasrat -Ul- Islam, Srinagar.	(20)
86.	Jammu & Kashmir Muslim Auqaf Trust, Zero Brigade, Srinagar.	(21)
87.	Jammu & Kashmir Muslim Auqaf Trust, Srinagar.	(22)
88.	All India Pease and Solidarity Organisation, K,1/16, Chitranjan Park, Main Road, New Delhi.	(23)

Sl. No.	Name of the Organisation	Notification No. Date of Notification S.I. No. in Notification
1.	2.	3.
89.	Indian Society for Cultural Co-operation and Friendship (ISCUF/CPI), 1, Lady Harding Road, Opp. Marina Hotel, Cannaught Place, New Delhi.	(24)
90.	All Indo-Korean Friendship Association, New Delhi.	(26)
91.	Indo-China Friendship Association, New Delhi.	(29)
92.	National Federation of Progressive Writers, 110, Kansal Bhavan, K.G. Marg, New Delhi.	(31)
93.	Moral Re-armament (MRA), Pachgani, Maharashtra.	(34)
		S.O. No. 380(E) dated 27-05-98
94.	Iranian Students Islamic Association (ISIA) or Union of Iranian students Islamic Association (UISIA), Bangalore.	(2)
95.	Indian Youth Congress (I), New Delhi.	(3)
96.	National Students Union of India (I), 5, Raisina Road, New Delhi.	(5)
97.	Yuva Janata, New Delhi.	(7)
98.	Janata Yuva Morcha, New Delhi.	(8)
99.	Tamir -e- Millat, Hyderabad.	(9)

Sl. No.	Name of the Organisation	Notification No. Date of Notification S.I. No. in Notification
1.	2.	3.
100.	Student Islamic Movement In India, (SIMI), 151, -C, Zakir Nagar, New Delhi.	(10)
101.	Student Islamic Movement In India, (SIMI), Aligarh.	(12)
102.	Mahase -e- Azadi, J&K.	(18)
103.	Jammat Ahle -e- Hadis, J&K.	(19)
104.	Rastra Sevika Samiti, Wardha, Maharashtra,	(20)
105.	Vishwa Hindu Parishad (VHP), Bombay.	(21)
106.	Hind Mazdoor Sabha, Bombay.	(23)
107.	Yuva Lok Dal, 3 Pt., Plant Marg, New Delhi.	(24)
108.	Dal Khalsa, Chandigarh.	(25)
109.	Jamat Ahle hadis or All India Ahle Hadis, 4116 Ahle Hadis Manzl, Urdu Bazar, Delhi.	(26)
110.	Jammat -e- Islami, Bulbul, Bagullah.	(27)

**S.O. No. 4(E)
dated 04-01-84**

111. Deeni Talimi Council, Luknow, (1)

Sl. No.	Name of the Organisation	Notification No. Date of Notification S.I. No. in Notification
1.	2.	3.
		S.O. No. 478(E) dated 07-08-86
112.	Islamic Welfare Trust, P.O., Ommessary, Koduvalli (via), Calicut Distt., Kerala.	(2)
113.	Orissa Gramin Mazdoor Sangh, Santapur, Bhubaneswar Distt., Puri, Orissa.	(3)
		S.O.No. 456(E) dated 27-04-87
114.	All India Cofederation of Bank Officer Organisations, Pandayan House, Ferere Road, Mumbai - 38.	(1)
		S.O. No.920(E) dated 05-10-88
115.	Iqbal Memorial Trust, bemina, Sromagar, Kashmir.	(1)
116.	All Assam Students Union, Gauhati University Campus, Jhalukhari, Guahati, Kamrup Distt., Assam.	(2)
117.	Assam Jatiyatabadi Yuba Chhatra Parishad, Silpukri, Guahati, Assam.	(3)

Sl. No.	Name of the Organisation	Notification No. Date of Notification S.I. No. in Notification
1.	2.	3.
118.	All India Railway Employee Confederation, 26/12, Railway colony, Kishanganj, Delhi - 7.	(5)
119.	Kisan Seva Samiti, Chhatarpur, M.P.	(6)
120.	Ishaat -e- Islam Trust, 1353, Chitli Qabar, Delhi.	(8)
121.	A.K. Gopalan Bhavan Trust, 27-29, Bhia Veer Singh Marg, Gole Market, New Delhi.	(9)
		S.O. No. 262(E) dated 05-04-89
122.	Indian National Plantation Workers Federation, Suit 125, 25A, Park Street, Calcutta - 16.	(6)
		S.O. No. 856(E) dated 09-11-90
123.	William Carey Study and Research Centre, Calcutta.	(1)
124.	All India Agricultural Workers Union, 12 B, Feroze Shah Road, New Delhi.	(1)
125.	All India Democratic Women's Association, 23, Vithal Bhai Patel House, Rafi Marg, New Delhi.	(2)
126.	All India Milli Council, 161/32, Joga Bhai, Jamia Nagar, New Delhi - 25.	(3)

Sl. No.	Name of the Organisation	Notification No. Date of Notification S.I. No. in Notification
1.	2.	3.
127.	All India Youth League, 62 North Avenue, New Delhi.	(4)
128.	Damdami Taksal, Gurudarshan Prakash Chowk, Mehta, New Delhi.	(5)
129.	Akhand Kirtni Jatha.	(6)

18 नवंबर 1998
27 कार्तिक 1920 (शक)

November 18, 1998
Kartika 27, 1920 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

ऐसे लेनदेन जिनके बारे में सभी प्रलेखों में स्थायी खाता सं. (पीएएन) या सामान्य सूचकांक रजिस्टर (जीआइआर) संख्या दी जानी है – केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3 में जारी 9 अक्टूबर 1998 की अधिसूचना

TRANSACTIONS IN RELATION TO WHICH PERMANENT ACCOUNT NO. (PAN) OR GENERAL INDEX REGISTER (GIR) NUMBER TO BE QUOTED IN ALL DOCUMENTS-NOTIFICATION DATED 9TH OCTOBER, 1998 ISSUED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART II, SECTION 3 BY CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

आयकर नियमावली, 1962 में नियम 114 बी से 114 डी शामिल करने के संबंध में उक्त विषय पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने 9 अक्टूबर 1998 को एक अधिसूचना जारी की है जो 1 नवंबर 1998 को लागू हो गयी है। अतः 12 अगस्त 1976 के परिपत्र में निहित पिछले अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है :

The Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance have issued Notification dated 9th October 1998 on the above subject regarding insertion of Rule 114B to 114D in the Income Tax Rules 1962 which has come into force with effect from 1st November 1998. Banks are, therefore, in supersession of the earlier instructions contained in the circular dated 12th August 1976 advised as under :

2. उक्त नियम 114 बी के अनुसार, हर व्यक्ति को निम्नलिखित लेनदेनों के संबंध में सभी प्रलेखों में अन्य बातों के साथ-साथ अपनी पीएएन या जीआइआर संख्या लिखनी चाहिए।

2. In terms of Rule 114B ibid, every person should quote his PAN or GIR Number in all documents pertaining, among other things, to the following transactions :

(क) बैंकिंग कंपनी के पास, जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू है (उक्त अधिनियम की धारा 51 में उल्लिखित किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित) रु. 50,000 से अधिक की मीयादी जमाराशि;

(ख) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खण्ड (एच) में परिभाषित प्रतिभूतियों को बिक्री या खरीद के लिए रु. 10 लाख से अधिक मूल्य की संविदा;

(ग) बैंकिंग कंपनी, जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू है (उक्त अधिनियम की धारा 51 में उल्लिखित किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित) के पास खाता खोलना ।

नियम के अनुसार किसी व्यक्ति को तब तक जीआइआर संख्या उद्धृत करनी है जब तक उसे स्थायी खाता संख्या आबंटित न कर दी जाये ।

3. अधिसूचना में निम्नलिखित का भी प्रावधान किया गया है :-

(क) जहां खाता खोलने वाला व्यक्ति अवयस्क हो तथा जिसकी किसी आय पर आयकर नहीं लगाया जाना हो, वह अपने पिता या माता या अभिभावक की, जैसी स्थिति हो, स्थायी खाता संख्या या सामान्य सूचकांक रजिस्टर संख्या उक्त लेनदेनों संबंधी प्रलेखों में लिखेगा;

(a) A time deposit, exceeding Rs. 50,000 with a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in Section 51 of that Act);

(b) A contract of a value exceeding Rs. 10 lakh for sale or purchase of securities as defined in clause (h) of Section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(c) Opening an account with a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in Section 51 of that Act).

The rule provides that a person shall quote GIR Number till such time the permanent account number is allotted.

3. The notification also provides for the following :-

(a) where a person making an application for opening an account is a minor and who does not have any income chargeable to income tax, he shall quote the Permanent Account Number or General Index Register Number of his father or mother or guardian, as the case may be in the document pertaining to the transaction;

(ख) उक्त लेनदेन करने वाले किसी व्यक्ति को यदि स्थायी खाता संख्या या सामान्य सूचकांक रजिस्टर संख्या आबंटित न की गयी हो, तो वह उक्त लेनदेन के ब्यौरे देते हुए फार्म सं. 60 (प्रति संलग्न) में घोषणा करेगा। ग्राहकों की सुविधा के लिए शाखाओं में फार्म सं. 60 छपवाकर पर्याप्त मात्रा में रखा जाये।

4. इसके अलावा, उक्त नियम 114 सी के अनुसार,

(क) जिसके पास कृषि संबंधी आय है तथा अन्य ऐसी कोई आय नहीं है जिस पर आयकर लगाया जाना हो, उन्हें उक्त लेनदेनों के संबंध में फार्म सं. 61 (प्रति संलग्न) में घोषणा करनी होगी तथा

(ख) उक्त किसी प्रकार के लेनदेन के लिए अनिवासी (अधिनियम की धारा 2 के खण्ड 30 में यथाविनिर्दिष्ट) अपने पासपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करेंगे।

5. अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे आयकर नियमावली 1962 के संबंध में उक्त नियम 114 (बी), 114 (सी) के प्रावधानों का अनुपालन करें तथा ग्राहकों की सुविधा के लिए फार्म सं. 60 और 61 छपवाकर पर्याप्त मात्रा में शाखाओं में रखें।

भवदीय

(सी.आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

(b) any person who enters into any transaction specified above and who has not been allotted a Permanent Account Number or General Index Register Number shall make a declaration in Form No. 60 (copy enclosed) giving therein the particulars of such transaction. The Form No. 60 be got printed and stocked adequately in branches for customers' convenience.

4. Further, in terms of Rule 114C *ibid*,

(a) those who have agricultural income and are not in receipt of any other income chargeable to Income Tax would have to make a declaration in Form No. 61 (copy enclosed) in respect of the transactions referred to above and

(b) Non Residents (as specified in Clause 30 of Section 2 of the Act) shall furnish his copy of the passport in respect of any transactions referred to above.

5. The banks are therefore, advised to comply with the provisions of the above Rules 114(B), 114(C) in respect of the Income Tax Rules 1962 and also get the Form No. 60 and 61 printed and stocked adequately in branches for customers' convenience.

Yours faithfully

(C.R. Muralidharan)
General Manager

"Form No. 60"
[see third proviso to rule 11 4B]

From of Declaration to be filed by a person who does not have either a Permanent Account Number or General Index Register Number and who makes payment in cash in respect of transactions specified in clauses (a) to (h) of rule 11 4B.

1. Full name and address of the declarant
2. Particulars of transaction
3. Amount of transaction
4. Are you assessed to tax? Yes/No
5. If yes,
 - (i) Details of Ward/Circle/Range where the last return of income was filed?
 - (ii) Reasons for not having Permanent Account Number/General Index Register Number?
6. Details of the document being produced in support of address in column (1)

Verification

I, _____ do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

Verified today, the _____ day of _____ 19 _____

Date _____

Place _____

(Signature of the declarant)

Instructions : Documents which can be produced in support of the address are :

- a) Ration Card
- b) Passport
- c) Driving licence
- d) Identity Card issued by any institution
- e) Copy of the electricity bill or telephone bill showing residential address
- f) Any document or communication issued by any authority of Central Government, State Government or local bodies showing residential address.
- g) Any other documentary evidence in support of his address given in the declaration

"Form No. 61"
[see proviso to clause (a) of rule 114C]

Form of Declaration to be filed by a person who has agricultural income and is not in receipt of any other income chargeable to income tax in respect of transactions specified in clauses (a) to (h) of rule 114B.

1. Full name and address of the declarant
2. Particulars of transaction
3. Details of documents being produced
in support of address in column (1) Yes/No

I hereby declare that my source of income is from agriculture and I am not required to pay income tax on any other income if any.

Date _____

Place _____

(Signature of the declarant)

Verification

I, _____ do hereby
declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

Verified today, the _____ day of _____ 19 ____

Place _____

(Signature of the declarant)

Instructions : Documents which can be produced in support of the address are :

- a) Ration Card
- b) Passport
- c) Driving licence
- d) Identity Card issued by any institution
- e) Copy of the electricity bill or telephone bill showing residential address
- f) Any document or communication issued by any authority of Central Government, State Government or local bodies showing residential address.
- g) Any other documentary evidence in support of his address given in the declaration

28 दिसंबर 1998
7 पौष 1920 (शक)

December 28, 1998
Pausha 7, 1920 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

मौद्रिक और ऋण नीति उपाय - पूंजी पर्याप्तता अनुपात - वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी बांडों/प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों पर जोखिम भार

**MONETARY & CREDIT POLICY
MEASURES - CAPITAL ADEQUACY
RATIO - RISK WEIGHT ON BANK'S
INVESTMENTS BONDS/SECURITIES
ISSUED BY FINANCIAL
INSTITUTIONS**

कृपया उपर्युक्त विषय पर 31 अक्टूबर 1998 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 103/21.01.002/98 का पैरा 2(ग) देखें।

Please refer to paragraph 2(c) of our circular DBOD.No.BP.BC.103/21.01.002/98 dated October 31, 1998 on the captioned subject.

2. यह निर्णय लिया गया है कि उक्त परिपत्र के अनुबंध - 1 में दी गयी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सूची में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (हुडको) को शामिल कर लिया जाये जिसके बांड और डिबेंचर बैंकों के पूंजी पर्याप्तता अनुपात हेतु 20% के जोखिम भारत के लिए पात्र होंगे।

2. It has been decided to include "Housing and Urban Development Corporation Ltd. (HUDCO)" in the list of All India Financial Institutions (AIFIs) given in the Annexure I to the above mentioned circular, whose bonds and debentures would qualify for risk weight of 20% for capital adequacy ratio of banks.

भवदीय

Yours faithfully,

(सी.आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

(C.R. Muralidharan)
General Manager

29 दिसम्बर 1998
8 पौष 1920 (शक)

December 29, 1998
Pausha 8, 1920 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और
प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण
मानदण्ड प्राकृतिक आपदाओं द्वारा
प्रभावित कृषि ऋण

**PRUDENTIAL NORMS ON INCOME
RECOGNITION, ASSET CLASSI-
FICATION AND PROVISIONING -
AGRICULTURAL LOANS AFFECTED
BY NATURAL CALAMITIES**

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग द्वारा जारी
अनुदेशों (देखें 21 जुलाई 1998 के परिपत्र
आरपीसीडी. सं. पीएलएफएस. बीसी. 9/
05.01.04/98-99 के साथ पठित 20 जून 1998
का परिपत्र आरपीसीडी. सं. पीएलएफएस. बीसी.
128/05.04.02/97-98 के अनुसार जहां प्राकृतिक
आपदाएं कृषि ऋणकर्ताओं की चुकौती की क्षमता
कम कर देती हैं, वहां बैंकों को राहत उपाय के रूप
में निम्नलिखित के बारे में स्वयं निर्णय लेने की
अनुमति दी गयी है, (क) अल्पकालिक उत्पादन
ऋण को मीयादी ऋण में परिवर्तित करना अथवा
चुकौती की अवधि को पुनर्निर्धारित करना और
(ख) 20 जून 1998 के उक्त परिपत्र के पैरा 2(v)
में उल्लिखित विभिन्न दिशा-निर्देशों के अधीन नये
अल्पकालिक ऋण स्वीकृत करना। हम सूचित करते
हैं कि परिवर्तन या पुनर्निर्धारण के ऐसे मामलों में,
मीयादी ऋण तथा नये अल्पकालिक ऋण को चालू
देयताओं के रूप में माना जाये तथा उनका वर्गीकरण
अनर्जक आस्तियों के रूप में करने की आवश्यकता
नहीं है। इन ऋणों का आस्ति वर्गीकरण इसके बाद

In terms of the instructions issued by RPCD
(c.f. Circular RPCD. No. PLFS.BC.128/
05.04.02/97-98 dated June 20, 1998 read
with RPCD. No. PLFS.BC. 9/05.01.04/98-
99 dated July 21, 1998), where natural
calamities impair the repaying capacity of
agricultural borrowers, banks have been
permitted to decide on their own as a relief
measure, (a) conversion of the short-term
production loan into a term loan or re-
schedulement of the repayment period and
(b) the sanctioning of fresh short-term loan,
subject to the various guidelines indicated
in para 2(v) of the above mentioned circular
dated June 20, 1998. We advise that in such
cases of conversion or re-schedulement, the
term loan as well as fresh short-term loan
may be treated as current dues and need not
be classified as NPA. The asset classification
of these loans would thereafter be governed

संशोधित शर्तों द्वारा प्रबंधित होगा तथा उसे अनर्जक आस्ति तभी माना जायेगा यदि ब्याज और/या मूलधन की किस्त पहले देय होने के बाद दो फसल मौसमों तक, परन्तु 4 मार्च 1998 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 17/21.04.048/98 में दर्शाये अनुसार दो छमाहियों से अनधिक अवधि के लिए अदत्त बनी रहे।

भवदीय

(सी.आर. मुलीधरन)
महा प्रबंधक

by the revised terms and conditions and would be treated as NPA if interest and/or instalment of principal remains unpaid, after it has become past due, for two harvest seasons but for a period not exceeding two half years as indicated in our Circular DBOD.No.BP.BC.17/21.04.048-98 dated March 4, 1998.

Yours faithfully,

(C.R. Muralidharan)
General Mangar

31 दिसम्बर 1998
10 पौष 1920 (शक)

December 31, 1998
Pausha 10, 1920 (Saka)

सोना/चांदी/प्लेटिनम का आयात करने के लिए
प्राधिकृत सभी नामित बैंक

All the nominated Banks authorised to
import Gold/Silver/Platinum

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

स्वर्ण ऋण

GOLD LOAN

कृपया 6 मार्च 1998 का परिपत्र ए.डी. (जी.पी. श्रृंखला) परिपत्र सं. 7 देखें, जिसके द्वारा नामित एजेंसियों/बैंकों को 180 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए ऋण के आधार पर सोना आयात करने की अनुमति दी गयी है। देश में उपलब्ध सोने के भंडार को जुटाने और उन्हें पुनर्नियोजित करने के लिए बैंकों को हाल ही में यह भी सूचित किया गया था कि वे स्वर्ण जमा योजना तैयार करें जिसके अंतर्गत सोने की वास्तविक जमा स्वीकार करना आवश्यक है।

Please refer to circular A.D. (G.P. Series) Circular No. 7 dated March 6, 1998 permitting the nominated agencies/banks to import gold on loan basis for a maximum period of 180 days. With a view to mobilising and recycling the gold stocks available in the country, the banks were also recently advised to formulate the Gold Deposit Scheme which entailed acceptance of physical deposits of gold.

2. बैंकों से हमें ऐसे अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि उन्हें आभूषण उद्योग को स्वर्ण ऋण प्रदान करने की अनुमति दी जाये। यह निर्णय लिया गया है कि नामित एजेंसियों को निर्यात-आयात नीति 1997-2002 तथा हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ दि एक्जिम पॉलिसी के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर स्वर्ण (धातु) ऋण स्वीकृत करने की अनुमति दी जाये :

2. We have been receiving requests from banks to permit them to extend gold loans to jewellery industry. It has been decided to permit nominated agencies to grant gold (metal) loans as per Export Import Policy 1997-2002 and the Hand Book of Procedures of the Exim Policy subject to the following conditions :

- (i) बैंकों को निर्यात आयात नीति और हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स दोनों के अध्याय 8 में निहित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना

- (i) The banks should ensure strict compliance with the terms and conditions contained in Chapter 8 of both the Export Import

चाहिए। नीति के अंतर्गत यह अपेक्षा की गयी है कि सोना प्राप्त करने वाले निर्यातक को ऋण के आधार पर सोना निर्मोचित किये जाने की तारीख से 120 दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर निर्यात पूरा करना है। अतः ऐसे ऋण की अवधि 120 दिनों से अधिक नहीं होगी। नामित बैंकों को नीति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार निर्यातक से निर्यातों का आवश्यक सबूत प्राप्त करना होगा तथा उसे राजस्व प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात पूरा करने में निर्यातक द्वारा चूक किये जाने पर नामित एजेंसियों को शुल्क की राशि और संबंधित स्थानीय करों का वहन करना होगा। अतः नामित बैंक पर्याप्त अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त करें ताकि चूक होने की स्थिति में शुल्क/कर संबंधी अपेक्षाएं पूरी की जा सकें। राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का, जिनमें बंधक-ग्रस्त (बांडेड) वाल्ट, रिकार्डों के रखरखाव, निर्यातकों के लिए एक बार का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने, निर्यातकों के स्तर पर होने वाली चूक के मामलों की रिपोर्टिंग तथा चूक की स्थिति में शुल्क की राशि जमा करने संबंधी दिशा-निर्देश शामिल हैं, सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

Policy and Hand Book of Procedures. The policy requires that the exporter who has obtained the gold, has to complete the exports within a maximum period of 120 days from the date of release of gold on loan basis. The period of such loan shall therefore not exceed 120 days. The nominated banks will have to obtain necessary proof of exports from the exporter as stipulated in the policy and furnish them to the Revenue authorities. In the event of default on the part of the exporter to complete the exports within the stipulated period, the nominated agencies will have to bear the duty amount and the relative local taxes. Therefore, nominated banks may obtain sufficient additional security so as to meet the duty/tax requirements in the event of default. The guidelines issued by the Revenue authorities including those regarding bonded vault, maintenance of records, obtaining one time registration certificate of the exporters, reporting cases of failure on the part of exporter and deposit of the duty amount in case of default should be meticulously observed.

(ii) ऋण सिर्फ आभूषण निर्यात करने वालों को ही दिये जाने चाहिए। उधारकर्ताओं से लिये जाने वाले ब्याज को अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण ब्याज-दर के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

(iii) 6 मार्च 1998 के उक्त ईसीडी परिपत्र के अनुसार स्वर्ण उधार तथा स्वर्ण जमा पर प्रारक्षित निधि संबंधी सामान्य अपेक्षाएं लागू होंगी। प्रारक्षित निधियां रखने के प्रयोजन के लिए सोने का मूल्यन सूचना देने वाले शुक्रवार को बंदी के समय डालर रुपया हाजिर दर के साथ गुणित सूचना देने वाले शुक्रवार को लंदन में प्रातः की निर्धारित दर पर आधारित होना चाहिए। पूंजी पर्याप्तता तथा तुलनपत्र के प्रयोजनों के लिए स्वर्ण ऋणों को रुपये में रूपांतरित करने के लिए उसी दर का प्रयोग किया जा सकता है।

(iv) भारत में आभूषणों के निर्यातकों के लिए दिये जाने वाले ऋण पूंजी पर्याप्तता तथा अन्य विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के अधीन होंगे।

(v) सोने के उधार तथा ऋण से उत्पन्न होने वाली बेमेल स्थितियां बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित विवेकपूर्ण जोखिम सीमाओं के भीतर होनी चाहिए।

(ii) The loans should be given only to jewellery exporters. Interest charged to the borrowers should be linked to the international gold interest rate.

(iii) The gold borrowings in terms of ECD circular dated March 6, 1998 referred to above and gold deposits will be subject to normal reserve requirements. Valuation of the gold for the purpose of maintaining reserves will be based on the London morning fix rate on reporting Friday crossed with closing dollar rupee spot rate on the reporting Friday. The same rate may be applied for translating gold loans to rupees for capital adequacy and balance sheet purposes.

(iv) The loan to the jewellery exporters in India will be subject to capital adequacy and other prudential requirements.

(v) Any mismatch arising out of the gold borrowings and lendings should be within the prudential risk limits approved by the bank's Board.

3. विदेश से उधार लिये गये/देशी बाज़ार से जुटाये गये तथा आभूषण निर्यात करने वालों को

3. The gold borrowed from abroad/ mobilised in the domestic market and lent

उधार दिये गये सोने की रिपोर्ट नामित बैंकों द्वारा बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे विवरण में की जानी चाहिए।

4. बैंकों को स्वर्ण ऋण देने में शामिल समग्र जोखिमों की पहचान करनी चाहिए तथा उपर्युक्त जोखिम प्रबंधन नियंत्रण और ऋण नीति तैयार करनी चाहिए। नीति के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ प्रति निर्यातक दी जाने वाली सोने की मात्रा तथा किसी एक समय बकाया रहने वाले ऐसे ऋणों की कुल मात्रा संबंधी सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

भवदीय

(देवकी मुत्तुकृष्णन)
महा प्रबंधक

to jewellery exporters may be reported in the statement being submitted to DBOD by the nominated banks.

4. The banks should recognise the overall risks in granting gold loans and lay down an appropriate risk management and lending policy. The policy should among others lay down a limit on the quantity of gold that may be supplied per exporter as also the total quantity of such loans that may be outstanding at any point of time.

Yours faithfully,

(Devaki Mathukrishnan)
General Manager

भाग XI
बैंकों में हिन्दी का प्रयोग

SECTION XI
USE OF HINDI IN BANKS

2 जून 1998
12 ज्येष्ठ 1920 (शक)

June 2, 1998
Jyestha 12, 1920 (Saka)

अध्यक्ष एवं प्रबंद निदेशक
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

The Chairman and Managing Director,
All Public Sector Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

हिन्दी संवर्ग का निर्माण और हिन्दी पदों को भरना

FORMATION OF HINDI CADRE AND FILLING UP OF HINDI POSTS

आपका ध्यान राजभाषा के प्रयोजन हेतु अलग संवर्ग निर्मित करने के संबंध में संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के प्रथम खंड में दी गयी सिफारिशों पर भारत के राष्ट्रपति के आदेश की ओर आकर्षित किया जाता है। इसकी सूचना गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राजभाषा विभाग के 30 दिसम्बर 1988 के संकल्प सं. 1/20012/1/87-01(ए-1) द्वारा दी गयी है। इससे पहले भारत सरकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) ने 27 अप्रैल 1981 के कार्यालय ज्ञापन सं.ओ.एम. सं. 13035/3/80-ओ.एल.(सी) द्वारा अनुदेश जारी किये थे। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) ने भी 1987 में एक स्टाफिंग पैटर्न जारी किया था, जिसे 1990 में संशोधित किया गया था।

Your attention is invited to the orders of the President of India on recommendations in the First Part of the Report of the Committee of Parliament on Official Language, regarding formation of separate cadre for Official Language purpose as advised by the Ministry of Home Affairs, GOI, Dept. of Official Language vide their resolution No. 1/20012/1/87-01 (A-I) dated 30th Dec. 1988. Earlier, the Government of India, Ministry of Home Affairs (Dept. of O.L.) had issued instructions vide O.M. No. 13035/3/80-O.L.(C) dated 27th April 1981. Further, the Ministry of Finance, (Banking Division) have also issued a Staffing Pattern in 1987, which was revised in 1990.

2. इस मामले पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 17 अक्टूबर 1996 को हुई 69वीं बैठक में चर्चा की गयी थी (देखें कार्यविवरण का पैरा 3(ii) (ख) और (ग)। बैंकों से स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त की गयी थी। स्थिति की समीक्षा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 21 अप्रैल

2. The matter was discussed in the 69th meeting of Official Language Implementation Committee of public sector banks held on 17th October 1996 (vide para 3 (ii) (b) and (c) of the minutes). Status Reports were obtained from the banks. The

1997 को हुई 71 वीं बैठक में की गयी थी और बैंकों से कहा गया था कि वे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग द्वारा निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार विभिन्न स्तरों पर राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठायें।

3. हम यह सूचित करते हैं कि संसदीय राजभाषा समिति ने मार्च 1997 में रिज़र्व बैंक के दौरे के समय कहा है कि कतिपय बैंकों ने अपने बैंकों में राजभाषा संवर्ग निर्मित नहीं किया है और यह कि अनेक पद रिक्त हैं। अतएव समिति यह चाहती है कि बैंक राजभाषा संवर्ग बनाने और संबंधित रिक्त स्थानों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठायें।

4. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से मामले में आवश्यक कार्रवाई करें। समिति के आदेश का पालन करने के लिए की गयी अथवा प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना हमें भेजें।

भवदीय

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

position was reviewed in the 71st meeting of OLIC held on 21st April 1997 and banks were advised to take effective steps to ensure posting of Rajbhasha Officers at different levels as per staffing pattern laid down by Government of India, Ministry of Finance (Banking Division).

3. We advise that the Committee of Parliament on Official Language, during its visit to RBI in March 1997, observed that certain banks had not formed the Official Language Cadre in their banks and that a number of posts were lying vacant. The Committee has, therefore, desired that banks may take necessary steps to form an Official Language Cadre and fill up the related vacancies.

4. Banks are advised to take necessary action in the matter with the approval of the Board of Directors. The action taken or proposed to be taken to comply with the Committee's Orders may be advised to us.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

26 जून 1998
5 आषाढ़ 1920 (शक)

June 26, 1998
Aashadha 5, 1920 (Saka)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

The Chairman and Managing Director,
All Public Sector Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा
कार्यान्वयन समिति की 75वीं बैठक -
अनुवर्ती कार्रवाई

**75TH MEETING OF OFFICIAL
LANGUAGE IMPLEMENTATION
COMMITTEE OF PUBLIC SECTOR
BANKS - FOLLOW-UP ACTION**

कृपया 27 अप्रैल 1998 को बंगलूर में आयोजित
उक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 75वीं बैठक
का कार्यविवरण देखें जिसमें निम्नलिखित प्रस्तावों
पर चर्चा की गयी थी:

Please refer to the Minutes of the 75th
Meeting of Official Language
Implementation Committee held on 27th
April 1998 at Bangalore in which the
following proposals came up for discussion :

1. (क) बैंकों में सीधी भर्ती हेतु वांछित
योग्यताओं में हिन्दी में प्रवीणता को
शामिल किया जाये।

1(a) Proficiency in Hindi may be included
in the desirable qualifications for the
purpose of direct recruitment in banks.

(ख) विशेषज्ञ/तकनीकी पदों के लिए भर्ती के
समय जिनके पास हिन्दी का कार्यसाधक
ज्ञान न हो उनके लिए नियुक्त के बाद
तीन वर्ष में ऐसा ज्ञान प्राप्त करना
अनिवार्य किया जाये।

(b) Acquiring working knowledge of
Hindi within **three years** from the
date of recruitment should be made
compulsory for specialised/technical
post holders in case the incumbents
did not have such knowledge at the
time of their recruitment.

2. सभी स्टाफ-सदस्यों (अधीनस्थ स्टाफ को
छोड़कर) की 'कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों' में
राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने में उनके योगदान से

2. 'Performance Appraisal Reports' of all
members of staff (excepting sub-staff)
should contain an item (column) regarding

संबंधित मद शामिल की जाये और इस मद के लिए समुचित अंक आबंटित किये जायें। स्व-मूल्यांकन फार्म में भी इस मद का समावेश किया जाये। जिन बैंकों में पहले ही ऐसा किया जा रहा है, वे इसे जारी रखें।

3. राजाभाषा कार्यान्वयन समिति की उक्त बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि उपर्युक्त प्रस्तावों के संबंद में कोई निर्णय लेने के पहले बैंकों के विचार प्राप्त किये जायें। अतः अनुरोध है कि आप निदेशक मंडल द्वारा विचार किये जाने के बाद उक्त प्रस्तावों पर अपने बैंक के विचारों से हमें अवगत करायें।

भवदीय

(राजेश्वर गंगवार)

महा प्रबंधक

the contribution in increasing the use of Official language with appropriate mark allotted to this item. This item should also be included in the Self Appraisal Form. The banks who are already doing so, may continue this.

3. In the OLIC Meeting it was agreed that views of banks should be first obtained before taking any decision in regard to the above mentioned proposals. We shall, therefore, be glad if you send us your bank's views on the proposals after consideration by the Board of Directors.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Gangwar)

General Manager

7726



